संपादकीय

रिजर्व बैंक के लिए आगे की राह

गत दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 90वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा कि बैंक

ने देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। दीर्घावधि की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए वित्तीय स्थिरता एक अनिवार्य शर्त है। इस समय रिजर्व बैंक इस महत्त्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मना रहा है और यह उचित अवसर है कि संस्थान न केवल अपनी अतीत की उपलब्धियों को सामने रखे बल्कि भविष्य के लिए अपनी योजनाएं भी प्रस्तुत करे। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि वृहद आर्थिक स्थिति और नियामकीय चुनौतियों में निरंतर बदलाव आ रहा है।साफ कहें तो केंद्रीय बैंक बीते दशकों में अपने दायित्वों और कार्यों के साथ निरंतर विकसित हुआ है। समय-समय पर मतभेद के बावजूद सरकार ने इस सफर में रिजर्व बैंक को विधिक और सांस्थानिक सहायता मुहैया कराई है। इन बातों का यह आशय कतई नहीं है कि भारत की व्यवस्थाएं पूरी तरह खामी रहित हैं लेकिन बीते वर्षों में जो विकास हुआ है वह भी सकारात्मक दिशा में है।हाल के वर्षों के सबसे अहम घटनाक्रम में एक रहा है आरबीआई अधिनियम में संशोधन करना ताकि उसे मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाले केंद्रीय बैंक में बदला जा सके। विभिन्न धड़ों के विरोध के बावजूद सरकार मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत बनाने के विचार पर सहमत है। इस बात ने मौद्रिक नीति के संचालन को अधिक पारदर्शी बनाया है और निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की है।हाल के समय में कुछ भ्रम की स्थिति बनने पर रिजर्व बैंक ने यह दोहरा कर सही किया कि वह मुद्रास्फीति को लक्षित करने के विधिक अधिदेश का पालन करेगा। इसके अलावा वृहद आर्थिक स्थिरता में सुधार की एक वजह रिजर्व बैंक द्वारा बाह्य क्षेत्र का कुशल प्रबंधन भी है। उसने अवसरों का लाभ लेकर बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार खड़ा किया जिसने मौद्रिक अस्थिरता को समाप्त किया।रिजर्व बैंक ने वृहद आर्थिक प्रबंधन को लेकर हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है। बहरहाल, बैंकिंग नियमन और निगरानी में सुधार की गुंजाइश है। यह अच्छी बात है कि बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज में कमी आई है तथा इस समय यह क्षेत्र तकरीबन एक दशक में सबसे बेहतर स्थिति में है। परंतु यह तथ्य बरकरार है कि बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय संकट के पहले और बाद में रिजर्व बैंक की निगरानी में अतियों की स्थिति बनी। हालांकि यह सही है कि रिजर्व बैंक के पास सरकारी बैंकों के नियमन के मामले में सीमित शक्ति है। इसे जरूरी कानूनी बदलावों की मदद से हल करने की आवश्यकता है।हाल ही में येस बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल ओवरसाइट सर्विसेज लिमिटेड जैसे दो उदाहरण बताते हैं कि हमें अपनी निगरानी व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। विनियमित संस्थाओं से निपटने के मामले में पारदर्शिता को लेकर भी चिंताएं हैं। उदाहरण के लिए नियामक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मामले में आगे बढ़कर सूचनाएं दे सकते थे। बल्कि ऐसी संस्थाओं से निपटना आने वाले वर्षों में एक बड़ी चुनौती बनेगा।भारतीय रिजर्व बैंक ने तकनीक को अपनाने की सुविधा देने के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। भारत पेमेंट सॉल्युशंस के मामले में दुनिया में अग्रणी देश है लेकिन उसे नए दौर की फिनटेक कंपनियों द्वारा तकनीक का इस्तेमाल करने से उत्पन्न होने वाले अनचाहे परिणामों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। कुछ इस तरह जिससे नवाचार प्रभावित न हो। रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी की दिशा में भी पहल की है, हालांकि यह देखना होगा कि इसे किस हद तक अपनाया जाता है।रिजर्व बैंक औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक नहीं है। सरकार को उसे स्वायत्त रूप से काम करने देना चाहिए और उसकी सांस्थानिक स्थिति का सम्मान करना चाहिए। उसके कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार को जरूरी कानूनी बदलावों पर विचार करना चाहिए ताकि बैंकिंग नियमन में उसे मजबूती दी जा सके। सरकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह राजकोषीय घाटे में कमी लाए ताकि मौद्रिक नीति के संभावित राजकोषीय दबदबे के जोखिम को कम कियाजा सके।

राहुल गांधी की हिम्मत, विपक्ष की हिम्मत

यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वह अपने सबसे विश्वसनीय, साहसी, अथकपरिश्रम करने वाले राहुल गांधी को वह साथ नहीं देती है जो उसे देना चाहिए। कांग्रेसियों को यह समझना चाहिए कि विपक्ष राहुल की विश्वसनीयता की वजह से ही एक गठबंधन में आने के लिए राज़ी हुआ। विपक्ष की एकता और राहुल की विश्वसनीयता इस चुनाव में सबसे बड़ी ताकत हैं। मोदी और हैटट्रिक के बीच बड़ी दीवार! यह चुनाव कांग्रेस हारे या जीते राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापितहो गए हैं। अब यह सवाल खत्म हो गया कि राहुल राजनीति में रहेंगे या नहीं ?या उन्हें रहना चाहिए या नहीं ? राहुल एक स्वाभाविक नेता की तरह पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।उन्हीं की मेहनत, हिम्मत, घुटने के असहनीय दर्द के बाद भी दो-दो भारतयात्राओं ने ही विपक्ष को जोड़ा। ममता बनर्जी जो बार बार छिटक रही थीं,बंगाल में कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर दिया वे भी दिल्ली कीरामलीला मैदान की रैली में अपनी पार्टी के नेताओं को पहुंचाती हैं औरकहती हैं कि मैं इन्डिया गठबंधन के साथ हूं।

शकील अख़्तर

यह सब किस की वजह से? राहुल के बन गए प्रभामंडल की वजह से! कोई माने या न माने आज की तारीख में राहुल भारतीय राजनीति के ऐसे चेहरे बन गए हैं जिनके इर्द गिर्द यह पूरा चुनाव होने वाला है। भाजपा ने हजारों करोड़ रूपया राहुल की छवि खराब करने के लिए ऐसे ही नहीं लगाया! उन्हें राजनीति की समझ है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी अगर बार बारवंशवाद की बात करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते। वे जानते है कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे विरोधी नेता हैं जिनकी वजह से कांग्रेस एक बनी हुई है और जो विपक्ष को भी खींच कर एकजुट कर सकते हैं। और भाजपा, मोदी का आकलन सही निकला भी। अब विपक्षी एकता बन गई है। कल तक किसी को यकीन नहीं था। आज भी विश्वास नहींहोता था। मगर यह सच है। और दिल्ली के रामलीला मैदान की मीटिंग के बाद लगताहै कि विपक्ष मोदी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया।

यह मजबूत दीवार राहुल ने ही बनाई है। और इसे भेदना इस बार नरेंद्र मोदी के लिएमुश्किल हो रहा है। इसलिए मोदी बार बार अपने मुद्दे बदल रहे हैं। उनकेपुराने हिन्दु मुसलमान और उग्र राष्ट्रवाद के मुद्दे इस बार बिल्कुल नहींचल रहे। इसलिए वे कभी भ्रष्टाचार और कभी पांच साल, दस साल बीस साल बादक्या करूंगा, जैसी हवा-हवाई बाते कर रहे हैं। जबकि जनता इस समय राहुल केरोजगार, मंहगाई और लोकतंत्र बचाओ के मुद्दों को सुन रही है।

यह ऐसे ही नहीं हुआ। राहुल ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। बहुत आलोचनासही है। कई बार उन्हें बुरी तरह खारिज कर दिया गया। मगर जैसे आग में तपकर सोना कुंदन हो जाता है वैसे ही राहुल हो गए। बीस साल कम नहीं होते। उनकी हर तरह की परिक्षाएं ली गई। और यह काम तोखुद कांग्रेसियों ने किया। राहुल का विरोध उनके रास्ते में बाधाएं खड़ीकरना उनके खिलाफ अफवाहें फैलाकर उनका चरित्रहनन करना जितना भाजपा और संघपरिवार ने किया उससे कम कांग्रेसियों ने नहीं किया। आखिर 2019 में राहुलको कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही पड़ा था! और उस पर भीकांग्रेसियों को चैन नहीं आया तो जी 23 के नाम से एक गिरोह बनाकर उन्हेंकांग्रेस से ही बाहर करने का षडयंत्र रचा था।

भाजपा करे। मोदी जी करें तो समझ में आता है। उन्हें लगता है कि जब तकराहुल या गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस में है कांग्रेस खतमनहीं होगी। लेकिन अगर गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस से हट जाए या राजनीतिसे हट जाए तो कांग्रेस को वे गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे।

उनको यह लगना सही भी है। परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस में न रहने परकांग्रेस कितने टुकड़े हो जाएगी कहना मुश्किल है। और केवल कांग्रेस हीखत्म नहीं होगी विपक्ष की राजनीति भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। देश में कोईदूसरा राष्ट्रीय दल नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का अकेलासाम्राज्य होगा। और मोदी जी चक्रवर्ती सम्राट! लगता है कांग्रेस को इसमें ज्यादा आपत्ति नहीं होगी।

विपक्ष के दूसरेदलों को भी नहीं उन्हें अपने विस्तार की संभावनाएं दिखाई देंगी। थोड़ीभाजपा नेताओं को होगी क्योंकि मोदी को कोई चुनौती न होने के बाद उनका अस्तित्व और कमजोर हो जाएगा। अभी वैसे ही भाजपा का कोई नेता अपना कोईसम्मान या महत्व नहीं रखता है। और जब मोदी जी के लिए कोई चुनौती ही नहींबचेगी तो फिर भाजपा नेता बिल्कुल ही महत्वहीन हो जाएंगे। किसी के बदल भीकोई भी बिठाया जा सकता है। आज राजनाथ सिंह और गडकरी को टिकट मिल गया।लेकिन जैसा कि एक आकलन हम बता रहे हैं उसके बाद राजनाथ या गडकरी, डाहर्षवर्धन और बिजय गोयल की श्रेणी में चले जाएंगे।

लेकिन इस पर केवल आपत्ति नहीं अस्वीकार्य होगा भारत की जनता को। देश की गरीब आमजनता को। गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस में न होना तो जनता कोअनाथ कर जाएगा। बेसहारा। यह कोई वंशवाद नहीं है। आम जनता की दुःख तकलीफों के साथ अगर कोई सबसेज्यादा खड़ा हुआ है तो वह यही परिवार है। मोतीलाल नेहरू से लेकर आज राहुलतक और किसने इतने संघर्ष किए हैं? त्याग, बलिदान किया। दो दो सदस्य देश कीएकता और अखंडता के लिए शहीद हुए। इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी जैसी कुर्बानियां कोई दे सकता है? यहां तो आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीकिसान आंदोलन में यह कहते हुए आते हैं कि कह देना अपने मुख्यमंत्री सेजिन्दा वापस जा रहा हूं! किसानों से ऐसा डर! तो भारत की जनता नेहरू-गांधी परिवार से प्यार करती है तो नाराज भी होती है। उसे हकहै इसका। इन्दिरा गांधी से भी हुई थी। उन्हें हराया। फिर वापस भी लाई।ऐसे ही 2014 और 2019 में हराया। और अगर उसे लगेगा कि फिर उसे परिवार केगरीब समर्थक रवैये की, बेरोजगार को रोजगार देने का वादा करने वाले राहुल की, महंगाई के खिलाफ लड़ने वाले की, उसके बच्चों के लिए सरकारी शिक्षादेने वाले की, उसके लिए सरकारी इलाज का इतंजाम करने वाले की जरूरत है तोवह राहुल को लाएगी। राहुल की मेहनत और धैर्य सफल होगा।

लोकतंत्र की यही खूबी है। जनता चाहती है तो वापस भी लाती है। वह वंशवाद,परिवार इन सब नकली मुद्दों पर यकीन नहीं रखती। वंशवाद क्या? क्या इस आरोपके कारण राहुल जनता के दुःख दर्द सुनना बंद कर दें ? ठीक है तो और कौनसुन रहा है? अग्निवीरों का दर्द राहुल ने उठाया ना! उसी के बादरक्षामंत्री राजनाथ सिंह को ठीक चुनाव में कहने पर मजबूर होना पड़ा किजीत गए तो इस समस्या पर विचार करेंगे। अभी तक तो मान ही नहीं रहे थे। और फिर यह युवाओं को पूछना चाहिए कि जीत गए से क्या मतलब? आज और अभी इसयोजना को निरस्त करने की घोषणा करो। क्या हो जाएगा। आपकी पार्टी पर कौनसी आचार संहिता लगती है? तो यह राहुल इम्पैक्ट है। राहुल ने इतने सालों में यही कमाया है कि अबउनकी बोली हुई कोई बात खाली नहीं जा रही है। यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वह अपने सबसे विश्वसनीय, साहसी, अथकपरिश्रम करने वाले राहुल गांधी को वह साथ नहीं देती है जो उसे देना चाहिए।कांग्रेसियों को यह समझना चाहिए कि विपक्ष राहुल की विश्वसनीयता की वजहसे ही एक गठबंधन में आने के लिए राज़ी हुआ।विपक्ष की एकता और राहुल की विश्वसनीयता इस चुनाव में सबसे बड़ी ताकतहैं। मोदी और हैटट्रिक के बीच बड़ी दीवार!

अध्यात्म

पीपल एवं पथवारी की कथा

एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रहीं थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे अन्न और धन होता है। बारह वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहु बोली ऐसी बात है। तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूँगी। गूजरी बहू रोजाना दूध-दही बेचने नहीं जाती वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध-दही का दाम माँगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूँगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध-दही का दाम माँगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है। ये भरा, डींडा पान पतूरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली पैसे ले आई बहू। बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा-मोती जगमगा रहें हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई ? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सीचूगीं। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है। मगर सासू कहती तू माँग। बहू बोली सासूजी पैसे ले आओ तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गयी। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े-मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासूजी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया मुझको कीड़ा-मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत् की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी । हे पथवारी माता! जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना।

किताबें: व्यक्तित्व निर्माण के साथ सिखाती हैं जीने की कला

आज बदलते जमाने के साथ हमारे इस दोस्त यानी किताबों का रंग-ढंग कुछ बदला-बदला रहने लगा है। जहां पहले किताबों को पढ़ते-पढ़ते उसकी सोंधी-सी महक भी हमारे मन पर छाप छोड़ा करती थी, आज किताबें डिजिटल होकर एक छोटे यंत्र में हमारी जेब में ही समा जाती हैं। हालांकि अगर कोई शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो उनके लिए यह वरदान से कम नहीं, क्योंकि वे एक जगह बैठे हुए पढ़ और सुन भी सकते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, क्योंकि इन्हें प्रकाशित करने के लिए सैकड़ों वृक्षों को काटने की आवश्यकता नहीं होती।

दीपिका शर्मा

जब कभी हम एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो यह नए विचारों, संभावनाओं और संस्कृतियों का ज्ञान अर्जित करने का मार्ग खोल देती है।' यह उक्ति वेरा नजारियान की है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं जो जीवन भर हमें एक शिक्षक की तरह सिखाती हैं। मां की तरह हर मुसीबत में हमारा साथ निभाती हैं और पिता के भांति अंगुली थामे हर परिस्थिति में सही राह दिखाने का जिम्मा उठाती हैं।

दरअसल, इनसे प्राप्त ज्ञान ही है जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कई बार बीच भंवर में ही कई रिश्ते हमें डूबता हुआ छोड़ जाते हैं, लेकिन किताबों से जुड़ा रिश्ता ही है, जो हमें कठिन दौर में सही रास्ता दिखा कर नाव पार लगाता है। किताबें हमारे दुख, दर्द, खुशी, अकेलेपन की साथी होती हैं। यही नहीं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान हस्तांतरित करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं।

यह एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए हम महान हस्तियों के बारे में आसानी से जान पाते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। कभी-कभी जीवन इतना नीरस हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। ऐसे में हम उन लोगों से चिर-परिचित होकर उनके पदचिह्नों पर चलने की प्रेरणा इन किताबों से ही हासिल करते हैं। किताबें न सिर्फ हमारा व्यक्तित्व गढ़ती, बल्कि हमें मानसिक समस्याओं से भी बचाती हैं। पढ़ने से दिमाग का अच्छा व्यायाम होता है।

पढ़ने के दौरान हमारे अंदर एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सीखते हैं। ये हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखती हैं। अगर हम अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं तो कुछ हद तक याददाश्त की कमजोरी या अवसाद से बचाने के लिए यह एक इलाज के तौर पर कारगर साबित होता है। इसके अलावा, अगर अच्छी किताबें पढ़ने के साथ-साथ हम अपने भीतर लेखन की आदत को अपना लेते हैं तो यह और बेहतर नतीजे देती है। आजकल तो चिकित्सक भी किसी बड़ी बीमारी का इलाज करते समय लिखने और पढ़ने की सलाह को इलाज के एक तरीके के तौर पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि अक्सर कई दवाइयों का दुष्परिणाम होता है कि वे तंत्रिका तंत्र पर असर डालती हैं। इससे याददाश्त कमजोर होने का भय रहता है। ऐसे में मरीज को लिखने और पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिससे दिमाग सक्रिय रूप से काम कर सके।

आज बदलते जमाने के साथ हमारे इस दोस्त यानी किताबों का रंग-ढंग कुछ बदला-बदला रहने लगा है। जहां पहले किताबों को पढ़ते-पढ़ते उसकी सोंधी-सी महक भी हमारे मन पर छाप छोड़ा करती थी, आज किताबें डिजिटल होकर एक छोटे यंत्र में हमारी जेब में ही समा जाती हैं। हालांकि अगर कोई शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो उनके लिए यह वरदान से कम नहीं, क्योंकि वे

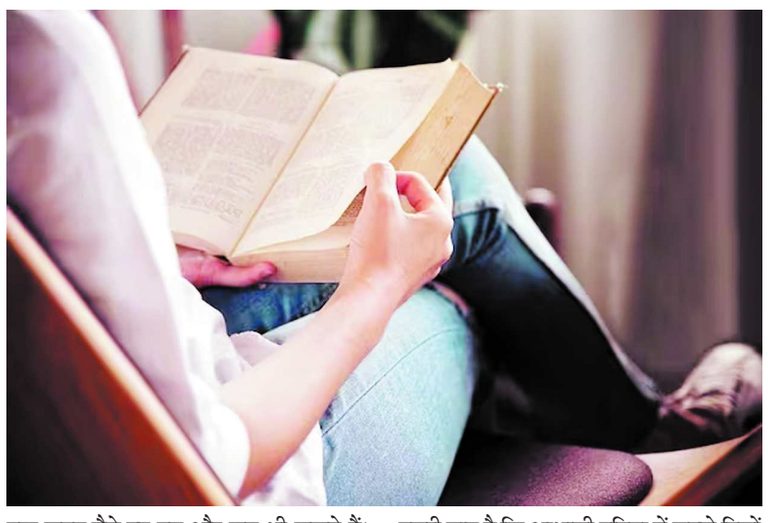

एक जगह बैठे हुए पढ़ और सुन भी सकते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, क्योंकि इन्हें प्रकाशित करने के लिए सैकड़ों वृक्षों को काटने की आवश्यकता नहीं होती।

छपी हुई किताबों को साझा कर हम सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। किताबें इस बात का भी सबूत हैं कि एक दूसरे से किताबें साझा करते समय कितने ही प्रेमी जोड़ों ने अपने दिल का पैगाम इन किताबों के जरिए साझा किया। आज सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों की मदद से कुछ लोग अपने दिल की बात महज एक क्लिक के जरिए बोल देते हैं। यह दूसरी बात है कि आभासी दुनिया में सच्चे दिलों में सिर्फ दस फीसद लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें सच्चा प्यार मिल पाता है।

यह भी देखा जाता है कि इन मंचों पर जो जितनी जल्दी पा लेता है, वह उतना ही जल्दी खो भी देता है। जब किताबों वाला इश्क हुआ करता था, तब बड़ी मशक्कत के बाद प्रेमी युगल अपने दिल की बात अपने साथी तक पहुंचा पाते थे। इस तरीके में एक डर होता था कि किताब महबूब या महबूबा के हाथों में पड़ेगी भी या नहीं और पढ़ने के बाद इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी!

कभी किताब में गुलाब रखना तो कभी मोर पंख। ऐसे कितने ही भाव हमारी किताबों से जुड़े हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी अगर हम अपनी किताबों को सीने से लगाते हैं तो न जाने कितनी ही कही-अनकही बातों की यादें ताजा हो जाती हैं। हर उम्र में किताबों के मायने बदलते जाते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो रंग-बिरंगे चित्र उसे अपनी नई दुनिया लगने लगती हैं। किशोरावस्था तक पहुंचते-पहुंचते ज्ञान के भंडार की खोज करने लगता है।

तब पाठ्यपुस्तक के साथ-साथ सहायक किताबें उसे अच्छे नंबर दिलाने का काम करती हैं। युवावस्था तक आते-आते ज्ञान का भंडार व्यक्तित्व का निर्माण करने लगता है। प्रौढ़ावस्था तक आते-आते किताबें दिल-दुनिया की तस्वीर बन जाती हैं। वहीं वृद्धावस्था में किताबों के जरिए मोक्ष का द्वारा ढूंढ़ा जाता है। दरअसल, किताबें शुरू से लेकर अंत तक हर रोज पग-पग चलना सिखाती हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक जैसे तमाम क्षेत्रों का ज्ञान हमें किताबों से ही मिलता है। मगर आज बाजारवाद के कारण किताबों में अश्लीलता ने पांव पसारे हैं। जिस कारण युवा पीढ़ी लक्ष्य से विचलित हो रही है। अच्छी किताबों से दिनोंदिन बढ़ती दूरी हमें नैतिक पतन, भौतिकवाद और आत्ममुग्ध आधुनिकता से ग्रस्त कर रही है। इसलिए जरूरी है कि हर बच्चे के अंदर नियमित और खुद ही पढ़ने-सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। पढ़ते-सीखते हुए अपने तय जीवन-लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ा जाए।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

आज माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निजी समस्याओं का निराकरण होगा। किसी रुके हुये काम के अचानक से बनने से मन प्रसन्न होगा।

वृषभ

पारिवारिक आयोजन किसी कारणवश टल सकते हैं। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। किसी के उकसावे में आकर काम न करें।

मिथुन

आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आज बुजुर्ग सदस्यों की राय अवश्य लें। भोग-विलास का भरपूर आनन्द उठायेंगे। आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा।

कर्क

शोध कार्यों में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में चुगलखोरी का शिकार हो सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में तीव्र आकर्षण रहेगा। इससे लोकप्रिय भी रहेंगे।

सिंह

कार्यक्षेत्र में आप काफी व्यस्त रहेंगे। आज धन से जुड़े मामलों को लेकर काफी सतर्क रहें। शाम के साथ मित्रों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

कन्या

नयी योजनाओं में सफलता मिलने में देर होगी। मानसिक स्थिति कुछ नकारात्मक हो सकती है। व्यर्थ में अपने शुभ चिन्तकों पर सन्देह न करें।

तुला

कारोबार से जुड़ी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। दूसरों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद न करें। रचनात्मक गतिविधियों में सुखद समय बीतेगा।

वृश्चिक

दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें। घर में कुछ रिश्तेदार आ सकते हैं। विदेश में व्यापार कर रहे लोगों को कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।

धनु

रुके हुये कार्य दोबारा से शुरू होंगे। छात्र पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। बेरोजगार लोगों को नयी जॉब मिल सकती है। किसी मांगलिक उत्सव में आप सम्मिलित हो सकते हैं।

मकर

आज आपको धैर्य और संयम के साथ अपने काम पर ध्यान देना चाहिये। दूसरों की सलाह पर ज्यादा ध्यान न दें। यदि किसी से प्रेम निवेदन करना चाहते हैं तो आज इससे बचें।

कुंभ

कार्यक्षेत्र में आपको पदोन्नति दी जा सकती है। जीवनसाथी और बच्चों से आपको प्रेम और सम्मान दोनों ही प्राप्त होगा। आपके विचारों से लोग शीघ्र प्रभावित होंगे।

मीन

परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिये दृढ़ संकल्पित रहेंगे। सहकर्मियों की तुलना में आपका प्रदर्शन विशेष और उत्कृष्ट हो सकता है।

मुश्किल वैश्विक हालात में कंपनियों की बढ़ती चुनौतियां

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम और विचारों के आदान-प्रदान पर पाबंदी में ढील उच्च आर्थिक वृद्धि का प्रमुख स्रोत थी। परंतु, इस समय चार ऐसी बातें या चुनौतियां हैं जो इस वैश्विक अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा रही हैं। दुनिया के देशों के बीच जुड़ाव एवं संपर्क बढने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होती है वहीं, अलगाव से जीडीपी कमजोर पड़ता है। चीन का प्रभाव कम करने के लिए संरक्षणवाद के खिलाफ आवाज उठाना नीति-निर्धारकों के हित में है। दुनिया में बदलती परिस्थितियों के बीच वित्तीय एवं गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए अपने संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा कर उनमें सुधार करना आवश्यक है। वे जब तक इस मोर्चे पर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वर्तमान परिस्थितियों में बेहतर कारोबार नहीं कर पाएंगे।आइए, अब हम उन चार चुनौतियों पर विचार करते हैं। वर्ष 2018 से हम 'तीसरे वैश्वीकरण के दौर में आ गए हैं। इस 'तीसरे वैश्वीकरण में विकसित देशों के साथ उन देशों का आर्थिक जुड़ाव अधिक कठिन हो गया है जो विदेश नीति एवं सैन्य मामलों में उपयुक्त एवं संतोषजनक स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। दूसरे वैश्वीकरण के दौरान यह तर्क दिया गया था कि रूस और चीन जैसे देशों को वैश्वीकरण के ताने-बाने में शामिल किए जाने के लाभ बाद में नजर आएंगे क्योंकि ये देश स्वतंत्रता की तरफ सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह गलत साबित हुआ। प्रत्येक अल्प विकसित देश को संपन्नता एवं स्वतंत्रता की तरफ बढने में कई पीढ़ियों तक संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन तृतीय वैश्वीकरण के पक्ष में दिए जा रहे तर्क में वजन दिख रहा है। दूसरा अहम बिंदु है कार्बन सीमा शुल्क (कार्बन बॉर्डर टैक्स)। कई लोग कार्बन सीमा शुल्क को संरक्षणवाद से जोड़कर देख रहे हैं जिसे उचित नहीं माना जा सकता। यूरोपीय उपभोक्ताओं ने ज्यादा कार्बन के इस्तेमाल से तैयार उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करने का समझौता किया है। यूरोपीय कार्बन सीमा समायोजन ढांचा (यूरोपीय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म) से आशय संरक्षणवाद से नहीं है बल्कि इसका संबंध यूरोप में उत्पादन या इसकी सीमा से बाहर होने वाले उत्पादन के बीच समान अवसर बहाल करना है।

लोकतंत्र को कमजोर करती है अवसरवादी राजनीति

आरती कुमारी

कांग्रेस में लगातार वफादार नेताओं का पलायन जारी है, नये नामों में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, महाराष्ट्र के जिम्मेदार एवं पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, निशाना साधने वाले मुक्केबाज विजेंदर, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बाय-बाय कर दी है। इन सभी ने कांग्रेस के मुद्दाविहीन होने, मोदी के विकसित भारत के एजेंडे, राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति एवं कांग्रेस की सनातन-विरोधी होने को पार्टी से पलायन का कारण बताया है। कुछ भी कहे, यह राजनीति में अवसरवाद का उदाहरण है, इस तरह का बढ़ता दौर चिंताजनक है। भारत की राजनीति में दलबदल की विसंगति एवं विडम्बना आजादी के बाद से लगातार देखने को मिलती रही है। पिछले साढ़े सात दशक के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पराभव के अक्स गाहे-बगाहे उजागर होते रहे हैं। दलबदल के बढ़ते दौर ने अनेक सवाल खड़े किये हैं। कल तक विपक्ष में जो नेता दागी होते थे, सतारूढ़ दल में शामिल होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनके दाग दाग नहीं रहते। राजनीति में निष्ठाएं बदलने की स्थितियां आम नागरिकों को उद्वेलित कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दागी नेता सत्ता की धारा में डुबकी लगाकर दूध का धुला घोषित हो जाता है।

हर बार चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में 'आयाराम-गयाराम' का खेल शुरु हो जाता है। विभिन्न दलों के प्रभावी नेताओं को अपने दल में शामिल कराने की होड़ मची है, कभी कोई एक दल बाजी मारती हैं तो कभी कोई दूसरा दल। सभी सेलिब्रिटी आखिर सत्ता की तरफ ही क्यों भागते हैं? पूर्व न्यायाधीश हो, पूर्व अधिकारी हो, अभिनेता हो या खिलाड़ी राजनीति में अपना भविष्य आजमाते रहे हैं। अगर भाजपा की विचारधारा किसी विजेंदर, गौरव या अनिल शर्मा जैसे लोगों हो क्यों अच्छी लगती है तो सवाल यह भी है कि पिछले पांच साल तक वे कांग्रेस में क्यों रहे? ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो गत वर्ष के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में एक पार्टी के चुनाव चिह्न पर उम्मीदवार थे तो अब दूसरी पार्टी का चुनाव चिह्न लेकर मैदान में उतरते दिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनदिनों भाजपा में जो विभिन्न दलों के तीस के लगभग राजनेता शामिल हुए हैं उनमें कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी, एसपी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता शामिल हैं। क्या यह भाजपा के निश्चित जीत की संभावनाओं का परिणाम है या केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर का परिणाम है। निश्चिय ही यह स्थिति किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये शुभ नहीं कही जा सकती। देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि दलबदल का बढ़ता दौर कैसे रूके। राजनीति एवं राजनेताओं में नीति एवं सिद्धान्तों की बात प्रमुख होनी चाहिए लेकिन ऐसा न होना लोकतंत्र की बड़ी विसंगति है। राजनीति में सबकुछ जायज है वाली सोच एवं स्वार्थ की नीति दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव का समय हर राजनेता के लिये अपने हित एवं स्वार्थ को चुनने का समय होता है, लेकिन उनके सामने लोकतंत्र के हिताहित का प्रश्न बहुत गौण हो जाता है। चुनावों में आचार संहिता के चलते कई प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में में दल-बदल पर नियंत्रण का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि यह लोकतंत्र की जीवंतता एवं पवित्रता के लिये प्राथमिकता होनी चाहिए। सत्ता का स्वाद ही ऐसा होता है कि कोई भी राजनेता इससे अछूता नहीं रहता। इसीलिए आजकल दल बदलने का दौर खूब हो रहा है। यह बात दूसरी है कि ज्यादातर नेताओं में भाजपा का दामन थामने की होड़ मची है। एक दिन पहले भाजपा पर निशाना साधने एवं जीभर कर कोसने वाले नेताओं को एकाएक भाजपा इतनी अच्छी क्यों लगने लगती है? भाजपा को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये अवसरवादी नेता जबभी उनके अनुकूल नहीं हुआ तो उसे भी बाय-बाय कर देंगे? भाजपा को यह भी देखना चाहिए कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर चंद घंटों पहले पार्टी में शामिल होने वाले को टिकट देना कहां तक उचित है। दलों को विचार करना ही होगा कि राजनीति के मायने चुनाव जीतना भर ही है या फिर वे विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देकर राजनीति को स्वस्थ रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज की ठेकेदारी राजनैतिक दलों एवं नेताओं ने ले रखी है, पर ईमानदारी से यह दायित्व कोई भी दल एवं नेता सही रूप में नहीं निभा रहा है। "सारे ही दल एवं नेता एक जैसे हैं" यह सुगबुगाहट जनता के बीच बिना कान लगाए भी स्पष्ट सुनाई देती है। राजनीतिज्ञ पारे की तरह हैं, अगर हम उस पर अँगुली रखने की कोशिश करेंगे तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। सभी दल राजनीति नहीं, स्वार्थ नीति चला रहे हैं।

भाजपा को अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है, इसके लिये वह हर-तरह के समझौते कर रही है, दागी नेताओं को भी अपनी पार्टी में जगह दे रही है। ऐसे नेताओं के अपराधों पर भी परदा डाला जा रहा है। विडंबना है कि राजनीतिक निष्ठा बदलना इन नेताओं के लिये राहतकारी साबित हुआ है। वजह यह कि इन नेताओं से जुड़े अपराध के मामले ठंडे बस्ते में डाल दिये गए हैं। जबकि दलील यह दी जाती है कि मामले बंद नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ी तो जांच और कार्रवाई भी होगी। जो विपक्ष के उन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुराग्रह एवं आग्रह के रूप में की जाती रही है। यही वजह है कि दल बदलने का फैसला राहत का रास्ता मान लिया जाता है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अचानक जांच एजेंसियां निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं? क्यों किसी एजेंसी को लेकर अदालत को कहना पड़ता है कि फलां एजेंसी पिंजरे में बंद तोता है और मालिक की बोली बोलता है। विपक्ष के ऐसे तमाम आरोपों की तार्किकता हाल में आई एक रिपोर्ट दर्शाती है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद उनमें से 23 को राहत मिल गई है। इनमें से तीन मामले बंद हो गए हैं और बीस की जांच रुकी हुई है। ऐसे अवसरवादी नेता फिर किसी नई पार्टी में नहीं जाएंगे इसको क्या गारंटी है? अच्छे लोग राजनीति में यदि सिर्फ पद पाने के लिए ही आए तो उसे क्या माना जाए? ऐसी जानी-मानी हस्तियां भी हैं जो आज यहां और कल वहां के उदाहरण पेश कर चुकी हैं। ऐसी सलेब्रिटी को पार्टी में शामिल होते ही टिकट से पुरस्कृत कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों को इस बड़ी विसंगति एवं अवसरवादिता पर विचार तो करना ही चाहिए कि आखिर कौन, किस इरादे से पार्टी में आ रहा है। ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं कि नामी-गिरामी लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया, टिकट भी मिला और चुनाव जीते भी। उसके बाद जनता से जुड़ ही नहीं पाए और अगले चुनाव में इनका टिकट कट गया। स्वस्थ राजनीति में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, सक्षम हो, सुदृढ़ हो, स्पष्ट एवं सर्वजनहिताय का लक्ष्य लेकर चलने वाला हो। लेकिन स्वार्थी, अक्षम, दागी नेताओं को किसी भी दल में जगह देना यह उस दल की मजबूती एवं स्वस्थ राजनीति पर एक बदनुमा दाग है। विडम्बना है कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, मस्तिष्क नहीं। इसका खामियाजा हमारा लोकतंत्र भुगतता है, भुगतता रहा है। ज्यादा सिर आ रहे हैं, मस्तिष्क नहीं। जाति, धर्म, स्वार्थ और वर्ग के मुखौटे ज्यादा हैं, मनुष्यता के चेहरे कम। तभी राजनीति अवसरवादिता का अखाड़ा बनती जा रही है।

बहुजन समाज पार्टी अब अपनी ताकत दिखाने की शुरुआत कर चुकी है !

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव हो या प्रदेश का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम का हमेशा से ही इन चुनावों पर प्रभाव रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो पश्चिम यूपी में सभी पार्टी के योद्धा करीब करीब मैदान में उतर ही चुके हैं। इन सब में सबसे खास उम्मीदवार अगर किसी के हैं तो बहुजन समाज पार्टी के हैं जिनको बड़ी ही सूझबूझ के साथ और चुन चुनकर मायावती ने टिकट दिया है। मेरठ हो या कैराना या बिजनौर ही क्यों न हो भाजपा के कोर वोटर को प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को बीएसपी ने अपने खेमे से उतारा है। मायावती की ये सूझबूझ भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दरअसल, मुस्लिम बहुल कुछ एक सीटों को छोड़कर बीएसपी ने अधिकतक सीटों पर अपने प्रत्याशी भाजपा के कोर वोट बैंक को प्रभावित करने वाले ही उतारे हैं। ध्यान देना होगा कि अगर ये बीएसपी के उतारे गए उम्मीदवारों ने अपने जाति से संबद्ध वोट पर कब्जा कर लिया तो भाजपा के साथ बड़ा खेल हो जाएगा। इस बारे के लोकसभा में पश्चिम उत्तरप्रदेश में जातिगत समीकरण का चुनाव पर गहरा असर रह सकता है जो परिणामों को बदलने का माद्दा रखते हैं। 2014 की बात करें तो में पश्चिम उत्तरप्रदेश में आने वाली सभी 14 सीटों पर भाजपा जीत हासिल किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा-रालोद गठबंधन का खास असर रहा था। बिजनौर, नगीना, सहारनपुर के साथ ही मुरादाबाद, संभल, रामपुर व अमरोहा सीटों पर गठबंधन ने नए जातीय समीकरण को भुनाकर जीत हासिल की थीं। 2019 से 2024 का चुनाव इस तरह अलग है कि बसपा इस बार किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। रालोद इस बार भाजपा के साथ है और सपा कांग्रेस का गठबंधन है। पश्चिम उत्तरप्रदेश में जातिगत समीकरण बिल्कुल साफ है। उत्तरप्रदेश के इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जातियां है जिनको भाजपा के कोर वोटर के तौर पर देखा जाता है- ये जातियां हैं- त्यागी, ठाकुर,ब्राह्मण, सैनी,प्रजापति, कश्यप,सेन आदि समाज । वहीं जाटों की पार्टी के तौर पर पश्चिम उत्तरप्रदेश में रालोद की पहचान है। इस तरह इन सभी जातियों का भाजपा के पक्ष में आना तय था। बाकी आर एल डी के जरिए जाट समाज का वोट भी हालिस किया जा सकता था। लेकिन गेम जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं क्योंकि एकेल चुनाव लड़ रहीं मायावती ने गेम को इतना सरल रहने नहीं दिया है। बिजनौर में भी बीएसपी ने भाजपा का गेम बिगाड़ते हुए जाट चेहरे विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। दरअसल, यहां पर जाट वोट बैंक रालोद व भाजपा के माने जाते रहे हैं लेकिन मायावती ने अपने बेहतरीन चुनावी रणनीति का परिचय देते हुए जाट, दलित समीकरण को भुनाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं सपा ने भी यहां दांव चलते हुए अति पिछड़े सैनी समाज के दीपक सैनी पर विश्वास किया है। यहां के सैनी समाज को भी भाजपा के वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। 2019 में बीएसपी ने गुर्जर उम्मीदवार पर भरोसा किया था और पिछड़े दलित, मुस्लिम समीकरण को भुनाते हुए सीट अपने पाले में भी कर लिया था। इस बार भाजपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान है जो मीरापुर से रालोद विधायक है और गुर्जर समाज से आते हैं। चौ। नारायण सिंह जोकि प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं उनके दादा थे। चंदन चौहान के पिता संजय चौहान सांसद रह चुके हैं। मेरठ से किसी त्यागी को पहली बार बीएसपी ने टिकट दिया है, अब से पहले तक मुस्लिम को ही पार्टी मौका देती रही थी। देवव्रत त्यागी बीएसपी कैंडिडेट हैं और त्यागी समाज को यहां पर भाजपा के कोर वोटर के रूप में देखा जाता रहा है। सपा ने पहले तो दलित भानु प्रताप सिंह को इस सीट से उतारा लेकिन अब गुर्जर विधायक अतुल प्रधान पर दांव लगाया है। वहीं वैश्य उम्मीदवार और रामायण में राम की भूमिका से प्रसिद्धि पाने वाले अरुण गोविल पर भाजपा ने विश्वास किया है। यहां इंतजार इस बात का होगा कि अरुण गोविल बीएसपी के देवव्रत त्यागी के सामने टिक पाते हैं या नहीं। कैराना की बात करते हैं, बीएसपी ने यहां स ठाकुर समाज से आने वाले श्रीपाल राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं यहां पर भाजपा का कोर वोटर ठाकुरों को माना जाता है। ऐसे में भाजपा के सामने बीएसपी कैंडिडेट एक चुनौती की तरह साबित हो सकता है। इकरा हसन को सपा-कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने गुर्जर समाज से आने वाले और यहां से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर फिर से भरोसा जताया है। स्पष्ट है कि मायावती का पूरा फोकस दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों पर दिखाई दे रहा है। मायावती की पार्टी की ओर से तीन अलग-अलग सूची जारी की गई है। बुधवार को 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले 16 प्रत्याशियों की पहली और नौ उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी पार्टी की ओर से जारी की गई थी। बसपा की ओर से सभी सीटों पर नए चेहरे पर दांव लगाया गया है। 2019 में चुनाव जीतने वाले 10 सांसदों में से सिर्फ गिरीश चंद्र जाटव को ही टिकट दिया गया है। उनकी सीट बदल दी गई है। इस बार नगीना की बजाय बुलंदशहर से उन्हें उतर गया है। तीसरी लिस्ट की 12 प्रत्याशियों में तीन ब्राह्मण, तीन दलित, दो मुस्लिम, एक ठाकुर और एक खत्री के अलावा दो ओबीसी हैं। जबकि पहले जो 25 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी उसमें आठ सवर्ण, 7 मुस्लिम, 7 अनुसूचित जाति और दो ओबीसी को मैदान में उतर गया था। पार्टी की ओर से ठीक इसी तरीके की रणनीति 2007 में दिखाई गई थी। मायावती की ओर से 2024 की चुनावी लड़ाई में ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम का फार्मूला बनाया गया है। पार्टी की ओर से इन्हीं तीन जातियों को महत्व भी दिया जा रहा है। दलित और मुस्लिम समुदाय से 10-10 उम्मीदवारों को अब तक टिकट दिया जा चुके हैं जबकि ब्राह्मण समुदाय से 8 प्रत्याशी उतारे गए हैं। इस सूची में पांच ठाकुर प्रत्याशी भी है। दिलचस्प बात यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा , समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक भी ठाकुर प्रत्याशी नहीं दिया है। लेकिन बसपा ने तीन पर भरोसा जताया है। बसपा की ओर से मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, कन्नौज, लखनऊ, रामपुर, सहारनपुर जैसी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी खेल बिगड़ सकता है। दरअसल, लगातार हार के बाद बसपा लगातार प्रयोग कर रही है। उसने 2022 और फिर नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम कार्ड खेला, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में मंथन के बाद बसपा फिर एक प्रयोग करने जा रही है। मायावती लगातार एक साल से कह रही हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेंगी। बैलेंस ऑफ पावर बनाने की भी बात कर रही हैं। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यह है कि चुनाव बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना भी बसपा का मकसद है। गठबंधन में उसे बहुत कम सीटें मिलतीं। ऐसे में कुल वोट प्रतिशत गिर सकता था। यही वजह है कि सीट के अनुसार जहां जिस जाति का प्रभाव है, उसके अनुसार टिकट दिए गए हैं

मेष राशिः आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज परिवार की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आज आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। छात्र आज कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए।

वृष राशिःआज का दिन आपके लिए समान्य रहेगा। आज आपके विरोधी भी आपके काम की सराहना करेंगे। आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को सहयोगीयो से मदद मिलेगी जिससे आपका कार्य जल्दी पूरा हो जायेगा। आज आपको बिजनेस के सिलसिले से राज्य से बाहर जाना पड़ सकता है।

मिथुन राशिःआज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप समाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ऑफिस के काम में आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएगी। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के आसार खुलेंगे।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। जीवनसाथी आज आपको खुशियाँ देंगे। आज कार्यों में माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज किसी से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरुरत है।

सिंह राशिः आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुए धन लाभ से आज अपनी जरुरत का सामान खरीदेंगे। दांपत्य जीवन में और मधुरता आएगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है, पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

कन्या राशिःआज का दिन आपके लिए खुशियाँ लेकर आया है। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आयेगा। कुछ लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से थोड़ा संभलकर रहना चाहिए। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आयेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता-पिता के साथ किसी धार्मिक कार्य की योजना बनायेंगे।

तुला राशिःआज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पडने से बचना चाहिए। छोटीःछोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। घर के बड़ो से कोई नई बात आप सीखेंगे। आज काफी दिनों से आपका रुका काम पूरा हो जायेगा, मानसिक शांति मिलेगी। सामाजिक तौर पर आप बहुत सक्रिय भी रहेंगे।

वृश्चिक राशिःआज आपका दिन उमंग से भरा रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आयेंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें, इससे जीवन में चल रही परेशानियो का हल मिलेगा। मिलजुल कर किए गए कार्यो में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ो से कोई नई सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा।

धनु राशिःआज नए कार्यों करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा, आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी। करियर में आप नये आयाम स्थापित करेंगे। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। किसी काम में जीवनसाथी की सलाह फायदेमंद रहेगी।

मकर राशिः आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिसे आप पूरी लग्न और मेहनत से करेंगे, काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। आपके आय के नए स्त्रोत बनेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वो आज अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज आर्थिक मामलो में माता-पिता का सहयोग मिलता रहेगा दोस्तों से भी मदद मिलेगी।

कुंभ राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज रोजमर्रा के कामों में आपको ज्यादा समय लग सकता है।आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ो की राय लेना आपके लिए बेहतर साबित होगी। बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे।

मीन राशि :आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ो की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जायेगा। किसी रिश्तेदार से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जीवनसाथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे, इससे रिश्तों में नयापन आयेगा।

भाजपा ने घोषणा पत्र को गारंटी का दस्तावेज बना दिया

डॉ. आशीष वशिष्ठ

साल 1980 में स्थापना के बाद 1984 के आम चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसदीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भाजपा के मेनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र का शीर्षक था, 'टुवर्डस न्यू पॉलिटी' यानी नई राजनीति की ओर। घोषणा पत्र वह दस्तावेज होता है जो चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दल जारी करते हैं। इसमें वे जनता के सामने अपने वादे रखते हैं। इसके जरिए बताते हैं कि वे चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या-क्या करेंगे। उनकी नीतियां क्या होंगी। सरकार किस तरह से चलाएंगे और उससे जनता को क्या फायदा मिलेगा। हालांकि, वास्तविकता में घोषणा पत्र वादों का पिटारा मात्र होता है, जिनसे जनता को लुभा कर वोट मांगा जाता है। ये वादे कितने पूरे होते हैं, यह अलग चर्चा का विषय है। घोषणा पत्र को लेकर ज्यादातर राजनीतिक दलों का रवैया, रात गई, बात गई वाला होता है।

भारत के संसदीय इतिहास में भाजपा अब तक 10 आम चुनाव में भाग ले चुकी है। चुनावी मैदान में भाजपा को हार मिली हो या जीत, भले ही इस यात्रा में लाख संकट या समस्याएं उसके सामने आई हों, लेकिन वह कभी अपनी विचारधारा और राष्ट्र सेवा के कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। भाजपा ने अपनी चार दशक की यात्रा में शून्य से शिखर तक पहुंची है। उसकी इस सफलता का रहस्य यही है कि वह जो देशवासियों से वादा करती है, उसे पूरा भी करती है। उसकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। अपनी इसी मनोवृत्ति ओर संकल्पवृति के चलते ही बीते 44 वर्ष में भाजपा का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र से होता हुआ अब गारंटी का दस्तावेज बन गया है। देश की जनता ने जब-जब भाजपा को केंद्र और राज्यों में सेवा करने का अवसर प्रदान किया, भाजपा ने चुनाव के समय किये वादों को संकल्प मानकर उन्हें पूरा करने की दिशा में पूरी ऊर्जा लगा दी। इसी सेवाभाव से आमजन के बीच भाजपा की छवि एक ऐसे दल के तौर पर उभरी जो केवल वादे करता ही नहीं बल्कि उसे पूरा भी करता है। 2014 में देश की जनता ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के चेहरे नरेन्द्र मोदी के वादों पर विश्वास कर, उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनता के विश्वास का मान रखा ही नहीं बल्कि वादों से ज्यादा बढ़कर जनकल्याण और विकास के कार्यों को करके दिखाया। उसी का नतीजा यह रहा कि विपक्ष के प्रलोभन और दुष्प्रचार के बावजूद देशवासियों ने 2019 में दूसरी बार उन्हें देश की सत्ता सौंपी। पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने रक्षा, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, स्वास्थ्य,

शिक्षा, रोजगार, व्यापार, विज्ञान, अनुसंधान, पर्यावरण, उद्योग और अंतरिक्ष विज्ञान यानी हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किया है। मोदी सरकार के एजेंडे में महिला, बच्चे, किसान, सैनिक, मजदूर, आदिवासी, दलित, वंचित और युवा प्रथम पायदान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने देशवासियों से किये एक-एक वादे को जमीन पर उतारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा ने चुनावी वादों को पूरा करने की कड़ी अनुच्छेद 370 हटाने के साथ शुरू की थी। विपक्ष की आपत्तियों और अल्पसंख्यकों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में अधिक मत से पारित कर दिया गया। 370 को हटाना किसी पहाड़ को हिलाने के बराबर का काम था। लेकिन भाजपा ने अपने इस वादे को पूरा करके दिखाया। भाजपा ने तीन तलाक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया था। दरअसल, मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर भाजपा ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया। साल 2019 में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला,विवाह अधिकार संरक्षण कानून बना कर अपना यह वादा भी पूरा कर दिया। एक लंबे संघर्ष और विरोध के बाद अयोध्या राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आना एक बहुत बड़ा मौका रहा। भाजपा ने वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही राम मंदिर का निर्माण कराएगी। अदालत का फैसला आने तक राम मंदिर पर किसी प्रकार के काम को रोका गया था, लेकिन फैसला आने के तुरंत बाद जोरशोर से मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके बाद 22 जनवरी, 2024 को भाजपा ने अपना वादा पूरा करते हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए-2019 को लागू कर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले अपना एक और वादा पूरा करने का काम किया। भाजपा के चुनावी वादों में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात भी कही गयी। हालांकि, यह कानून पूरे देश में लागू न होकर केवल कुछ भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' की बात की थी। आज दस साल के कार्यकाल के बाद मैक्सिमम गवर्नेंस को आम आदमी साफ तौर पर अनुभव कर रहा है। इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता को 'भ्रष्टाचार मुक्त सरकार' देने का वादा किया था। कुर्सी पर बैठते ही प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी। उसके नतीजे आज सबके सामने है। खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रहार करके उन्होंने वो काम किया है, जो आज तक कोई दल या राजनेता नहीं कर पाया।

महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार को लगातार घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर लगातार काम किया है। महंगाई कम करना भी भाजपा के मुद्दे में रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा की सरकार ने महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर उस दिशा में काम किया है। आज दुनिया के विकसित और तेजी से आगे बढ़ते देशों की तुलना में भारत में महंगाई नियंत्रण में हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज महंगाई आकाश छू रही है तो बांग्लादेश और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, रिसर्च और इनोवेशन की चुनौतियों को दूर करने के लिए नई सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने का वादा किया था। नई शिक्षा नीति देश में लागू हो चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहा है। देश भर में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ है, और ये काम लगातार जारी है। 2014 में भाजपा ने पूरे देश से खेल प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए एक प्रणाली बनाने की घोषणा की थी। आज उसके नतीजे देश के सामने हैं। विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी रिकार्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में सुधार पर चुनावी प्रचार में भाजपा का खासा जोर था। दस वर्षों में पीडीएस सिस्टम में व्याप्त दोषों को खत्म करने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं, उससे बिचौलियों का हिस्सेदारी न्यून हुई। पीडीएस प्रणाली में सुधार का ही नतीजा है कि आज देश में 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज का वितरण सुविधा और पारदर्शिता से हो पा रहा है। पिछले एक दशक में जिन राज्यों में गैर भाजपा की सरकारें बनीं। वो चुनाव के समय जनता से किये हुए वादों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। वर्तमान में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारें इसका जीता जागता प्रमाण हैं। वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के कागज पर लिखे वादों को जमीन पर उतारकर करोड़ों देशवासियों का विश्वास जीता है। इसलिए देशवासी विपक्ष के वचन पत्र की बजाय भाजपा के संकल्प पत्र पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब तो बात मोदी की गारंटी तक पहुंच चुकी है। पिछले साल दिसंबर में एक समाचार संचार माध्यम को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''मेरे लिए गारंटी केवल शब्द या चुनावी वादे नहीं हैं, यह मेरी दशकों की कड़ी मेहनत है। यह समाज के प्रति संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ब्याज दरमें राहत नहीं

लोकसभा चुनावोंकी घोषणाके बाद हुई भारतीय रिजर्व बैंककी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पहली बैठकसे लोगोंको सस्ते ब्याजकी बहुत उम्मीदें थीं लेकिन उन्हें इसपर कोई राहत नहीं मिली है। रिजर्व बैंकने एक बार फिर रेपो रेटको यथावत साढ़े छह प्रतिशतपर बरकरार रखा है। रिवर्स रेपो रेट भी पूर्ववत ३.३५ प्रतिशत रखा गया है। रिजर्व बैंकके गवर्नर शक्तिकांत दासने शुक्रवारको एमपीसीके बैठकके निर्णयकी घोषणा की। इससे उन लोगोंको निराशा हाथ लगी है, जिन्हें रेपो रेटमें कटौती किये जानेकी उम्मीद थी। यह लगातार सातवां अवसर है जब रेपो रेटमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह वित्त वर्ष २०२४-२५ की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा है। एक अप्रैलसे शुरू नये वित्त वर्षमें एमपीसीकी कुल छह बैठकें आयोजित होगी। रिजर्व बैंकने अन्तिम बार फरवरी २०२३ में रेपो रेटमें वृद्धि की थी। इस वृद्धिके बाद रेपो रेट ६.५ प्रतिशत कर दी गयी थी। महंगीको चार प्रतिशतपर लाने और वैश्विक अनिश्चितताके बीच आर्थिक वृद्धिको गति देनेके उद्देश्यसे रेपो रेटको यथावत रखा गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंकने २०२४-२५ के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के सात प्रतिशतपर रहनेका अनुमान जताया है। खुदरा मुद्रास्फीतिके ४.५ प्रतिशतपर रहनेका भी अनुमान रखा गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने चालू वित्त वर्षकी पहली और दूसरी तिमाहीके लिए सकल घरेलू उत्पादके वृद्धि दरके अनुमानको अब संशोधित करके क्रमश: ८.२ प्रतिशत और ८.१ प्रतिशत कर दिया है। पिछले वित्त वर्षकी दिसम्बर तिमाहीमें वृद्धि दर ८.४ प्रतिशत थी। शक्तिकांत दासका यह भी कहना है कि खुदरा महंगी दर कम होकर भले ही ५.०९ प्रतिशतपर आ गयी है लेकिन खाने-पीनेकी चीजोंके मामलेमें महंगीकी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। महंगीके मुद्देपर अभी काफी प्रयास करनेकी जरूरत है। दूसरी ओर कुछ उत्साहजनक बातें भी सामने आयी हैं। भारतका विदेशी मुद्रा भण्डार ६४५.६ अरब डालरके रिकार्ड उच्च स्तरपर आ गया है। कुछ समय पूर्व विदेशी मुद्रा भण्डारको लेकर चिन्ताएं बढ़ गयी थीं। रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दोंसे निबटनेके लिए अब बेहतर स्थितिमें है। एमपीसी मुद्रास्फीतिको चार प्रतिशतके लक्ष्यके अनुरूप करनेकी अपनी प्रतिबद्धताके प्रति दृढ़ रहेगी लेकिन वैश्विक स्तरपर राजनीतिक तनाव, व्यापारिक मार्गपर बाधाओंसे चिन्ता बनी हुई है। भारतीय रुपयेकी स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्थाकी मजबूतीके अनुरूप है। सरकारी प्रतिभूतियों और बाण्ड्समें निवेश तेजीसे बढ़नेके संकेत हैं। इसके साथ ही गवर्नर शक्तिकांत दासने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब यूपीआई सिस्टमसे एटीएममें धन जमा किया जा सकेगा। इससे ग्राहकोंको राहत मिलेगी और कहीं भी धन भेजनेमें समयकी बचत भी होगी। इसके बावजूद रिजर्व बैंकके समक्ष बड़ी चुनौती मुद्रास्फीतिकी दरको कम करनेकी है। साथ ही भविष्यमें सस्ते कर्जका भी मार्ग प्रशस्त करना होगा।

आतंकी साजिश विफल

देशकी बदसे बदतर होते हालात और वैश्विक स्तरपर अपनी गिरती साखसे कोई सबक न लेते हुए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतोंसे बाज नहीं आ रहा है। यूपी एटीएसने बुधवारको जिन तीन आतंकियोंको भारत-नेपाल सीमाके सोनौली बार्डरसे दबोचे हैं उनमें दो पाकिस्तान और एक जम्मू-कश्मीरका रहनेवाला है। तीनों आतंकी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संघटन हिजबुल मुजाहिदीनसे जुड़े हैं। इनके पाससे दो पाकिस्तानी, एक भारतीय पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड तथा नेपाल, बंगलादेश, भारत और अमेरिकी मुद्रा समेत आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार तीनों आतंकी पाकिस्तानकी खुफिया एजेंसी आईएसआईके सहयोगसे हिजबुल मुजाहिदीनके ट्रेनिंग कैम्पमें प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनसे पूछताछमें जो बात सामने आयी है वह इनके खतरनाक इरादेका खुलासा करती है। अयोध्यामें राम मन्दिर निर्माणके बाद पहली रामनवमी और लोकसभा चुनावकी सरगर्मीके बीच उत्तर प्रदेशको दहलानेकी साजिशको एटीएसने नेपालसे भारत आ रही बसकी चेकिंगके दौरान आतंकियोंको गिरफ्तार कर विफल कर दिया। यह पुलिसकी सतर्कताकी बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तानमें चाहे कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो लेकिन स्टेयरिंग वहांकी सेना और आईएसआईके हाथमें रहती है। आईएसआई जिहादके नामपर युवाओंका ब्रेन वासिंग करती है और आतंकियोंको भारतमें शरिया कानून लागू करवानेका सपना दिखाती है, जो न अबतक पूरा हुआ और न ही भविष्यमें कभी पूरा होगा। फिर भी भारतको पूरी तरह सतर्क रहना होगा और अपने निगरानी तंत्रको और मजबूत करनेकी जरूरत है। भारत-नेपालकी हजारों किलोमीटर सीमा पूरी तरह खुली हुई है जिसकी सतत निगरानी होनी चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेशमें विशेष सतर्कता बरतनेकी जरूरत है, तभी पाकिस्तानकी घृणित और कायराना साजिशको विफल किया जा सकता है।

लोक संवाद

सोचनेकी क्षमता बढ़ायें

महोदय,-सैकंड हैंड शब्द सुनते ही सामान्य तौरपर हम सभीके मनमें पहली तस्वीर जो आती है, वह किसी वस्तुकी होती है। ज्यादासे ज्यादा उसके बाद भी आप विचारेंगे, तब भी आपके दिमागमें किसी वस्तु या उससे संबंधित स्थानके विचार ही आयंगे। किन्तु आज अपने सोचनेकी क्षमताको बढ़ायें, क्योंकि अब आपकी विचारधारामें परिवर्तनका समय आ गया है। हमारे समाजमें अब वस्तुएं ही नहीं, इनसान भी। माफ कीजिएगा, महिला अर्थात स्त्री भी सैकंड हैंड होती है। यदि आप यह सुनकर कुछ हैरान-परेशान हैं या तर्क-वितर्क कर रहे हैं तो मैं आपकी इस समस्याको यहीं खत्म करनेका प्रयास करती हूं। हमारे प्यारे देशमें जहां महिलाको देवीका दर्जा देनेकी बात कही जाती है, वहीं उसी देशमें उसे सैकंड हैंड होनेका टैग भी दिया जाता है। यदि आप नहीं मानते हैं तो आपको बताना चाहूंगी मुम्बईके एक केसके बारेमें, जहां पति द्वारा पत्नीको सैकंड हैंड कहे जानेकी बात सामने आयी है। सारा मामला इस प्रकार है कि मुम्बईके एक नवविवाहित जोड़के नेपालमें हनीमूनके दौरान पतिने उसे सैकंड हैंड कहकर प्रताड़ित किया, क्योंकि उसकी पिछली सगाई टूट चुकी थी। बादमें अमेरिकामें पत्नीने आरोप लगाया कि उसके साथ शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया गया। पतिने उसके चरित्रपर लांछन लगाये और उसके अपने भाइयों एवं अन्य पुरुषोंके साथ अवैध संबंध रखनेका आरोप लगाया। इस मामलेमें जनवरी २०२३ में ट्रायल कोर्टने पत्नीके पक्षमें फैसला सुनाया और पतिको तीन करोड़ रुपयेका मुआवजा देनेका आदेश दिया। इसके अतिरिक्त अदालतने पत्नीको दादरमें न्यूनतम 1000 वर्ग फुट आवासीय स्थान या ७५,000 रुपयेका मासिक किराया देनेका प्रावधान किया। पतिको पत्नीके सारे गहने वापस करने और 1,50,000 रुपयेका मासिक गुजारा भत्ता देनेका भी आदेश दिया गया। इसके बाद पतिने ट्रायल कोर्टके फैसलेको बॉम्बे हाईकोर्टमें चुनौती दी थी, जिसे कोर्टने अस्वीकार्य करते हुए ट्रायल कोर्टका फैसला बरकरार रखा। टू फिंगर टैस्ट, तीन तलाक जैसे अधिकतर फैसलोंको देखकर ऐसा लगता है, जैसे हमारे देशका कानून और न्यायालयों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि भारतीय समाजमें महिलाओंको भी बराबरका सम्मान मिले। किन्तु हमारे समाजमें रहनेवाले पुरुष और साथ ही महिलाओंका भी एक श्रेणी यह नहीं सोचती कि महिला भी इनसान है। हमारे समाजमें महिलाओंको इनसान न समझनेका जो कार्य किया जाता है, वह महिलाको अपमान और अपराधका शिकार बना देता है। भारतीय समाजकी स्थिति आज ऐसी हो चली है कि पढ़े-लिखे बच्चोंमें, जो पुरुष प्रधान समाजके भविष्यके पुरुष हैं, वह अभीसे महिला वर्गको दबानेका कार्य करने लगे हैं। अपनी बहनोंको बाहर न निकलने देनेकी विचारधारा, दूसरोंकी बहनोंके लिए बलात्कार जैसे शब्दोंका प्रयोग हो या फिर जिस लड़कीसे प्रेमका कथन कहते हैं, उसे ही धमकाना आदि कार्य आजके किशोरोंमें देखनेको मिल रहे हैं, जिन्हें समझ पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है या हम आंखोंपर पट्टी बांधकर तमाशा देख रहे हैं। पुरुष प्रधान समाजमें किशोर, युवा, बुजुर्ग कोई भी हो, यदि वह अपनी विचारधारामें महिलाओंके लिए बदलाव नहीं लायगा तो आप हमारे समाज और देशका विकास भूल ही जाइये। जब आधी आबादीको हम बस जानवर समझ उन्हें अपने उपभोगकी वस्तु बनाकर रखेंगे तो देशका विकास कैसे होगा। हमारा सम्पूर्ण समय तो अपनी ही आधी आबादीको बर्बाद करनेमें गुजर रहा है। यदि आप देश हितके बारेमें नहीं सोचते तो स्वयंके हितपर भी विचार करें तो आजके समाजमें महिलाओंको वस्तु समझनेकी विचारधाराको त्याग देना ही उचित होगा। हमें अपने आनेवाले युवकोंको सही शिक्षा देनी होगी, नहीं तो भारतीय संस्कृतिका समापन दूर नहीं। **-राखी सरोज, वाया ईमेल।**

बौद्धिक क्षमतामें वृद्धि जरूरी

बौद्धिक सम्पदा विषयोंपर प्रकाशित हो रही रिपोर्टोंमें कहा जा रहा है कि भारत तेज विकासके लिए नवाचार और बौद्धिक सम्पदाकी डगरपर तेजीसे बढ़ रहा है। हालमें अमेरिकी उद्योग मंडल द्वारा जारी रिपोर्टमें आईपी सूचकांक २०२४ में भारत दुनियाकी भारत दुनियाकी ५५ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओंमेंसे ४२वें स्थानपर है।

❐ डा.जयंतीलाल भंडारी

अमेरिकी उद्योग मंडल 'यूएस चैंबर्स ऑफकॉमर्स' के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटरके द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्टमें सूचकांकके तहत शीर्ष क्रमपर जिन दस देशोंकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें क्रमश: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन तथा स्विट्जरलैंड हैं। बौद्धिक सम्पदामें आविष्कार, रचनात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, शोध एवं नवाचार शामिल हैं। गौरतलब है कि इस नयी आईपी रिपोर्टमें भारतकी बौद्धिक सम्पदा आधारित नवाचार गतिविधियोंकी प्रशंसा की गयी है और कहा गया है कि भारत बौद्धिक नवाचारके जरिये अर्थव्यवस्थाको और तेजीसे बढ़ानेकी संभावनाओंवाला देश है। रिपोर्टमें यह भी बताया गया है कि आईपी मापदंडोंके मद्देनजर भारतका आकार और आर्थिक रसूख वैश्विक पटलपर बढ़ रहा है। रिपोर्टके मुताबिक भारतने कॉपीराइट अधिकारोंके उल्लंघनपर गतिशील निषेधात्मक आदेश जारी कर कॉपीराइटकी नकल रोकनेके सशक्त प्रयास किये हैं। इसके अलावा आईपी आधारित कर रियायतें देकर और नकली उत्पादोंके बारेमें जागरूकता फैलाकर भी भारतने इस दिशामें उल्लेखनीय काम किया है। यदि हम बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचारसे जुड़े अन्य वैश्विक संघटनोंकी रिपोर्टोंको देखें तो पाते हैं कि भारत इस क्षेत्रमें लगातार आगे बढ़नेका प्रयास कर रहा है। लेकिन अब भी देशके तेज विकासके ऊंचे लक्ष्योंके लिए बौद्धिक संपदा शोध और नवाचारमें भारतको ऊंचाई प्राप्त करना जरूरी है। विश्व बौद्धिक संपदा संघटन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) २०२३ की रैंकिंगमें १३२ अर्थव्यवस्थाओंमें भी भारत ४०वें पायदानपर दिखाई दे रहा है। खास बात यह भी है कि इस सूचकांकमें भारत ३७ निम्न-मध्यम-आय समूह अर्थव्यवस्थाओंके बीच अग्रणी बनकर उभरा है। साथ ही भारत नवाचारके संबंधमें मध्य और दक्षिणी एशियाकी दस अर्थव्यवस्थाओंमें सबसे ऊपर है। बौद्धिक सम्पदा शोध एवं नवाचारकी दुनियामें भारतकी रैंकिंग यह दर्शा रही है कि भारत इनोवेशनका हब बनता जा रहा है। भारतमें शोध एवं नवाचारको बढ़ानेमें डिजिटल ढांचे और डिजिटल सुविधाओंकी भी अहम भूमिका है। भारत आइटी सेवा निर्यात और वेंचर कैपिटल हासिल करनेके मामलेमें लगातार आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार करनेमें भी भारत दुनियामें सबसे आगे है। भारतके उद्योग-कारोबार तेजीसे समयके साथ आधुनिक हो रहे हैं। कृषिसे संबंधित चुनौतियोंके समाधानके लिए भारतने जिस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकीका प्राथमिकताके आधारपर उपयोग किया, उससे भारत कृषि विकासकी डगरपर तेजीसे आगे बढ़ा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मकता, राजनीतिक और संचालनसे जुड़ी स्थिरता, सरकारकी प्रभावशीलता जैसे विविध क्षेत्रोंमें अच्छे सुधार किये हैं। साथ ही भारतमें घरेलू कारोबारमें सरलता, विदेशी निवेश जैसे मानकोंमें भी बड़ा सुधार दिखाई दिया है। भारतकी शोध एवं नवाचार ऊंचाईमें अपार ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न, पेटेंट वृद्धि, घरेलू उद्योग विविधकरण, हाइटेक विनिर्माण और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संघटनों द्वारा किये गये प्रभावी कार्योंके साथ-साथ अटल इनोवेशन मिशनने भी अहम भूमिका निभायी है। कोविड-१९ भारतमें नये चिकित्सकीय शोध और नवाचारको बढ़ावा देनेका भी एक अवसर बना है। भारत बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, डिजिटल, कृषि, शिक्षा, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रोंमें प्रगति कर रहा है। भारतके नवाचार दुनियामें सबसे प्रतियोगी, किफायती, टिकाऊ, सुरक्षित और बड़े स्तरपर लागू होनेवाले समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भारतमें करीब १.२५ लाख स्टार्टअप हैं, जिनमें सौसे अधिक यूनिकॉर्न हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचारके बहुआयामी लाभ होते हैं। इनके आधारपर किसी देशमें विभिन्न देशोंके उद्यमी और कारोबारी अपने उद्योग-कारोबार शुरू करने संबंधी निर्णय लेते हैं। पूरी दुनियाके विभिन्न देशोंकी सरकारें भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सको ध्यानमें रखकर अपने वैश्विक उद्योग-कारोबारके रिश्तोंके लिए नीति बनानेकी डगरपर बढ़ती हैं। भारतमें इंटरनेट आफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रोंमें शोध और विकास और जबरदस्त स्टार्टअप माहौलके चलते हुए अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशोंकी बड़ी-बड़ी कम्पनियां अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर (जीआईसी) तेजीसे शुरू करते हुए दिखाई दे रही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सके तेजीसे बढ़नेसे भारतमें ख्यातिप्राप्त वैश्विक फायनेंस और कॉमर्स कम्पनियां अपने कदम तेजीसे बढ़ा रही हैं। यद्यपि भारतके विकासमें बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचारसे जुड़े तीन आधारोंकी बढ़ती भूमिका दिखाई दे रही है, लेकिन इन आधारोंसे विकासको ऊंचाई देनेके लिए इस क्षेत्रमें सरकार एवं निजी क्षेत्रका परिव्यय बढ़ाना होगा। इस समय भारतमें आर एंड डीपर जीडीपीका करीब ०.६७ प्रतिशत ही व्यय हो रहा है। दुनियाके कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब दो फीसदी शोध एवं विकासमें व्यय किया जाता है। यूरोपीय संघमें आर एंड डीपर जीडीपीका करीब दो प्रतिशत तथा अमेरिका, जापान और अन्य कई विकसित देशोंमें इसपर तीन फीसदीसे भी अधिक व्यय किया जा रहा है। भारतमें शोध एवं नवाचारपर खर्च ब्रिक्स देशोंकी तुलनामें कम है और विश्व औसत १.८ फीसदीसे भी कम है। इस समय देशमें निजी क्षेत्रका आर एंड डीपर खर्च जीडीपीके करीब ०.३५ फीसदीके स्तरपर है। दो मत नहीं हैं कि सरकार बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचारकी अहमियतको समझते हुए इस क्षेत्रको प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रही है। वर्ष २०२४-२५ के अंतरिम बजटमें वित्तमंत्री सीतारमणने उभरते क्षेत्रोंमें नवाचार और शोधको प्रोत्साहन देनेके लिए एक लाख करोड़ रुपयेके कोषकी स्थापना करनेकी घोषणा की है। उम्मीद है कि सरकार अमेरिकी उद्योग मंडल, यूएस चैम्बर्स आफ कॉमर्सके वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट २०२४ के तहत भारत सरकार बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचारके वर्तमान ढांचेमें मौजूद खामियोंको दूर करने और भारतकी आर्थिक वृद्धिके लिए एक नया मॉडल बनानेकी डगरपर आगे बढ़ेगी। साथ ही सरकार इस रिपोर्टमें भारतके बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्डको २०२१ में भंग किये जाने और न्यायपालिकापर बढ़ते मामलोंके बोझकी चिंताको दूर करेगी, क्योंकि इससे बौद्धिक संपदा अधिकारोंको लागू करनेकी क्षमता प्रभावित होती है। हम उम्मीद करें कि सरकार और देशके उद्योग-कारोबार जगतके द्वारा देशके तेज विकास और आम आदमीके आर्थिक-सामाजिक कल्याणके मद्देनजर दुनियाके विभिन्न विकसित देशोंकी तरह भारतमें भी बौद्धिक समझ, शोध एवं नवाचारपर जीडीपीकी दो फीसदीसे अधिक धनराशि व्यय करनेकी डगरपर आगे बढ़ा जायगा। इससे जहां ब्रांड इंडिया और मेड इन इंडियाकी वैश्विक स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कारोबार, ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, संचार, अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रोंमें देश तेजीसे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा।

पूरी दुनियाके विभिन्न देशोंकी सरकारें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सको ध्यानमें रखकर अपने वैश्विक उद्योग-कारोबारके रिश्तोंके लिए नीति बनानेकी डगरपर बढ़ती हैं। भारतमें इंटरनेट आफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रोंमें शोध और विकास और जबरदस्त स्टार्टअप माहौलके चलते अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशोंकी बड़ी कम्पनियां अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर तेजीसे शुरू कर रही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सके तेजीसे बढ़नेसे भारतमें ख्यातिप्राप्त वैश्विक फाइनेंस और कॉमर्स कम्पनियां अपने कदम तेजीसे बढ़ा रही हैं।

उपग्रही कचरेसे मिशनको खतरा

पृथ्वीके वायुमंडल और उसकी जलवायुका नये ढंगसे अध्ययन करनेवाला यूरोपीय स्पेस एजेंसीका निष्क्रिय और बेकाबू ईआरएस-२ उपग्रह पृथ्वीके वायुमंडलमें लौट आया। दशकों पुराने अंतरिक्ष यानके अवशेषसे उपग्रह पृथ्वीपर गिरा।

❐ मुकुल व्यास

यूरोपीय स्पेस एजेंसीका निष्क्रिय और बेकाबू ईआरएस-२ उपग्रहके पृथ्वीपर गिरनेकी खबर पृथ्वीवासियोंको झकझोर सकती है। लेकिन इस घटनासे किसी नुकसानकी कोई खबर नहीं है। करीब ढाई टन वजनी ईआरएस-२ उपग्रहको वर्ष १९९५ में अंतरिक्षमें लांच किया गया था और वर्ष २०११ में उसने अपना आखिरी मिशन पूरा किया था। तबसे यह उपकरण पृथ्वीकी कक्षामें अंतरिक्ष कबाड़के रूपमें बना हुआ था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसीका कहना है कि उसने उपग्रहको १५ वर्षोंके भीतर किसी समय पृथ्वीके वायुमंडलमें वापस लानेके लिए शुरूमें कुछ अभ्यास किये थे। वह दिन आखिरकार बुधवारको आ ही गया जब उपग्रहने अलास्का और हवाईके बीच प्रशांत महासागरके ऊपर पुन: प्रवेश किया। विशेषज्ञोंका कहना है कि ईआरएस-२ जैसे अधिकांश उपग्रह वायुमंडलमें प्रवेश करते ही टूट जाते हैं और पूरी तरहसे विघटित हो जाते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसीने कहा कि यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि उपग्रह पृथ्वीके वायुमंडलमें कहां पुन: प्रवेश करेगा, क्योंकि हवाके घनत्वका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, जहांसे उपग्रह गुजरता है। वैसे ईआरएस-२ जैसी बड़ी वस्तुओंको ट्रैक किया जाता है, लेकिन वायुमंडलीय घनत्वमें भिन्नतासे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कोई वस्तु वास्तवमें कहां दोबारा प्रवेश करेगी। ईआरएस-२ की पुन: प्रविष्टि अनियंत्रित थी। उसमें लम्बे समयसे ईंधन खत्म हो चुका था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसीके अनुसार जो भी टुकड़े वायुमंडलमें नहीं जले, वे सैकड़ों किलोमीटरकी दूरीमें बेतरतीब ढंगसे फैल जायंगे। अंतरिक्ष एजेंसीने कहा कि जहांतक वह बता सकती है, ईआरएस-२ के पुन: प्रवेशके बाद संपत्तिको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन विशेषज्ञोंका कहना है कि किसी व्यक्तिका अंतरिक्ष कबाड़के टुकड़ेकी चपेटमें आना पूरी तरहसे असंभावित नहीं है। पृथ्वीका अधिकांश भाग महासागरोंसे ढका है। ये वस्तुएं आम तौरपर महासागरोंके ऊपर गिरती हैं, जिससे मनुष्योंको खतरा थोड़ा कम होता है। छोटे उपग्रह हर समय पृथ्वीके वायुमंडलमें पुन: प्रवेश करते हैं और वे बहुत कम ही कोई समस्या पैदा करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे अधिक उपग्रह अंतरिक्षमें भेजे जायंगे, गिरनेवाली वस्तुकी घटनाएं और अधिक हो जायंगी। ये वस्तुएं पुन: प्रवेश करनेपर जल जाती हैं जिससे वायुमंडलीय प्रदूषणकी मात्रा भी बढ़ती है।

किसी व्यक्तिपर या किसी आबादीवाले क्षेत्रके पास अंतरिक्ष यानसे छोटी वस्तुओंके गिरनेकी पिछली घटनाओंमेंसे किसीने भी किसीकी जान नहीं ली है। आम तौरपर मामूली चोटसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आबादीवाले क्षेत्रोंके पास अंतरिक्ष मलबेके पाये जानेके कई मामले भी हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल नासाका एक वैज्ञानिक उपग्रह ४० सालतक पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके बाद अलास्काके तटके पास गिर गया था। लेकिन इस घटनासे कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल रूसका भी एक उपग्रह पृथ्वीकी कक्षामें विखंडित हो गया था। इससे मलबेका जो गुबार पैदा हुआ वह लम्बे समयतक कक्षामें बना रहेगा। इस विखंडनसे उत्पन्न कमसे कम ४८५ टुकड़ोंको ट्रैक किया जा सकता है। चीनके उपग्रहों और रॉकेटोंके टूटने बिखरने और पृथ्वीपर गिरनेकी घटनाएं हो चुकी हैं। हर साल २००-४०० वस्तुएं पृथ्वीके वायुमंडलमें प्रवेश करती हैं। सौभाग्यसे पृथ्वीकी आबादी इन गिरनेवाली वस्तुओंसे प्रभावित नहीं होती। हर साल एक उपग्रह दूसरे उपग्रहों या अंतरिक्ष मलबेसे टकरा कर नष्ट हो जाता है। आज अंतरिक्षमें जमा हो चुका कचरा विकराल समस्या बन चुका है। अंतरिक्षका कचरा पृथ्वीपर रोजमर्राके जीवनको ठप कर सकता है। आज हम उपग्रहोंपर जितने निर्भर हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। चाहे टेलीविजनके सिग्नल हों या मौसमकी रिपोर्ट, हमें उपग्रहोंकी ही मदद लेनी पड़ती है। हमारे जीपीएस सिस्टम उपग्रहोंके बिना काम नहीं कर सकते। अंतरिक्षके कचरेमें पुराने उपग्रहोंके कलपुर्जोंके अलावा ऐसे उपग्रह भी शामिल हैं जो पुराने पड़ चुके हैं और जिन्होंने अब काम करना बंद कर दिया है। कचरेके टुकड़ोंमें नट और बोल्ट भी शामिल हैं जो अंतरिक्ष यात्रियोंके स्पेसवॉकके दौरान गुम हो गये थे। अंतरिक्षमें कचरेकी बढ़ती हुई मात्रासे किसी न किसी बिंदुपर कोई बड़ी टक्कर हो सकती है। अंतरिक्षमें उपग्रहोंके बीच टक्करका एक नजारा दुनियाने फरवरी, २००९ में देखा था, जब एक बेकार रूसी उपग्रह और एक अमेरिकी दूरसंचार उपग्रह आपसमें टकरा गये थे। यदि कचरेके दो बड़े टुकड़े आपसमें टकराते हैं तो वे अंतरिक्षमें हजारों छोटे-छोटे टुकड़े बिखेर देंगे। सैद्धांतिक तौरपर ये सारे टुकड़े सैटेलाइट किलर हो सकते हैं। ये टुकड़े दूसरे ग्रहों अथवा उपग्रहोंसे टकरा कर नया मलबा उत्पन्न कर सकते हैं। यदि अंतरिक्षमें टुकड़ोंके बीच टक्करसे कोई चेन रिएक्शन शुरू होता है तो इससे न सिर्फ पृथ्वीके दूरसंचार और जीपीएस सिस्टम ध्वस्त हो जायंगे, बल्कि विश्वकी अर्थव्यवस्थापर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। अंतरिक्षमें कचरा जमा होनेकी वर्तमान दर जारी रही तो पृथ्वीसे नये अंतरिक्षयान छोड़ना भी मुश्किल हो जायगा।

जलवायु परिवर्तनसे आनेवाले समयमें पृथ्वीकी कक्षामें तैनात उपग्रहोंके लिए खतरा बढ़ जायगा और अंतरिक्ष प्रदूषणकी समस्या बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंगके चलते पृथ्वीके वायुमंडलमें कार्बन डाइऑक्साइडका स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऊपरी वायुमंडलमें इस गैसका बढ़ा हुआ स्तर वायु घनत्वमें दीर्घकालिक गिरावटका कारण बनेगा। यह कम घनत्व ऊपरी वायुमंडलमें ९० और ५०० किलोमीटरकी ऊंचाईपर परिक्रमा करनेवाली वस्तुओंपर खिंचावको कम करेगा। इससे अंतरिक्ष मलबेका जीवनकाल बढ़ेगा और उपग्रहोंके साथ मलबेके टकरावकी संभावना बढ़ जायगी। इन टक्करोंसे गम्भीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि समाज नौसंचालन प्रणालियों, मोबाइल संचार और पृथ्वीकी निगरानीके लिए उपग्रहोंपर अधिकसे अधिक निर्भर होता जा रहा है। एक अध्ययनके अनुसार मार्च, २०२१ तक पृथ्वीकी निचली कक्षामें २००० किलोमीटरकी ऊंचाईतक लगभग ५००० सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रह थे। कई कम्पनियां अगले दशकमें हजारों और उपग्रह जोड़नेकी योजना बना रही हैं। सेवामुक्त कर दिये जानेके बाद भी उपग्रह परिक्रमा करना जारी रखते हैं, लेकिन वायुमंडलीय खिंचावके कारण उनकी रफ्तार धीरे-धीरे धीमी हो जाती हैं। वे नीचे आने लगते हैं और अंततः निचले वायुमंडलमें पहुंचकर जल जाते हैं।

अंतरिक्ष मलबेसे संबंधित समन्वय कमेटी द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देश सलाह देते हैं कि उपग्रह संचालक यह सुनिश्चित करें कि निष्क्रिय किये गये उपग्रह २५ वर्षोंके भीतर कक्षासे हट जायं। लेकिन कम वायुमंडलीय घनत्वसे प्लानिंग और गणनामें त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। निचले वायुमंडलकी तुलनामें मध्य और ऊपरी वायुमंडल ठंडा हो रहा है। इससे घनत्व कम होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसीके अनुसार पृथ्वीकी निचली कक्षामें दस सेंटीमीटरसे अधिक व्यासवाले ३०,००० से अधिक मलबेके टुकड़े और एक सेंटीमीटरसे बड़े दस लाख टुकड़े मौजूद हैं। टक्करके जोखिमके कारण अंतरिक्ष मलबा उपग्रह ऑपरेटरोंके लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है। ऊपरी वायुमंडलके घनत्वमें दीर्घकालिक गिरावटके कारण यह समस्या बदतर हो रही है।

जीवन

❐ बाबा हरदेव

भावना अंत:करणकी एक वृत्ति है। संकल्प, चिंतन, मनन आदि इसीके नाम हैं। भावना तीन प्रकारकी होती है सात्विक, राजसी और तामसी। आत्माका कल्याण करनेवाली जो ईश्वर विषयक भावना है वह सात्विकी है। सांसारिक विषय भोगोंकी राजसी एवं अज्ञानसे भरी हुई हिंसात्मक भावना तामसी है। संसारके बंधन छुड़ानेवाली होनेके कारण सात्विकी भावनाके अनुसार इच्छा, इच्छाके अनुसार कर्म, कर्मके अनुसार संस्कार, संस्कारोंके अनुसार ही मनष्यके स्वभाव बनते हैं। कर्मोंके अनुसार जीवन बनता है। भावनाएं मानव जीवनको दिशा देती हैं। फिर मानव कर्म करता है। इस प्रकार सद्गुरुकी शरण प्राप्त करनेवाला मनुष्य संतों, महात्माओंसे सद्विचार प्राप्त करता है। मनुष्यकी पहलेकी भावनाएं और विचार परिवर्तित होते हैं। मनुष्य लालसाओंमें फंसा है। इसलिए मनुष्यको शुभकर्मोंकी ओर मोड़नेकी आवश्यकता है। मनुष्यका हर कदम श्रेष्ठताकी ओर बढ़े। सद्कर्मोंसे मनुष्य औरोंको भी सुख पहुंचाता है। मनुष्यको सद्विचार जहांसे भी प्राप्त हों, वहां जाकर अवश्य प्राप्त करने चाहिए। संतों, महात्माओंका संग सद्विचार प्रदान करता है। कूड़ेके ढेरसे दुर्गन्ध आती है जबकि फूलोंके बागीचेसे सुगंध आती है। अब मानवके हाथमें है कि वह किसकी इच्छा करता है। भक्त प्रह्लादको संतोंका संग मिला तो उसके जीवनमें सत्यका प्रवेश हुआ। संतने भक्त प्रह्लादको पावन पवित्र प्रभु नामसे जोड़ दिया। भक्त प्रह्लादने यह बात प्रत्यक्ष दिखला दी कि विष भी अमृत हो गया, अग्नि शीतल हो गयी, अस्त्र-शस्त्र निरर्थक हो गये। सर्पोंके विषका कुछ भी असर नहीं हुआ। यहांतक कि जड़ स्तंभमें भी चेतनामय, सर्वशक्तिमान भगवान नरसिंहके रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हो गये। प्रह्लाद भगवानके भक्त थे। यह सब उत्तम भावनाका फल है। संतोंके उपदेशोंको ग्रहण करने एवं अपने जीवनमें अपनानेका फल है। मनुष्य जैसे विचार करता रहता है उसका प्रभाव उसके कर्मोंपर पड़ता है। मनुष्यको सदैव निरीक्षण करते रहना चाहिए कि वह क्या सोच रहा है और क्या कर्म करने जा रहा है। उस कर्मका परिणाम कैसा होगा। कभी भी बुरा न सोचो क्योंकि बार-बार बुरा सोचनेसे मनुष्य एक दिन बुरा कर बैठता है। मनसे किसीका भी बुरा सोचना पाप है। जो बुरा कर्म कर बैठता है वह पापी बन जाता है। बुरा सोचनेवाला पकड़ा नहीं जाता और बुरा करनेवाला एक दिन पकड़में आ जाता है और अपराधी कहलाता है। चाहे बुरा करनेवाला पकड़में न भी आये परन्तु उसकी आत्मा तो उसे कहती है कि तूने गलत किया है, ठीक नहीं किया। हमारे मनमें बुरे विचार उत्पन्न न हों, इसका एक ही उपाय है कि अच्छा साहित्य पढ़ें और बुरेका संग त्यागें। अपने आपको बदलें, आप दुनियाको नहीं बदल सकते। उससे झगड़ा करनेसे क्या लाभ।

गर्म होते जलवायुके जोखिमोंकी गम्भीरता

❐ ज्ञानेन्द्र रावत

अगले पांच सालमें वैश्विक तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसतक बढ़नेके ६६ फीसदी आसार हैं। प्रतिवर्ष १.५ डिग्री सेल्सियस तापमानके करीब पहुंचना भी बड़ा संकट है। ला नीनासे अल नीनोमें तबदील होनेकी स्थितिमें जहां पहले बाढ़ आती थी वहां अब सूखा पड़ेगा और जहां पहले सूखा पड़ता था वहां अब बाढ़के आनेका अंदेशा है। दुनियामें तापमानमें हो रही वृद्धि खतरेका संकेत है। जलवायु परिवर्तनने इसमें अहम भूमिका निभायी है। दरअसल तापमानकी तुलनाका यह वह समय है जब औद्योगीकरणसे फॉसिल फ्यूलका उत्सर्जन शुरू नहीं हुआ था। विज्ञानियोंने अल नीनोके कारण गर्मीके इस तरहके भीषण उफानकी आशंका जतायी है। यह सब कोयला, तेल और गैसके जलानेकी सभी सीमाएं पार करनेका दुष्परिणाम है। फिर बीते सालोंकी प्राकृतिक घटनाओंको देखते हुए यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि जलवायु परिवर्तनके दुष्प्रभावोंसे निबटनेमें तत्परतासे कारगर कदम उठानेमें वैश्विक समुदाय उतना सजग नहीं दिखता जितना होना चाहिए। बीते साल मार्च, २०२३ से इस साल २०२४ के बीचके बारह महीनोंमें वैश्विक तापमानने १.५ डिग्रीकी सीमाको पार कर लिया है। विश्व मौसम विज्ञान संघटन यानी डब्ल्यूएमओकी रिपोर्टकी मानें तो न केवल बीता वर्ष, बल्कि पूरा बीता दशक धरतीपर अभीतकका सबसे गर्म दशक रहा है। संघटनने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह वर्ष भी गर्मीका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यूरोपीय पर्यावरणीय एजेंसी यानी ईईएकी मानें तो यूरोप तेजीसे बढ़ते तापमानके कारण जलवायु संबंधित खतरोंसे जूझनेके लिए तैयार नहीं है। जंगलोंकी आगकी चपेटमें वहांके घर आ रहे हैं, मौसमी आपदाओंका असर लोगोंकी आर्थिक स्थितिको प्रभावित कर रहा है। इस बाबत ईईएकी एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर कहती हैं कि यूरोपकी जलवायु खतरेमें है। यह खतरा हमारी तैयारियोंकी तुलनामें तेज गतिसे बढ़ रहा है। हमें फसल और लोगोंकी सुरक्षाके लिए तात्कालिक कारवाईकी जरूरत है। यदि निर्णायक कारवाई अभी नहीं हुई तो सदीके अंततक अधिकतर जलवायु खतरे गम्भीर होंगे। यदि तापमान वृद्धि दरपर अंकुश नहीं लगा तो सदीके अंततक गर्मीसे १.५ करोड़ लोगोंकी जिन्दगी संकटमें आ जायेगी। इसका अहम कारण जीवाश्म ईंधनके उत्सर्जनसे सदीके अंततक सर्वाधिक गर्मी होना है। अमेरिकाकी पर्यावरण संस्था ग्लोबल विटनेस और कोलंबिया यूनिवर्सिटीके वैज्ञानिकोंने कहा कि दुनियाकी प्रमुख जीवाश्म ईंधन कम्पनियों द्वारा तेल और गैसका अत्यधिक मात्रामें उत्सर्जन अहम कारण है। यदि उत्सर्जन स्तर २०५० तक यही रहा तो २१०० तक गर्मी भयावह स्तरतक पहुंच जायेगी। नतीजा लाखों जिन्दगियोंके अस्तित्वपर सवालिया निशान हो सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटीके मॉडलपर गौर करें तो प्रत्येक मिलियन टन कार्बनमें वृद्धिसे दुनियाभरमें २२६ अतिरिक्त हीटवेवकी घटनाओंमें वृद्धि होगी। यूरोपीय देशोंमें तेल कम्पनियोंमें उत्पादित जीवाश्म ईंधनमें २०५० तक वायुमंडलमें ५१ अरब टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन बढ़ जायेगा। वहीं शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यकी प्राप्तिके बाद भी ५५ लाख जिन्दगियां जोखिममें होंगी। शोधकर्ताओंके मुताबिक पिछले कुछ वर्षोंमें हीटवेवने तकरीबन हर महाद्वीपको प्रभावित किया। क्लाइमेट चेंज जर्नलमें प्रकाशित अध्ययनकी मानें तो यदि तापमानमें तीन डिग्रीकी वृद्धि होती है तो जहां हिमालयमें सूखा पड़नेकी संभावना प्रबल है, वहीं सर्वाधिक नुकसान कृषि क्षेत्रको उठाना पड़ेगा। इससे सबसे अधिक भारत और ब्राजीलका ५० फीसदीसे अधिक कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा। क्लाइमेट ट्रेंड्सकी रिपोर्टके मुताबिक जलवायु परिवर्तनके दुष्प्रभावसे हिमालयपर कम सर्दीका सामना करना पड़ेगा। इसका कारण मौसमका पैटर्न बदलना रहेगा। ब्लूमबर्गकी रिपोर्टकी मानें तो बढ़ते तापमानसे अमेरिकासे चीनतक खेत तबाह हो चुके हैं। इससे फसलोंकी कटाई, फलोंका उत्पादन और डेयरी उत्पादन सभी दबावमें हैं। बाढ़, सूखा और तूफानकी बढ़ती प्रवृत्तिने इसमें और इजाफा किया है। वाशिंगटनमें सेंटर फार स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीजके खाद्य विशेषज्ञ कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशियाके बड़े हिस्सेके किसान मुश्किलमें हैं। दक्षिणी यूरोपमें गर्मीके कारण गायें दूध कम दे रही हैं। इटलीमें अंगूर, खरबूजे, सब्जियों और गेहूंका उत्पादन प्रभावित हुआ है। यदि धरतीके तापमानको १.५ डिग्री सेल्सियसपर रोकना है तो २०३० तक कार्बन उत्सर्जनको ४३ फीसदीतक घटाना होगा। आज धरती १.७ डिग्री सेल्सियसतक गर्म हो चुकी है। समस्याकी जड़ जीवाश्म ईंधन है जिससे हमें दूर जानेकी जरूरत है। फिर जलवायु संरक्षणकी कारवाईमें जी-२०, सीओपी-२९ और सीओपी ३० का आपसमें कुछ न कुछ जुड़ाव जरूर है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसमें ग्लोबल साउथकी भूमिका कहांतक और कितनी सफल होगी, यह भविष्यके गर्भमें है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जो मित्र आपके सामने चिकनी-चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्त्तन के समान है, जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है।

चाणक्य

सन्मार्ग
पटना, शनिवार, 06 अप्रैल 2024
www.live7tv.com

अंतरिक्ष मिशनों हेतु खतरा है उपग्रही कचरा

मुकुल व्यास

पृथ्वी के वायुमंडल और उसकी जलवायु का नये ढंग से अध्ययन करने वाला यूरोपीय स्पेस एजेंसी का निष्क्रिय और बेकाबू ईआरएस-2 उपग्रह पिछले बुधवार को पृथ्वी के वायुमंडल में लौट आया। लेकिन वैज्ञानिक इस बारे में निश्चित नहीं थे कि दशकों पुराने इस अंतरिक्ष यान के अवशेष वास्तव में कहां और कब गिरेंगे। उपग्रह के पृथ्वी पर गिरने की खबर पृथ्वीवासियों को झकझोर सकती है। लेकिन इस घटना से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। करीब ढाई टन वजनी ईआरएस-2 उपग्रह को वर्ष 1995 में अंतरिक्ष में लांच किया गया था और वर्ष 2011 में उसने अपना आखिरी मिशन पूरा किया था। तब से यह उपकरण पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में बना हुआ था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि उसने उपग्रह को 15 वर्षों के भीतर किसी समय पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाने के लिए शुरू में कुछ अभ्यास किए थे। वह दिन आखिरकार बुधवार को आ ही गया जब उपग्रह ने अलास्का और हवाई के बीच प्रशांत महासागर के ऊपर पुनः प्रवेश किया।

विशेषज्ञों का कहना है कि ईआरएस-2 जैसे अधिकांश उपग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते ही टूट जाते हैं और पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में कहां पुनः प्रवेश करेगा क्योंकि हवा के घनत्व का पूवार्नुमान लगाना कठिन होता है, जहां से उपग्रह गुजरता है। वैसे ईआरएस-2 जैसी बड़ी वस्तुओं को ट्रैक किया जाता है, लेकिन वायुमंडलीय घनत्व में भिन्नता से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कोई वस्तु वास्तव में कहां दोबारा प्रवेश करेगी। ईआरएस-2 की पुनः प्रविष्टि अनियंत्रित थी। उसमें लंबे समय से ईंधन खत्म हो चुका था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार जो भी टुकड़े वायुमंडल में नहीं जले, वे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में बेतरतीब ढंग से फैल जाएंगे। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि जहां तक वह बता सकती है, ईआरएस-2 के पुनः प्रवेश के बाद संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी व्यक्ति का अंतरिक्ष कबाड़ के टुकड़े की चपेट में आना पूरी तरह से असंभावित नहीं है। पृथ्वी का अधिकांश भाग महासागरों से ढका हुआ है। ये वस्तुएं आमतौर पर महासागरों के ऊपर गिरती हैं, जिससे मनुष्यों को खतरा थोड़ा कम होता है। छोटे उपग्रह हर समय पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हैं और वे बहुत कम ही कोई समस्या पैदा करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे अधिक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, गिरने वाली वस्तु की घटनाएं और अधिक हो जाएंगी। ये वस्तुएं पुनः प्रवेश करने पर जल जाती हैं जिससे वायुमंडलीय प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती है।किसी व्यक्ति पर या किसी आबादी वाले क्षेत्र के पास अंतरिक्ष यान से छोटी वस्तुओं के गिरने की पिछली घटनाओं में से किसी ने भी किसी की जान नहीं ली है। आमतौर पर मामूली चोट से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आबादी वाले क्षेत्रों के पास अंतरिक्ष मलबे के पाए जाने के कई मामले भी हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल नासा का एक वैज्ञानिक उपग्रह 40 साल तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद अलास्का के तट के पास गिर गया था। लेकिन इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल रूस का भी एक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में विखंडित हो गया था। इससे मलबे का जो गुबार पैदा हुआ वह लंबे समय तक कक्षा में बना रहेगा। इस विखंडन से उत्पन्न कम से कम 85 टुकड़ों को ट्रैक किया जा सकता है। चीन के उपग्रहों और रॉकेटों के टूटने बिखरने और

पृथ्वी पर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। हर साल 200-400 वस्तुएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। सौभाग्य से पृथ्वी की आबादी इन गिरने वाली वस्तुओं से प्रभावित नहीं होती। हर साल एक उपग्रह दूसरे उपग्रहों या अंतरिक्ष मलबे से टकरा कर नष्ट हो जाता है। आज अंतरिक्ष में जमा हो चुका कचरा विकराल समस्या बन चुका है। अंतरिक्ष का कचरा पृथ्वी पर रोजमर्रा के जीवन को ठप कर सकता है। आज हम उपग्रहों पर जितने निर्भर हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। चाहे टेलीविजन के सिग्नल हों या मौसम की रिपोर्ट, हमें उपग्रहों की ही मदद लेनी पड़ती है। हमारे जीपीएस सिस्टम उपग्रहों के बगैर काम नहीं कर सकते। अंतरिक्ष के कचरे में पुराने उपग्रहों के कलपुर्जों के अलावा ऐसे उपग्रह भी शामिल हैं जो पुराने पड़ चुके हैं और जिन्होंने अब काम करना बंद कर दिया है। कचरे के टुकड़ों में नट और बोल्ट भी शामिल हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेसवॉक के दौरान गुम हो गए थे।

अंतरिक्ष में कचरे की बढ़ती हुई मात्रा से किसी न किसी बिंदु पर कोई बड़ी टक्कर हो सकती है। अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच टक्कर का एक नजारा दुनिया ने फरवरी, 2009 में देखा था,जब एक बेकार रूसी उपग्रह और एक अमेरिकी दूरसंचार उपग्रह आपस में टकरा गए थे। यदि कचरे के दो बड़े टुकड़े आपस में टकराते हैं तो वे अंतरिक्ष में हजारों छोटे-छोटे टुकड़े बिखेर देंगे। सैद्धांतिक तौर पर ये सारे टुकड़े ह्यसैटेलाइट किलरह्ण हो सकते हैं। ये टुकड़े दूसरे ग्रहों अथवा उपग्रहों से टकरा कर नया मलबा उत्पन्न कर सकते हैं। यदि अंतरिक्ष में टुकड़ों के बीच टक्कर से कोई चेन रिएक्शन शुरू होता है तो इससे न सिर्फ पृथ्वी के दूरसंचार और जीपीएस सिस्टम ध्वस्त हो जाएंगे, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। अंतरिक्ष में कचरा जमा होने की वर्तमान दर जारी रही तो पृथ्वी से नए अंतरिक्षयान छोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से आने वाले समय में पृथ्वी की कक्षा में तैनात उपग्रहों के लिए खतरा बढ़ जाएगा और अंतरिक्ष प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऊपरी वायुमंडल में इस गैस का बढ़ा हुआ स्तर वायु घनत्व में दीर्घकालिक गिरावट का कारण बनेगा। यह कम घनत्व ऊपरी वायुमंडल में 90 और 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं पर खिंचाव को कम करेगा। इससे अंतरिक्ष मलबे का जीवनकाल बढ़ेगा और उपग्रहों के साथ मलबे के टकराव की संभावना बढ़ जाएगी। इन टक्करों से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं क्योंकि समाज नौसंचालन प्रणालियों, मोबाइल संचार और पृथ्वी की निगरानी के लिए उपग्रहों पर अधिक से अधिक निर्भर होता जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार मार्च, 2021 तक पृथ्वी की निचली कक्षा में 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 5,000 सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रह थे। कई कंपनियां अगले दशक में हजारों और उपग्रह जोड़ने की योजना बना रही हैं। सेवामुक्त कर दिए जाने के बाद भी उपग्रह परिक्रमा करना जारी रखते हैं, लेकिन वायुमंडलीय खिंचाव के कारण उनकी रफ्तार धीरे-धीरे धीमी हो जाती हैं। वे नीचे आने लगते हैं और अंततः निचले वायुमंडल में पहुंच कर जल जाते हैं। अंतरिक्ष मलबे से संबंधित समन्वय कमेटी द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देश सलाह देते हैं कि उपग्रह संचालक यह सुनिश्चित करें कि निष्क्रिय किए गए उपग्रह 25 वर्षों के भीतर कक्षा से हट जाएं। लेकिन कम वायुमंडलीय घनत्व से प्लानिंग और गणना में त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। निचले वायुमंडल की तुलना में मध्य और ऊपरी वायुमंडल ठंडा हो रहा है। इससे घनत्व कम होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार पृथ्वी की निचली कक्षा में 10 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले 30,000 से अधिक मलबे के टुकड़े और 1 सेंटीमीटर से बड़े दस लाख टुकड़े मौजूद हैं। टक्कर के जोखिम के कारण अंतरिक्ष मलबा उपग्रह ऑपरेटरों के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है। ऊपरी वायुमंडल के घनत्व में दीर्घकालिक गिरावट के कारण यह समस्या बदतर हो रही है।

ब्रह्म ही तो है अन्न

भारतीय जीवन दर्शन में अन्न को प्रसाद मानकर सम्मान देने की परंपरा में उसे ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। आज भी जिम्मेदार पीढ़ी के लोग खाने से पहले भोजन को प्रणाम करते तथा पहला कौर जीव-जंतुओं के लिये निकालते हैं। मकसद अन्न के महत्व को गरिमा देना और उसका उचित इस्तेमाल ही होता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की वह रिपोर्ट एक काले सच को उजागर करती है कि पूरी दुनिया में 19 फीसदी भोजन बर्बाद कर दिया जाता है। एक भयावह सच्चाई यह भी है कि दुनिया में करीब 78.3 करोड़ लोग लंबे समय से भूख से जूझ रहे हैं। युद्धरत गाजा में इस भूख के संकट की भयावह स्थिति जब-तब उजागर होती रहती है। संयुक्त राष्ट्र की यह हालिया रिपोर्ट एक कठोर हकीकत से रूबरू भी कराती है कि पर्याप्त संसाधनों के बावजूद खाद्यान्न का न्यायसंगत वितरण नहीं हो पा रहा है। दूसरे शब्दों में यह एक नैतिक संकट भी है। दरअसल, भोजन की बबार्दी एक तरह से हमारे पर्यावरण को भी अस्थिर करती है। निश्चित रूप से यह संकट भारत में भी विद्यमान है। खाद्य सुरक्षा के नजरिये से भोजन की बबार्दी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार भारत में कुल भोजन का एक-तिहाई हिस्सा उपभोग से पहले खराब हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार भोजन की यह बबार्दी एक साल में प्रतिव्यक्ति पचास किलो होने की आशंका है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रिपोर्ट भारत में कुपोषण से जुड़े संकट को भी उजागर करती है। जिसमें बताया गया है कि देश की 74 फीसदी आबादी स्वस्थ आहार का खर्च वहन नहीं कर सकती। ऐसे में भोजन का एक-तिहाई हिस्सा बर्बाद होना नैतिक अपराध ही है। वहीं दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी खाद्य उत्पादन और अपशिष्ट से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। दरअसल, कचरे के ढेरों में खराब खाद्यान्नों के अंश विघटित होने से ग्लोबल वार्मिंग के वाहक मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। वैश्विक संगठनों का आग्रह है कि दुनिया में खाद्य प्रणालियों में पूर्ण बदलाव लाएं। साथ ही समान वितरण को प्राथमिकता देने को प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसे में जब देश में लाखों लोग रोटी के लिये संघर्ष कर रहे हों, भोजन की बबार्दी नैतिक दृष्टि से अपराध ही है। इस संकट से उबरने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रणनीति की जरूरत है। जिसके लिये जागरूकता अभियान चलाने, नीतिगत उपायों में बदलाव लाने तथा समुदाय संचालित पहलों को एकीकृत प्रयासों से मूर्त रूप देने का प्रयास होना चाहिए। वहीं सरकारी हस्तक्षेप से अपशिष्ट को कम करने के लिये नियम बनाने की भी जरूरत है। समाज के स्तर पर भोजन को बर्बाद होने से रोकने के लिये दीर्घकालीन प्रयासों को प्रोत्साहित करना होगा।

मंडी में कंगना की दावेदारी के किंतु-परंतु

राजेंद्र राजन

लोकसभा हो या विधानसभा, फिल्मी सितारों की लोकप्रियता को बैसाखी बनाकर चुनाव जीतने की परम्परा नयी नहीं है। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविन्दा से लेकर हेमा मालिनी जैसे नामचीन फिल्मी कलाकारों की लम्बी फेहरिस्त है जिन्हें राजनीतिक दलों ने सिर-आंखों पर बिठाया। कुछ जीते तो कुछ हारे। मतदाताओं को रिझाने, फिल्मी हस्तियों से उनके भावनात्मक जुड़ाव को भुनाने को सभी राजनीतिक दल तत्पर रहते हैं। अपनी पार्टी को विजयी बनाने, सत्ता हासिल करने की जंग में उम्मीदवार का अनुभव, योग्यता, जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता खास मायने नहीं रखते।

बहरहाल, जिस फिल्म अभिनेत्री की इन दिनों हिमाचल और देशभर में चर्चा है, वे हैं कंगना रणौत। जिन्हें भाजपा ने मंडी से लोकसभा चुनाव के लिये उम्मीदवारी सौंपी है। लम्बे वक्त से विवादों और कंगना का गहरा नाता रहा है। वे निश्चित रूप से एक कामयाब एक्ट्रेस हैं। अपने अभिनय के जरिये करोड़ों सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करती हैं। लेकिन अनेक नेताओं की तरह कई बार बोलने में अतिरेक की प्रवृत्ति रही है। वे अपने उस बयान को लेकर ट्रोल भी हुई थीं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद ही देश का सही मायने में विकास हुआ है। अकसर नेताओं द्वारा सियासी फायदे यानी चुनावी टिकट हासिल करने के लिये ऐसी बयानबाजी होती रही है। विगत में कंगना रणौत जब पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से भिड़ गयीं तो उनके पक्ष या विपक्ष में देशभर में जन आंदोलन छिड़ गये थे। उन्हें मोदी सरकार ने सुरक्षा प्रदान की। यह नैरेटिव उन्हीं दिनों रचा जा चुका था जब वे दक्षिणपंथी विचारधारा को आत्मसात करने की तैयारी कर रही थीं। अपने सियासी ह्यप्रबन्धनह्ण में उन्हें एक तरह से सफल ही कहा जा सकता है। हालिया प्रकरण है, टिकट

घोषणा के पहले ही रोज कंगना का कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से विवाद हो गया।

दरअसल, अभद्र भाषा के प्रयोग में विपक्षी दलों के कुछ नेता भी पीछे नहीं हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण कंगना पर की गयी वह टिप्पणी है जिसमें मंडी का भाव पूछा गया था। चुनाव आयोग लाख दावे करे, लेकिन वह नेताओं के तीखे, आपत्तिजनक बयानों का कड़ा संज्ञान लेने में प्रो एक्टिव मोड में नहीं माना जा सकता है। लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति की पृष्ठभूमि में भाजपा की निगाह महिला मतदाताओं पर खासतौर पर टिकी है क्योंकि वह 400 का आंकड़ा पार करने के लिए अपनी कमान में मौजूद सभी तीरों का प्रयोग कर लेना चाहती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की मौजूदगी काफी उत्साहवर्धक थी।

विगत 5 सालों में सम्पन्न 23 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 18 में महिला मतदाता पुरुषों से आगे थीं। कांग्रेस या विपक्षी दल इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में संकीर्णता की शिकार हैं तो इस मामले में भाजपा की दरियादिली कही जा सकती है। कंगना रणौत का चयन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अपने तेवरों के लिये वे चर्चित रही है। अपने फिल्मी कैरियर की शुरूआत कंगना ने 18 साल की उम्र में ह्यगैंगस्टरह्ण से की थी। रानी झांसी का किरदार ह्यमणिकर्णिकाह्ण में अभिनीत किया तो जयललिता की बायोपिक में भी सराही गयीं। ह्याएमरजेंसीह्ण फिल्म में वे इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आयेंगी। लब्बोलुआब यह कि सशक्त महिला प्रधान फिल्मों में वे जिन जननायिकाओं की भूमिकाओं में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं, उनकी बदौलत वे मंडी सीट पर आम लोगों से खुद को जुड़ा हुआ देखना चाहती हैं। पर यह कांटों भरी डगर है। सिनेमा और राजनीति की कोई जुगलबन्दी नहीं है।

दरअसल, हिमाचल में कांग्रेस सरकार व पार्टी में जारी उठापठक के चलते कंगना अपनी सफलता को लेकर उम्मीद जता रही हैं। जिसकी बानगी उनके मुकाबले उतरी कांग्रेसी प्रत्याशी की बेमन से चुनाव लड़ने की कवायद में नजर आती है। बहरहाल, जन आकांक्षाओं, जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिये कंगना को एक ह्यमैच्योरह्ण राजनेता की छवि को अर्जित करना होगा। एक चैनल को दिये गये साक्षात्कार में कंगना ने कहा है कि तत्कालीन कुछ नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को 1945 में गायब करवा दिया था। यह भी कि आईएनए के फौजियों व स्वतन्त्रता सेनानियों को भूखे रहकर जान गंवानी पड़ी थी। दरअसल, बयान देने से पहले किसी भी नेता के पास अच्छे सलाहकार होने जरूरी हैं। इतिहास के तथ्यों को कभी बदला नहीं जा सकता। यह प्रश्न भी विचारणीय है कि फिल्मों से जितने भी सितारे राजनीति में जीतकर संसद में पहुंचे हैं उनकी विकास करने व जनसमस्याओं के निवारण में कैसी भूमिका रही है। संसद में उन्होंने क्या-क्या मुद्दे उठाए? विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में ज्यादातर का योगदान खास तो नहीं रहा है। कंगना की दावेदारी को लेकर सार्वजनिक विमर्श में विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं कि यदि कंगना लोकसभा सीट पर चुनाव जीतती भी हैं तो क्या वे मंडी का जनप्रतिनिधि होने के दायित्व को निभा पाएंगी? वे स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय कहीं मायानगरी के सम्मोहन में बंधकर तो नहीं रह जाएंगी?

राजनीति में बदल रहे नैतिकता के मायने

सुरेश हिंदुस्तानी

भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो आज भी नैतिकता के आदर्श हैं। लेकिन आज की राजनीति को देखकर ऐसा लगने लगा है कि नैतिकता की राजनीति दूसरा तो अवश्य करें, पर जब स्वयं को नैतिकता की कसौटी पर परखने की बारी आए तब नैतिकता के मायनों को बदल दिया जाता है। भारतीय राजनीति में राजनेताओं पर आरोप लगने पर कई लोगों ने अपने पद को त्याग दिया था, दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भारतीय राजनीति को अलग राह पर ले जाने का उदाहरण पेश किया है, हालांकि इस उदाहरण को आदर्श वादिता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। यह एक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं हैं। केजरीवाल स्वयं कहते थे कि वे राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आए हैं, लेकिन अब जब उन पर ही सवाल उठ रहे हैं, तब उनसे भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की आशा करना बेमानी ही कही जाएगी। यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि दिल्ली के शराब घोटाले में अभी तक जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनको जमानत लेने का पर्याप्त आधार नहीं मिल रहा, इसका आशय यह भी है कि सरकार की ओर से कोई न कोई गलत आचरण किया गया होगा, अन्यथा एक मुख्यमंत्री को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जाता। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी यही कहा जा रहा है, उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के संकेत पर पैसों का लेनदेन हुआ।

दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है, उस पर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इन सवालों की परिधि में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर विपक्ष कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह साफ तौर पर संकेत दिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है। अब यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे आरोप किस हद तक सही हैं या फिर केजरीवाल अपने आपको निर्दोष साबित कर पाते हैं या नहीं। अगर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लगाए गए आरोपी प्रमाणित होते हैं तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संवैधानिक पद के प्रभाव का दुरुपयोग किया है।

हम यह भली भांति जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल ने अपने आपको ऐसा प्रचारित किया कि एक वे ही भारतीय राजनीति के उच्चतम आदर्श हैं। लेकिन उनके आचरण पर स्वयं अण्णा हजारे ने सवाल उठाए थे, हालांकि अण्णा हजारे के सवालों को केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया। इसका तात्पर्य यही है कि अन्ना हजारे राजनीति में जिस प्रकार का पारदर्शी व्यवहार चाहते थे, वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी समाजसेवी अण्णा हजारे की ओर से साफ सुथरी टिप्पणी आई है, जिसमें अण्णा हजारे ने शराब पर नीति बनाने से रोका था। अण्णा हजारे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनके कर्मों का परिणाम बताया। आज दिल्ली का शराब घोटाला यही चरितार्थ करते हुए लग रहा है कि शराब किसी भी संस्था या व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। यह बात केजरीवाल पर लागू होती है या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन जब आग लगती है तब ही धुंआ उठता है और इस धुंए का कालिमा किस किस के शक्ल को बिगाड़ने का काम करेगी, यह समय के गर्भ में है।

केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठना तो उसी समय प्रारंभ हो गए थे, जब उनका पहला मंत्री जेल में गया। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। राजनीतिक शुचिता लाने का दम दिखाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगने केवल राजनीतिक विद्वेष नहीं हो सकता। अगर यह कार्यवाही राजनीतिक होती तो स्वाभाविक रूप से इन सभी को जमानत भी मिल जाती। जमानत नहीं मिलने से यह आशंका प्रबल हो जाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता भी केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ही विरोध कर रहे हैं, कोई भी यह नहीं कह रहा कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ या फिर गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लगाया। यह बात सही है कि राजनीतिक तौर पर तर्क तो कई दिए जा सकते हैं, लेकिन इन तर्कों का आधार क्या है? यह कोई नहीं बता पाता। भारत की राजनीति में इसे विसंगति ही माना जाएगा कि कोई अपराधी और उसके समर्थक उसे ऐसे नायक के रूप में प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं, जैसे वह समाज के लिए आदर्श बन गया हो। ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें नेता जमानत पर बाहर आकर राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ करने की बात करते हैं। क्या वास्तव में ऐसे राजनेता देश के राजनीतिक वातावरण को सकारात्मक दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। कदाचित नहीं। क्योंकि आज के राजनीतिक माहौल में राजनेता जैसा अपने आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसा सिद्धांततः होता नहीं है। उनके क्रियाकलाप केवल और केवल भ्रमित करने वाली राजनीति करने की ही होती है। देश में एक समय यह आम धारणा बन चुकी थी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश की नियति बन चुकी है, लेकिन पिछले दस साल में इस धारणा को बदलने की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। यह सुगबुगाहट कई राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आ रही। ऐसे कई राजनेता हैं जो भ्रष्टाचार के दोषी सिद्ध हो चुके हैं और देश की राजनीति को सुधारने की कवायद कर रहे हैं। अब सवाल यह भी आता है कि क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करने का साहस दिखा सकते हैं। इसका उत्तर नहीं ही होगा, लेकिन वे फिर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। भारत में साफ सुथरी राजनीति के क्या यही मायने हैं? क्या ऐसे नेता राजनीति को सही दिशा दे सकते हैं, इसका उत्तर हमें स्वयं तलाश करना होगा? ऐसे ही दिल्ली सरकार के घोटाला में होता हुआ लग रहा है। क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा कि गोवा में 45 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से दिए गए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यही साफ सुथरी राजनीति के मायने हैं? तर्क कुछ भी हों, परन्तु अब ऐसी राजनीति से देश को अलग करने का समय आ गया है।

https://t.me/AllNewspaperPdf

मध्यम अवधि की आर्थिक नीति

सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी योजना एक विकसित भारत तैयार करने की है। इस लक्ष्य के लिए कई तिथियों के सुझाव सामने आए, हालांकि सबसे अधिक जिक्र 2047 का है जब देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी। ऐसी महत्त्वाकांक्षा तय करना एकदम उचित है। बहरहाल, ऐसे लक्ष्य के लिए जिस पैमाने पर वृद्धि हासिल करनी होगी उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए दशकों तक साल दर साल कम से कम आठ फीसदी की दर से वृद्धि हासिल करनी होगी। यदि हम ऐसा कर सके तब जाकर 14,000 डॉलर प्रति व्यक्ति के नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद तक पहुंच सकेंगे जो उच्च आय वाले देशों के लिए वर्तमान मानक है। अब तक करीब छह देशों ने यह स्तर हासिल किया है। परंतु ऐसी वृद्धि हासिल करना संभव है। चीन वर्षों की तेज वृद्धि के बाद अगले कुछ वर्षों में 14,000 डॉलर का स्तर प्राप्त कर सकता है। यह स्थिति तब है जबकि हाल के दिनों में चीन की आर्थिक गति कमजोर पड़ी है। पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया के कई देशों ने भी इस समय में तेज वृद्धि बरकरार रखी है। भारत जैसे जटिल देश में यह स्पष्ट है कि ऊंची और टिकाऊ वृद्धि अपने आप नहीं आएगी। वर्तमान परिदृश्य में तो ऐसा ही प्रतीत होता है। सन 1990 और 2000 के दशक की स्वर्णिम अवधि के उलट आज वैश्विक हालात प्रतिकूल हैं। महत्त्वाकांक्षी विकासशील देशों के लिए भी हालात मुश्किल हैं। इसकी कई वजह हैं। पहली, कारोबारी व्यवस्था बहुत सीमित हो गई है क्योंकि विभिन्न देश ऐसी औद्योगिक नीतियों में व्यस्त हैं जहां घरेलू सब्सिडी और शुल्क दरों से जुड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दूसरा, अमेरिका और चीन के बीच छिड़े शीतयुद्ध ने मूल्य श्रृंखलाओं को विभाजित कर दिया और निवेश रणनीतियों को जटिल बना दिया। तीसरा, तकनीकी बदलावों ने किफायती श्रम लागत के इर्दगिर्द बनी विकास नीतियों को मुश्किल बना दिया है। अन्य वृहद रुझानों को भी इसमें शामिल करना होगा जिसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा पर्यावरण के अनुकूल बदलावों का असर शामिल है।

भाजपा ने घोषणा पत्र को गारंटी का दस्तावेज बना दिया

डॉ. आशीष वशिष्ठ

साल 1980 में स्थापना के बाद 1984 के आम चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसदीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भाजपा के मेनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र का शीर्षक था, 'टुवर्डस न्यू पॉलिटी' यानी नई राजनीति की ओर। घोषणा पत्र वह दस्तावेज होता है जो चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दल जारी करते हैं। इसमें वे जनता के सामने अपने वादे रखते हैं। इसके जरिए बताते हैं कि वे चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या-क्या करेंगे। उनकी नीतियां क्या होंगी। सरकार किस तरह से चलाएंगे और उससे जनता को क्या फायदा मिलेगा। हालांकि, वास्तविकता में घोषणा पत्र वादों का पिटारा मात्र होता है, जिनसे जनता को लुभा कर वोट मांगा जाता है। ये वादे कितने पूरे होते हैं, यह अलग चर्चा का विषय है। घोषणा पत्र को लेकर ज्यादातर राजनीतिक दलों का रवैया, रात गई, बात गई वाला होता है। भारत के संसदीय इतिहास में भाजपा अब तक 10 आम चुनाव में भाग ले चुकी है। चुनावी मैदान में भाजपा को हार मिली हो या जीत, भले ही इस यात्रा में लाख संकट या समस्याएं उसके सामने आई हों, लेकिन वह कभी अपनी विचारधारा और राष्ट्र सेवा के कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। भाजपा ने अपनी चार दशक की यात्रा में शून्य से शिखर तक पहुंची है। उसकी इस सफलता का रहस्य यही है कि वह जो देशवासियों से वादा करती है, उसे पूरा भी करती है। उसकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। अपनी इसी मनोवृत्ति ओर संकल्पवृति के चलते ही बीते 44 वर्ष में भाजपा का घोषणा

पत्र, संकल्प पत्र से होता हुआ अब गारंटी का दस्तावेज बन गया है। देश की जनता ने जब-जब भाजपा को केंद्र और राज्यों में सेवा करने का अवसर प्रदान किया, भाजपा ने चुनाव के समय किये वादों को संकल्प मानकर उन्हें पूरा करने की दिशा में पूरी ऊर्जा लगा दी। इसी सेवाभाव से आमजन के बीच भाजपा की छवि एक ऐसे दल के तौर पर उभरी जो केवल वादे करता ही नहीं बल्कि उसे पूरा भी करता है। 2014 में देश की जनता ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के चेहरे नरेन्द्र मोदी के वादों पर विश्वास कर, उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनता के विश्वास का मान रखा ही नहीं बल्कि वादों से ज्यादा बढ़कर जनकल्याण और विकास के कार्यों को करके दिखाया। उसी का नतीजा यह रहा कि विपक्ष के प्रलोभन और दुष्प्रचार के बावजूद देशवासियों ने 2019 में दूसरी बार उन्हें देश की सत्ता सौंपी। पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने रक्षा, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, विज्ञान, अनुसंधान, पर्यावरण, उद्योग और अंतरिक्ष विज्ञान यानी हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किया है। मोदी सरकार के एजेंडे में महिला, बच्चे, किसान, सैनिक, मजदूर, आदिवासी, दलित, वंचित और युवा प्रथम पायदान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने देशवासियों से किये एक-एक वादे को जमीन पर उतारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा ने चुनावी वादों को पूरा करने की कड़ी अनुच्छेद 370 हटाने के साथ शुरू की थी। विपक्ष की आपत्तियों और अल्पसंख्यकों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में अधिक मत से पारित कर दिया गया। 370 को हटाना किसी पहाड़ को हिलाने के बराबर का काम था। लेकिन भाजपा ने अपने इस वादे को पूरा करके दिखाया। भाजपा ने तीन तलाक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया था। दरअसल, मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर भाजपा ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया। साल 2019 में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला,विवाह अधिकार संरक्षण कानून बना कर अपना यह वादा भी पूरा कर दिया। एक लंबे संघर्ष और विरोध के बाद अयोध्या राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आना एक बहुत बड़ा मौका रहा। भाजपा ने वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही राम मंदिर का निर्माण कराएगी। अदालत का फैसला आने तक राम मंदिर पर किसी प्रकार के काम को रोका गया था, लेकिन फैसला आने के तुरंत बाद जोरशोर से मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके बाद 22 जनवरी, 2024 को भाजपा ने अपना वादा पूरा करते हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए-2019 को लागू कर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले अपना एक और वादा पूरा करने का काम किया।

जनतंत्र पर कुछ तीखे सवाल, प्रशासन का असली चेहरा .....

प्रदीप कुमार नायक

भ्रष्टतंत्र और भ्रष्ट कार्यप्रणाली, भ्रष्ट प्रशासन , भ्रष्ट अनुशासन के रहते भ्रष्टाचार मिटाना किसी से संभव नहीं हैं । अगर समय रहते भ्रष्टाचार पर अंकुश ईमानदारी पूर्वक नही लग पाया तो भ्रष्टाचार के भय से प्राकृतिक कार्य प्रणाली बदल जायेगी । मधुबनी जिले में भ्रष्टाचार रोग का ही नतीजा हैं कि जिला के सकरी थाना अंतर्गत गंधवारी गांव निवासी 44 वर्षीय शंकर ठाकुर ने अपने 39 वर्षीय छोटे भाई घनानंद ठाकुर के परिवार सहित को घर से मारपीट कर जबरदस्ती निकाल दिया । पीड़ित परिवार के मुखिया घनानंद ठाकुर ने बताया कि मेरा बड़ा भाई दिल्ली के एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है । जब उन्हें पता चलता है कि मैं घर में जाकर रहने लगा हूं तो वे वहां से आकर मेरे और मेरे परिवार के साथ मारपीट कर घर से निकाल देता है । मैं कई महीनों से अपने पुत्र,पुत्री और पत्नी को लेकर इधर - उधर भटक रहा हूं । दाने - दाने को मोहताज हूं । कहां जाऊं,किधर जाऊं समझ में नहीं आता । उन्होंने कहां कि इसके लिए मेरी पत्नी ने अभियुक्त शंकर ठाकुर पर सकरी थाना कांड संख्या - 233 / 23 पर यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है कि मेरे भैसुर ने असामाजिक तत्वों के सहयोग से मुझे और मेरे परिवारजनों के साथ मारपीट कर घायल अवस्था में पैतृक घर से निकाल बाहर कर घर में ताला लगा दिया । इसके बाद मैंने अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी, आरक्षी उपाधीक्षक मधुबनी,जिला पधाधिकारी मधुबनी,अंचलाधिकारी रहिका,लोक अदालत जिला विधिक सेवा पदाधिकारी मधुबनी,मानवाधिकार पटना,आरक्षी महानिरीक्षक दरभंगा से लेकर मुख्यमंत्री (बिहार सरकार) तथा स्थानीय सरपंच तक से इस समस्या के निदान हेतु आवेदन देते हुए गुहार लगाई । लेकिन कोई मेरी बातों को सुनता ही नहीं । सभी लोग एक दूसरे के यहां जाने को कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे है । उन्होंने यह भी कहां कि स्थानीय प्रशासन ने मुझे यह कहां कि आपको जहां जाना हो जाइए हम कुछ भी नही कर सकते । उनका यह भी कहना हैं कि लोकसभा चुनाव - 2024 भी नजदीक आ रहा है । हम इस बार चुनाव में सरीक भी नही हो सकते । क्योंकि हम सपरिवार इधर उधर भटककर यंत्र तंत्र रहते हैं । ऐसी स्थिति में हम वोट भी नही गिरा सकते । प्रशासनिक विभाग तथा न्यायालय को न्याय का मंदिर कहां गया हैं । परन्तु अब यहां के कुछ स्वार्थी और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारीगणों के कारण इसे अन्यायालय कहां जाता हैं । वैसे इस न्याय के मंदिर की गरिमा बनाएं रखने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयत्नशील रहते है । क्या इस पीड़ित परिवार को अपना घर बार मिल पायेगा ? क्या इन्हे उचित न्याय मिल पायेगा ? क्या वे इस बार लोकसभा चुनाव - 2024 में अपना मतदान कर पायेंगे ? ऐसी स्थिति में प्रशासनिक न्याय के इस मंदिर की गरिमा कितनी बनी रहेगी ? यह आसानी से सोचा जा सकता है ।

बिहार मे एनडीए को वाकओवर देता महागठबंधन

समरेंद्र कुमार ओझा

जैसा की इस बार के लोकसभा चुनाव मे यह संभावना जताई जा रही थी की इस बार के चुनाव बिहार मे एनडीए के लिए काफी मुश्किल भरे होने वाले है, बिहार मे नितीश कुमार के प्रति लोगो मे काफी नाराजगी देखि जा रही थी और यह कयास लगाए जा रहे थे की इस बार नितीश कुमार को साथ लाना कही भाजपा पर भी भारी न पड़ जाय परन्तु इन सारी संभावनाओं पर बिहार महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाने मे पानी फेर दिया है और एनडीए उम्मीदवारों के जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है या यूँ कहे की बिहार महागठबंधन मे शामिल दलों द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 मे वाकओवर दे दिया गया है। एक तरफ जहां एनडीए नित गठबंधन ने वजाप्ता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेस कर अपनी सीटों, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर आपसी सामंजस्य को दिखाया वही राजद -कांग्रेस नित महागठबंधन ने अभी तक ना तो किसी उम्मीदवार के बारे मे बताया गया ना ही कोई एक संयुक्त रैली हुई। यहाँ सभी आपस मे ही एक दूसरे को परास्त करने की जी तोड़ कोशिश मे लगे है जिसका सीधा उदाहरण पूर्णिया मे पप्पू यादव प्रकरण, कटिहार मे अशफाक करिम, सीवान मे हीना शहाब, कन्हैया प्रकरण इससे साफ जाहिर है की महागठबंधन आपस मे ही एक दूसरे को परास्त करने मे लगे है।सीमांचल के सबसे मजबूत इलाके मे किसी भी हद तक जा के महागठबंधन के सबसे मजबूत साथी पप्पू यादव को ही हराने मे जोड़ लगाए दिख रहे है। शिवहर सीतामढ़ी जहां एनडीए ने अपने वर्तमान सांसदों जो वैश्य समाज से थे का टिकट काट दिया और वहाँ वैश्य समुदाय खासा नाराज है वहा कौन लड़ेगा कुछ पता नहीं। शिवहर, सितामढ़ी, बेतिया, बाल्मीकिनगर,सीवान, महाराजगंज, हाजीपुर, वैशाली, मधेपुरा,सुपौल, ,पाटलीपुत्र,अररिया, समस्तीपुर जैसी कमसे कम 15-20सीटे ऐसी है जहां महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा यह भी पता नहीं है। जब अभी तक उम्मीदवार ही तय नहीं है तो वह चुनाव क्या लड़ेगा। एक तरफ जहां एनडीए नित गठबंधन के आखिरी चरण के होनेवाले मतदान के लिए भी उम्मीदवार मैदान मे उतर कर अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे है तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपने दूसरे चरण मे होने वाले सीटों पर उम्मीदवार का ही पता नहीं है। महागठबंधन मे बिहार मे नेतृत्व कर रहे राजद के नेता तेजस्वी आराम से बैठे है उन्हें इस चुनाव की कोई चिंता नहीं है,वह तो जैसे यह सोच कर बैठे है की यह चुनाव उनका नहीं है उनका चुनाव तो वर्ष 2025 मे होगा उधर कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी विश्रामगृह मे है तो युवराज राहुल वायनाड मे अपने नामांकन के बाद वही बैठे है। कही से भी नहीं दिख रहा की विपक्ष लोकसभा चुनाव मे अपने पूर्ण समर्पण के साथ चुनाव मैदान मे है और यह एक तरह से एनडीए को पूर्ण रूप से वाकओवर देने के समान है।

बंद हो किसी भी भारतवासी को 'बाहरी' उम्मीदवार बताना

आर.के. सिन्हा

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने और चुनाव प्रचार का काम प्रतिदिन गति पकड़ता जा रहा है। इसके साथ ही सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी करते जा रहे हैं। संयोग से अभी तक किसी प्रत्याशी पर 'बाहरी' उम्मीदवार होने का आरोप नहीं लगा है। हालांकि, हमारे यहां किसी को भी बिना किसी कारण के बाहरी उम्मीदवार बता दिया जाता है। याद करें 2014 के लोकसभा चुनाव के समय जब नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो कांग्रेस के नेता उन्हें 'बाहरी' बताने में लगे थे। इसी तरह अरुण जेटली के 2014 में अमृतसर से चुनाव लड़ने पर विवाद खड़ा हो गया था। उन्हें भी कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार कहा था।

यह आरोप उस कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे जिस पार्टी ने देश के 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में बाहरी दिल्ली सीट से मलयाली सज्जन सी.कृष्ण नायर को अपना उम्मीदवार बनाया था। दिल्ली उन्हें गांवों का गांधी कहती थी। सी.कृष्ण नायर की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को स्थापित करने में अहम भूमिका रही थी। वे लोकसभा के 1957 में हुए चुनाव में भी जीते थे। जिस कांग्रेस ने नायर साहब को टिकट दिया था उसी ने 1957 के लोकसभा चुनाव में अंबाला में जन्मी बांग्ला परिवार से संबंध रखने वालीं सुचेता कृपलानी को नई दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। सुचेता जी आगे चलकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनीं। सच में अपने ही देश में कोई बाहरी उम्मीदवार कैसे हो सकता है। सारा भारत हम सबका है। यहां हरेक भारतवासी नागरिक को कहीं भी रहने या कहीं से भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। तब किसी को बाहरी कहना हर लिहाज से निंदनीय है। सुचेता जी के पति और प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी आचार्य कृपलानी बिहार के भागलपुर और सीतामढ़ी से सांसद रहे। यानी एक सिंधी बिहार से सांसद बना।

अब जार्ज फर्नांडीज को लें। जार्ज साहब भले ही दक्षिण भारत से आते थे, पर बिहार उन्हें अपना मानता था और वे बिहार को अपना मानते थे। बिहार ने उन्हें तहेदिल से आदर भी दिया। उन्होंने भी बिहार को पूरी तरह अपना लिया था। वे भोजपुरी भाषा और मैथली भाषा भी मजे की बोल लिया करते थे। जॉर्ज साहब को बिहार की जनता ने कई बार लोकसभा में भेजा। वह मुंबई से भी लोकसभा का चुनाव जीते। बिखरे बाल, बिना प्रेस किया हुआ खादी का कुर्ता-पायजामा, मामूली सी चप्पल पहनने वाले जॉर्ज साहब जैसा मजदूर नेता, प्रखर वक्ता, उसूलों की राजनीति करने वाले इंसान अब फिर से देश शायद ही देखेगा। वे चिर बागी थे। उनका कोई चुनावी जातीय समीकरण भी नहीं था। उनका कोई संगठित कॉडर भी नहीं था, फिर भी वह अंतरराष्ट्रीय हैसियत के नेता थे।

इससे पूर्व भी 1962 और 1967 में बिहार ने मराठी मधु लिमये को लोकसभा में बार-बार भेजा। वह जब संसद में होते थे, तो सत्तापक्ष को डर सताता रहता था कि कब उनपर तीखे सवालों की बौछार हो जाएगी। बिहार की राजनीति की बात मधु लिमये के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। वह मूल रूप से पुणे के थे। एक मराठी व्यक्ति का बिहार से चार बार चुनाव जीतना अपने आप में अनोखा है। राज्यसभा में ऐसे कई दूसरे नेता हुए हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसे उदाहरण कम ही देखे गए हैं। लिमये का बचपन महाराष्ट्र में बीता, उनकी पूरी पढ़ाई भी वहीं से हुई, वो महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय थे। उन्होंने जब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा तो चुनाव लड़ने के लिए बिहार ही चुना।

पहली बार वो 1962 में मुंगेर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1964 में, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विलय हुआ और यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। मधु लिमये पहली बार यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा गए थे। 1967 के चुनाव में लिमये ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर मुंगेर से जीत हासिल की। 1973 में लिमये ने बिहार के बांका से चुनाव जीता। किसी को अपने ही देश में बाहरी कह कर अपमानित करना सही नहीं है। कानपुर से एस.एम.बैनर्जी लंबे समय तक सांसद बनते रहे। वह बांग्लाभाषी थे और बंगाल से कानपुर में आकर बसे थे। वह मजदूर नेता थे। अजीब विडंबना है कि हमारे यहां कुछ तंग दिल लोग जिसको चाहते हैं बाहरी बता देते हैं। यह स्थिति तब है जब हम भारतीय करीब एक-डेढ़ दर्जन देशों में सांसद से लेकर प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक बन गए। इनमें मलेशिया, मारीशस, त्रिनिडाड, ग्याना, केन्या, फीजी, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा वगैरह देश शामिल हैं। कैरिबियाई देश ग्याना में 1960 के दशक में भारतीय मूल के छेदी जगन राष्ट्रपति बन गए थे। उसके बाद तो शिवसागर राम गुलाम (मॉरीशस), नवीन राम गुलाम (मॉरीशस), महेन्द्र चौधरी(फीजी), वासदेव पांडे (त्रिनिडाड), एस.रामनाथन (सिंगापुर), श्रषि सुनक (ब्रिटेन), कमला हैरिस (अमेरिका) सरीखे भारतवंशी विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनते रहे।

अभी हाल में ही एक भारतीय मूल के नागरिक थरमन षणमुखरत्नम को भारी बहुमत से सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया। बेशक, हम भारतीयों को अपना नजरिया बदलना होगा। अपनी सोच के दायरे का विस्तार करना होगा। हमें जाति, भाषा, मजहब, लिंग आदि के बंधनों को तोड़ना होगा। आपको वर्तमान में भारतवंशी सांसद अफ्रीका से लेकर यूरोप, अमेरिका और न्यूजीलैंड की संसद में मिलेंगे। मतलब यह है कि रोजगार की तलाश में दूर देश जाने वाले भारतीय अब वहां की किस्मत ही लिखने लगे। अगर बात साउथ अफ्रीका की करें तो वहां पर मेवा रामगोंविद सांसद हैं। उनसे पहले भी कुछ और भारतवंशी सांसद रहे हैं। परमिंदर सिंह मारवाह युगांडा की पार्लियामेंट में थे। वह चाहते हैं कि भारत के निवेशक युगांडा के कृषि क्षेत्र में आएं। उनके परिवार ने 1970 के दशक में भी युगांडा को नहीं छोड़ा था जब ईदी अमीन भारतीयों पर जुल्म ढा रहे थे। उनके दादा युगांडा में बसे थे। उनके दादा रेलवे में थे। उन्होंने 1930 और 1940 के दशक में ईस्ट अफ्रीकी देशों में रेल लाइनें बिछाईं थीं। अब बात केन्या की। इधर कुछ साल पहले तक एक सरदारनी सांसद थीं। उनका नाम है सोनिया विरदी। सोनिया केन्या में महिलाओं के अधिकारो के लिए लड़ती हैं। दरअसल वह पहली एशियाई मूल की महिला सांसद हैं केन्या में। सियासत में नाम कमाने के लिहाज से भारतवंशियों के लिए कनाडा बहुत उर्वरा भूमि है। वहां कई भारतीय मूल के सांसद हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे यहां किसी को अपने सियासी स्वार्थों के लिए बाहरी कहना बंद होना चाहिए। देश अब बदल रहा है। हवा के रुख को पहचानें।

मेष राशिः आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज परिवार की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आज आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। छात्र आज कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए।

वृष राशिःआज का दिन आपके लिए समान्य रहेगा। आज आपके विरोधी भी आपके काम की सराहना करेंगे। आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को सहयोगीयो से मदद मिलेगी जिससे आपका कार्य जल्दी पूरा हो जायेगा। आज आपको बिजनेस के सिलसिले से राज्य से बाहर जाना पड़ सकता है।

मिथुन राशिःआज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप समाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ऑफिस के काम में आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएगी। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के आसार खुलेंगे।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। जीवनसाथी आज आपको खुशियाँ देंगे। आज कार्यों में माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज किसी से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरुरत है।

सिंह राशिः आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुए धन लाभ से आज अपनी जरुरत का सामान खरीदेंगे। दांपत्य जीवन में और मधुरता आएगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है, पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

कन्या राशिःआज का दिन आपके लिए खुशियाँ लेकर आया है। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आयेगा। कुछ लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से थोड़ा संभलकर रहना चाहिए। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आयेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता-पिता के साथ किसी धार्मिक कार्य की योजना बनायेंगे।

तुला राशिःआज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पडने से बचना चाहिए। छोटीःछोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। घर के बड़ो से कोई नई बात आप सीखेंगे। आज काफी दिनों से आपका रुका काम पूरा हो जायेगा, मानसिक शांति मिलेगी। सामाजिक तौर पर आप बहुत सक्रिय भी रहेंगे।

वृश्चिक राशिःआज आपका दिन उमंग से भरा रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आयेंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें, इससे जीवन में चल रही परेशानियो का हल मिलेगा। मिलजुल कर किए गए कार्यो में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ो से कोई नई सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा।

धनु राशिःआज नए कार्यों करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा, आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी। करियर में आप नये आयाम स्थापित करेंगे। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। किसी काम में जीवनसाथी की सलाह फायदेमंद रहेगी।

मकर राशिः आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिसे आप पूरी लग्न और मेहनत से करेंगे, काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। आपके आय के नए स्त्रोत बनेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वो आज अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज आर्थिक मामलो में माता-पिता का सहयोग मिलता रहेगा दोस्तों से भी मदद मिलेगी।

कुंभ राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज रोजमर्रा के कामों में आपको ज्यादा समय लग सकता है।आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ो की राय लेना आपके लिए बेहतर साबित होगी। बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे।

मीन राशि :आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ो की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जायेगा। किसी रिश्तेदार से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जीवनसाथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे, इससे रिश्तों में नयापन आयेगा। समाजिक कार्यो में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा।

शब्द सामर्थ्य -018

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. कतार, क्रम, पांत 2. लज्जत, जायका 4. कारण, वजह 7. सुंदर प्रतीत होना, सुखद होना 8. घोड़े आदि का मल 9. अक्सर, ज्यादातर 10. चक्की में पीसना, मसलना, कुचलना 12. धनुष, फौजी टुकड़ी 13. आभूषण, जेवर 15. लहरों का चक्कर, जलावर्त, भ्रमर 17. बायां, विरुद्ध 18. गाना, नगमा 19. लाचार, विवश 22. नमन, प्रणाम 25. चौकी, थाना 26. इकरार, समझौता, ठेका 27. अधिकार होना, सामर्थ्य होना (मुहा.)।

ऊपर से नीचे

1. एक प्रदेश जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है 2. हविर्दान के समय उच्चारित एक शब्द, भष्म 3. दन-दन करते हुए 5. बलशाली, बलवाला 6. परिवर्तित करना, पहले से भिन्न हो जाना 7. चांद, चंद्रमा, रजनीश 11. अप्रिय, अरुचिकर 14. मैं का बहुवचन 15. भंगेड़ी, भंग करने वाला, झाड़ू लगाने तथा मैला साफ करने वाला 16. मातृभूमि, स्वदेश 19. मक्खन, माखन 20. बुढ़ापा, धन, ज्वर 21. टालना, हटाना, बहाना करके हटाना 23. सीमा, हद 24. सौ का पाचंवा हिस्सा 25. घोड़े के पैरों में लगाने का लोहे का टुकड़ा, पौधे आदि का डंठल।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 017 का हल

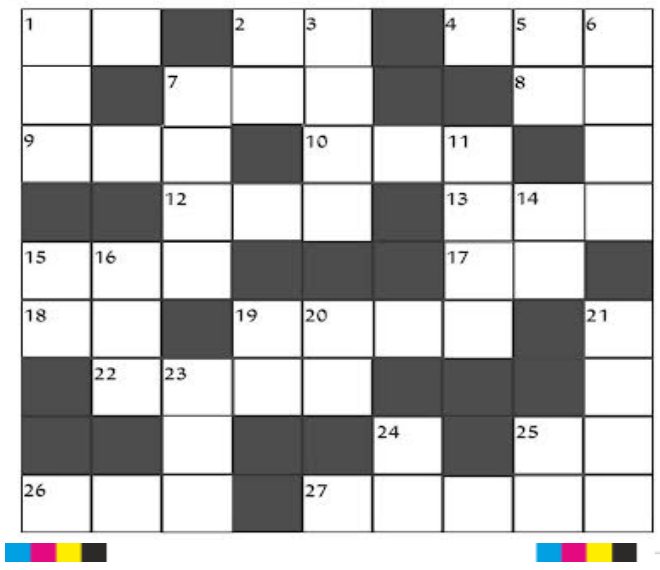

वि	ज	य		ब	नि	या		दे
वा		ती	त	र		रा	जी	व
ह	मा	म		स	प	ना		ता
	न				टा			
दा	व	त		वि	ना	श		अ
य		ह	त्या			ह	र्जा	ना
रा	ह	त		न	ज	र		व
	वा				मी		ना	श्य
दु	ला	रा		जा	न	की		क

सूडोकु नवताल- 7027

★★★★☆ मध्यम

		8				1	5	
2					1	8		
3			4		6	7		9
5					9			
	9		2	3	4		7	
			1					8
4		7	6		5			1
		6	7					4
	5	3				2		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7026 का हल

3	9	7	5	2	1	4	8	6
5	4	2	9	6	8	7	1	3
8	6	1	3	7	4	9	5	2
2	8	9	1	5	3	6	4	7
4	7	3	2	8	6	5	9	1
6	1	5	4	9	7	2	3	8
9	3	4	7	1	2	8	6	5
7	5	6	8	3	9	1	2	4
1	2	8	6	4	5	3	7	9

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देशप्राण
स्वतंत्र हिन्दी दैनिक

महाराष्ट्र की सियासत में पेंच

जिन कुछेक राज्यों में आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण सबसे ज्यादा जटिल माने जा रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र प्रमुख है। इसी जटिलता का ताजा उदाहरण है पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम का पार्टी से अलगाव सार्वजनिक होने के बाद पूर्व घोषणा के बावजूद यह न बता पाना कि वह किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। गुरुवार को वह इसकी घोषणा करने वाले थे, लेकिन यह कहते हुए दो-तीन दिनों का और वक्त ले लिया कि अब उसकी कोई जल्दी नहीं है। दरअसल अनिश्चितता के पीछे सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अभी महायुति यानी भाजपा और उसके अन्य सहयोगी दलों में भी सीटों के बंटवारे पर पूरी सहमति नहीं बन पाई है। इससे कई सीटों पर यह निश्चित नहीं हो पा रहा कि वह आखिरकार किस दल के हिस्से में जाएगी और एनडीए प्रत्याशी को किस निशान पर चुनाव लड़ना होगा। इस बार का चुनाव इस मायने में खास है कि प्रदेश के दो प्रमुख दलइन शिवसेना और एनसीपी- दोफाड़ होकर आमने-सामने हैं। ऐसे में सीटों को लेकर पारंपरिक दावे पुराने रूप में नहीं रह गए हैं। दोनों खेमों में हर सीट पर न केवल दलों के बीच दावेदारी बढ़ी हुई है बल्कि संभावित प्रत्याशियों की संख्या भी ज्यादा है। नतीजतन, यह रस्साकशी नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह तो बन ही रही है, कई सीटों पर इसने विचित्र स्थिति पैदा कर दी है। उदाहरण के लिए, विदर्भ की बुलढाणा सीट को लिया जा सकता है, जो महायुति में शिंदे सेना को दी गई, लेकिन उस पर भाजपा की भी दावेदारी थी। पार्टी के झुकने के बावजूद स्थानीय भाजपा नेता ने वहां से पर्चा भर दिया। दिलचस्प है कि उस नेता ने दो पर्चे भरे हैं एक भाजपा नेता के रूप में और दूसरा निर्दलीय के तौर पर। यह स्थिति आगे चाहे जो भी रूप ले, इतना तो स्पष्ट है कि चुनावी समीकरणों के अंतर्विरोध को साधना विभिन्न पार्टियों के नेतृत्व के लिए आसान साबित नहीं हो रहा। राजनीतिक अंतर्विरोध इस बार पार्टियों पर खास परिवारों के दबदबे की ही नहीं, एक परिवार के अंदर विरासत पर अलग-अलग दावेदारी की भी झलक दे रहा है। यह सबसे स्पष्ट रूप में बारामती सीट पर दिख रहा है, जो पिछले करीब छह दशकों से शरद पवार का गढ़ रही है। इस बार वहां इसी परिवार के दो अहम सदस्य इन बेटी सुप्रिया सुले और बहू सुनेत्रा पवार- आमने सामने हैं। जहां सुप्रिया पिता शरद पवार की ओर से लड़ रही हैं, वहीं सुनेत्रा अपने पति अजित पवार के नाम पर वोट मांग रही हैं। जाहिर है, कम से कम महाराष्ट्र में यह चुनाव केंद्र की अगली सरकार तय करने में भूमिका ही नहीं निभाएगा, प्रदेश राजनीति के स्वरूप और उसकी राजनीतिक संस्कृति को भी नए ढंग से परिभाषित कर सकता है।

बंद हो किसी भी भारतवासी को बाहरी उम्मीदवार बताना

आर.के. सिन्हा
(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

अब जार्ज फर्नांडीज को लें। जार्ज साहब भले ही दक्षिण भारत से आते थे, पर बिहार उन्हें अपना मानता था और वे बिहार को अपना मानते थे। बिहार ने उन्हें तहेदिल से आदर भी दिया। उन्होंने भी बिहार को पूरी तरह अपना लिया था। वे भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा भी मजे की बोल लिया करते थे। जॉर्ज साहब को बिहार की जनता ने कई बार लोकसभा में भेजा। वह मुंबई से भी लोकसभा का चुनाव जीते। बिखरे बाल, बिना प्रेस किया हुआ खादी का कुर्ता-पायजामा, मामूली सी चप्पल पहनने वाले जार्ज साहब जैसा मजदूर नेता, प्रखर वक्ता, उसूलों की राजनीति करने वाले इंसान अब फिर से देश शायद ही देखेगा। वे चिर बागी थे।

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने और चुनाव प्रचार का काम प्रतिदिन गति पकड़ता जा रहा है। इसके साथ ही सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी करते जा रहे हैं। संयोग से अभी तक किसी प्रत्याशी पर बाहरी उम्मीदवार होने का आरोप नहीं लगा है। हालांकि, हमारे यहां किसी को भी बिना किसी कारण के बाहरी उम्मीदवार बता दिया जाता है। याद करें 2014 के लोकसभा चुनाव के समय जब नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो कांग्रेस के नेता उन्हें बाहरी बताने में लगे थे। इसी तरह अरुण जेटली के 2014 में अमृतसर से चुनाव लड़ने पर विवाद खड़ा हो गया था। उन्हें भी कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार कहा था। यह आरोप उस कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे जिस पार्टी ने देश के 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में बाहरी दिल्ली सीट से मलयाली सज्जन सी.कृष्ण नायर को अपना उम्मीदवार बनाया था। दिल्ली उन्हें गांवों का गांधी कहती थी। सी.कृष्ण नायर की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को स्थापित करने में अहम भूमिका रही थी। वे लोकसभा के 1957 में हुए चुनाव में भी जीते थे। जिस कांग्रेस ने नायर साहब को टिकट दिया था उसी ने 1957 के लोकसभा चुनाव में अंबाला में जन्मी बांग्ला परिवार से संबंध रखने वाली सुचेता कृपलानी को नई दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। सुचेता जी आगे चलकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनीं।

सच में अपने ही देश में कोई बाहरी उम्मीदवार कैसे हो सकता है। सारा भारत हम सबका है। यहाँ हरेक भारतवासी नागरिक को कहीं भी रहने या कहीं से भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। तब किसी को बाहरी कहना हर लिहाज से निंदनीय है। सुचेता जी के पति और प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी आचार्य कृपलानी बिहार के भागलपुर और सीतामढ़ी से सांसद रहे। यानी एक सिंधी बिहार से सांसद बना। अब जार्ज फर्नांडीज को लें। जार्ज साहब भले ही दक्षिण भारत से आते थे, पर बिहार उन्हें अपना मानता था और वे बिहार को अपना मानते थे। बिहार ने उन्हें तहेदिल से आदर भी दिया। उन्होंने भी बिहार को पूरी तरह अपना लिया था। वे भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा भी मजे की बोल लिया करते थे। जॉर्ज साहब को बिहार की जनता ने कई बार लोकसभा में भेजा। वह मुंबई से भी लोकसभा का चुनाव जीते। बिखरे बाल, बिना प्रेस किया हुआ खादी का कुर्ता-पायजामा, मामूली सी चप्पल पहनने वाले जार्ज साहब जैसा मजदूर नेता, प्रखर वक्ता, उसूलों की राजनीति करने वाले इंसान अब फिर से देश शायद ही देखेगा। वे चिर बागी थे। उनका कोई चुनावी जातीय समीकरण भी नहीं था । उनका कोई संगठित कैडर भी नहीं था, फिर भी वह अंतरराष्ट्रीय हैसियत के नेता थे।

इससे पूर्व भी 1962 और 1967 में बिहार ने मराठी मधु लिमये को लोकसभा में बार-बार भेजा। वह जब संसद में होते थे, तो सत्ता पक्ष को डर सताता रहता था कि कब उन पर तीखे सवालों की बौछार हो जाएगी। बिहार की राजनीति की बात मधु लिमये के ज़िक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। वह मूल रूप से पुणे के थे। एक मराठी व्यक्ति का बिहार से चार बार चुनाव जीतना अपने आप में अनोखा है। राज्यसभा में ऐसे कई दूसरे नेता हुए हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसे उदाहरण कम ही देखे गए हैं। लिमये का बचपन महाराष्ट्र में बीता, उनकी पूरी पढ़ाई भी वहीं से हुई, वो महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय थे। उन्होंने जब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा तो चुनाव लड़ने के लिए बिहार ही चुना। पहली बार वो 1962 में मुंगेर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1964 में, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विलय हुआ और यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। मधु लिमये पहली बार यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा गए थे। 1967 के चुनावों में, लिमये ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर मुंगेर से जीत हासिल की। 1973 में, लिमये ने बिहार के बांका से चुनाव जीता। किसी को अपने ही देश में बाहरी कह कर अपमानित करना सही नहीं है। कानपुर से एस.एम.बैनर्जी लंबे समय तक सांसद बनते रहे। वह बांग्लाभाषी थे और बंगाल से कानपुर में आकर बसे थे। वह मजदूर नेता थे।

अजीब विडंबना है कि हमारे यहां कुछ तंग दिल लोग जिसको चाहते हैं बाहरी बता देते हैं। यह स्थिति तब है जब हम भारतीय करीब एक-डेढ़ दर्जन देशों में सांसद से लेकर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक बन गए। इनमें मलेशिया, मॉरीशस, त्रिनिडाड, ग्याना, केन्या, फीजी, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा वगैरह देश शामिल हैं। कैरिबियाई देश ग्याना में 1960 के दशक में भारतीय मूल के छेदी जगन राष्ट्रपति बन गए थे। उसके बाद तो शिवसागर रामगुलाम (मॉरीशस), नवीन रामगुलाम (मॉरीशस), महेन्द्र चौधरी(फिजी), वासुदेव पांडेय (त्रिनिदाद), एस.रामनाथन (सिंगापु?), श्रृषि सुनक (ब्रिटेन), कमला हैरिस (अमेरिका) सरीखे भारतवंशी विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनते रहे। अभी हाल में ही एक भारतीय मूल के नागरिक भी थरमन षणमुख रत्नम को भारी बहुमत से सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया।

बेशक, हम भारतीयों को अपना नजरिया बदलना होगा। अपनी सोच के दायरे का विस्तार करना होगा। हमें जाति, भाषा, मजहब, लिंग आदि के बंधनों को तोड़ना होगा। आपको वर्तमान में भारतवंशी सांसद अफ्रीका से लेकर यूरोप, अमेरिका और न्यूजीलैंड की संसद में मिलेंगे। मतलब यह है कि रोजगार की तलाश में दूर देश जाने वाले भारतीय अब वहां की किस्मत ही लिखने लगे। अगर बात साउथ अफ्रीका की करें तो वहां पर मेवा रामगोविंद सांसद हैं। उनसे पहले भी कुछ और भारतवंशी सांसद रहे हैं। परमिंदर सिंह मारवाह युगांडा की पार्लियामेंट में थे। वह चाहते हैं कि भारत के निवेशक युगांडा के कृषि क्षेत्र में आएं। उनके परिवार ने 1970 के दशक में भी युगांडा को नहीं छोड़ा था जब ईदी अमीन भारतीयों पर जुल्म ढा रहे थे। उनके दादा युगांडा में बसे थे। उनके दादा रेलवे में थे। उन्होंने 1930 और 1940 के दशक में ईस्ट अफ्रीकी देशों में रेल लाइनें बिछाईं थीं। अब बात केन्या की। इधर कुछ साल पहले तक एक सरदारनी सांसद थीं। उनका नाम है सोनिया विरदी। सोनिया केन्या में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। दरअसल वह पहली एशियाई मूल की महिला सांसद हैं केन्या में।

सियासत में नाम कमाने के लिहाज से भारत वंशियों के लिए कनाडा बहुत उर्वरा भूमि है। वहां कई भारतीय मूल के सांसद हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे यहां किसी को अपने सियासी स्वार्थों के लिए बाहरी कहना बंद होना चाहिए। देश अब बदल रहा है। हवा के रूख को पहचानें।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

देश की आर्थिकी को गति भी देगा अंधाधुंध चुनावी खर्च

मधुरेन्द्र सिन्हा

चुनाव में उम्मीदवार तरह-तरह के खर्चों के लिए पैसे लगाते हैं जिनमें कार्यकताओं से लेकर व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों को बड़ी राशि मिलेगी। लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को हजारों कार्यकताओं की सेवा लेनी होती है। हर बूथ पर कार्यकर्ता रखने से लेकर प्रचार करने तक। वह जमाने गये जब पार्टी या उम्मीदवार के नाम पर कार्यकर्ता खुद ब खुद आ जाते थे और अपना योगदान देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, कार्यकर्ता की हैसियत और उसकी ताकत के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं जो वह उस पूरी चुनाव अवधि यानी दो या तीन महीने तक पाता रहता है। यह भी एक तरह का रोजगार है। ऐसे ही पैसे ट्रांसपोर्टरों, रसोइयों, खाने-पीने का सामान बेचने वालों, होटलों-रेस्तरां, प्रिंटिंग प्रेस वालों, संचार साधनों की व्यवस्था करने वालों को भी मिलते हैं। इसकी भी संख्या लाखों में होती है। झंडे-पर्चे की अगर पार्टी ने व्यवस्था कर दी तो ठीक है अन्यथा उम्मीदवार खुद ही उन पर खर्च करता है और यह राशि मोटी होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की मदद के लिए कई तरह से खर्च करते हैं।

लोकसभा चुनाव आ गये हैं और पूरे देश में हलचल है। राजनीतिक दल, उनके उम्मीदवार और सरकार सभी सक्रिय हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता प्रचार में निकल पड़े हैं और सभाएं होने लगी हैं। बड़े नेताओं के तूफानी दौरे अब शुरू होने वाले हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि बड़े पैमाने पर पैसा बंटेगा और लगेगा। एक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में खर्च की एक सीमा तय है और लोकसभा चुनाव में इस बार यह 95 लाख रुपये है जो पिछली बार से कहीं ज्यादा है। लेकिन सच्चाई है कि खर्च कई गुना ज्यादा होगा। देश में कुल कितना खर्च होने की संभावना है, इस पर बहस जारी है लेकिन अनुमान है कि इस बार यह पिछले लोकसभा चुनाव से दुगना होगा।

वर्ष 2024 में लोकसभा की 543 सीटों के चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवार कितना खर्च करेंगे, यह उनके सामर्थ्य, उनकी पार्टियों और इलाके पर निर्भर करेगा। कई चुनाव क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं और काफी खचीर्ले भी होते हैं। स्वतंत्र संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 75-80 चुनाव क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां 2019 के चुनाव में हर निर्वाचन क्षेत्र में खर्च औसतन 40 करोड़ रुपये हुआ जबकि खर्च की सीमा महज 70 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार थी। संस्था का कहना है कि उस चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए जो अनुमान से कहीं ज्यादा है। इसके पहले यानी 2014 में आम चुनाव में 30,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि 1999 में कुल खर्च 10,000 करोड़ रुपये था जिसे उस समय भी बहुत अधिक माना गया था।

अब 2024 का यह चुनाव कितना खचीर्ला होगा, इसका भी अंदाजा लगाना उचित रहेगा। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में कुल 11.2 खरब रुपये यानी लगभग 14 अरब डॉलर खर्च होंगे। यह राशि पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुल सालाना बजट के एक-तिहाई से भी ज्यादा है। और अगर इतना खर्च हुआ तो यह दुनिया का सबसे खचीर्ला चुनाव होगा। इसमें सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार की भूमिका होगी। जाहिर है, सत्तारूढ़ दल सबसे ज्यादा खर्च करेगा। कई निर्वाचन क्षेत्रों में रिकॉर्ड खर्च होगा। सरकारी एजेंसियों की रोक-टोक के बावजूद खर्च में कमी नहीं आएगी क्योंकि सवाल फिर वही यानी अस्तित्व का है और कोई भी हारना नहीं चाहता है। हर उम्मीदवार चाहे वह दमदार न हो, बड़ा खर्च करने से बाज नहीं आ सकता है, क्योंकि एक जीत उसकी जिंदगी बदल सकती है।

चुनाव में उम्मीदवार तरह-तरह के खर्चों के लिए पैसे लगाते हैं जिनमें कार्यकताओं से लेकर व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों को बड़ी राशि मिलेगी। लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को हजारों कार्यकताओं की सेवा लेनी होती है। हर बूथ पर कार्यकर्ता रखने से लेकर प्रचार करने तक। वह जमाने गये जब पार्टी या उम्मीदवार के नाम पर कार्यकर्ता खुद ब खुद आ जाते थे और अपना योगदान देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, कार्यकर्ता की हैसियत और उसकी ताकत के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं जो वह उस पूरी चुनाव अवधि यानी दो या तीन महीने तक पाता रहता है। यह भी एक तरह का रोजगार है। ऐसे ही पैसे ट्रांसपोर्टरों, रसोइयों, खाने-पीने का सामान बेचने वालों, होटलों-रेस्तरां, प्रिंटिंग प्रेस वालों, संचार साधनों की व्यवस्था करने वालों को भी मिलते हैं। इसकी भी संख्या लाखों में होती है। झंडे-पर्चे की अगर पार्टी ने व्यवस्था कर दी तो ठीक है अन्यथा उम्मीदवार खुद ही उन पर खर्च करता है और यह राशि मोटी होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की मदद के लिए कई तरह से खर्च करते हैं। यह सारा खर्च लगातार बाजार में पहुंचता रहता है। ऐसे ही एक अवधि तक लगातार पैसे खर्च होते रहते हैं और फिर अर्थव्यवस्था में ही जाते हैं।

ऐसा नहीं है कि चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार, राजनीतिक दल या उनके समर्थक ही पैसा खर्च करते हैं। सरकारें भी बड़े पैमाने पर खर्च करती हैं। कर्मचारियों तथा पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती, उनके खाने-पीने से लेकर वाहनों की व्यवस्था पर सरकारें बड़े पैमाने खर्च करती हैं। इसके अलावा भी अन्य तरह के सामानों की खरीद की जाती है जिस पर भारी खर्च आता है। यह खर्च भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। खरीदारी और खपत बढ़ती जाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित है और इसका विकास खपत पर ही निर्भर करता है। आपको याद होगा कि श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह बात कही थी कि देश में घरेलू खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा है। जीडीपी के विकास की दर बढ़ी है। पूंजी प्रवाह से ही हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इस बार इतना धन आ रहा है कि इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। चुनाव जैसे मामले में जहां पैसा संबद्ध लोगों को मिलता है वहां खर्च भी तेजी से होता है। इस धन का बड़ा हिस्सा व्हाइट मनी नहीं होता है और चंदे वगैरह के रूप में आता है जो बैंकों वगैरह में फिर जमा नहीं होता है बल्कि सीधे खर्च कर दिया जाता है। खर्च करने की यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में तेजी लाती है। चुनाव में लाखों लोगों को अस्थायी रोजगार मिलता है और उनके पारिश्रमिक का पैसा भी खर्च होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नकदी का प्रवाह कम होता है वहां चुनाव के समय काफी हलचल रहती है क्योंकि उम्मीदवारों या पार्टियों का पैसा उन तक पहुंचता है। यह उनके काम आता है और वे खरीदारी करते हैं तथा खपत बढ़ाते हैं। यह सरकारी योजना मनरेगा की ही तरह है जहां उन्हें थोड़े समय के लिए ही सही पारिश्रमिक मिलता है और उनके खर्च पूरे करने में काम आता है। यह खपत बड़े पैमाने पर होती है और इससे काफी पैसा इधर से उधर होता है। इससे बाजारों में तेजी आ जाती है।

बेशक यह अस्थायी है लेकिन इसका असर दूरगामी होता है। कई मामलों में इसका असर चक्रीय भी होता है। कुछ क्षेत्रों में यह फिर निवेश की तरह काम करता है जिसके अपने फायदे हैं। इस बार संभावना है कि इतनी बड़ी राशि यानी 14 अरब डॉलर तक खर्च हो सकता है। यह राशि पाकिस्तान के सालाना बजट का एक-तिहाई है और यह अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर असर डालेगा। इसका सकारात्मक असर अवश्य दिखाई देगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इंतजार कीजिए चुनाव खत्म होने का।

अभिमत

अब तक सामने आए सबूत कमजोर, संदिग्ध और संभवतः विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित हैं। शराब नीति के 'लाभार्थियों' से आप के खजाने तक धन की आवाजाही को साबित करने के कोई ठोस सबूत नहीं है। यह न्यायपालिका पर निर्भर करता है कि वह मामलों को ठीक करे और केजरीवाल को जल्द से जल्द जमानत पर रिहा करने का आदेश दे। अफसोस की बात है कि कुल मिलाकर भारत में जमानत न्यायशास्त्र निराशाजनक है जो राज्य और अभियोजन पक्ष के पक्ष में है।

वेंटिलेटर पर है भारतीय लोकतंत्र

हरेश एम. जगतियानी

अब समय आ गया है कि संयुक्त विपक्ष एक संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशित करे जिसमें वे पीएमएलए, यूएपीए, मकोका जैसे घातक कानूनों और ऐसे अन्य कठोर अधिनियमों को निरस्त करने का वादा करें जिनका उपयोग सत्ता में बैठी एक दुर्भावनापूर्ण कार्यपालिका द्वारा विरोधियों के खिलाफ उत्पीड़न के हथियार के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त विपक्ष को हमारी न्यायिक मशीनरी को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने और ऊर्जा प्रदान करने की शपथ लेनी चाहिए। इस मुकाबले को न्यायपालिका बनाम 'मोदी की अदालत' तक सीमित न किया जाए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी आबकारी शराब नीति के लिए गिरफ्तार किया है। ईडी को व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी का अंग माना जाता है। ईडी का दावा है कि यह शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई थी। जिन कुछ लोगों को इसका फायदा हुआ उन्होंने केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को रिश्वत के रूप में सौ करोड़ रुपये दिए जिनका उसने गोवा में चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। इस प्रकार अपराध (रिश्वत) की आय को चुनावी उद्देश्यों के लिए वैध बनाया गया था जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) यानी मनी लांड्रिंग का प्रकरण बनता है। केजरीवाल को 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और न्यायपालिका के अलग आदेश आने तक 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले सबूत कहते हैं कि केजरीवाल ने रिश्वत ली थी। मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और सबूत यह है कि कुछ संभावित सरकारी गवाह हैं। आरोपपत्र भी अभी तैयार नहीं हुआ है और यह कि ईडी कार्यालय द्वारा नौ समन जारी किए जाने के बावजूद केजरीवाल द्वारा पूछताछ के लिए कार्यालय जाने से इनकार करना इस बात का संकेत है कि वे इस अपराध में शामिल हैं। इसी कारण से उनकी गिरफ्तारी की गई है। यह सब लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर हो रहा है जो नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल दे सकता है। सवाल यह है कि यह प्रकरण क्या दर्शाता है?

क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर जायज थी? यहां तक कि अगर आप इस आधार से शुरू करते हैं कि सभी राजनेता बेईमान हैं, तो भी इसका एक ही जोरदार जवाब है– नहीं। सत्तारुढ़ हर राजनीतिक दल का काम राजकोषीय नीतियों को कानून बनाना है। सिर्फ इसलिए कि इस तरह की नीति जनता के एक वर्ग को लाभ पहुंचाती है या लाभ प्रदान करती है, यह अपने आप में एक विधेय अपराधिक कृत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है जिससे मिली आय पीएमएलए के दायरे में आती है।

अब तक सामने आए सबूत कमजोर, संदिग्ध और संभवतः विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित हैं। शराब नीति के 'लाभार्थियों' से आप के खजाने तक धन की आवाजाही को साबित करने के कोई ठोस सबूत नहीं है। यह न्यायपालिका पर निर्भर करता है कि वह मामलों को ठीक करे और केजरीवाल को जल्द से जल्द जमानत पर रिहा करने का आदेश दे। अफसोस की बात है कि कुल मिलाकर भारत में जमानत न्यायशास्त्र निराशाजनक है जो राज्य और अभियोजन पक्ष के पक्ष में है। यह जानते हुए भी कि वास्तविक मुकदमे में असाधारण रूप से देरी हो सकती है जिससे अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर नहीं मिलता है, अदालतें अक्सर अपराध के एक संदिग्ध को दंडित करने के साधन के रूप में जमानत से इनकार करती हैं। महिलाओं को इस संबंध में कुछ हद तक वैधानिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त हैं लेकिन यह एक और गंभीर चर्चा का विषय है। यह कहने के लिए पर्याप्त अवसर है कि न्यायिक प्रणाली, विशेष रूप से निचली अदालतें आरोपी के साथ उदार नजर नहीं आती हैं।

एक अधिक प्रभावशाली शिकायतकर्ता अपने से कम प्रभावशाली विरोधी के नुकसान के लिए मामले में हेरफेर कर सकता है। मोदी बनाम केजरीवाल मुकाबले में परिणाम पहले से तय मालूम होता है। केवल जमानत न देकर केजरीवाल को चुनावी मैदान से बाहर रखा जा सकता है।

जब किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता को दौड़ से बाहर रखा जाता है तो ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का क्या होगा? लोकतंत्र वेंटिलेटर के लिए रोता है। इस जीवन निर्वाह उपकरण का प्रभारी कौन है? फिलहाल तो मोदी हैं और जब तक कि निम्नलिखित दोनों परिस्थितियां न बनती हों और वे मोदी के हाथ को स्विच से दूर करने का प्रयास न करें। पहला, ममता बनर्जी और वामपंथियों समेत पूरे विपक्ष को अपने महत्वहीन मतभेदों को भुलाकर भाजपा के खिलाफ संयुक्त चुनावी जंग लड़नी होगी। एक भी लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होना चाहिए। भाजपा के पास देश के 36 प्रतिशत वोट हैं। शेष 64 फीसदी वोट यदि निराश नहीं हैं तो भी निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल पर मोहित नहीं हैं। मोदी इस बात को जानते हैं। दूसरी, और शायद अधिक महत्वपूर्ण बात है कि न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को मजबूती के साथ स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव के हित में हो तो केजरीवाल को समय पर जमानत मिलनी चाहिए। यहां तक कि अगर अदालत केजरीवाल को जमानत देने की इच्छुक हो तो वह उनसे वचन भी ले सकती है कि चुनाव के बाद वे एक बार फिर खुद ईडी के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। लोकतंत्र के हित में ऐसा हो सकता हो, तो ऐसा ही सही। चुनावी मैदान से एक राष्ट्रीय पार्टी को बाहर रखने की कोशिश में लोकतंत्र की मौत की घंटी बज गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को केवल इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसे लगा कि सार्वजनिक महत्व के मामलों में गोपनीयता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह एक गंभीर स्थिति है। प्रधानमंत्री पद के तीसरे कार्यकाल के आकांक्षी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को जेल में बंद कर दिया। इसके बावजूद उसकी आकांक्षाओं की एक वैध चुनौती को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है।

यह वैश्विक चिंता का विषय है कि भारत में लोकतंत्र बना रहे। हम ऐसे भावी लोकतंत्रों से घिरे हैं जो युवा और महत्वाकांक्षी हैं जहां रूस और चीन एक होने का दिखावा भी नहीं करते हैं। हमारे नागरिकों को अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने के निरंकुश विकल्प से वंचित करके उनसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लें तो समझिये कि लोकतंत्र मर चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ('यदि' शब्द ज्यादा उचित है) केजरीवाल को कब रिहा किया जाता है और वे भाजपा की जीत को खतरे में डालने के लिए अपेक्षित समर्थन हासिल नहीं करते हैं। उनकी रिहाई से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तब भाजपा निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से जीत जाती। लेकिन केजरीवाल की उपस्थिति के बिना होने वाला चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो कभी हुआ ही नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने कहा है– 'मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकता हूं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के आपके अधिकार की रक्षा मैं अपनी आखिरी सांस तक करूंगा।' अपने प्रवक्ता के जरिए जर्मनी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं लेकिन भारत ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा है। 'भारतीय मामलों में जर्मनी के हस्तक्षेप' के बावजूद यह भारत के मजबूत लोकतांत्रिक होने के महत्व का संकेत है। यह सभ्य दुनिया के लिए मायने रखता है।

अब समय आ गया है कि संयुक्त विपक्ष एक संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशित करे जिसमें वे पीएमएलए, यूएपीए, मकोका जैसे घातक कानूनों और ऐसे अन्य कठोर अधिनियमों को निरस्त करने का वादा करें जिनका उपयोग सत्ता में बैठी एक दुर्भावनापूर्ण कार्यपालिका द्वारा विरोधियों के खिलाफ उत्पीड़न के हथियार के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त विपक्ष को हमारी न्यायिक मशीनरी को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने और ऊर्जा प्रदान करने की शपथ लेनी चाहिए। इस मुकाबले को न्यायपालिका बनाम 'मोदी की अदालत' तक सीमित न किया जाए। आम धारणा यह है कि भाजपा अजेय है और उसकी जीत की घोषणा औपचारिक रूप से की जानी चाहिए। फिर अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से रोककर और सलाखों के पीछे रखकर मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की गरिमा को क्यों धूमिल कर रहे हैं? प्रिय प्रधानमंत्री जी, लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शित करें कि आप अपने आप में विश्वास रखते हैं।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सिंडिकेट-द बिलियन प्रेस)

बीता सप्ताह

30 मार्च

- जम्मू के रामबन में 300 फीट गहरी खाई में एक टैक्सी के गिर जाने 10 लोगों की मौत हो गई।
- उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का जेल में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई।
- बस्सिरों दिओमाये फेम सेनेगल गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
- मेडागास्कर में चक्रवात गैमेन के कारण 14 लोगों की मौत हो गई।

31 मार्च

- चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डाक्टर एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया।
- ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
- भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजनाथ सिंह को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
- ईडी ने दिल्ली के आप पार्टी के विधायक और मंत्री कैलाश गहलोत से भी की पूछताछ।

1 अप्रैल

- राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा लालकृष्ण आडवानी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया।
- भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- बेटे अशोक कुमार को मिला हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीव मेंट अवॉर्ड।
- अमेरिकी राज्य कैलिफोर्नया में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई।

2 अप्रैल

- पाकिस्तान की अदालत ने तोशाटवीना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी।
- गाजा में इजरायली हमले में 3278782 लोगों की मौत की मौत हुई।
- भारतीय टेनिस स्टार सुमीत नागल ने हासिल की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग।
- टैक्स वसूली मामले में आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि –लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर नहीं होगी कार्रवाई।

3 अप्रैल

- शराब घोटाले में सालों से जेल में बंद आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।
- बस्तर के बीजापुर जिले में नक्सली और जवानों के बीच हुए मुठभेड़ में 11 नक्सली मारे गए।
- सुप्रसिद्ध योग गुरु और पतंजलि के प्रमुख बाबा रा रामदेव द्वारा भ्रामक विज्ञापन प्रचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी।
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसले में बीएड पास सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई।

4 अप्रैल

- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए।
- केरल में 11 राज्यों में पुरूषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक।
- ताइवान में आए शक्तिशाली भूकंप से नौ लोगों की मौत हो गई, हजारों हुए घायल।
- घाना में एक पादरी ने नाबालिग लड़की से रचाई शादी, देश भर में फैला आक्रोश।

5 अप्रैल

- छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में दो सीएसपी एक टीआई सहित 27 आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- सोनिया गांधी, अश्वनी वैष्णव सहित 14 सांसदों ने राज्य सभा सदस्य के रूप में शपथ ली।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं सामरिक कमान ने संयुक्त रूप से ओडीशा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के निकट बैलिस्टिर मिसाइल अग्नि प्राइस का सफल परीक्षण किया।
- जापान के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गिसाबुरो सोनोबे का टोक्यो के पास चिबा प्रांत में 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

काले धन के समतुल्य हैं इलेक्टोरल बॉण्ड

■ वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

चुनावी बॉण्ड असंवैधानिक करार कर उनसे राजनैतिक दलों को चुनाव फंडिंग न किये जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह संज्ञान में रहना चाहिये कि कम-से-कम मान्य चुनावी प्रक्रियाओं के संदर्भ में चुनावी बॉण्ड से मिला धन शुचिता वाला धन न होकर काले धन के समतुल्य ही था। दुखद यह रहा कि जब प्रजातांत्रिक चुनावों में काले धन का वर्चस्व हर बीतते चुनावों के साथ बढ़ता ही जा रहा था, चुनावी बॉण्ड की गुमनामी धनराशि भी उसी रूप में इसमें मददगार भी हो रही थी। जब ये ऐन चुनावों के पहले जारी होते थे, तब तो खासकर इनसे पाये करोड़ों रुपयों से राजनैतिक दलों को चुनाव लड़ने में आसानी होती थी। लगभग पांच साल देरी से आये इस निर्णय से पहले चुनावों में गैर-बराबरी जारी थी। इससे कई दलीय उम्मीदवारों की हार-जीत पर असर भी पड़ा होगा।

जब चुनावी फंडिंग की चुनावी बॉण्ड योजना आई थी, तो संसदीय परम्परा के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का विचार था कि राजनैतिक दल चुनावों में कालेधन का भारी उपयोग करते हैं। राजनैतिक दलों को इन बॉण्डों को देने वालों का नाम जाहिर करना बाध्यकारी नहीं है, अतः पारदर्शिता का अभाव तो रहेगा ही। जिनका गैर-कानूनी काम किया गया है वे भी तो नेताओं के कहने पर उनके दलों को बॉण्ड दे सकते हैं। फर्जी कम्पनियों के माध्यम से राजनैतिक बॉण्ड खरीदकर राजनैतिक आकाओं के दलों को उपकृत करने की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसा धन राजनैतिक इस्तेमाल के लिए शुचिता वाला धन कैसे हुआ?

> **जब चुनावी फंडिंग की चुनावी बॉण्ड योजना आई थी, तो संसदीय परम्परा के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का विचार था कि राजनैतिक दल चुनावों में कालेधन का भारी उपयोग करते हैं। राजनैतिक दलों को इन बॉण्डों को देने वालों का नाम जाहिर करना बाध्यकारी नहीं है, अतः पारदर्शिता का अभाव तो रहेगा ही। जिनका गैर-कानूनी काम किया गया है वे भी तो नेताओं के कहने पर उनके दलों को बॉण्ड दे सकते हैं।**

अक्टूबर 2023 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का बयान था कि इलेक्टोरल बॉण्ड के पहले जो कुछ पारदर्शिता थी वह भी खत्म हो गई। पहले राजनैतिक दलों को बीस हजार रुपये और उससे ज्यादा धन देने वालों की सूची चुनाव आयोग के पास होती थी। वह उनको सार्वजनिक भी करता था, परन्तु इलेक्टोरल बॉण्ड जारी होने के बाद यह अनिवार्यता और पारदर्शिता भी नहीं रही।

समाचारों में ही था कि नवम्बर 2023 में जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे वहां जब्त राशि पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले सात गुना ज्यादा थी। यदि सालों के अंतराल के बाद 31 अक्टूबर 2023 से चुनावी बॉण्ड की वैधता पर पुनः शुरू हुई सुनवाई पूरी होने के बाद भी उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय 2 नवम्बर 2023 को सुरक्षित न रखा होता तो शायद नवम्बर 2023 के विधानसभा चुनावों के पहले चुनावी बॉण्ड जारी भी न होते। स्टेट बैंक औफ इण्डिया की 29 शाखाओं से 29वीं बार 6 नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 के दौरान चुनावी बॉण्डों की बिक्री, खरीदारी हुई थी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जो 2 नवम्बर के काफी बाद हुए थे, कुछ राजनैतिक दलों को चुनावी बॉण्ड का फायदा मिल ही गया।

पहली बार चुनावी बॉण्ड मार्च 2018 में बिके थे। इसके बाद वे विभिन्न सालों में विभिन्न अवधियों में बिकते रहे। अप्रैल 2021 में भी गैर-सरकारी संस्था एडीआर (एसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तब कुछ राज्यों में होने वाले विधान सभा के चुनावों के पूरे होने तक इलेक्टोरल बॉण्ड की बिक्रियों पर रोक लगाने की मांग की थी, किन्तु बेंच ने उसे खारिज कर दिया। केन्द्र ने एक अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक बॉण्ड जारी भी किये थे। तब याचिकाकर्ता संस्था एडीआर का कहना था कि गैर-कानूनी और अवैध धन की मुखौटा कम्पनियों के माध्यम से फंडिंग की और ज्यादा होने की संभावनायें बढ़ जायेगी। दो नवम्बर 2023 को चुनावी बॉण्डों की वैधता पर अपने निर्णय को सुरक्षित रखने के पहले अदालत ने ये टिप्पणी भी की थी कि सरकार की यह दलील मानना मुश्किल है कि मतदाताओं को राजनैतिक चंदों का स्त्रोत जानने का अधिकार नहीं है।

भारत आये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन 12 दिसम्बर 2023 को बिना लाग-लपेट यह कह गये थे कि बॉण्ड चुनावी फंडिंग का नकदी से भी ज्यादा खराब विकल्प है। यह गैर-पारदर्शी है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ही जानता है कि चुनावी बॉण्ड से पैसे देने वाला कौन है। गुमनाम चुनावी बॉण्ड राजनैतिक दलों के बीच गैर-बराबरी के मैदान तैयार करता है। किसी काम के एवज में भी राजनैतिक दल चुनावी बॉण्ड से पैसे ले सकते हैं। सत्तारूढ़ दल तो चुनावी बॉण्ड से अकूत धन पाकर चुनावी खर्चे के चेक काट सकता है, किन्तु विपक्ष ऐसा नहीं कर सकता। चुनाव बराबरी में लड़ा जा सके इसके लिये विपक्ष को भारी नकदी का इंतजाम करना पड़ता है। काले धन पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हीं दिनों राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू से जुड़े ठिकानों में तीन सौ करोड़ रूपये की बरामदगी भी सुर्खियों में थी।

यह विडम्बना ही थी कि दो जनवरी 2018 को अधिसूचित जिस चुनावी बॉण्ड योजना को वैकल्पिक पारदर्शी राजनैतिक फंडिंग की पहल बताया गया था उससे भ्रष्टाचार पनपने व सत्तारूढ़ दलों को ही ज्यादा फायदा पहुंचने की शंकायें छः साल पूरे होते-होते काफी गहरा गईं। बॉण्डों से प्राप्त धन चुनाव आयोग द्वारा सत्यापित एक अलग एकाउण्ट में रखना होता था। नियमतः कार्पोरेट या निजी दानदाता विभिन्न मूल्यों के बॉण्डों को खरीदकर पात्र राजनैतिक दलों को दे सकते थे। बॉण्डों पर न देने वाले का नाम होना था, न दाता की पहचान बताई जानी थी। कम्पनी के अंशधारकों या जनता के संज्ञान में नहीं आ सकता था कि राजनैतिक दलों को कौन धन दे रहा है। मोदी सरकार ने कहा था इससे हालांकि राजनैतिक दलों को मिले चंदे का विवरण पता चल जायेगा, किन्तु देने वालों के नामों का पता नहीं चलेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी इसे धनशोधन या मनी-लॉण्डरिंग के समकक्ष ही माना था। बैंकों का भी ऐसा ही सोचना था। चुनाव आयोग की भी चाहत थी कि खरीदकर बॉण्ड देने वालों का नाम गुप्त रखा जाये।

भविष्य में जब स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अब तक बिके बॉण्ड के मूल्यों, उनके खरीदारों, उनके मूल्यों व उनसे जिन राजनीतिक दलों को जब-जब धन मिलने की सूचना चुनाव आयोग को दी जायेगी तो उसके सार्वजनिक होने के बाद खोजी जानकारी से ही मालूम चल सकेगा कि किन मामलों में चुनावी बॉण्डों से राजनैतिक दलों को धन दिये जाने में व्यवसायिक लाभ लिये व दिये जाने के कारण थे। परन्तु जिन मामलों में ऐसा हुआ होगा उनमें तो बाद में भी और काले धन बनने और उसकी एक श्रृंखला बनने की संभावना बन जाती है। साफ धन दिया जाना है तो सीधे चेक से पार्टी को दिया ही जा सकता था तो कई क्षेत्र के नियमों में बदलाव लाकर चुनावी बाण्ड जैसे नये गुमनामी वाले दस्तावेज बनाने की योजना पर संदेह के कारण तो थे ही।

(लेखक पैन्यूली स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

सेवाग्राम में साझे भविष्य की तलाश

नवाचार

■ बाबा मायाराम

हाल ही में गांधीजी की कर्मस्थली सेवाग्राम में अनूठे बीजोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें देश के कई कोनों से जैविक व प्राकृतिक खेती करने वाले कई किसान शामिल हुए। इस तीन दिनी कार्यक्रम में देशी बीजों की खेती, जलवायु बदलाव, बीजों के कानून और नई खेती पद्धतियों पर विचार-विमर्श हुआ। यह कार्यक्रम 29 से 31 मार्च तक आयोजित था।

सेवाग्राम यानी सेवा का गांव। यह महाराष्ट्र के वर्धा शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सेवाग्राम आश्रम में गांधीजी ने जीवन के उत्तरार्ध का एक दशक से ज्यादा समय बिताया था। गांधीजी के साथ यहां उनके कुछ सहयोगी भी रहे। यहां जो छोटे घर बनाए गए, उन्हें कुटी के नाम से जाना जाता है। जिनमें बापू कुटी व बा (कस्तूरबा गांधी) कुटी शामिल हैं। उस जमाने की ये कुटियां गांधीजी की सादगी व सरलता की बानगी देती हैं।

यहां मिट्टी के घर,लकड़ी और छतों पर खपरैल से बने हैं। प्राकृतिक खेती, नई तालीम का स्कूल, खादी व चरखा और सादा रसोईघर है। हरे-भरे पेड़-पौधे, रंग-बिरंगे फूल व लताओं से सजा परिसर है। सादगी व सुघड़ता यहां की पहचान है। यहां प्रकृति की अपनी संस्कृति है, लय है। गांधी इसी लय को समाज में उचित स्थान दिलाना चाहते थे।

बीजोत्सव भी गांधी की प्रेरणा की एक मिसाल है। यह खेती के गहरे संकट से जुड़ा है। इसकी शुरूआत करीब एक दशक पहले कपास के किसानों की खुदकुशी से चिंतित होकर की गई थी। उस समय अधिकांश किसान बैंक से कर्ज लेकर खेती करते हैं और कर्ज के बोझ तले दबकर ही जान दे रहे थे।

गांधीवादी सोच के कुछ लोगों व संस्थाओं ने मिलकर इसकी शुरूआत की थी, जिससे किसानों की मदद की जा सके। मैं इसमें दूसरी बार शामिल हुआ। बीजोत्सव में सुरक्षित व पौष्टिक खान-पान पर ज़ोर दिया जाता है। देशी बीजों की गोबर खाद व हल-बैल वाली प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें खेती को पशुपालन से जोड़ने की सोच है, जिससे मिट्टी को गोबर व केंचुआ खाद से उर्वर बनाया जाए और दूध-घी से भोजन में पौष्टिकता भी बढ़े। यह खेती रासायनिक खाद से मुक्त होती है।

> **हाल के दिनों में आई स्वास्थ्य जागरूकता के कारण जैविक उत्पादों की मांग बढ़ गई है, पर पूर्ति कम है। क्योंकि जैविक खेती कम होती है और जो जैविक किसान करते भी हैं तो उनके उत्पाद बेचने में कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ जगहों पर यह देखने में आया है कि जैविक किसानों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है।**

कोविड-19 के बाद से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक और प्राकृतिक तरीके से उत्पादित अनाज और सब्जियां जरूरी हैं। सभी जानते हैं कि रासायनिक खेती में उत्पादन के साथ बीमारियां भी बढ़ी हैं।

इसका एक उदाहरण जबलपुर से अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन है। इसमें अधिकांश सवारियां मरीज होती हैं, जो नागपुर इलाज कराने जाती हैं। इस कारण इस ट्रेन को ही लोग एम्बुलेंस कहने लगे हैं। इसी ट्रेन से मैं 30 मार्च को इटारसी से वर्धा पहुंचा था।

सतपुड़ा अंचल वही इलाका है जहां 70-80 के दशक में आधुनिक रासायनिक खेती शुरूआत हुई थी। सोयाबीन, गेहूं और धान की रासायनिक खेती का प्रचलन बढ़ा। यह पूरी खेती ट्रेक्टरों व हारवेस्टरों से होती है और रासायनिक खाद, कीटनाशक, नींदानाशक दवाईयों का भरपूर उपयोग होता है। लेकिन अब सोयाबीन की खेती इस इलाके में लगभग खत्म हो गई है पर गेहूं और धान की फसलें रासायनिक खेती से ही की जा रही है। इससे बीमारियां भी काफी बढ़ी हैं।

हाल के दिनों में आई स्वास्थ्य जागरूकता के कारण जैविक उत्पादों की मांग बढ़ गई है, पर पूर्ति कम है। क्योंकि जैविक खेती कम होती है और जो जैविक किसान करते भी हैं तो उनके उत्पाद बेचने में कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ जगहों पर यह देखने में आया है कि जैविक किसानों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है।

कई बार किसानों के पास सही जानकारियों का अभाव रहता है और कई बार उन्हें समय पर अच्छे बीज नहीं मिल पाते। बीजोत्सव का आयोजन इन्हीं उद्देश्यों को लेकर किया जाता है, जिससे किसानों को उचित जानकारी, एक दूसरे से सीखना, नई तकनीक, वैज्ञानिक जानकारी और परंपरागत बीजों का आदान-प्रदान किया जा सके।

इसके अलावा, खेती में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की महिलाएं कई कारणों से ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पातीं। इसलिए उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले, इसका प्रयास किया जाता है।

इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं ने उनके जैविक उत्पादों के स्टॉल भी लगाए थे। मैंने उनकी आंखों में जैविक उत्पाद बेचते हुए आत्मविश्वास की चमक देखी, यह आत्मनिर्भरता का भी अच्छा उदाहरण है।

इस कार्यक्रम में मिट्टी की उर्वरता बचाने पर ज़ोर दिया गया। फसलों के ठंडल व अवशेष न जलाएं जाएं बल्कि उनसे जैव खाद बनाई जाए। खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाएं जाएं, जिससे खेतों में नमी बने रहे, उनकी पत्तियों से जैव खाद भी बने। जलवायु बदलाव के दौर में पेड़ लगाना और भी जरूरी हो गया है।

यह एक ऐसा मौका होता है जब किसान और उपभोक्ताओं का आपस में जुड़ते हैं। जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम मिले और उपभोक्ताओं को भी वाजिब दाम में पौष्टिक अनाज मिल सके। यहां वे साझा भविष्य तलाशते हैं। जलवायु बदलाव बहुत ही गंभीर मुद्दा है। धरती की सभी प्रजातियां खतरे में हैं। इसलिए पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली बहुत जरूरी है। इसके लिए मिल-जुलकर काम करना जरूरी है।

खेती का संकट जलवायु बदलाव से भी जुड़ा हुआ है। पर्यावरण के संकट से जुड़ा है। कुछ समय पहले तक देशी बीजों की खेती ऋतु के अनुसार होती थी। अब मौसम बदलाव में बारिश अनिश्चित हो गई है। कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी सूखा तो कभी अकाल, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। इसका सीधा असर परंपरागत खेती करने वाले और भूमिहीन किसानों पर पड़ता है।

मौसम बदलाव का यह संकट आधुनिक रासायनिक खेती का भी संकट है। भूजल नीचे चला जा रहा है, रासायनिक व कीटनाशक खेती के कारण मिट्टी की उर्वर शक्ति कम हो रही है। मिट्टी-पानी जहरीला हो रहा है। बिजली का संकट है। भारी पूंजी से होने वाली मशीनीकृत खेती से लागत बढ़ रही है। किसानों पर कर्ज बढ़ रहा है। मशीनों से काम से बेरोजगारी बढ़ रही है। पलायन हो रहा है। बाजार में फसलों के उचित दाम जैसी कई समस्याएं हैं।

विशेषज्ञों द्वारा पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए दो समाधान बताए जा रहे हैं। एक है कि कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए और दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक अपनाने पर जोर दिया जाए। यह बहुत अच्छा है लेकिन तकनीकी उपायों से ही पर्यावरण का संकट हल नहीं होगा।

इसके लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी है। हमें यह तय करना होगा कि क्या हमें तामझाम व विलासिता वाली जीवनशैली चाहिए, जो ज्यादा ऊर्जा गटकती है या फिर समता व सादगी के सिद्धांत अपनाना चाहिए, जो गांधी की सोच का मूल है।

गांधी जी ने आजादी के संघर्ष के साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाए। जैसे शराबबंदी, चरखा और साफ-सफाई, लघु कुटीर उद्योग, छुआछूत मिटाना, प्राकृतिक चिकित्सा और शिक्षा को उत्पादक काम से जोड़ने वाली नई तालीम। आज भी इनमें से कुछ कार्यक्रम आश्रम में जारी हैं। जैसे नई तालीम का स्कूल, एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें बच्चे जीवनशिक्षा सीखते हैं। यानी हाथ से उत्पादक काम करके शिक्षा हासिल करते हैं।

गांधी जी ने स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांवों का सपना देखा था। आज भी ऐसे कामों की बहुत जरूरत है जिससे गांव स्वावलंबी बने। उनका प्रसिद्ध कथन था कि- 'पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरा करने का सामर्थ्य रखती है, पर उसके लालच का नहीं।' गांधी जी यह कथन आधुनिक विकास की सीमा बताता है। प्रकृति से सामंजस्य बनाकर चलने की सीख देता है।

कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि बीजोत्सव जैसे कार्यक्रम हमें नई जैविक, प्राकृतिक खेती का मार्ग तो दिखाते ही हैं, जिस पर चलकर मिट्टी-पानी का संरक्षण किया जा सके, जैव विविधता व पर्यावरण रक्षा की जा सके। नई तकनीकों की जानकारी भी देते हैं। किसान- उपभोक्ताओं में आपस में मेल-मिलाप कराते हैं, जिससे किसानों को फसलों को उचित दाम मिले और उपभोक्ताओं को भी वाजिब दाम में अच्छा अनाज मिल सके।

इसके साथ ही खेती को स्वावलंबी, कुदरती, विविधतापूर्ण, रसायनमुक्त, कम ऊर्जा वाली, कम पूंजी वाली, एक कम जोखिम वाली बनाया जाए। जैविक व प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाया जाए। साथ ही फिजूलखर्जी, शान-शौकत, तामझाम को बढ़ावा देने वाली भोगवादी संस्कृति पर भी लगाम लगाई जाए, तभी हम खेती, पर्यावरण के संरक्षण के साथ बेहतर जीवन भी जी पाएंगे। जलवायु बदलाव का भी मुकाबला कर पाएंगे।

दैनिक
जलते दीप

जोधपुर, शनिवार 6 अप्रैल 2024

बदजुबान होते नेता

मुद्दों के आधार पर तर्कों के जरिए अपने प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हुए भाषा में तल्खी का इस्तेमाल अनुचित नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करते हुए बदजुबानी या अभद्रता हावी होने लगे तो यह हर लिहाज से गलत है। अफसोसनाक यह है कि इस मसले पर अक्सर विवाद उभरने और ज्यादातर मामलों में माफी मांगने या सफाई देने की नौबत आने के बावजूद राजनीतिक शख्सियतों के बीच आरोप-प्रत्यारोप अक्सर बेलगाम बोल में तब्दील हो जाते हैं। न तो निजी स्तर पर अपनी सोच-समझ का ध्यान रखा जाता है, न ही चुनावों के संदर्भ में लागू आचार संहिता का। इससे एक ओर स्वस्थ बहस की स्थितियां बाधित होती हैं, वहीं कई बार ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि बाद में किसी मौके पर एक दूसरे का सामना करने में भी असहज होना पड़े। अपनी बात कहने के क्रम में नाहक ही किसी शब्द का इस्तेमाल करने से उभरे विवाद के बाद किसी नेता की ओर से सफाई के तौर पर भले यह कहा जाता है कि उनकी बातों को आधे-अधूरे संदर्भ में या फिर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, मगर सवाल है कि बिना किसी जरूरत के किसी को लक्षित करके वैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, जिसके लिए सफाई देना या माफी मांगना पड़े। विडंबना यह है कि ऐसे असुविधाजनक हालात और उनके हश्र बार-बार सामने आने के बावजूद कुछ नेताओं को न तो अपने प्रतिद्वंद्वियों की और न अपनी गरिमा का खयाल रखना जरूरी लगता है। फिलहाल आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस क्रम में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने भाषण में जिस तरह भाजपा की एक महिला नेता की गरिमा का हनन करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, वह सिर्फ एक उदाहरण है कि कई वरिष्ठ नेता भी अपनी जुबान पर काबू रखना जरूरी नहीं समझते। जब अवांछित शब्दों से विवाद खड़ा हो गया और मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तब सफाई के तौर पर सुरजेवाला ने कहा कि उनकी बातों को आधे-अधूरे तरीके से पेश किया गया। मगर सभी जानते हैं कि गैरजरूरी तरीके से कुछ बोल जाने के बाद इस तरह की सफाई का कोई मतलब नहीं होता। यह अकारण नहीं है कि इस मसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। यह अकेला मामला नहीं है जिसमें किसी नेता ने अमर्यादित टिप्पणी की हो। अक्सर राष्ट्रीय पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बोल भी बहक जाते हैं और किसी की गरिमा को चोट पहुंचा जाते हैं। अफसोसनाक यह भी है कि इस तरह बोलते हुए इसका खयाल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि किसी महिला को लक्ष्य बना कर अभद्र या मजाक उड़ाने की भाषा का प्रयोग करने का क्या असर पड़ता है। इस तरह की बदजुबानी से न केवल किसी अन्य नेता के सम्मान को चोट पहुंचती है, बल्कि ऐसी बातें बोलने वाले के व्यक्तित्व में छिपी कुंठा भी सामने आती है। सवाल है कि भाषणों में बदजुबानी या गलत तरीके से कुछ बोलने के जरिए चुनाव में जीत की कोशिश करने वाले नेता क्या अपना सम्मान इसी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं! आमतौर पर चुनाव आयोग भी ऐसा करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर कोई ठोस संदेश नहीं देता। लोकतंत्र में सहमति-असहमति एक जरूरी प्रक्रिया है। मगर इस क्रम में कोई भी नेता अगर किसी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट शब्द या लहजे का प्रयोग करता है, तो यह राजनीति में गिरावट का ही संकेत है।

भूकंप से बचाव का ताईवानी सिस्टम

बीते बुधवार को ताइवान ने पिछले पच्चीस साल में आए सबसे तेज भूकंप का सामना किया। निश्चित रूप से भूकंप से हमारे संरचनात्मक विकास सड़क, पुल व सार्वजनिक निर्माण को क्षति पहुंचती है। लेकिन ताइवान ने पिछले भूकंपों से हुई मानवीय त्रासदी से सबक लेकर जिस तरह जनधन की हानि को कम किया है, वह काबिले तारीफ है। इस भूकंप में गिनती के लोगों को जान गंवानी पड़ी। बड़ी बिल्डिंगें हिली मगर क्षति मामूली हुई। दरअसल, ताइवान ने आधुनिक तकनीक व कुशल अग्रिम सूचना की व्यवस्था से आपदा से होने वाली क्षति को टाला है। भूकंप के केंद्र उत्तरी तट पर स्थित ख्वालिएन में 7.4 तीव्रता के भूकंप से क्षति स्वाभाविक थी, लेकिन सुनियोजित राहत व बचाव से जनक्षति को कम किया जा सका। सुरंगों व इमारतों में फंसे लोगों को बचाने का काम तत्परता से किया जा रहा है। जहां तक इस पहाड़ी इलाके में भूस्खलन का सवाल है तो मानव उसे टाल नहीं सकता। भूकंप से बचाव के ताइवानी सिस्टम बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जापान आदि पड़ोसी देशों ने भूकंप के बाद सुनामी की अग्रिम सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी। दरअसल भूकंप से होने वाली क्षति इस बात पर निर्भर करती है वह किस समय आया। भूकंप सुबह आया, यदि यह देर रात या तड़के आता तो क्षति ज्यादा हो सकती थी। यद्यपि ताइवान में भी सड़क व रेल परिवहन प्रभावित जरूर हुआ है। दरअसल, सितंबर 1999 में ताइवान में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप में करीब ढाई हजार लोगों की मौत हुई थी और करीब पांच हजार इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थीं। जिसके बाद वहां भवन व सार्वजनिक निर्माण में सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लिया गया। इन मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया गया और सख्ती से उसकी निगरानी की गई। सरकारों की सजगता व नागरिकों की जागरूकता ने इस संकट का मुकाबला करना सीख लिया। वहीं हमारे सामने जापान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो इतने बड़े भूकंपों के बाद नुकसान कम करने में सफल रहा। दरअसल, मनुष्य को भूकंप से ज्यादा हमारे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की कमी और नियमों की अनदेखी मारती है। भारत में भूकंप से बचाव के लिये पर्याप्त अनुसंधान हुए और सुरक्षित घरों के लिये कोड बने हैं। लेकिन संकट उनके ईमानदारी से क्रियान्वयन तथा आर्थिक संसाधनों के अभाव का है। घर खरीदने वाले लोगों को उलटे उस्तरे से मूंडने वाले बिल्डर इन मानकों का इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं क्योंकि इसे लागू करने से उनका मुनाफा कम हो जाता है। गरीब व्यक्ति जैसे-तैसे मकान तो बना लेता है लेकिन भूकंप के मानकों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। सरकारी गंभीरता भी नजर नहीं आती। सरकारों की प्राथमिकता आपदा के बाद राहत सामग्री व मुआवजा बांटने में होती है। समय रहते भवन निर्माण में भूकंप से बचाव के कोड लागू करवाने में संबंधित विभाग लगातार आपराधिक लापरवाही दर्शाते रहते हैं। हमें जापान से सबक लेना चाहिए जिसने भूकंप के साथ जीना सीख लिया है। वर्ष 2011 में भयावह नौ तीव्रता के भूकंप से जो तबाही हुई और उसके बाद सुनामी ने कहर बरपाया, उसके बाद जापान सरकार ने जनक्षति टालने के लिये गंभीर पहल की। इशिकावा की तबाही व फुकुशिमा की पॉवर प्लांट दुर्घटना के सबकों को जापान ने गंभीरता से लिया। आज भूकंप के अलार्म की चेतावानियां जापानियों के लिये आम बात है। हम मान लें कि बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है तो क्या हमारी इमारतें इसके लिये सुरक्षित हैं? जापान ने 2011 की त्रासदी के बाद भूकंपरोधी निर्माण में कोई चूक नहीं की। वैसे तो वहां 1981 के बाद भवन निर्माण में सुरक्षा मानकों को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन बाद के अनुभवों के साथ इन मानकों में लगातार सुधार भी किया गया। यही वजह थी कि इशिकावा के तेज भूकंप के बाद अधिकांश इमारतें सुरक्षित रहीं। जापान ने याद रखा कि कांतो भूकंप के बाद इस शहर का बड़ा हिस्सा समतल हो गया था। जिसके बाद पहले भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग कोड बनाया गया। फिर भवन निर्माण में स्टील व कंक्रीट का प्रयोग अनिवार्य हो गया। हर नये भूकंप के बाद नियम बदले जाते हैं।

प्रसंगतः **जीवन रूपी जागीर**

तर्कशास्त्र के महान पंडित रामनाथ नवद्वीप के वन में एक गुरुकुल चलाते थे। उस समय कृष्णनगर में महाराज शिव चंद्र का शासन था। उन्होंने जब पं. रामनाथ की कीर्ति सुनी, तो उनसे मिलने गए। पंडित जी अपनी छोटी सी झोपड़ी में शांत भाव से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। महाराज को देख पं. रामनाथ जी ने उनका उचित स्वागत-सत्कार किया। कुशल-क्षेम पूछने के उपरांत कृष्णनगर नरेश ने उनसे पूछा, पंडित प्रवर, मैं आपकी क्या मदद करूं? रामनाथ जी ने कहा, राजन, भगवत्कृपा ने मेरे सारे अभाव मिटा दिए हैं, मैं संतुष्ट हूं। राजा शिवचंद्र कहने लगे, विद्वत् वर, मैं घर के खर्च के बारे में पूछ रहा हूं। रामनाथ जी मुस्कराए। फिर शिवचंद्र की मनःस्थिति को भांपकर कहा, घर के खर्चों के बारे में तो गृहस्वामिनी ही अधिक जानती हैं। उन्हीं से पूछ लें। महाराज पंडित जी के घर गए और उनकी पत्नी से पूछा, माताजी घर खर्च के लिए कोई कमी तो नहीं है? इस पर उन परम साध्वी ने कहा, महाराज, भला सर्व समर्थ परमेश्वर के रहते उनके भक्तों को क्या कमी रह सकती है? फिर भी माताजी? महाराज, कोई कमी नहीं है। पहनने को कपड़े हैं, सोने के लिए बिछौना है। पानी रखने के लिए मिट्टी का घड़ा है। खाने के लिए विद्यार्थी ले आते हैं। झोपड़ी के बाहर जमीन में साग-भाजी हो जाती है। और भला क्या जरूरत होगी? गुरुपत्नी बोलीं। शिवचंद्र ने कहा, फिर भी हम आपको कुछ गांवों की जागीर देना चाहते हैं। इसकी आय से गुरुकुल भी ठीक तरह से चल सकेगा और आपके जीवन में भी कोई अभाव नहीं रहेगा। उत्तर में वह वृद्धा मुस्कराईं और कहने लगीं, राजन, प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने जीवन रूपी जागीर पहले से ही दे रखी है। जो जीवन की इस जागीर को भली प्रकार संभालना सीख जाता है, उसे फिर किसी चीज का कोई अभाव नहीं रह जाता। नरेश का मस्तक श्रद्धा से झुक गया।

भाजपा स्थापना दिवस विशेष

भाजपा ने राजनीति को सेवा करने का सर्वोत्तम माध्यम बनाया

- डॉ. आशीष वशिष्ठ

देश के राजनीतिक इतिहास में छह अप्रैल का दिन खास अहमियत रखता है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने आज ही के दिन, 1980 में यानी 44 साल पहले, पार्टी की स्थापना के समय ये शब्द कहे थे। शायद उन्होंने यह बात पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही होगी लेकिन उस समय पार्टी कार्यकर्ताओं या फिर विपक्षी दलों में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले दिनों में अटल जी की बातें सही साबित होंगी। 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल दो सीटें हासिल करने से लेकर 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा ने अपने इस शानदार सफर में कई उतार-चढ़ाव भी देखे, बड़े झटके भी खाए और मायूसी भी महसूस की।

धरातल पर बदलाव लाने के लिए राजनीति सबसे सशक्त माध्यम है। राजनीति के माध्यम से हम समाज के दबे-कुचले लोगों और उपेक्षित समुदायों को ऊपर उठाते हुए सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। एक व्यापक बदलाव लाने का जो कार्य, बड़े से बड़े वेतन वाली प्रतिष्ठित नौकरी करके भी नहीं किया जा सकता है, उसे राजनीति के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर चलते हुए भाजपा ने आरंभ से ही राजनीति को सत्ता की बजाय सेवा का माध्यम माना है।

आजादी के बाद के लंबे कालखंड तक भारतीय राजनीति में परिवार और व्यक्ति केंद्रित दलों ने राजनीति को कमाई का जरिया बनाया और सेवा भाव को नदी के जलधारा में प्रवाहित कर दिया। बीच-बीच में केंद्र की सत्ता पर आसीन गैरकांग्रेसी सरकारों ने लोक कल्याण के लिए कुछ करने की सोची तो उन्हें अस्थिर कर दिया गया। 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार का गठन हुआ, तब से तस्वीर में बदलाव आया है। पिछले दस वर्षों में आम आदमी को इस बात का आभास हुआ है कि राजनीतिज्ञ अगर सेवा करने के भाव से राजनीति करें तो कितना बड़ा और व्यापक बदलाव देश और आम आदमी की जिंदगी में लाया जा सकता है। भाजपा की रीति-नीति और संकल्पों की डगर पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया कि राजनीति सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। परिवारवादी दल जो अपने परिवारजनों के विकास और उत्थान में सारी ऊर्जा खपाते हैं, वह राजनीति को सेवा का नहीं, बल्कि मेवा का माध्यम मानते हैं। उनकी डिक्शनरी में परिवार पहले और देश बाद में आता है।

तीन मार्च, 2024 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में इंडी अलांयस की रैली में बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा था कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो पत्नी के साथ नहीं रहते। कैसे जानेंगे कि परिवार क्या होता है? लालू प्रसाद की आपत्तिजनक टिप्पणी के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विपक्ष की ओर से उनके परिवार को लेकर किए गए हमले का परोक्ष रूप से जवाब दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। जिनका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है।' जो दल एक परिवार या व्यक्ति द्वारा द्वारा संचालित हो रहे हैं, उनके लिए परिवार ही सर्वोपरि है। उनकी सारी ऊर्जा परिवार के विकास और कल्याण में ही खर्च होती है। उनके एजेंडे में आम आदमी का विकास और कल्याण अंतिम पायदान पर होता है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की विचारधारा ने भारतीय राजनीति की इसी विचारधारा को पलटने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अन्य नेता कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। विपक्ष के लिए तो फैमिली फर्स्ट इसे सारा देश अब अनुभव करने लगा है।

श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन को राजनीति और कूटनीति के माध्यम से राज्य, धर्म एवं समाज की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। धर्म के विपरीत आचरण करने वालों और सत्ता, सुख-संपदा, धन-वैभव एवं ऐश्वर्य के लिए जीने वालों को उन्होंने समस्त संसार के लिए विनाशकारी बताया है। इसलिए हमारी राजनीति के विमर्श में लोकमंगल की भावना होना बहुत आवश्यक है। राजनीति को सत्ता पाने का अवसर मानने वाली अनैतिकता ही अस्वस्थ राजनीतिक परंपरा को पोषित करती रहती है। यदि राजनीति की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए और नैतिकता, मूल्यों एवं आदर्श का समावेश करते हुए सेवाभाव से कार्य किया जाए तो एक स्वस्थ, सक्षम एवं सजग समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।

भाजपा के चाहे दो सांसद रहे हों या 303 भाजपा ने राजनीति को हमेशा सेवा का माध्यम माना। और ये बात उसके चरित्र और आचरण से झलकती भी है। राजनीति का चरित्र-चित्रण, उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। सही राजनीतिक नेतृत्व किसी भी संस्था या अभियान को जन-जन के बीच पहुंचा सकता है और उसे जनभागीदारी का प्रतीक बना सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना के समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्तमान भारत सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों एवं असहायों की सहायता के लिए राजनीतिक दूरदृष्टि के साथ शासन एवं प्रशासन का कार्य किया है, वह संस्थाओं के नेतृत्व का श्रेष्ठ उदाहरण है। कोरोना के समय विपक्ष ने नकारात्मक भूमिका निभाई। देश में बनी वैक्सीन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं का उपहास उड़ाया। देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया।

इसमें कोई दोराय नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत जैसे देश में कोरोना के संकट से निपटते हुए गरीबों, मजदूरों, किसानों, शोषितों और वंचितों के हितों की रक्षा करने से लेकर देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने तक का कार्य, किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन संकट के ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने देश के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ जोड़ने का समेकित प्रयास करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने और जन-कल्याण करने के लिए सरकार की भावी प्राथमिकताओं और योजनाओं को धरातल पर उतारा है।

राजनीति का मूल उद्देश्य जनता के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है। यदि राजनीति का पूरी तरह से सही और सकारात्मक दिशा में प्रयोग की जाए तो विकास के नए शिखर छुए जा सकते हैं, मानवता की सेवा की जा सकती है और देश को निरंतर आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी साफ-सफाई जैसे छोटे से बिंदु से लेकर गरीबों को आवास की सुविधा के बारे में एक साथ सोचते हैं। उनकी सोच के दायरे में किसान, महिलाएं, युवा, दलित, आदिवासी, वंचित और देश का एक-एक नागरिक है। प्रधानमंत्री मोदी में सेवा के गुण पार्टी की रीति-नीति और विचारों की वजह से प्रभावी हैं, क्योंकि भाजपा के संस्थापकों ने सेवा भाव से ही राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाया और अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी सेवाभाव को कूट-कूट कर भरने का काम किया।

कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। प्रधानमंत्री ने देश की और देशवासियों की सेवा करने में दिन-रात एक किया। आज आदमी अपना भला-बुरा सब बहुत अच्छे से समझता है। उसे पता है कि कौन राजनीति को सेवा का माध्यम मानता है, और कौन सत्ता हासिल करके अपना पेट भरना चाहता है। इसलिए देशवासी विपक्ष के दुष्प्रचार, प्रलोभन और मायाजाल में नहीं फंसे। वर्तमान में देश में आम चुनाव का माहौल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है। देश की जनता भलीभांति यह समझ चुकी है कि उसका कल्याण और उत्थान वही व्यक्ति कर सकता है जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझता है। जो बिना किसी भेदभाव और पूर्वाग्रह के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा में जुटा रहता है।

वर्ष 2023 में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही पार्टियां हमारे खिलाफ साजिश करती रहेंगी। लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी कमल की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा भारत के लिए दिन-रात काम कर रही है, और हमारी पार्टी मां भारती, संविधान और राष्ट्र को समर्पित है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे दल भी भाजपा से इस सेवाभाव को ग्रहण कर राष्ट्र और राष्ट्र वासियों के कल्याण और उत्थान के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

नमक सत्याग्रह की चिंगारी राजस्थान से उठी

- गुलाब बत्रा

बापू की हथेली में मुटठी भर नमक ने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। गुजरात में अरब सागर के तटीय गांव दांडी में आज से 94 बरस पहले 6 अप्रैल 1930 का यह परिदृश्य भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च को नमक सत्याग्रह से जुड़ी प्रसिद्ध दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरम्भ हुई। लेकिन नमक सत्याग्रह की यह चिंगारी 1926 में पश्चिमी राजस्थान के पचपदरा से फूटी थी। इसकी दिलचस्प कहानी है।

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा के रूप में दांडी यात्रा अहम पड़ाव था। यह मार्च 1882 के नमक अधिनियम के प्रतिरोध में समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति के उल्लंघन का प्रतीक बना। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 स्वयंसेवक रोजाना औसतन 16 से 19 किमी पदयात्रा करते हुए करीब 386 किमी की दूरी 24 दिन में तय करके नवसारी के दांडी पहुंचे। अगले दिन 6 अप्रैल को प्रातःकाल दांडी के समुद्र तट पर बापू ने नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। ब्रिटिश कानून के तहत उन्हे हिरासत में ले लिया। एक शीशी में बंद नमक की यह देली बाद में संग्रहालय में रखी गई।

सत्याग्रह एवं नमक और इसके अर्न्तसम्बन्धों का महात्मा गांधी की आत्मकथा में रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। बापू के लिए सत्याग्रह आत्मशुद्धि के रूप में था। सत्याग्रह शब्द को गुजराती में लोग पेसिव रेजिस्टेन्स% के अंग्रेजी नाम से पहचानने लगे। लेकिन गोरो की सभा में इसे संकुचित अर्थ में कमजोरों का हथियार मानने पर बापू ने विरोध किया। तब बापू ने समाचार पत्र इण्डियन ओपिनियन के पाठकों से सत्याग्रह शब्द के लिये प्रतियोगिता करवायी। एक पाठक मगनलाल ने सत+ आग्रह की संधि करके सदाग्रह शब्द बनाकर भेजा। इस शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए बापू ने य अक्षर बढ़ाकर सत्याग्रह शब्द बनाया। गुजराती में यह लड़ाई इस नाम से पहचानी जाने लगी। सत्याग्रह के साथ नमक के घालमेल की कहानी 1908 में बापू की पहली जेल यात्रा से जुड़ गई। जेल के डाक्टर से हिन्दुस्तानी बंदियो के लिए करी पाउडर मांगा और नमक बनती हुई रसोई में डालने की बात को अनसुना कर दिया। बापू ने पुस्तकों में पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है। घर पर कस्तूर बां से दाल नमक के परहेज के प्रसंग पर बापू ने एक साल तक नमक नहीं खाने के संकल्प को सत्याग्रह का नाम दिया।

राजस्थान से नमक सत्याग्रह के सूत्रपात का प्रसंग लगभग 550 वर्ष पुराना है। घोड़े पर सवार मेवाड़ रियासत के झांझा नमक अधिकारी को पचपदरा के पास बरसाती पानी से भरे गड्ढ़ो में चमकते हुए रवेदार कण दिखाई दिए। जिज्ञासावश उसने पानी में हाथ डाला और चखा तो वह खारा लगा। सूखने पर हाथ में रवेदार कण चिपक गये। पांचा जाट की ढाणी में रात्रि विश्राम मे झांझा को सपने में पेड़ के पास जमीन में दबी देवियो की दो प्राचीन मूर्तियों को मन्दिर में प्रतिष्ठित करने की बात कही। खुदाई में सांभरा एवं आसापुरा नामक देवियों की प्रतिमा मिली। बाद में पचपदरा साल्ट मे देवल बनाया गया। फिर तो झांझा और पांचा के कुटुम्बजन नामक उत्पादन की सफेद चांदी के काम धंधे में जुट गए। वही रियासतों ने राजस्व के लिए नमक उत्पादन के पट्टे देने की शुरूआत की।

यूरोप में औद्योगिक क्रांति के दौर में भारत से कच्चे माल के रूप में कई, जूट तिलहन, लाख, रबड, ऊन, कच्चा खनिज इत्यादि समुद्री मार्ग से इंग्लैण्ड भेजा जाता था। वापसी में तैयार माल कम जगह घेरता और भार संतुलन के लिए जहाज मे भारी पाथर रखे जाते। इस परेशानी से बचने के लिए समुदी नगक भारत में खपाने के विचार से नमक उत्पादन वितरण पर एकाधिकार कायम करने की रणनीति बनी। प्रथम चरण में राजस्थान के विभिन्न इलाकों में नमक उत्पादन के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने देशी रियासतों के साथ नमक संधियों का जाल बिछाते हुए 1857 की क्रांति के 25 वर्षों पश्चात् 1882 में नमक कानून बनाया। नमक को सेन्ट्रल एक्साइज के अन्तर्गत लेने से नमक उत्पादन एवं वितरण सरकार के अधिकार में आ गया। इससे हुकूमत को मनमानी की छूट मिल गई। मारवाड़ में नमक से जुड़ी तीन सथियो में कुचामन, नांवा गुढ़ा फिर 1869-70 मे जयपुर-जोधपुर के शामिलाती हिस्से में सांभर झील तथा सबसे अंत में 1879 में तीसरी संधि पचपदरा डीडवाना, फलोदी, लूणी नमक क्षेत्र के लिए की गई। इन संधियों की आड़ में मारवाड़ में करीब 89 स्थानों पर नमक उत्पादन बंद किया गया।

बाडमेर जिले के पचपदरा में नमक उत्पादन का विशिष्ट तरीका है। अन्य स्थानों पर भूमिगत नमक स्त्रोतों पर अधिकांशतः झीले है जिसके लवणीय पानी को क्यारियों में सूखाकर नमक बनाया जाता था। सांभर झील डीडवाना, फलौदी तथा गुजरात के

खारागोडा में ऐसी झीले थी। लेकिन पचपदरा में पूर्व से पश्चिम दिशा में 100 से 500 फिट लम्बाई तथा 40 से 100 फिट तक चौडाई में खाने खोदकर नमक निकाला जाता था। इन खानों में पानी का बहाव उत्तर से दक्षिण दिशा में था और पाच से छः फिट गहराई पर पानी भर जाता था। इस पानी का घनत्व 13 से 14 डिग्री था जो समुद्री पानी के शुरूआत में तीन डिग्री होता है। पचपदरा के गांडे पानी से बढ़ी डली का नमक मौराली नामक कटीली झाड़ी की मदद से बनता है जो अपेक्षाकृत महंगा होता था। बनजारे इस नमक को बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि राज्यो में बेचने जाते थे। ज्ञात स्त्रीतो से पचपदरा में 1879 से नमक उत्पादन की जानकारी मिलती है।

ब्रिटिश हुकूमत ने प्रथम युद्ध के पश्चात् मंदी के दौर में 1926 में पचपदरा के नमक उद्योग से नुकसान का बहाना बनाकर नमक उत्पादन बन्द करने के आदेश दिये। इससे नमक उत्पादक खारवाल मजदूर तथा अन्य वर्गों के करीब बीस हजार लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। इसके खिलाफ पचपदरा के नमक व्यवसायी गुलाबचंद सालेचा ने आवाज बुलंद की। उन्होंने जोधपुर रियासत के दीवान से मिलकर महकमा खास की लाईब्रेरी में उपलब्ध पुरानी नमक संधियों की धाराओं तथा नमक विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर वकील जालमंवद की मदद से प्रतिवेदन तैयार कराया। पचपदरा नमक के उपभोक्ताओं से हस्ताक्षर अभियान चलवाया। वही जोधपुर रेलवे के अधिकारियों से मिलकर नमक लदान की रियायती दर की मंजूरी ली। सरकारी पक्ष द्वारा पचपदरा नमक की मांग नहीं होने के दावे को झुठलाने के लिए गुलाबचन्द सालेचा ने कराची बंदरगाह से नमक का लदान कलकत्ता के लिए कराया। वहां उन्होने कैपिटल पायोनियर अमृत बाजार पत्रिका इस्टर्न इकोनोमिस्ट इत्यादि समाचार पत्रो में लेख एवं सम्पादकीय लिखवाये। इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री से इस मामले को उठवाया। वर्ष 1926 में दिल्ली की लेजिस्लेटिव एसेम्बली की कार्यवाही इस बात का प्रमाण है कि धार मरूस्थल के एक कोने से अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज दिल्ली के दरबार में गूंज चुकी थी। उधर सरकारी नमक कम्पनियों ने गुलाब चन्द सालेचा का मनोबल तोड़ने के लिए कलकत्ता के बाजार में नमक के दाम घटाये जिसके कारण वह आर्थिक नुकसान उठाकर पचपद्रका का गुणवत्तापूर्ण नमक बेचने को मजबूर हुए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और सरकारी की नमक नीति के विरोध को तेज किया। देशव्यापी विरोध देखते हुए सरकार ने टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी बिठाई। इसके सम्मुख सालेचा ने नमक पर एक्साईज डयूटी के दुष्प्रभावो की जानकारी दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में टेरिफ बोर्ड ऑन साल्ट इण्डस्ट्री गठन का सुझाव दिया। वही नमक उत्पादक खारवालों ने अपनी मांगो के समर्थन में 1926 में हड़ताल की। टेरिफ बोर्ड के पश्चात् गठित साल्ट सर्वे कमेटी मे हड़ताल का आरोप गुलाबचन्द सालेचा पर लगाया गया। साल्ट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् भी जब सरकारी नीति के खिलाफ आवाज नहीं दबी तो अंग्रेज अधिकारी स्टेथी का एक सदस्यीय आयोग बनाया गया। आयोग के समक्ष सालेचा ने यह तथ्य रखा कि यदि पचपदरा में नमक उत्पादन बंद किया गया तो नमक संधि की एक धारा के तहत सरकार को लगभग एक करोड़ रूपये का हर्जाना भरना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में सरकार को हिदायत दी गयी कि वह नमक उत्पादन चालू रखे। यदि सरकार इस नमक स्त्रोत को बंद करना चाहती है तो वह ऐसी नीति अपनाये जिससे नमक स्त्रोत अपनी स्वाभाविक मौत मर जाये तथा ब्रिटिश सरकार भारी हर्जाने से बच सके। इस रिपोर्ट ने अंग्रेज नीति का भांडाफोड़ करते हुए सालेचा के चार साल लम्बे संघर्ष को विजय में परिवर्तित करने के साथ पचपदरा के नमक उद्योग का संकट टल गया। इस प्रकार नमक उद्योग के लिए सरकार की बदनियति के खिलाफ गांधीजी के नमक सत्याग्रह के रूप में पृष्ठभूमि तैयार हो गई जिस पर अगले वर्ष दांडी मार्च का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(लेखक राज्य के वरिष्ठ पत्रकार है।)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

लोकतंत्र को कमजोर करती है अवसरवादी राजनीति

-ललित गर्ग

कांग्रेस में लगातार वफादार नेताओं का पलायन जारी है, नये नामों में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, महाराष्ट्र के जिम्मेदार एवं पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, निशाना साधने वाले मुक्केबाज विजेंदर, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बाय-बाय कर दी है। इन सभी ने कांग्रेस के मुद्दाविहीन होने, मोदी के विकसित भारत के एजेंडे, राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति एवं कांग्रेस की सनातन-विरोधी होने को पार्टी से पलायन का कारण बताया है। कुछ भी कहे, यह राजनीति में अवसरवाद का उदाहरण है, इस तरह का बढ़ता दौर चिंताजनक है। भारत की राजनीति में दलबदल की विसंगति एवं विडम्बना आजादी के बाद से लगातार देखने को मिलती रही है। पिछले साढ़े सात दशक के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पराभव के अक्स गाहे-बगाहे उजागर होते रहे हैं। दलबदल के बढ़ते दौर ने अनेक सवाल खड़े किये हैं। कल तक विपक्ष में जो नेता दागी होते थे, सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनके दाग दाग नहीं रहते। राजनीति में निष्ठाएं बदलने की स्थितियां आम नागरिकों को उद्वेलित करती रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दागी नेता सत्ता की धारा में डुबकी लगाकर दूध का धुला घोषित हो जाता है।

हर बार चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में ख्याआयाराम-गयाराम का खेल शुरू हो जाता है। विभिन्न दलों के प्रभावी नेताओं को अपने दल में शामिल कराने की होड़ मची है, कभी कोई एक दल बाजी मारता है तो कभी कोई दूसरा दल। सभी सेलिब्रिटी आखिर सत्ता की तरफ ही क्यों भागते हैं? पूर्व न्यायाधीश हो, पूर्व अधिकारी हो, अभिनेता हो या खिलाड़ी राजनीति में उनका अपना भविष्य आजमाते रहे हैं। अगर भाजपा की विचारधारा किसी विजेंदर, गौरव या अनिल शर्मा जैसे लोगों को क्यों अच्छी लगती है तो सवाल यह भी है कि पिछले पांच साल तक वे कांग्रेस में क्यों रहे? ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो गत वर्ष के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में एक पार्टी के चुनाव चिह्न पर उम्मीदवार थे तो अब दूसरी पार्टी का चुनाव चिह्न लेकर मैदान में उतरते दिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन दिनों भाजपा में जो विभिन्न दलों के तीस के लगभग राजनेता शामिल हुए हैं उनमें कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी, एसपी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता शामिल हैं। क्या यह भाजपा के निश्चित जीत की संभावनाओं का परिणाम है या केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर का परिणाम है। निश्चिय ही यह स्थिति किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये शुभ नहीं कही जा सकती।

देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि दलबदल का बढ़ता दौर कैसे रुके। राजनीति एवं राजनेताओं में नीति एवं सिद्धान्तों की बात प्रमुख होनी चाहिए लेकिन ऐसा न होना लोकतंत्र की बड़ी विसंगति है। राजनीति में सबकुछ जायज है वाली सोच एवं स्वार्थ की नीति दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव का समय हर राजनेता के लिये अपने हित एवं स्वार्थ को चुनने का समय होता है, लेकिन उनके सामने लोकतंत्र के हितार्थ का प्रश्न बहुत गौण हो जाता है। चुनावों में आचार संहिता के चलते कई प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में दल-बदल पर नियंत्रण का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि यह लोकतंत्र की जीवंतता एवं पवित्रता के लिये प्राथमिकता होनी चाहिए। सत्ता का स्वाद ही ऐसा होता है कि कोई भी राजनेता इससे अछूता नहीं रहता। इसीलिए आजकल दल बदलने का दौर खूब हो रहा है। यह बात दूसरी है कि ज्यादातर नेताओं में भाजपा का दामन थामने की होड़ मची है। एक दिन पहले भाजपा पर निशाना साधने एवं जीभर कर कोसने वाले नेताओं को एकाएक भाजपा इतनी अच्छी क्यों लगने लगती है? भाजपा को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये अवसरवादी नेता जवाबी उनके अनुकूल नहीं हुआ तो उसे भी बाय-बाय कर देंगे? भाजपा को यह भी देखना चाहिए कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर चंद घंटों पहले पार्टी में शामिल होने वाले को टिकट देना कहां तक उचित है। दलों को विचार करना ही होगा कि राजनीति के मायने चुनाव जीतना भर ही है या फिर वे विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देकर राजनीति को स्वस्थ रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज की ठेकेदारी राजनीतिक दलों एवं नेताओं ने ले रखी है, पर ईमानदारी से यह दायित्व कोई भी दल एवं नेता सही रूप में नहीं निभा रहा है। हमारे ही दल एवं नेता एक जैसे हैं यह सुगबुगाहट जनता के बीच बिना कान लगाए भी स्पष्ट सुनाई देती है। राजनीतिज्ञ पारे की तरह हैं, अगर हम उस पर अँगुली रखने की कोशिश करेंगे तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। सभी दल राजनीति नहीं, स्वार्थ नीति चला रहे हैं। भाजपा को अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है, इसके लिये वह हर-तरह के समझौते कर रही है, दागी नेताओं को भी अपनी पार्टी में जगह दे रही है। ऐसे नेताओं के अपराधों पर भी परदा डाला जा रहा है। विडंबना है कि राजनीतिक निष्ठा बदलना इन नेताओं के लिये राहतकारी साबित हुआ है। वजह यह कि इन नेताओं से जुड़े अपराध के मामले ठंडे बस्ते में डाल दिये गए हैं। जबकि दलील यह दी जाती है कि मामले बंद नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ी तो जांच और कार्रवाई भी होगी। जो विपक्ष के उन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुराग्रह एवं आग्रह के रूप में की जाती रही है। यही वजह है कि दल बदलने का फैसला राहत का रास्ता मान लिया जाता है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अचानक जांच एजेंसियां निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं? क्यों किसी एजेंसी को लेकर अदालत को कहना पड़ता है कि फलां एजेंसी पिंजरे में बंद तोता है और मालिक की बोली बोलता है। विपक्ष के ऐसे तमाम आरोपों की तार्किकता हाल में आई एक रिपोर्ट दर्शाती है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद उनमें से 23 को राहत मिल गई है। इनमें से तीन मामले बंद हो गए हैं और बीस की जांच रुकी हुई है। ऐसे अवसरवादी नेता फिर किसी नई पार्टी में नहीं जाएंगे इसकी क्या गारंटी है? अच्छे लोग राजनीति में यदि सिर्फ पद पाने के लिए ही आए तो उसे क्या माना जाए? ऐसी जानी-मानी हस्तियां भी हैं जो आज यहां और कल वहां के उदाहरण पेश कर चुकी हैं। ऐसी सेलेब्रिटी को पार्टी में शामिल होते ही टिकट से पुरस्कृत कर दिया जाता है।

राजनीतिक दलों को इस बड़ी विसंगति एवं अवसरवादिता पर विचार तो करना ही चाहिए कि आखिर कौन, किस इरादे से पार्टी में आ रहा है। ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं कि नामी-गिरामी लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया, टिकट भी मिला और चुनाव जीते भी। उसके बाद जनता से जुड़ ही नहीं पाए और अगले चुनाव में इनका टिकट कट गया। स्वस्थ राजनीति में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, सक्षम हो, सुदृढ़ हो, स्पष्ट एवं सर्वजनहिताय का लक्ष्य लेकर चलने वाला हो। लेकिन स्वार्थी, अक्षम, दागी नेताओं को किसी भी दल में जगह देना यह उस दल की मजबूती एवं स्वस्थ राजनीति पर एक बदनुमा दाग है। विडम्बना है कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, मस्तिष्क नहीं। इसका खामियाजा हमारा लोकतंत्र भुगतता है, भुगतता रहा है। ज्यादा सिर आ रहे हैं, मस्तिष्क नहीं। जाति, धर्म, स्वार्थ और वर्ग के मुखौटे ज्यादा हैं, मनुष्यता के चेहरे कम। तभी राजनीति अवसरवादिता का अखाड़ा बनती जा रही है।

बहुजन समाज पार्टी अब अपनी ताकत दिखाने की शुरुआत कर चुकी है!

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव हो या प्रदेश का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम का हमेशा से ही इन चुनावों पर प्रभाव रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो पश्चिम यूपी में सभी पार्टी के योद्धा करीब करीब मैदान में उतर ही चुके हैं। इन सब में सबसे खास उम्मीदवार अगर किसी के हैं तो बहुजन समाज पार्टी के हैं जिनको बड़ी ही सूझबूझ के साथ और चुन चुनकर मायावती ने टिकट दिया है। मेरठ हो या कैराना या बिजनौर ही क्यों न हो भाजपा के कोर वोटर को प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को बीएसपी ने अपने खेमे से उतारा है। मायावती की ये सूझबूझ भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

दरअसल, मुस्लिम बहुल कुछ एक सीटों को छोड़कर बीएसपी ने अधिकतक सीटों पर अपने प्रत्याशी भाजपा के कोर वोट बैंक को प्रभावित करने वाले ही उतारे हैं। ध्यान देना होगा कि अगर ये बीएसपी के उतारे गए उम्मीदवारों ने अपने जाति से संबद्ध वोट पर कब्जा कर लिया तो भाजपा के साथ बड़ा खेल हो जाएगा। इस बारे के लोकसभा में पश्चिम उत्तरप्रदेश में जातिगत समीकरण का चुनाव पर गहरा असर रह सकता है जो परिणामों को बदलने का माद्दा रखते हैं।

2014 की बात करें तो में पश्चिम उत्तरप्रदेश में आने वाली सभी 14 सीटों पर भाजपा जीत हासिल किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा-रालोद गठबंधन का खास असर रहा था। बिजनौर, नगीना, सहारनपुर के साथ ही मुरादाबाद, संभल, रामपुर व अमरोहा सीटों पर गठबंधन ने नए जातीय समीकरण को भुनाकर जीत हासिल की थीं। 2019 से 2024 का चुनाव इस तरह अलग है कि बसपा इस बार किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। रालोद इस बार भाजपा के साथ है और सपा कांग्रेस का गठबंधन है। पश्चिम उत्तरप्रदेश में जातिगत समीकरण बिल्कुल साफ है। उत्तरप्रदेश के इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जातियां है जिनको भाजपा के कोर वोटर के तौर पर देखा जाता है- ये जातियां हैं- त्यागी, ठाकुर,ब्राह्मण, सैनी,प्रजापति, कश्यप,सेन आदि समाज। वहीं जाटों की पार्टी के तौर पर पश्चिम उत्तरप्रदेश में रालोद की पहचान है। इस तरह इन सभी जातियों का भाजपा के पक्ष में आना तय था। बाकी आर एल डी के जरिए जाट समाज का वोट भी हालिस किया जा सकता था। लेकिन गेम जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं क्योंकि एकेल चुनाव लड़ रहीं मायावती ने गेम को इतना सरल रहने नहीं दिया है।

बिजनौर में भी बीएसपी ने भाजपा का गेम बिगाड़ते हुए जाट चेहरे विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। दरअसल, यहां पर जाट वोट बैंक रालोद व भाजपा के माने जाते रहे हैं लेकिन मायावती ने अपने बेहतरीन चुनावी रणनीति का परिचय देते हुए जाट, दलित समीकरण को भुनाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं सपा ने भी यहां दांव चलते हुए अति पिछड़े सैनी समाज के दीपक सैनी पर विश्वास किया है। यहां के सैनी समाज को भी भाजपा के वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। 2019 में बीएसपी ने गुर्जर उम्मीदवार पर भरोसा किया था और पिछड़े दलित, मुस्लिम समीकरण को भुनाते हुए सीट अपने पाले में भी कर लिया था। इस बार भाजपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान है जो मीरापुर से रालोद विधायक है और गुर्जर समाज से आते हैं। चौ। नारायण सिंह जोकि प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं उनके दादा थे। चंदन चौहान के पिता संजय चौहान सांसद रह चुके हैं। मेरठ से किसी त्यागी को पहली बार बीएसपी ने टिकट दिया है, अब से पहले तक मुस्लिम को ही पार्टी मौका देती रही थी। देवव्रत त्यागी बीएसपी कैंडिडेट हैं और त्यागी समाज को यहां पर भाजपा के कोर वोटर के रूप में देखा जाता रहा है। सपा ने पहले तो दलित भानु प्रताप सिंह को इस सीट से उतारा लेकिन अब गुर्जर विधायक अतुल प्रधान पर दांव लगाया है। वहीं वैश्य उम्मीदवार और रामायण में राम की भूमिका से प्रसिद्धि पाने वाले अरुण गोविल पर भाजपा ने विश्वास किया है। यहां इंतजार इस बात का होगा कि अरुण गोविल बीएसपी के देवव्रत त्यागी के सामने टिक पाते हैं या नहीं। कैराना की बात करते हैं, बीएसपी ने यहां स ठाकुर समाज से आने वाले श्रीपाल राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं यहां पर भाजपा का कोर वोटर ठाकुरों को माना जाता है। ऐसे में भाजपा के सामने बीएसपी कैंडिडेट एक चुनौती की तरह साबित हो सकता है। इकरा हसन को सपा-कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने गुर्जर समाज से आने वाले और यहां से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर फिर से भरोसा जताया है। स्पष्ट है कि मायावती का पूरा फोकस दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों पर दिखाई दे रहा है। मायावती की पार्टी की ओर से तीन अलग-अलग सूची जारी की गई है। बुधवार को 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले 16 प्रत्याशियों की पहली और नौ उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी पार्टी की ओर से जारी की गई थी। बसपा की ओर से सभी सीटों पर नए चेहरे पर दांव लगाया गया है। 2019 में चुनाव जीतने वाले 10 सांसदों में से सिर्फ गिरीश चंद्र जाटव को ही टिकट दिया गया है। उनकी सीट बदल दी गई है। इस बार नगीना की बजाय बुलंदशहर से उन्हें उतर गया है। तीसरी लिस्ट की 12 प्रत्याशियों में तीन ब्राह्मण, तीन दलित, दो मुस्लिम, एक ठाकुर और एक खत्री के अलावा दो ओबीसी हैं। जबकि पहले जो 25 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी उसमें आठ सवर्ण, 7 मुस्लिम, 7 अनुसूचित जाति और दो ओबीसी को मैदान में उतर गया था। पार्टी की ओर से ठीक इसी तरीके की रणनीति 2007 में दिखाई गई थी। मायावती की ओर से 2024 की चुनावी लड़ाई में ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम का फामूर्ला बनाया गया है। पार्टी की ओर से इन्हीं तीन जातियों को महत्व भी दिया जा रहा है। दलित और मुस्लिम समुदाय से 10-10 उम्मीदवारों को अब तक टिकट दिया जा चुके हैं जबकि ब्राह्मण समुदाय से 8 प्रत्याशी उतारे गए हैं। इस सूची में पांच ठाकुर प्रत्याशी भी है। दिलचस्प बात यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा , समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक भी ठाकुर प्रत्याशी नहीं दिया है। लेकिन बसपा ने तीन पर भरोसा जताया है। बसपा की ओर से मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, कन्नौज, लखनऊ, रामपुर, सहारनपुर जैसी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी खेल बिगड़ सकता है। दरअसल, लगातार हार के बाद बसपा लगातार प्रयोग कर रही है। उसने 2022 और फिर नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम कार्ड खेला, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में मंथन के बाद बसपा फिर एक प्रयोग करने जा रही है। मायावती लगातार एक साल से कह रही हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेंगी। बैलेंस ऑफ पावर बनाने की भी बात कर रही हैं। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यह है कि चुनाव बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना भी बसपा का मकसद है। गठबंधन में उसे बहुत कम सीटें मिलतीं। ऐसे में कुल वोट प्रतिशत गिर सकता था। यही वजह है कि सीट के अनुसार जहां जिस जाति का प्रभाव है, उसके अनुसार टिकट दिए गए हैं।

इंडिया शाइनिंग से कितना अलग अबकी बार 400 पार का नारा

-नरेंद्र तिवारी 'पत्रकार'

भारत में आमचुनाव 2024 की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों में टिकिट चयन की प्रक्रिया चल रही है। गठबंधनों में सीटों के बटवारे पर मंथन जारी है। इन सबके बीच नेताओं के इस दल से उस दल में जाने की खबरों से वातावरण में गर्मी व्याप्त है। लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च महीने की 16 तारीख को हुई। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों एवं नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई। चुनावी घोषणा के बाद होली के रंगों में सियासी रंगो की वर्षा होने लगी। रमजान माह पर भी इफ्तारी की सियासत का असर दिखाई देने लगा। मध्यप्रदेश के जनजातीय अंचल में सांस्कृतिक पर्व भगोरिया होलिका दहन के पूर्व एक सप्ताह तक जारी रहा भगोरिया हाट बाजारों में भी राजनीति का प्रभाव देखा गया। देश के उत्सव, तीज, त्यौहारों पर चुनावी रंग चढ़ रहा है।

लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हर पांच साल में आमचुनाव के रूप में आता है। सभी पर्वो, त्यौहारों, उत्सवों पर लोकतंत्र के इस महापर्व का प्रभाव पड़ता है। इस लोकतांत्रिक चुनावी उत्सव में नारों एवं श्लोगनो का अपना महत्व और असर रहता है। भारत में वर्ष 1951-52 के प्रथम लोकसभा चुनाव से वर्ष 2019 के सत्रहवें लोकसभा चुनाव तक हरेक निर्वाचन में सियासी दलों या नेताओं द्वारा दिए गए नारों का असर हुआ है। आममतदाताओं के लिए यह चुनावी नारे जैसे सूत्र वाक्य बन गए। यह नारे आमजन की जुबान से होते हुए जहन में उतरे इन नारों ने आमजन के मानस को तैयार किया। नारों का अपना असर है, रंग है, इन नारों ने अनेकों बार देश की सरकार को बनाया, बनी हुई सरकारों को उखाड़ फैंका। नारे देश की जनता को उद्वेलित ही नहीं करतें इन नारों में सरकार बनाने बिगाड़ने की ताकत होती है। भारत में 18 वीं लोकसभा के गठन की तैयारियों चल रही है। सत्ताधारी भाजपा संगठन के द्वारा अबकी बार 400 पार का नारा वातावरण में गूंज रहा है। इस नारे ने विपक्ष की नींद भी उड़ा दी है, और कुछ हद तक उसे संगठित करने की भूमिका भी निभाई है। यह नारा 2014 के लोकसभा चुनाव में अबकी बार मोदी सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी और अच्छे दिन आने वाले है। जैसे सफलतम और चुनाव जिताऊ नारों की जोड़ का नारा बताया जा रहा है, तो कुछ इसे इंडिया शाइनिंग की तरह देख रहे है। जो बदलते विकसित भारत की तस्वीर बतलाता प्रतीत होता है, किंतु जनता की अदालत में इस नारे को सफलता नहीं मिल पाई थी। इस लिहाज से यह विचारणीय है, की इंडिया शाइनिंग से कितना अलग है, अबकी बार 400 पार का यह लोकलुभावन नारा। क्या जनता इस नारे से प्रभावित होगी या महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याएं अबकी बार 400 पार के नारे पर भारी पढ़ जाएंगी।

भारत के भूतकालिक राजनैतिक परिदृश्य में नारों के असर पर नजर दौड़ाई तो पाया की वर्ष 1971 में कांग्रेस का गरीबी हटाओ अभियान एक नारे के रूप में देश की जनता को गहरे प्रभावित कर गया, गरीबी हटाओ नारे का व्यापक असर हुआ। कांग्रेस इस चुनाव में सफल रही। वक्त गुजरा 12 जून 1975 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को गलत तौर तरीके अपनाने का दोषी माना। उनका चुनाव रद्द करते हुए 6 वर्ष के लिए अयोग्य ठहरा दिया। आपात काल के बाद अनेकों विपक्षी दल जनता मोर्चा के बैनर तले एक हुए, नारा दिया इंदिरा हटाओ, देश बचाओ देश की जनता में इस नारे की अनुगुंज सुनाई देने लगी, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ के नारे ने जनता को गहरा संदेश दिया। विपक्षी एकता की जीत हुई।

भारत देश में हर एक दौर में राजनैतिक नारों का अपना असर रहा है। नारों से देश की जनता आंदोलित भी हुई और अंदर तक प्रभावित भी। वर्ष 1965 में पाकिस्तान से युद्ध में उलझे देश में अनाज का संकट पैदा हो गया था। देश अनाज की कमी से जूझ रहा था। लालबहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान, जय किसान इस नारे ने संकट के समय देश के आत्मसम्मान को बढ़ाया नागरिकों को आंदोलित किया। जय जवान जय किसान के नारे ने कांग्रेस की विजय को सुनिश्चित कर दिया। वर्ष 2014 में मनमोहनसिंह की सरकार के विरुद्ध भाजपा का मुखर अंदाज और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देश के आकर्षण का केंद्र बन गया। भाजपा ने नारा दिया अबकी बार, मोदी सरकार, इन नारों के साथ हर-हर मोदी, घरझघर मोदीॢ का नारा भाजपा कार्यकताओं का सूत्र वाक्य बन गया। इस नारे ने देश को नरेंद्र दामोदरदास मोदी के रूप ने नया नेतृत्व दिया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा ने चुनाव लडा इस बार भाजपा के नारे में आंशिक परिवर्तन हुआ वह था, ॢअबकी बार,फिर मोदी सरकारॢ। भाजपा को इस नारे से भरपूर सफलता मिली। पूर्ण बहुमत से भाजपा के नेतृत्व में देश में सरकार गठित हुई। वर्ष 2024 के आमचुनाव में भाजपा का नारा अबकी बार, 400 पार का शोर सुनाई दे रहा है। यह नारा कितना सफल होगा इसका पता मतगणना की तारीख 4 जून 2024 को चल पाएगा। किंतु इससे पूर्व इस नारे ने कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को बैचेन कर रखा है। अबकी बार 400 पार के नारे ने भले ही इंडिया गठबंधन को बैचेन कर रखा हो, बावजूद इसके अबकी बार, 400 पार का भाजपा का अतिमहत्वाकांक्षी नारा प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेई की सरकार द्वारा साल 2004 के लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग के विज्ञापन जिसने नारे का रूप धारण कर लिया था। जिसके प्रचार के लिए तत्कालीन सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया। देश की जनता को खुशनुमा एहसास कराने वाला इंडिया शाइनिंग का नारा चुनावी सफलता दिलाने में विफल रहा था। अब जबकि 2024 के चुनाव में अबकी बार 400 पार का नारा भाजपा के राजनीतिक मंचो से बुलंद हो रहा है, कितना सफल हो पाएगा? यह वक्त के गर्त में छुपा है। इसके पूर्ण रूपेण सफल होने में संशय भी व्यक्त किया जा रहा है। जिसका कारण इंडिया गठबंधन का दक्षिण सहित कुछ राज्यों में मजबूत होना है। महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल में एनडीए को 2019 जैसी सफलता मिलने के आसार कम नजर आते है। इन सबके बावजूद 2014 के चुनाव के बाद देश में मोदी मैजिक चल रहा है। सफलता दर सफलता हासिल करने वाली भाजपा ने अपनी सांगठनिक क्षमता से जनता तक गहरी पकड़ बनाई है। देश में बरसों से अटके विषयों का निराकरण किया है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार की महत्वपूर्ण सफलता है। जिसने बहुसंख्यक समाज की भाजपा से नजदीकियों को बढ़ाया है। काश्मीर में धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने देश की जनता के सामने निर्णय लेने वाली, मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार होने का दावा पुख्ता किया। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों नागरिकों के घरों का सपना पूरा किया है। गरीबों को मुफ्त अनाज देने की सरकारी योजना भी एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है। इंडिया शाइनिंग की तरह अबकी बार 400 पार का नारा भी बैनरों, पोस्टरों और विज्ञापनों के माध्यम से जनझजन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके विपरित देश में बढ़ रही कमरतोड़ मंहगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। रोजगार के अभाव में देश के युवा मतदाताओं में सरकार के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं पर मंहगाई का साफ असर देखा जा रहा है। इन समस्याओं से ग्रसित देश का बहुत बड़ा गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग मोदी सरकार के अबकी बार 400 पार के नारे पर किस प्रकार विश्वास व्यक्त करता है। इलेक्ट्रोल बांड ने भी सरकार की ईमानदारी और राजनैतिक स्वच्छता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। क्या अबकी बार 400 पार का नारा सफलता की इबारत लिखेगा या इंडिया शाइनिंग जैसा पिटेगा यह बात आम मतदाताओं के जहन में चल रही है। नारे की सफलता या असफलता 4 जून को आए परिणामों के दौरान सिद्ध हो सकेगी। फिलहाल अबकी बार मोदी सरकार, हर-हर मोदी घर-घर मोदी या अबकी बार फिर मोदी सरकार की अपार सफलता के बाद भाजपा को यह विश्वास हो चला है की अबकी बार, 400 पार भी सफल नारे के रूप में देश के राजनीतिक पटल पर अंकित हो सकेगा।

गांधी परिवार के सामने क्या बड़ी सियासी लाइन खींचना चाहते हैं रॉबर्ट वाड्रा

-अजय कुमार

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाता कर अमेठी की राजनीति में सनसनी फैला दी है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम कहीं और से चर्चा में नहीं आया ।वाड्रा ने स्वयं अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है,लेकिन संभवता गांधी परिवार के लिये यह फैसला लेना मुश्किल होगा कि रॉबर्ट को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाये ।इसके पीछे ठोस आधार भी है। रॉबर्ट को लड़ाने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी छवि काफी खराब यानी एक भ्रष्टाचारी के रूप में बनी हुई है। रॉबर्ट को अमेठी से चुनाव लड़ाया गया तो बीजेपी के लिये कांग्रेस और गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला तेज करने का और भी मौका मिल जायेगा। फिर रॉबर्ट की कोई सियासी पहचान भी नहीं है। रॉबर्ट को चुनाव लड़ने पर यदि गांधी परिवार के भीतर सहमति बनी हुई होती तो कांग्रेसियों की एक बड़ी फौज रॉबर्ट को चुनाव लड़ाने के लिये हो हल्ला मचाने लगती,लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस मतलब साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी ससुराल से अलग लाइन पर चल रहे हैं। दरअसल,रॉबर्ट चुनाव लड़कर कांग्रेस में अपना रूतबा बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में वह राहुल गांधी के समानांतर खड़े नजर आ सकते हैं ।कुल मिलाकर रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के सामने एक बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं। वह गांधी परिवार को चुनौती देते दिख सकते हैं। इसलिये राबर्ट का अमेठी से चुनाव लड़ने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है।

खैर, रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने के बाद इतना जरूर हुआ है कि अब कांग्रेस का ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि अमेठी की चुनावी रणभूमि में जल्द से जल्द अपना योद्धा उतारकर कमजोर हो रहे कार्यकताओं को मजबूती देने का है। माना जा रहा है कि पार्टी अब कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता प्रतापगढ़ से रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना पर दांव खेल सकती है। अब सभी को कांग्रेस राहुल गांधी की हां और न का ही इंतजार है। राहुल गांधी की ओर से तस्वीर साफ होते ही किसी एक प्रत्याशी का नाम उजागर हो जायेगा। वहीं, कांग्रेस के अमेठी के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमारे हिसाब से तो राहुल भइया ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। गौरतलब हो, रॉबर्ट वाड्रा ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। वर्षों तक गांधी परिवार ने रायबरेली व अमेठी में कड़ी मेहनत की। अमेठी के लोग वास्तव में वर्तमान सांसद (स्मृति ईरानी) से परेशान हैं, मतदाताओं को लगता है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को चुनकर गलती की है।

ब्हरहाल, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है. कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली समेत 17 सीटें लड़ने के लिए मिली हैं. अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है. इन दोनों ही सीटों पर संशय बना हुआ है. ये दोनों सीटें अहम हैं, क्योंकि ये सीटें हमेशा गांधी परिवार का गढ़ रही हैं. हालांकि, 2019 में राहुल गांधी अमेठी सीट हार गए थे.दशकों तक जिस अमेठी में गांधी-नेहरु परिवार का डंका बजता था। आज उसी अमेठी में भाजपा की स्मृति का जादू चल रहा है। दस साल पहले आम चुनाव 2014 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुकाबला करने अमेठी आई स्मृति ईरानी ने मात्र 23 दिनों में ही यहां के लोगों से कुछ ऐसा नाता जोड़ा कि उन्हें तीन लाख से अधिक मत प्राप्त हुए।

मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को हार के बाद भी मंत्री बनाया गया। इसी के साथ स्मृति ने अमेठी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। स्मृति की सक्रियता का लाभ भाजपा को मिलने लगा और एक के बाद एक चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आने लगे। गांव-गांव, घर-घर स्मृति अपनी नई पहचान बनाने में पूरी तरह सफल रही। आम चुनाव 2019 में स्मृति अमेठी में भाजपा का कमल खिलाने में कामयाब हुई। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जीत का सिलसिला भी चौथी बार थम गया। इससे पहले राहुल गांधी ने 2004, 2009 व 2014 में अमेठी हैट्रिक लगा चुके थे। अमेठी के चुनावी रणभूमि में भले ही अभी तक केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी अकेली घोषित योद्धा हों पर उनकी सक्रियता चुनाव को लेकर काफी बढ़ गई है। पिछले चार दिन वह अमेठी में रहकर बूथवार चुनावी लड़ाई में बड़ी जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटी रही।

वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई अमेठी संसदीय सीट में कुल पांच विधानसभाएं हैं। इनमें अमेठी, जगदीशपुर, गौरीगंज व तिलोई अमेठी जिले की हैं, जबकि सलोन विधानसभा रायबरेली जिले की है। बीते तीन चुनावों की बात करें तो अमेठी की जनता का मूड बदला-बदला नजर आया। वर्ष 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतरे राहुल गांधी ने 57.24 फीसदी मतों के अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन, 2014 के चुनाव में परिणाम कुछ अलग दिखा। इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरीं स्मृति जूबिन ईरानी मजबूती से लड़ीं। यह बात अलग है कि राहुल गांधी ने जीत दर्ज की, लेकिन मतों का प्रतिशत 25.07 फीसदी घटने के साथ ही जीत के अंतर में 32.83 फीसदी कमी आई। फिर वर्ष 2019 के चुनाव में स्मृति ने गांधी परिवार के गढ़ को ध्वस्त कर जीत दर्ज कर ली। संसदीय सीट की पांच विधानसभाओं में से चार पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार गैर कांग्रेसी सांसद के दोबारा जीतने, जीत का अंतर बढ़ाने, सभी पांचों विधानसभा सीटों से जीत हासिल करने की एक बड़ी चुनौती स्मृति ईरानी के सामने है।

दृष्टि हीनता से बचने उपाय करें स्वयं बचें, लोगों को भी बचाएं

आंखे आदमी के लिए वह नियमाक है जो, न रहे तो सारा संसार अंधकार में डूब जाता है। आंखे हमारे लिए सबसे अधिक मुल्यवान और महत्वपूर्ण अंग है। जरा सी अज्ञानता की वजह से हम इस बहुमूल्य अंग को खो देते हैं! और फिर सामना करते हैं, जिंदगी भर के अंधेरे और अंधत्व का। अच्छी नेत्रदृष्टि के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। और यह हमें आसानी से पालक, चौलाई, सब्जियों, सीताफल, गाजर, टमाटर आदि में सर्व सुलभ है। अंचल में कुछ वर्षों से नेत्र संबंधी विकारों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। धूल भरे वातावरण व अज्ञानता की वजह से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बच्चों में दृष्टिहीनता की शिकायतों में वृद्धि हुई है। आगामी दिनों में शीघ्र ही अंधत्व निवारण के लिए केंद्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से देशभर में मोतिया बिंद से अंधे हुए 85 लाख लोगों की आंखों का आपरेशन कराएगी, केंद्रीय मंत्रीमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने विश्व बैंक की सहायता से देश भर में मोतिया बिंद से हो रहे अंधेपन के खिलाफ अभियान पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 448 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जिसमें 2.26 करोड़ रुपया विश्व बैंक और 32 करोड़ रुपया जेनिस सिस्टम से आएगा। बताया गया है कि अगले तीन वर्षों में 85 लाख लोगों की आंखों में मोतिया बिंद के आपरेशन का लक्ष्य रखा गया है।

हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में अंधत्व रोग होने के कई कारण हैं जैसे वहां फूलामाड़ा नामक बीमारी सामन्यतः ज्यादा होती है, चेचक के कारण ही यह रोग होता है। साथ ही विटामिन ए की कमी भी इस रोग के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इसके अतिरिक्त धान कटाई के समय उड़ने वाले कचरे आंख को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषित वातावरण एलर्जी की शिकायत को जन्म देने वाला प्रमुख कारण है। फलतः आंख की बीमारी जन्म लेने लगती है। मोतिया बिंद का रोग बिना किसी लक्षण के अचानक ही प्रकट होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति धीरे-धीरे अंधत्व का शिकार हो जाता है।

नेत्र विषयक व्याधियों की जानकारी प्रारंभिक अवस्था में ज्ञात करने शालेय स्तर पर नेत्र परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह के परीक्षण से कुछ दृष्टि दोष जो बचपन में सुधारे नहीं जा सकते, उनका समय रहते निदान किया जा सके, उदाहरण के तौर पर हायपर मेट्रोपिया रोग आठ वर्ष की उम्र में बच्चों को होते हैं। जो आगे चलकर आंखों के तिरछेपन के लिए उत्तरदायी होता है। इस तरह के रोग समय रहते उपचारित किए जाएं तो नेत्र व्याधियों से बचा जा सकता है। बच्चों में नेत्र व्याधियों के बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण टी वी, विडियो अधिक समय तक देखते रहने की आदत भी है। वहीं गाजर, पपीता, बथुआ, पालक जो सहज सुलभ हैं , अधिकांश लोग अज्ञानता के कारण इनका समुचित मात्रा में प्रयोग नहीं करते और अंधत्व के कगार पर चले जाते हैं। एक जानकारी के अनुसार आज भारत में एक करोड़ पैतीस लाख लोग पूर्ण दृष्टिहीनता के शिकार हैं ।और इतने ही आंशिक रूप से अंधत्व से प्रभावित हैं। आंकड़े बताते हैं कि विश्व का हर तीसरा दृष्टिहीन व्यक्ति भारत का है।

डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप के कारण अब एक नई बीमारी रैटिवोवेथी दिखाई पड़ती है, पर यदि सही समय पर नेत्र परीक्षण व शल्यक्रिया किया जाए तो व्यक्ति अपनी खोई हुई ज्योति पुनः प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग नेत्रदान से कतराते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि. नेत्रदान ही ऐसा दान है जिसके माध्यम से व्यक्ति की आंखे मरणोपरांत भी दुनिया को देखती रहती हैं। वर्तमान में छोटे बच्चों में नेत्र संबंधी विकारों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। विशेषकर कम उम्र के बच्चों के नेत्रों की पुतली में अल्स बन जाने एवं आंखों में एलर्जी की शिकायतें बढ़ी हैं। धूल, धुएं व अन्य प्रदूषण से आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का उपयोग लाभदायक है। साथ ही सोने से पूर्व प्रतिदिन रात्रि में आंखों को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। नेत्र संबंधी किसी भी तकलीफ की उपेक्षा न कर तुरंत ही नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। कांटैक्ट लैंस चश्मे का एक अच्छा विकल्प हैं, चिकित्सक के उचित परामर्श के बाद 'चश्माधारी सहजतापूर्वक कांटेक्ट लेंस लगवा सकते हैं। कांटैक्ट लेंस का चलन इसलिए भी ज्यादा है कि इससे दृष्टि ज्यादा स्पष्ट रहती है। साथ ही चेहरे की सुंदरता भी बनी रहती है।

दृष्टिहीनता से संबंधित अस्सी प्रतिशत बीमारियों जो छोटी शल्यक्रिया के द्वारा पूर्णतः ठीक की जा सकती है। लोगों की अज्ञानता या लापरवाही की वजह से मरीज नेत्र चिकित्सकों के लिए काफी दुस्कर हो जाता है और मरीज अंधत्व का शिकार हो जाता है। नेत्रों की सुरक्षा के लिए जन जागरण पर जोर दिया जाना चाहिए, हालांकि शासन की अंधत्व निवारण योजना के तहत नेत्र सुरक्षा व नेत्र विकारों को दूर करने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रभावी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी को दूर करने दवाओं... का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में परामर्श दिया जा रहा है कि दृष्टिहीनता से बच्चों की रक्षा के लिए पांच वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्रति छह माह में संतृप्त विलयन की एक खुराक पिलानी चाहिए। दृष्टिहीनता से बचने बचाने के लिए हम सभी को स्वप्रेरण ही आगे आना चाहिए, एवं शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए इस दिशर में हमारे क्षेत्र में भंडारी नेत्र सेवा समिति का कार्य उल्लेखनीय है।

-सुरेश सिंह बैस ''शाश्वत''

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अनमोल वचन

यदि पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो, वो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देंगी

-जवाहरलाल नेहरू

घर से हो सख्ती

कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह कथन बिल्कुल उचित है कि, संदेशखालि में यदि यौन उत्पीड़न की एक प्रतिशत आरोप सही पाए गए तो यह बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। यौन उत्पीड़न के कथित पीड़ितों के लगभग सौ हलफनामे इसमें शामिल हैं। इसमें जमीन कब्जा के मामले व हिंसा की घटनाएं भी हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने कहा पूरा जिला प्रशासन और सत्तारूढ़ शासन को जिम्मेदारी निभानी होगी। सौ प्रतिशत जिम्मेदारी निभानी होगी। संदेशखालि में निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख व उसके सहयोगियों पर स्थानीय लोगों की जमीनें हड़पने व महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं। इस पर एक याचिकाकर्ता वकील ने इस घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजंसी से कराने की मांग अदालत से की। जिस पर

पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता ने विरोध करते हुए दावा किया कि केंद्रीय एजंसियों ने भरोसा खो दिया है। पशिचम बंगाल के कूचविहार में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संदेशखालि की घटनाओं का जिक्र करते हुए आश्वासन दिया कि दोषियों को अपना शेष जीवन जेल में बिताना होगा। इस दरम्यान ईडी ने शेख के बैंक खातों समेत उसके स्वामित्व वाले व्यवसायों से जुड़े खातों को फ्रीज करना चालू कर दिया है। पीड़िताओं ने दिल दहलाने वाली आपबीती सुनाई। उन्हें मजदूरी की आड़ में बुलाया जाता था, परंतु युवा व आकर्षक महिलाओं को मनोरंजन के नाम पर जबरन रोक लिया जाता था। उनके साथ मारपीट होती व अन्य तरीकों से उन्हें प्रताड़ित किया जाता। हालांकि स्थानीय नेता व ममता बनर्जी के करीबी इसे शुरुआत से ही बंगाल विरोधी प्रचार बता रहे हैं, परंतु यह सिर्फ भाजपा या सीपीएम के दुष्प्रचार का नतीजा नहीं कहा जा सकता। घटना को लेकर राज्य सरकार के भीतर शंका न होती तो वह आनन-फानन शेख को निलंबित करने से हिचकती। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नेतागीरी की आड़ में यह दबंगई केवल बंगाल में ही हो रही है। वास्तव में इस तरह का अत्याचार राजनीति की छत्रछाया में देश भर में होता रहता है। जिस में जमीनों के कब्जे व बेवजह आम जनता का उत्पीड़न शामिल है। यह गंभीर समस्या है, इस पर दलों के मुखियाओं को सख्ती बरतनी चाहिए और ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना चाहिए।

चीन की कुटिलता

चीन ने भारत के विरुद्ध टकराव एवं संघर्षपूर्ण रवैया जारी रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नए नामों की चौथी सूची जारी की है। इससे जाहिर होता है कि इसने अपनी विस्तारवादी नीति का परित्याग नहीं किया है। चीन की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के करीब एक पखवाड़े बाद आई है। हालांकि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के समय ही चीन ने अपना राजनयिक विरोध दर्ज कराया था। मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13 हजार फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। इस सुरंग से क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का

अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। राजनयिक स्थिति यह है कि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश को विवादास्पद करार देता है। इसी आधार पर पिछले अनेक वर्षों से चीन की ओर से स्टेपल वीजा जारी किए जाते हैं। वस्तुतः चीन यह अपेक्षा रखता है कि समूची दुनिया उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे, लेकिन विडंबना देखिए कि वह स्वयं दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि चीन ने दुनिया विशेषकर एशियाई देशों का सहयोग गंवाया है। जापान, दक्षिण कोरिया, वियेतनाम और कई आसियान देश दक्षिण चीन सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में चीन की दादागीरी को लेकर आशंकित हैं। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के दुःस्साहस से उसने भारत का भी विश्वास खोया है। वस्तुतः अरुणाचल में चीन के अनधिकृत दावे से स्पष्ट होता है कि वह भारत को ऐसा देश समझता है, जिसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय खेमे में भी दृढ़ता आई है। चीन तिब्बत को अपना स्वायत्तशासी प्रदेश कहता है तथा भारत भी 'एक चीन नीति' के तहत ताइवान के साथ तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार करता है। आने वाले दिनों में यह स्थिति बदल सकती है।

कटाक्ष/ कबीरदास

नई हिस्ट्री नहीं आसां...!

तीसरी बार वाले मोदी जी के विकसित भारत वाली नई हिस्ट्री में, नेहरू जी की छुट्टी होना तो तय है। वह स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी से तो जरूर उतार दिए जाएंगे, लेकिन यह तो नई हिस्ट्री का आसान वाला हिस्सा है। नेहरू जी की कुर्सी पर किसे बैठाना है, यह तय करना फिर भी आसां नहीं होगा। इस पर चार सौ पार वालों के बीच ही बड़ा कन्फ्यूजन है। हिमाचल से चार सौ पार की उम्मीदवार कंगना राणावत बताती हैं कि पहले प्रधानमंत्री तो सुभाष चंद्र बोस थे, जो बाद में कहीं गायब हो गए। पर तमिलनाडु के अन्नामलाई की अपनी अलग ही लाइन है--महात्मा गांधी पहले प्रधानमंत्री थे।

यानी मोदी जी की दो बारियों में सिर्फ इतना तय हो पाया है कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। कौन था, यह तय करने के लिए तीसरी बारी चाहिए। अब चार सौ पार में अगर अन्नामलाई और कंगना दोनों ाामिल हुए, तब तो तीसरी बारी में भी जल्दी से तय होना मुकिल है। मोदी जी के घर में भी उत्तर-दक्षिण का झगड़ा छिड़ जाएगा, हालांकि होना चाहिए था पश्चिम और पूर्व का झगड़ा। पर यह भी तो पक्के राष्ट्रवाद की ही निशानी है कि पचिम और पूर्व की दावेदारी पर भी, उत्तर और दक्षिण ही झगड़ रहे होंगे। और गेंद आखिरकार, मोदी के पाले में होगी। अब, नेहरू जी के अलावा किसी और का मामला होता, तब तो मोदी जी एक्सटेंान पर एक्सटेंशन ही देते रहते। पर नेहरू जी को तो एक्सटेंशन दे नहीं सकते और खुद अपने नाम पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी कर नहीं सकते, जब तक कि 2014 को स्वतंत्रता वर्ष घोषित नहीं कर देते। लगता है कि नई हिस्ट्री में पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत दिनों खाली ही रहेगी। नई हिस्ट्री में जगहें नेहरू जी के अलावा भी बहुत सी खाली रहेंगी। बाबरी मस्जिद ने बनने से लेकर गिराए जाने तक घेरे रखी, वह जगह। 2002 के गुजरात के दंगों में मरने वालों की जगह। गोरक्षकों के हाथों मॉब लिंचिंग के िकार होने वालों की जगह। जेलों में ठूंसे गए सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों वगैरह से लेकर, विरोधी मंत्रियों से लेकर, मुख्यमंत्रियों तक की जगह। डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, स्वतंत्र प्रेस, तार्किकता, सचाई, आदि, से खाली करायी जगह। और हां! गांधी की हत्या के प्रसंग को मिटाने से खाली हुई जगह भी। तभी तो कहा--नई हिस्ट्री नहीं आसां...।

ऐसी संवेदनहीनता क्यों

शिक्षक

सतीश सिंह

अहमदाबाद के एक नामचीन निजी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने नौवीं कक्षा के मिर्गी की बीमारी से पीड़ित 'एक्स' छात्रा के समक्ष उसके पिता से कहा 'अगर मिर्गी की बीमारी की वजह से आपकी बेटी कक्षा में लगातार अनुपस्थित रह रही है तो आप किसी ओपेन स्कूल में उसका दाखिला करवा दीजिए, ताकि उसे रोज स्कूल जाने के बंधन से मुक्ति मिल जाए और सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही स्कूल जाना पड़े।'

प्रत्युत्तर में 'एक्स' छात्रा के अभिभावक ने कहा, 'मैडम, इस बीमारी में बच्चे का कम से कम 9 से 10 घंटे सोना जरूरी होता है, अन्यथा मिर्गी का ट्रिगर आ सकता है। इसलिए नींद नहीं पूरा होने पर 'एक्स' स्कूल नहीं जा पाती है, इस वजह से पूर्व के स्कूलों में भी 'एक्स' का 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरा नहीं हुआ था, पर कभी भी किसी शिक्षक या प्रिंसिपल ने इस तरह की आपत्तिजनक सलाह नहीं दी, एक शिक्षक होकर आप ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकती हैं, क्या आपको नहीं मालूम है कि ऐसा करने से बच्चे पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास भी बाधित हो सकता है आदि।' वाइस प्रिंसिपल से इस तरह के संवेदनहीन और अनैतिक सलाह की कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वह भी पीड़ित छात्रा के सामने, लेकिन शिक्षा के संक्रमण के दौर में शिक्षा और शिक्षकों का इस कदर बाजारीकरण हो चुका है कि शिक्षकों के संवेदनशील होने की कल्पना करना बेमानी है।

अब टीचर और बुचर के बीच के फर्क की परत बहुत तेजी से छीज रही है। शायद इसी वजह से कोटा और देशभर में बड़ी संख्या में बच्चे हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। निजी स्कूलों में सुविधाओं की बात करें तो मुश्किल से 5 प्रतिशत स्कूलों में ही खेल का मैदान है। ऐसे में, इंडोर गेम खेलकर बच्चे शारीरिक रूप से कितने फिट रहेंगे? अमूमन, निजी स्कूलों में न ही लाइब्रेरी होती है और न ही फर्स्ट एड की व्यवस्था। आजकल निजी स्कूलों में बच्चों को विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देने के लिए काउंसलर भी रखा जा रहा है, लेकिन इनकी उपयोगिता भी सवालों के घेरे में हैं। कुछ स्कूलों में तो आज ड्रग्स और पॉर्न का बाजार भी फल-फूल रहा है। नर्सरी कक्षा से ही निजी स्कूलों में अभिभावकों से 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना फीस वसूली जा रही है। बस का चार्ज अलग से लिया जा रहा है। आर्ट व क्राफ्ट एवं अन्य गतिविधियों के नाम पर अभिभावकों को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके, स्कूलों में अभिभावकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। निजी स्कूलों में मोटी फीस जरूर वसूल की जा रही है, लेकिन ऐसे अधिकांश स्कूलों में शिक्षा का स्तर दोयम दर्जे

का है। कई निजी स्कूलों की हालत सरकारी स्कूलों से भी बदतर है। निजी स्कूलों में शिक्षकों का वेतन कम होने के कारण ज्ञानहीन शिक्षक अध्यापन का काम कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाने की कला से अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं होते हैं।

दरअसल, बेरोजगारी की वजह से युवा कम वेतन में भी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते है, लेकिन आमतौर पर उनके घर की जरूरतें वेतन से पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण उन्हें ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। ट्यूशन के लिए स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को राजी करना सबसे आसान होता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बच्चों को स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाता है कि विषय की सामग्री उन्हें समझ में नहीं आए। साथ ही, वार्षिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं, परियोजनाओं, अतिरिक्त गतिविधियों में 20 में से 20 नंबर उन्हीं बच्चों को दिया जाता है, जो ट्यूशन पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है और शिक्षकों द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है। अकूत पैसा कमाने की चाहत की वजह से एक कक्षा में 40 से 50 बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षक कक्षा में सिर्फ तेज बच्चों के तरफ ध्यान देते हैं, जिसके कारण अधिकांश बच्चों की संकल्पनाएं विषय के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाती है। हालांकि, यह सच है कि अगर स्कूल में शिक्षक समुचित तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मौजूदा समय में पेन, पेंसिल, कॉपी, स्कूल बैग, जूते, मोजे, ड्रेस, किताब हर चीज की खरीदगी में स्कूल कमीशन ले रहा है। निजी स्कूलों में किताबों को एमआरपी पर बेचने का ढोंग किया जाता है, क्योंकि उनकी एमआरपी उनकी वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक होती है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर एडुकेशन (यूडीआईएसई) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में कुल स्कूलों की संख्या 14,08,115 थी, जबकि निजी स्कूलों की संख्या लगभग 3.40 लाख थी। भले ही सरकारी स्कूलों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आर्थिक रूप से सबल अभिभावक; बच्चे को अंग्रेजी में बेहतर शिक्षा मिले, वे संचार कौशल में प्रवीणता हासिल करें आदि के लिए उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला करवाते हैं।

देखा जाए तो देश में आज एक ऐसा पारिस्थितकी तंत्र का निर्माण हो चुका है, जिसमें सरकारी स्कूलों को हेय की दृष्टि से देखा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि अगर निजी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तभी उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। निजी स्कूल, अभिभावकों की इस कमजोरी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वे जान गए हैं कि अभिभावक अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं अर्थात वे बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। इसलिए, निजी स्कूल के शिक्षक और प्रबंधन अभिभावक से पैसे वसूलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं।

आज शिक्षा कारोबार बन चुका है, जिसके कारण शिक्षा के मंदिरों में संवेदनशीलता और मानवता का भी लोप हो रहा है। स्कूल प्रबंधन का लक्ष्य ज्ञान वितरित करने की जगह मुनाफा अर्जित करना हो गया है। लिहाजा, देशभर में निजी स्कूलों के आभामंडल को लगातार चमकीला, आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, ताकि आमजन खुद व खुद इसकी तरफ खिंचा चला आए। देश के हिंदी पट्टियों में अभी भी अंग्रेजी का प्रभामंडल बहुत ही ज्यादा प्रकाशमान है। इसलिए, आमजन अपने बच्चों को अंग्रेजी में प्रवीण बनाने और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु निजी स्कूलों के सब्जबाग में फंस जाते हैं। आज शिक्षा बाजार बन चुका है और इस बाजार में अभिभावक स्कूलों में मोटी फीस जमा करने के बाद भी शिक्षकों के सामने डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।

आज शिक्षा कारोबार बन चुका है, जिसके कारण शिक्षा के मंदिरों में संवेदनशीलता और मानवता का भी लोप हो रहा है। स्कूल प्रबंधन का लक्ष्य ज्ञान वितरित करने की जगह मुनाफा अर्जित करना हो गया है। लिहाजा, देशभर में निजी स्कूलों के आभामंडल को लगातार चमकीला, आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, ताकि आमजन खुद व खुद इसकी तरफ खिंचा चला आए। देश के हिंदी पट्टियों में अभी भी अंग्रेजी का प्रभामंडल बहुत ही ज्यादा प्रकाशमान है। इसलिए, आमजन अपने बच्चों को अंग्रेजी में प्रवीण बनाने और व्यक्तित्व विकास हेतु निजी स्कूलों के सब्जबाग में फंस जाते हैं

खरीदारों को अब अतिरिक्त पैकेजिंग जरूरी नहीं लगती

- भारत में 10 में से 7 (लगभग 69 प्रतिशत) खरीदारों का कहना है कि वे अतिरिक्त पैकेजिंग के बगैर उत्पाद की डिलीवरी खुशी से लेना चाहेंगे
- यह निष्कर्ष एक अध्ययन से ऐसे समय मिला है जब ऑनलाइन उत्पादों की बिक्री करने वाली बड़ी कारोबारी कंपनियों ने अधिक से अधिक आवश्यक चीजें जैसे टॉयलेट रोल और पेय पदार्थ बगैर अतिरिक्त पैकेजिंग के डिलीवर करने शुरू कर दिए हैं। वे रियूजेबल क्रेट या टोट बैग का उपयोग करके खरीदी गई चीजों की सुरक्षा करती हैं

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

मेरे बहुत सारे संबंधियों, जिनमें से कई धर्मपरायण हिन्दू हैं, में से कुछ ने भाजपा को वोट किया था, लेकिन उन्हें लगता है कि अब नहीं। मिली-भगत की पूंजी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे महाघोटालों, जो धर्म को आगे रखकर किए गए तथा भारत के संस्थानों का ह्रास किया जाना उन्हें अस्वीकार्य है।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

माय-बाप समीकरण की ठाठ

बिहार

प्रो. नवल किशोर

किसी भी राजनीतिक दल के उदय, स्थापना और विस्तार में जन समर्थन ही मुख्य तत्व है। प्रायः चुनावी दंगल में किसी भी दल को हासिल जनादेश को तीन खंड में देखने की कोशिश की जाती है जिसे कोर वोट, समर्थन वोट और तिरती वोट की संज्ञा दी गई है। इन तीनों में कोर वोट किसी भी दल की रीढ़ होती है। इसका टूटना मतलब उस दल का पतन। बाकी दोनों प्रकार के वोटों का ऊपर-नीचे होना स्वाभाविक है क्योंकि वह समसामयिक मुद्दों और अभियान पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 25 जुलाई 1997 को हुई जो लालू प्रसाद के लिए एक विपरीत कालखंड में हुआ करता था। एक तरफ वह अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर थे वहीं दूसरी तरफ पशुपालन घोटाले के आरोप में उनकी राजनीतिक जीवन बिल्कुल संक्रमण काल से गुजर रही थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने दो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लिए थे। पहला, जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की गठन की घोषणा करना और दूसरी अपनी गिरफ्तारी से पूर्व राज्य सरकार के नेतृत्व परिवर्तन को अंतिम रूप देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना। उनके नेतृत्व में राजद की सरकार लगभग आठ साल (1997-2005) तक रही थी। उन्नीस सौ नब्बे के दशक में लालू प्रसाद यादव अपनी चुनावी सभाओं में कहा करते थे कि जब तक 'माय' का आशीर्वाद रहेगा तब तक कोई माई का लाल उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता। उन्होंने जेपी आंदोलन (1974), जनता पार्टी (1977) और जनता दल (1989) के रास्ते बिहार की राजनीति में करिश्माई नेतृत्व, स्वीकार्यता और लोकप्रियता अर्जित की। फिर एक खास परिस्थिति में राजद (1997) का गठन किया। यह उनके सक्रिय राजनीतिक हस्तक्षेप से अर्जित आत्मविश्वास की एक झलक थी। उसी दौर में केंद्र-राज्य के मद्देनजर झटकते हुए उन्होंने एलान किया कि वे घुटनना टेक नहीं बल्कि सीनातान मुख्यमंत्री हैं। इस प्रकार उनके नेतृत्व उभार से स्थापित होने में स्पष्टवादिता एक रोचक पक्ष रही है। उनकी भूमिका मंडल आयोग रिपोर्ट को लागू कराना हो या आडवाणी को गिरफ्तार कर बिहार में रथयात्रा से संभावित

दंगों को रोकने में हो, दोनों परिघटनाओं ने लालू प्रसाद यादव को पिछड़ों-अकलियतों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। अपनी करिश्माई एवं जनवादी नीतियों के मद्देनजर वे समाजवाद, सामाजिक न्याय और सौहार्द के मुखर प्रवक्ता बन चुके थे। अपनी वाकपटुता और जन-संपर्क से राष्ट्रीय राजनीति में भी वे सदैव अग्रणी भूमिका में रहते थे। लगभग एक दशक (2005-15) तक विपक्ष में रहने के बाद जब राजद सत्ता में वापस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण समीक्षा की बात को चुनाव प्रचार में भाजपा विरोध अस्त्र बनाने सफल रहे। परिणामस्वरूप भाजपा को करारी शिकस्त मिली। राजद सबसे बड़े दल रूप में जीत हासिल की और तेजस्वी प्रसाद यादव विधायक दल के नेता निर्वाचित हुए। महागठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री भी बने। लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति उन्होंने एनडीए के खिलाफ बिहार विधानसभा (2020) चुनाव पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और कारवाई को अभियान का मुख्य बिंदु बनाने में सफल रहे। लगभग सत्रह महीने के कार्यकाल में नौकरी, जाति गणना और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को तय करने में तेजस्वी ने अहम भूमिका निभाया। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन से नाता तोड़ा और राजद सरकार से बाहर हुए, लेकिन अल्पकालिक कार्यकाल में पांच लाख नौकरी देने के मुद्दे पर सभी जातियों के युवाओं के बीच तेजस्वी की स्वीकार्यता ज्यादा बढ़ती दिखी। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ माय की पार्टी नहीं बल्कि बाप (बीएएपी) की भी पार्टी है, जिसका तात्पर्य बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी (महिला) और पुअर (गरीब) है। मूल आशय था कि यह पार्टी सभी जाति/धर्म के सदस्यों के लिए एक समान है।

अपने सीमित कार्यकाल में दिए पांच लाख नौकरी की चर्चा 'एनडीए के सत्रह साल बनाम सत्रह महीने' को सक्रिय अभियान का हिस्सा बनाया। दरअसल 'ए टू जेड' की राजनीति से तेजस्वी प्रसाद ने समाज के सभी धर्म/वर्ग/जातियों को जोड़ने की शुरुआत की है। इटली के सुविख्यात राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली ने की उक्ति यहां समुचित प्रतीत होता है -'प्रत्येक राजनेता अपने समय-देशकाल का शिशु होता है। उसके समक्ष अपनी प्राथमिकताएं एवं चुनौतियां होती हैं।' दूसरे शब्दों में, कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के 'माय' समीकरण की राजनीति आज व्यापक फलक को प्राप्त करता हुआ 'बीएएप' अर्थात समावेशी एवं समदर्शी राजनीति को प्राप्त कर चुका है। यह बिहार जैसे विविधतासम्पन्न राजनीतिक प्रदेश के लिए मील का पत्थर सरीखा उपलब्धि है। इससे समाज के प्रत्येक तबके का सतत एवं सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सकेगा।

संगत का असर

संत राजिन्दर

इंसान किस किस्म की संगत रखता है, उसका बहुत बड़ा असर इंसान के ऊपर होता है। जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि एक ही

घराने के बच्चे जब अलग-अलग माहौल में जी रहे होते हैं, तो उनका चरित्र, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके खयालात, सब अलग-अलग होने शुरू हो जाते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम अच्छी संगत रखें। दोस्ती उन लोगों से करें जिनके खयालात शुद्ध हों। महापुरुष हमें बार-बार समझाते हैं कि हम अपनी संगत अच्छी रखें। ऐसे लोगों के साथ जियें, ऐसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करें, जिनका ध्यान प्रभु की ओर हो। जब उनकी संगत में रहेंगे, तो हमारे विचार भी उसी किस्म के हो जाएंगे और हमारा ध्यान भी प्रभु की ओर लगता जाएगा। अगर उन लोगों की संगत की जिनका ध्यान दुनिया की ओर है, तो हमारा ध्यान भी प्रभु से हटकर उस ओर होना शुरू हो जाएगा। तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगत रखें, किस से दोस्ती रखें, और किस माहौल में जियें। कई बार इंसान सोचता है कि मैं अपना माहौल नहीं बदल सकता, लेकिन महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम अपने साथ जुड़े पूर्व कर्मों को तो नहीं बदल सकते, परंतु हमारी पच्चीस प्रतिशत जिंदगी हम पर निर्भर करती है। अगर हम अच्छी तरफ कदम उठाएंगे, तो प्रभु की नजदीकी पाएंगे और अगर हमारे कदम अच्छी ओर नहीं उठे, तो हमारी जिंदगी और अधिक खराब होती चली जाएगी। इसीलिए समझाया जाता है कि हम अपनी संगत अच्छी करें। अच्छी संगत का असर हमारी पूरी शख्सियत पर पड़ता है। जब हम महापुरुषों की जिंदगी को देखते हैं, तो उनके अंग-संग जो माहौल होता है, उसमें ध्यान हर समय प्रभु की ओर जाता है। क्योंकि वे चाहते हैं कि हम प्रभु को जानें, हम प्रभु को पाएं, हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ हो। हम जितना ज्यादा ध्यान प्रभु की ओर करेंगे, उतना ही हमें उनके पास पहुंचने में आसानी होगी। जिस ओर हम ध्यान देते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। संगत अच्छी होने से हमारा ध्यान आसानी से प्रभु की ओर लग जाता है। स्वाभाविक है कि अच्छी संगत हमें प्रभु के करीब ले जाती है, उनसे हमारा रिश्ता बेहतर और मजबूत बनाती है। इसीलिए संगत अच्छी रखना बहुत जरूरी है।

रीडर्स मेल

जनता के बीच रहना होगा

लोकप्रिय टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल न ही पहले और आखिरी सितारे हैं जिन्होंने राजनीति की धरती पर कदम रखा है। इससे पहले भी दारा सिंह, राज बब्बर, दीपिका चिखिलया, अरविन्द त्रिवेदी, रूपा गांगुली इत्यादि ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है। और ऐसा कई बार हुआ है कि नीतीश भारद्वाज की तरह ही उस क्षेत्र के लोग 'अपना सांसद लापता है' के पोस्टर लगा देता है। गुरदासपुर में अभिनेता सनी देओल के साथ ऐसा हुआ है। तो इन फिल्मी और टीवी सितारों को यह समझने की जरूरत है कि राजनीति का मैदान संघर्षों से भरा हुआ है और दिन-रात की कड़ी मेहनत और तपस्या मांगता है। ऐसा नहीं कि एक बार चुने जाने के बाद आप नदारद हो गए। तो अरुण गोविल को भी यह भलीभांति समझना होगा कि आज वो अगर गली-गली, मोहल्ले जाकर वोट मांग रहे हैं तो चुने जाने के बाद इन्हीं लोगों की समस्या को निबटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है, इससे वह किनारा नहीं कर सकते हैं।

बाल गोविंद, नोएडा

स्वार्थ नेताओं की पौ-बारह

कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लोक सभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनावी घोषणा के बाद कांग्रेस में नेताओं को पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। यह कांग्रेस नेतृत्व की असफलता है कि वह अपने नेताओं को एकजुट रखने में असफल रही है। आज की राजनीति में विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है। आज की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य पद और धन की प्राप्ति हो चुका है। कांग्रेस में रहकर नेताओं को पद की प्राप्ति नहीं हो रही है एवं दूसरी ओर भाजपा उन नेताओं के लिए अपनी पार्टी के द्वार खोल दिए हैं। जब पार्टी का बुरा वक्त आता है, तो ऐसे नेता सबसे पहले पार्टी को छोड़ते हैं। समय का चक्र बदलता रहा है, अभी नेताओं को भाजपा में अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। दल-बदल की राजनीति लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है।

हिमांशु शेखर, गया

न हो खाने की बर्बादी

भोजन प्राणी जाति के तंदरुस्त रहने के लिए लिए बेहद जरूरी है, लेकिन भोजन संतुलित और प्रकृति के दायरे में होना चाहिए और खाने की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए। दुनिया के बहुत से देश भुखमरी की समस्या भी झेल रहे हैं। हमारे देश में शादियों और दूसरे समारोहों में खाने की बर्बादी भी बहुत होती देखी जा सकती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक यह सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों को खाने की बर्बादी से होने वाले नुकसानों को समझाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में एक अध्याय जरूर शामिल किया जाए। उद्योगपति रतन टाटा ने बताया था कि एक बार वो जब विदेश गए थे। उन्होंने देखा की रेस्टोरेंट खाली है, वहां सिर्फ एक लड़का व लड़की बैठे थे। वहाँ मैने खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद मुझसे कुछ खाना बच गया था। खाने के बिल अदा कर जब मै वहां से जाने लगा तो मुझे वहां बैठे लड़का व लड़की ने रोका, और फिर मुझ से खाना बर्बादी के लिए जुर्माना वसूला गया था। निःसंदेह अन्न की बर्बादी बेहद गंभीर समस्या है और इसकी समझ हर किसी को होनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 234
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

कांग्रेस का घोषणा पत्र जमीनी हकीकत से कितना दूर

कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रत्येक गरीब परिवार को एक लाख रु. सालाना देने वाली महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। पार्टी ने यह भारी-भरकम वादा तो किया लेकिन यह नहीं बताया कि 'सबसे जरूरतमंद परिवार' की परिभाषा क्या होगी और ऐसे कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा। घोषणा-पत्र में 'आधार से इनकम पिरामिड' शब्द-समूह का प्रयोग है। देश में 'गरीब' और 'अति-गरीब' मापने के दर्जनों पैमाने और अनेक आयाम हैं- आय, उपभोग और बहु-आयामी गरीबी। उधर अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को लें तो औसतन कुल संख्या फ्री राशन या आयुष्मान कार्ड या अन्य आय के मानक पर करीब दस करोड़ परिवार हैं। क्या कांग्रेस यह वादा कर रही है कि वह कम से कम पांच से दस करोड़ परिवारों के मुखिया को एक लाख रुपया सालाना देगी? इस लिहाज से यह राशि कम से कम पांच से दस लाख करोड़ रु. की होगी। फिलहाल देश में अनाज, खाद, पेट्रोल सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता में कुल व्यय करीब तीन से पांच लाख करोड़ का होता है। भारत का बजट आज 45 लाख करोड़ रु. का है। इस वादे के अनुसार बजट का कम से कम 10-20% इस योजना की भेंट चढ़ गया तो बाकी योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा?

प्रेरणा

खुद को जानना हर तरह के ज्ञान की शुरुआत है।
- अरस्तू

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

नववर्ष में मन, वचन, कर्म से एक रहने का संकल्प लें

हमें धर्म की जानकारी है पर हम धर्म में जी नहीं पाते हैं। हमें ध्यान की विधियां तो मालूम हैं, पर ध्यान कर नहीं पाते हैं। अच्छाइयों के सारे सूत्र हम सुन चुके होते हैं लेकिन अच्छाई उतार नहीं पाते हैं। ऐसे जीवन के अनेक क्षेत्र हैं, जिसमें हम चूक रहे हैं। फिर वो क्या माध्यम हो कि हम जागरूक रहें। उस माध्यम का नाम है संस्कार। गिनती की दृष्टि से देखें तो सोलह संस्कार ऋषि-मुनियों ने दिए। हर संस्कार जीवन जीने की एक गहरी शैली है। संस्कार एक ऐसी गतिविधि है, जिसमें मन, वचन और कर्म को एक रखकर कार्य किया जाता है। जहां भी इन तीनों में भेद आया, आप अच्छी बात लेने में चूक जाएंगे। भारतीय पंचांग के अनुसार नव संवत्सर 9 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। अब बहुत कम लोग हैं जो कैलेंडर, इस नववर्ष से आरंभ करते हों। लेकिन नव संवत्सर के दिन ग्रह, नक्षत्र, वातावरण अनुकूल होंगे। इस मौके पर एक संकल्प लें कि हम मन, वचन, कर्म में एक रहकर काम करेंगे। कोलकाता में नववर्ष की पूर्व संध्या पर 8 अप्रैल को हनुमान चालीसा का महापाठ होता है और इस कार्यक्रम का नाम है- एक शाम संस्कारों के नाम। इस कार्यक्रम से विभिन्न डिजिटल माध्यमों से जुड़ सकते हैं। • Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • सुधार के लिए कॉमन डेटाबेस जरूरी है

एक बड़ी इकोनॉमी बनना ही काफी नहीं, चुनौतियां और हैं

डॉ. अरुणा शर्मा
प्रैक्टिशनर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव
arunasharmal908@gmail.com

इस साल भारत में लोकसभा चुनावों के साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तेजी से दलबदल का चलन देखा गया है। इस पर भी सवालिया निशान हैं कि वे पार्टी के घोषणापत्र का पालन करते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से यह महत्वपूर्ण दस्तावेज अप्रासंगिक बनकर रह गया हो? मतदान से पहले और बाद में क्रॉस फ्लोर की अधिक घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में समय आ गया है कि नागरिकों के पास एक डिमांड-चार्टर हो, जिसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना हो। नई योजनाएं लाने का प्रयोग बहुत हुआ। ये नई बोतल में पुरानी शराब की तरह प्रस्तुत की जाती हैं, जबकि भूख, गरीबी, बेरोजगारी की चिंताएं पहले की तरह बनी रहती हैं।

अव्वल तो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मानवाधिकार का मामला है, ये कोई वैसी लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं, जिनसे सरकार जनता को उपकृत करती हो। इनमें असंगठित क्षेत्र के लिए पीएफ, हेल्थकेयर और गारंटीशुदा उत्तम शिक्षा शामिल हैं। नागरिकों द्वारा खरीदे जाने वाले प्रत्येक लीटर ईंधन पर भी एक शिक्षा 'उपकर' लगता है। उस राशि का उपयोग हर इलाके में स्कूलों को सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा और किफायती दरों पर अच्छे शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। याद रखें कि किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया कराना सरकार का मूलभूत दायित्व है, इन्हें निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

दूसरे, खाद्य सुरक्षा केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण नहीं है, बल्कि मध्याह्न भोजन, खाद्य उत्पादकता और पूरक आहार प्रदान करने के अलावा पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए खाना पकाने की शिक्षा सुनिश्चित करना भी है। आने वाले पांच सालों में कुपोषण और भूख की समस्या पर काबू पाने के लिए मिशन-मोड में काम करने की जरूरत है।

वहीं, जनगणना और अन्य सर्वेक्षण भी जरूरी हैं, ताकि सभी राज्यों के पास एक कॉमन घरेलू डेटाबेस हो। इसी की मदद से स्वास्थ्य व गरीबी की स्थिति, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय संस्थानों तक पहुंच, ऋण और विकास की निगरानी पर रियल टाइम डेटा सुनिश्चित करने हुए 'समग्र' मॉडल को अमल में लाया जा सकेगा। 'समग्र' न केवल ग्रांट्स की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करेगा, बल्कि पीएफ, बीमा, उपचार की सुविधाएं भी देगा। कॉमन डेटाबेस गड़बड़ियों की गुंजाइश को काफी हद तक कम करता है।

कृषि और एमएसएमई में स्थायी रोजगार-सृजन का प्रवाह नियमित रहना जरूरी है। कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों को सरकार द्वारा समर्थन-लागत पर कृषि कल्याण केंद्र और एमएसएमई के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है। वेतनभोगी नौकरियों में जेंडर-इनक्लूजन भी योग्यता के आधार पर हो, हालांकि बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल, मातृत्व लाभ जैसी विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करना आवश्यक है। औद्योगिक विकास ग्रोथ का इंजन है, हालांकि उसका पर्यावरण के प्रति जवाबदेह होना जरूरी है। उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश, एफडीए और बैंक ऋण के जरिए इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

वास्तव में हर क्षेत्र का अपना महत्व है। फूड प्रोसेसिंग का ही उदाहरण लें, जिसे केंद्रीकृत करना जरूरी है। फाइनेंशियल इनक्लूज़न, नेट कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी के संदर्भ में बुनियादी ढांचे का महत्व भी कम नहीं। चाहे डाकघर हो, सहकारी बैंक,

सामाजिक सुरक्षा मानवाधिकार का मामला है। ये वैसी लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं, जिनसे सरकार जनता को उपकृत करती हो। लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया कराना सरकार का मूलभूत दायित्व है।

छोटे बैंक या बैंक हों, सभी के लिए भौतिक वित्तीय संस्थानों का होना जरूरी है। पिछले डेढ़ दशक में डिजिटल भुगतान से काफी सफलता मिली है और अब कोई भी सरकारी भुगतान चेक या नकद से नहीं होता। फिर भी जरूरत आसान ऋणों, बचतों, जमा, बीमा और भविष्य निधि जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने की है। नेट कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें तो बहुत ही जरूरी हैं।

5 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी के लक्ष्य को हासिल करना समय पर निर्भर करता है। लेकिन एक बड़ी अर्थव्यवस्था के गवर्नेंस की परीक्षा तो इसी से होती है कि वह कितनी समावेशी है। भारत का समावेशी विकास केवल उसकी अर्थव्यवस्था के आकार पर आधारित नहीं हो सकता। युवाओं को स्थायी नौकरियों की जरूरत है, बेहतर शिक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के साथ ही देश में शांति कायम रखने और सुरक्षा चाक-चौबंद रखना केंद्रीय महत्व का है। इन लक्ष्यों से हमारा ध्यान डिगे नहीं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं।)

विश्लेषण • मतदाताओं को ब्योरे जानने का हक है...

इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिया फैसला पारदर्शिता लाएगा

मकरंद परांजपे
लेखक, चिंतक, जेएनयू में प्राध्यापक
MarkrandParanspe

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 200 से अधिक वर्षों के इतिहास वाली एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे कठघरे में खड़ा कर दिया। भारत के नंबर एक राष्ट्रीयकृत ऋणदाता बैंक को सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना में दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों के बारे में 24 घंटे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया। शीर्ष अदालत द्वारा अपने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने के बाद एसबीआई ने कई हफ्तों तक टाल-मटोल की और वह 20 जून तक का समय चाहता था। तब तक आम चुनाव सम्पन्न हो चुके होते और फैसला भी सामने आ चुका होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोटूक कहा, अब और देरी नहीं चलेगी। शुक्र है कि एसबीआई डेडलाइन से पहले ही निर्देशों को पूरा करने में सफल रहा। हालांकि अदालत ने इस पर जोर नहीं दिया था कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड्स खरीदने वालों का मिलान राजनीतिक दलों के साथ भी करे, लेकिन सिविल सोसायटी कार्यकर्ता और राजनीतिक निगरानीकर्ता इसमें देरी नहीं करते। कारण? क्योंकि इसमें भारी मात्रा में धन शामिल है, और सत्तारूढ़ भाजपा को उस धन का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है।

हालांकि चुनाव आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजनीतिक दलों के वार्षिक खातों का डेटा अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, लेकिन मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए 16,518 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, जिनमें से अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलों के खाते में गए। ये वे ही लोग थे, जिनके पास सत्ता है- फिर चाहे वह केंद्र में हो या राज्यों में। ऐसे में क्या भारतीय नागरिकों और मतदाताओं को यह जानने का अधिकार नहीं था कि ये दानदाता कौन हैं? किसे, कितना पैसा मिला? सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट सोच है कि उन्हें यह पूरा अधिकार है। बहरहाल, 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना आदर्श से बहुत दूर होने के बावजूद सही दिशा में उठाया कदम थी। क्योंकि यह चुनावी फंडिंग प्रणाली में उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वैध और जवाबदेह धन के प्रवाह को लेकर आई थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को रद्द क्यों कर दिया? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सहमति से इस योजना को इसलिए रद्द किया, क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करती थी।

संविधान का यह अनुच्छेद अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 भी अंतर्निहित माना जाता है। लेकिन चुनावी बॉन्ड गुमनामी और अस्पष्टता के लिहाफ में लिपटे हुए थे, जिसे शीर्ष अदालत ने आपत्तिजनक माना। हालांकि राजनीतिक दल जानते थे कि दानदाता कौन थे, लेकिन वे चुनाव आयोग या जनता के सामने उनकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं थे। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, मतदान की प्रभावी आजमाइश के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। नतीजतन, बेंच ने आयकर अधिनियम, 1961 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में हुए संशोधनों को भी इसके साथ रद्द कर दिया, जिसके आधार पर गुमनाम राजनीतिक चंदे को स्वीकार्य माना गया था।

जब चुनावी बॉन्ड की बात आती है तो हमें नहीं

चुनावों के लिए फंडिंग एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका में पिछले चुनाव पर 1,19,520 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जो 2016 में हुए चुनाव की तुलना में दोगुने से भी अधिक था। भारत में होने वाले चुनाव तो इससे भी खर्चीले हो सकते हैं।

भूलना चाहिए कि इसमें दानदाताओं को कर-छूट दी गई है। वास्तव में धन के एडमिनिस्ट्रेशन की वास्तविक लागत का भुगतान भारत के कंसोलिडेटेड फंड से किया गया था, जिसमें सभी कर राजस्व शामिल हैं। यानी आम नागरिक एक ऐसी योजना के संचालन के लिए भुगतान कर रहे थे, जिससे राजनीतिक दलों को फायदा हो रहा था। इसके अलावा, बॉन्ड शब्द भी भ्रामक है। बॉन्ड एक ऋण होता है, दान नहीं। क्या हमें इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर भुगतान करके बॉन्ड खरीदे थे, उन्हें उम्मीद थी कि उनका पैसा सूद समेत लौटकर उनके पास आ जाएगा? एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़ों से हम पता लगा सकते हैं कि किसने, कितना और किस लाभ के बदले में पैसा दिया। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं भी करते हैं, तो भी चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि आगे जो भी योजना आएगी, वह अधिक पारदर्शी होगी जिससे उसके दुरुपयोग की सम्भावना कम होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

The Economist
6 अप्रैल के अंक से
विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने चीन की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान की पड़ताल की है
दैनिक भास्कर
अब आप द इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

बिजनेस ब्रीफ

2020 के बाद से टेस्ला की बिक्री में पहली बार आई गिरावट

टेस्ला ने 2024 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 386,810 वाहन की बिक्री की। यह पिछले साल की पहली तिमाही की तुलना में 8.5% की कमी है और 2020 के बाद से कंपनी की पहली गिरावट है। निवेशक पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की धीमी वृद्धि से परेशान हैं। इसी वजह से टेस्ला के स्टॉक भी गिरे हैं। वहीं फोर्ड और हुंडई ने अमेरिका में ईवी बिक्री में बड़ी वृद्धि दर्ज की और जनरल मोटर्स ने भारी गिरावट की घोषणा की।

यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट, गैस भंडार भी बढ़ा

यूरोप में नेचुरल गैस की कीमत में गिरावट आई है। यह तब दर्ज हुई जब यह बताया गया कि यूरोपीय संघ में गैस के भंडार लगभग 60% भरे हुए हैं, जो वर्ष के इस समय के लिए एक रिकॉर्ड ऊंचाई है। आने वाले गर्म महीनों में इसमें ग्रोथ होगी क्योंकि गैस की आपूर्ति फिर से बहाल होगी। दो साल पहले रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और कम भंडारण स्तर के कारण यूरोप को गैस की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल गैस की कीमत 26 पाउंड प्रतिघंटे मेगावाट है, जो पिछले साल 56 पाउंड थी।

एफटीएक्स धोखाधड़ी केस में सैम बैंकमैन ने बचाव में दलील दी

एफटीएक्स क्रिप्टोकरेंसी मामले में सजा काट रहे सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ गलत कर रहा था।' एफटीएक्स में धोखाधड़ी के लिए सैम को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने वाले न्यायाधीश ने कहा कि बैंकमैन- फ्राइड ने अदालत में झूठी गवाही दी थी और अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया था। सैम ने एफटीएक्स नामक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज स्थापित किया था, जो 2022 में ढह गया।

डिज्नी बोर्ड की लड़ाई में सीईओ बॉब इगर के पक्ष में आया फैसला

इस हफ्ते डिज्नी के शेयर धारकों की वार्षिक बोर्ड मीटिंग हुई। दरअसल निवेश फर्म ट्रायन पार्टनर्स के संस्थापक नेल्सन पेल्ट्स डिज्नी के बोर्ड में दो सीट की मांग कर रहे थे। लेकिन नेल्सन की यह मांग पूरी नहीं हुई। फैसला डिज्नी सीईओ बॉब इगर के ही पक्ष में आया। उन्हें ब्लैकरॉक, डिज्नी परिवार और फिल्म निर्माता जॉर्ज लुकास का समर्थन मिला। वहीं नेल्सन को अपनी मांग के समर्थन में सिर्फ 31 फीसदी ही वोट मिले।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

30 साल में पहली बार संकट में चीन की इकोनॉमी 2050 तक यहां की वर्कफोर्स 20% घट जाएगी

अर्थव्यवस्था

चीन की रीयल एस्टेट बिक्री घट रही, कंपनियों पर वैश्विक प्रतिबंध से व्यापार कम हुआ

पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश के उत्तर-पूर्वी प्रांत हेइलोंगजियांग के दौरे पर थे। उस समय यह प्रांत कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था। हेइलोंगजियांग की जन्म दर चीन में सबसे कम थी। यहां के बड़े शहरों में घरों की कीमत गिर रही थी। प्रांत की जीडीपी सिर्फ 2.6 प्रतिशत बढ़ी थी। यह बताने के लिए काफी था कि इस प्रांत की आर्थिक हालत खराब थी। एक साल बाद अब जिनपिंग को अहसास हो चुका है कि 30 साल में पहली बार चीन की आर्थिक स्थिति हेइलोंगजियांग की तरह ही हाशिए पर है। फिलहाल चीनी इकोनॉमी के सामने तीन बड़े संकट हैं।

चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्कफोर्स रही है। 1996 से 2015 तक चीनी कार्यबल 10 करोड़ तक बढ़ा। लेकिन अब चीन की इंडस्ट्री वर्कफोर्स सिकुड़ रही है। अनुमान है कि 2050 तक चीन की वर्कफोर्स 20 फीसदी तक कम होगी। चीन की प्रॉपर्टी इंडस्ट्री यहां के जीडीपी का पांचवां बड़ा हिस्सा है। यह भी संकट में है। इससे नकदी की कमी से जूझ रही स्थानीय सरकारों को नुकसान होगा, जो राजस्व के लिए प्रॉपर्टी बिक्री और विकास के लिए समृद्ध रीयल एस्टेट पर निर्भर थीं। तीसरी चुनौती है अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते। चीनी अधिकारी आश्वस्त हैं कि नवंबर में व्हाइट हाउस में जो भी जीतेगा, वह चीनी आयात पर प्रतिबंध बढ़ाएगा और चीनी कंपनियों पर सख्ती जारी रखेगा। टिकटॉक हालिया उदाहरण है।

हालांकि, चीनी राष्ट्रपति के पास इससे निपटने के लिए एक योजना है। वे देश में 'न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस' रणनीति अपना रहे हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को गति देने की बात है। स्टील जैसे पारंपरिक बिजनेस को छोड़ इलेक्ट्रिक कारों, बैटरी, बायोमैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन-आधारित उत्पादों पर अधिक फोकस होगा। इस नई रणनीति को लागू करने के लिए चीन में हर साल 1.6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा, जो कुल निवेश का पांचवां हिस्सा होगा। यह 2023 में अमेरिका में सभी व्यावसायिक निवेश के 43% के बराबर है। इसके फायदे हैं। कुछ उद्योगों में फैक्टरी क्षमता 2030 तक 75 प्रतिशत से अधिक बढ़ सकती है। चीन में अब कॉलेज से ही टेक्नोलॉजी पर फोकस शुरू हो गया है। चीनी शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में हाई-एंड सेमीकंडक्टर विज्ञान और इंजीनियरिंग में एक नई स्नातक पढ़ाई को मंजूरी दी है।

अलीबाबा और मीटुआन जैसी कंपनियों पर कार्रवाई से उद्यमी नाराज

चीन को उसके अपने नेताओं ने भी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने 2021 में देश की कई बड़ी तकनीकी कंपनियों पर कार्रवाई की थी। इन पर डेटा का दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा को विफल करने और श्रमिकों का शोषण करने के आरोप लगाए। इसमें अलीबाबा और मीटुआन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को टारगेट किया गया। इसी वजह से चीन के घरेलू उद्यमी जिनपिंग से खुश नहीं हैं। कई लोग जिनपिंग की अप्रत्याशित योजनाओं से परेशान हैं और गिरफ्तारी के खौफ में जी रहे हैं। यही वजह है कि चीन के शेयर बाजार का मूल्यांकन 25 साल के निचले स्तर पर है। जब तक उद्यमियों का विश्वास नहीं जीता जाएगा, तब तक इनोवेशन नहीं हो पाएंगे और सिर्फ संसाधन ही बर्बाद होंगे।

घरेलू बाजार में नहीं खर्च कर रहे लोग, वैश्विक निर्यात पर भी संकट

कंसल्टेंसी फर्म गैवेकल ड्रैगनोमिक्स के टिली झांग कहते हैं, 'चीन वास्तव में अगली औद्योगिक क्रांति का लीडर बनना चाहता है।' हालांकि जिनपिंग रणनीति में उपभोक्ताओं को नकार रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि चीन की जीडीपी में उपभोक्ता का हिस्सा सिर्फ 37% ही बचा है। यह वैश्विक मानदंडों से बहुत कम है। संपत्ति में गिरावट के लिए जिनपिंग को चाहिए कि वे लोगों का विश्वास जीतें ताकि उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दें। इसे अपनाने में जिनपिंग की अनिच्छा उनकी कठोर मानसिकता दर्शाती है।

चीन में कमजोर घरेलू मांग का मतलब है कि नए उत्पादन का निर्यात वैश्विक देशों में करना होगा। अमेरिका निश्चित रूप से चीन के आयात को रोक देगा। यूरोप चीन के बढ़ते इलेक्ट्रिक मार्केट से दहशत में है, तो वहां व्यापार भी संभव नहीं दिखता। चीनी अधिकारियों का कहना है कि वे निर्यात को ग्लोबल साउथ (उभरती इकोनॉमी) शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर उभरते देशों को लगेगा कि चीनी व्यापार उन्हें कमजोर कर रहा है तो वे भी सावधान हो जाएंगे। फिलहाल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 31% है। जिनपिंग यह आंकड़ा कितना ही बढ़ा पाएंगे?

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बदलता ट्रेंड

ब्रिटेन में हर पांचवां नागरिक किराए के घर में रह रहा है

ब्रिटेन में अब लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। यहां का हर पांचवां नागरिक किराए पर ही रह रहा है। पिछले दो दशक में ब्रिटेन में किराए पर रहने का ट्रेंड बढ़ा है। राजधानी लंदन में तो हर तीन में से एक नागरिक किराए पर रहता है। ब्रिटेन में कुल 1 करोड़ 30 लाख निजी किराएदार हैं। इसके पीछे मुख्य वजह ब्रिटेन में अपर्याप्त घरों की संख्या है। लंदन की ही बात करें तो 1930 के दशक में हर साल 62 हजार घरों का निर्माण होता था, जो अब सिर्फ 40 हजार प्रति वर्ष होता है। इसके अलावा युवाओं को किराए पर रहते देखा जाता है। लेकिन ब्रिटेन में आधे से ज्यादा किराएदार 35 से अधिक उम्र के हैं। वहीं राजधानी लंदन में 10 लाख किराएदार 55 से ज्यादा उम्र वाले हैं। लंदन ब्रिटेन का सबसे महंगा शहर है। यहां रह रहे लोग औसतन सैलरी (टैक्स से पहले की इनकम) का 40 फीसदी हिस्सा किराए पर खर्च करते हैं। जनवरी में यहां औसतन किराया 2,650 डॉलर था, जो तीन वर्षों में एक तिहाई से अधिक बढ़ गया। इसी अवधि में देश भर में लोगों की सैलरी 17.5 फीसदी ही बढ़ी।

ब्रिटेन को नई पॉलिसी की जरूरत

लंदन में किराएदारों के लिए कई समस्याएं हैं। जैसे यहां के किराएदारों की सुरक्षा कमजोर है। यहां किराएदार छह महीने या एक साल तक रहते हैं, जिसके बाद मकान मालिक बिना कोई कारण बताए केवल दो महीने के नोटिस पर किराएदारों को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, या उनका किराया बढ़ा सकते हैं। अक्सर इसका उपयोग मकानमालिक मरम्मत करने से बचने के लिए करते हैं। इंग्लैंड के राजनेता अपने पड़ोसी क्षेत्र ग्लासगो से कुछ सीख सकते हैं कि कैसे किराएदारों के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई जाए। वहां के किराएदारों को लंबे समय से लंदन के किराएदारों की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्राप्त है। स्कॉटलैंड ने 2017 में बिना किसी गलती के निष्कासन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ब्रिटेन में भी कंजरवेटिव पार्टी पिछले आठ साल से सुधार का वादा कर रही है। हाउस सेक्रेटरी माइकल गोव ने बिना किसी गलती के बेदखली पर प्रतिबंध लगाने और विवादों को सुलझाने के लिए एक कानून बनाने का वादा किया है। लेकिन ये योजनाएं भी संदेह के घेरे में हैं।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com

ट्रम्प राष्ट्रपति बने तो कई देश परमाणु हथियार बना सकते हैं

डिफेंस

ट्रम्प नाटो के साथ सहयोग को समाप्त कर सकते हैं

नाटो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकता है। 'न्यूक्लियर डिटेरेंस' यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु शक्तियां एक-दूसरे पर खुलेआम हमला न करें। इस नीति की सफलता का एक संकेत यह है कि केवल नौ देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं। नाटो की परमाणु नीति के तहत अमेरिका अपने यूरोपीय और एशियाई सहयोगियों की परमाणु सहायता करता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो वे रूस को खुली छूट दे सकते हैं। ऐसे में नाटो के उन छोटे देशों को खतरा है, जिनका रक्षा बजट कम है। इससे सभी के लिए परमाणु मुक्त होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

चुनावी बयानबाजी में ट्रम्प ने सहयोगियों को एक संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक बोझ के रूप में बताया है। फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि ट्रम्प क्या करेंगे। लेकिन उनके पुराने बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे नाटो छोड़ सकते हैं। ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी ने भी अमेरिकी कांग्रेस में महीनों तक उन बिल को रोकने की कोशिश की, जो यूक्रेन और गाजा में सहायता प्रदान करने की बात कर रहे थे।

पोलैंड से लेकर जर्मनी... सभी देश परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में हैं

ट्रम्प मानते हैं कि जो यूरोपीय देश जीडीपी के 2 फीसदी से कम हिस्सा रक्षा पर खर्च करते हैं, उन्हें इस सुरक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और इस विचार को भूल जाना चाहिए कि 'किसी एक नाटो देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला है।' पोलैंड के विदेश मंत्री रैडोस्लाव सिकोरस्की ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को हथियार देने में कमी होगी तो सहयोगी देश अपने स्वयं के परमाणु-हथियार बनाने की योजना तैयार करेंगे। जर्मनी से लेकर दक्षिण कोरिया तक के राजनेताओं ने ऐसी ही बातें कही हैं। अन्य लोग नाटो के 'यूरोपीयकरण' की बात करते हैं। इसका उद्देश्य अमेरिकी हथियारों की जगह ब्रिटेन और फ्रांस के परमाणु हथियारों को जगह देनी है। हालांकि इन देशों का संयुक्त भंडार रूस के दसवें हिस्से से भी कम है।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

पायनियर
नई दिल्ली , शनिवार, 6 अप्रैल, 2024

डा. मनमोहन सिंह
गरिमापूर्ण कार्यकाल

डा. मनमोहन सिंह ने अपने 33 वर्षीय संसदीय कॅरियर की समाप्ति बहुत गरिमापूर्ण ढंग से की। भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक शांत व महत्वपूर्ण क्षण के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में 33 उल्लेखनीय वर्षों के बाद संसद और सार्वजनिक जीवन को अलविदा कह दिया। उच्च सदन से उनकी विदाई एक उल्लेखनीय कॅरियर का अंत है जिसने राष्ट्र के आर्थिक परिदृश्य व राजनीतिक विमर्श पर अमिट छाप छोड़ी है। 26 सितंबर, 1932 को अब पाकिस्तान में स्थित पंजाब के गह में जन्मे मनमोहन सिंह की यात्रा अकादमिक अर्थशास्त्री से लेकर राजनीति के सर्वोच्च स्तर तक फैली है। यह जनता की सेवा में उनकी प्रतिभा, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र में डाक्टरेट उपाधि प्राप्त की। इसके बाद मनमोहन सिंह अकादमिक कॅरियर में आ गए और उन्होंने दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक्स जैसे सम्मानित संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। लेकिन डा. सिंह के नीति-निर्माण में आने के बाद पूरे देश का ध्यान उनकी ओर गया। 1971 में उनको भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया जहां अर्थशास्त्र में उनकी विशेषज्ञता तथा व्यावहारिक नीति-निर्माण की व्यापक प्रशंसा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर के रूप में 1982 से 1985 तक के कार्य ने उनका सम्मान और बढ़ाया। लेकिन 1990 के दशकारंभ में वित्त मंत्री के रूप में उनकी भूमिका ने सचमुच इतिहास रच दिया। जब भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब डा. मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था का

उदारीकरण कर उसे बाधा बने विनियमनों से आजाद किया तथा विदेशी निवेश के दरवाजे खोले। ऐतिहासिक उदारीकरण उपायों ने भारत के वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का रास्ता साफ कर दिया।

2004 में डा. मनमोहन सिंह ने अपने उल्लेखनीय कॅरियर में एक और अध्याय जोड़ा और वे संप्रग सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले सिख तथा पहले गैर-हिंदू थे। वे लगातार दो कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने समावेशी विकास, समाज कल्याण योजनाओं तथा ढांचागत विकास पर खास ध्यान दिया। अपने दस साल के कार्यकाल में डा. सिंह को प्रशंसा और निन्दा, दोनों का सामना करना पड़ा। समर्थकों ने जहां उनकी राजनय, आर्थिक क्षमताओं तथा सेक्युलरवाद के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, वहीं आलाचकों ने उन पर एक कमजोर नेता होने का आरोप लगाया जिस पर कांग्रेस नेतृत्व हावी था। अक्सर 'मौन मोहन सिंह' कह कर उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन डा. सिंह ने कभी सज्जनता नहीं छोड़ी, जबकि भारतीय राजनीति में यह गुण विरल होता जा रहा है। डा. मनमोहन सिंह नियमित रूप से प्रेस सम्मेलन करते थे तथा चुनौतीपूर्ण सवालों का जवाब देते थे। 2014 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी जन कल्याण के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता बनी रही। वे राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी सेवायें देते रहे तथा राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अपनी विशेषज्ञता और गहन अंतर्दृष्टि से योगदान दिया। मृदुभाषी वक्ता के रूप में डा. सिंह ने संसद को अलविदा कह दिया है जो भारतीय राजनीति में एक युग का अंत है। आलोचक भले ही उनकी राजनीतिक विरासत पर सवाल उठाएं, पर शायद ही किसी को संदेह हो कि उन्होंने भारत का आर्थिक रास्ता तथा वैश्विक महत्व तय करने में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सीखे सबक ज्यादा समृद्ध व समातापूर्ण भविष्य के लिए नीति निर्माताओं को निर्देशित करते रहेंगे।

कच्चातिबू पर संप्रभुता का सवाल

1974 में कच्चातिबू द्वीप को भारत द्वारा श्रीलंका को सौंपने पर आजकल बहस तेज हो गई है। इससे संप्रभुता पर देश के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की समीक्षा हो रही है।

प्रफुल्ल गोराडिया
(लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं)

1974 में कच्चातिबू द्वीप को भारत द्वारा श्रीलंका को सौंपने पर आजकल बहस तेज हो गई है। इससे संप्रभुता पर देश के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की समीक्षा हो रही है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि तमिलनाडु के तट से थोड़ी दूर स्थित कच्चातिबू द्वीप 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था। हालांकि, इसके बहुत पहले 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वे इस छोटे द्वीप को 'बिल्कुल कोई महत्व नहीं देते हैं।' भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 'मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचक नहीं है।' संभवत: यह कथन उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की जानकारी में भी था जिन्होंने अंतत: 1974 में इसे श्रीलंका को दे दिया। भारत की संप्रभुता पर नेहरू का दृष्टिकोण वर्तमान की तुलना में एकदम अलग भा। इसी लापरवाही भरे दृष्टिकोण के चलते नेहरू ने 1950 के दशकांत में लोकसभा में कहा था, 'यह सच है कि चीन ने अक्साई चिन में तिब्बत को सिनकियांग-वर्तमान में जिनजियांग से जोड़ने वाली सड़क बना ली है। यह सच है कि अक्साई चिन भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है, पर यहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता है।' स्पष्ट रूप से उनका संकेत इस ओर था कि इस क्षेत्र का कोई महत्व नहीं था। अपने इसी दृष्टिकोण के चलते जवाहरलाल नेहरू ने वायसराय माउंटबेटन की सलाह मान कर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाने का निर्णय किा था।

इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने यह कदम 'शेरे कश्मीर' कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए उठाया था। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के उसी क्षेत्र के 'शेर' थे जहां कश्मीरी बोलने वाले लोग रहते थे, जबकि उनका बाकी क्षेत्रों से कोई खास लेनादेना नहीं था। शेख अब्दुल्ला के करिश्मे का विस्तार पंजाबी बोलने वाले मुजफ्फराबाद व मीरपुर तक नहीं था और इसे वे अपने भावी राज्य का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। भारत की संप्रभुता तथा जम्मू कश्मीर के प्रति इसी दृष्टिकोण के कारण आज पाक अधिकृत कश्मीर-पीओके हमारे सामने है।

जब चीन ने 1962 में अरुणांचल या तत्कालीन नार्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी पर हमला बोला तो यह अधिकांश भारतीयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अपमानजनक बात थी। लेकिन 1962 की विभीषिका तथा राष्ट्रीय अपमान के जिम्मेदार तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने इस्तीफा देने की सभ्यता भी नहीं दिखाई थी। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में भारतीय क्षेत्र के दूसरे देशों द्वारा हड़पे जाने या भारतीय संप्रभुता के नुकसान को बड़ी लापरवाही से देखा जाता था। यह एक अधकचरे संप्रभु देश का लक्षण था। निश्चित रूप से उस समय हम संप्रभुता की जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे। 1776 में 'अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा' पहला ऐसा दस्तावेज था जिसने संप्रभुता को नये राज्य का आवश्यक तत्व बताया था। 1791 में बने फ्रांसीसी संविधान में कहा गया था, 'संप्रभुता एक, अविभाज्य, न देने योग्य तथा वर्णनातीत गुण है। इसका संबंध राष्ट्र से है। कोई समूह स्वयं को संप्रभु नहीं घोषित कर सकता है या कोई व्यक्ति इसे अपने लिए तोड़ नहीं सकता है।'

संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले 16वीं शताब्दी के फ्रांस में जीन बोडिन के विचार में आई थी और इसे सामन्तवाद से राष्ट्रवाद की ओर एक कदम के रूप में समझा गया था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार में कैबिनेट मंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा के उपाध्यक्ष पर कागजों का एक बंडल फेंका था जो उस समय पश्चिम बंगाल में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का विरोध कर रही थीं। उन्होंने खुलासा किया था कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय मतदाता सूचियों में शामिल कर लिया गया था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में यही महिला पश्चिम बंगाल को एक और बांग्लादेश बनने की संभावना से जरा भी चिन्तित नहीं हैं। अपने वोटबैंक का विस्तार करने के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चा बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन देते रहते थे। ममता बनर्जी आज इसी रणनीति की नकल कर रही हैं।

2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने से पहले जम्मू कश्मीर में भी घुसपैठ की यही कहानी दुहराई जा रही थी। सालों पहले संसद ने सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पास कर कहा था कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अखंड व अविभाज्य अंग है जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर-पीओके भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर पर लागू अनुच्छेद 370 पूरे 70 साल बना रहा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान था। इसके चलते जहां कोई कश्मीरी देश के किसी भी हिस्से में संपत्ति खरीद सकता था, वहीं कोई गैर-कश्मीरी कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकता था। इन सभी प्रकरणों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले सत्तारूढ़ सभी सरकारें जनता को विश्वास दिलाती थीं कि हम एक संप्रभु राज्य हैं। इन सरकारों को जम्मू कश्मीर में सबके साथ संप्रभुता का साझा करने में कोई हिचक नहीं होती थी जिसमें अलगाववादी तथा जिहादी आतंकवाद-समर्थक शामिल थे। उनको इस बात की भी चिन्ता नहीं थी कि कश्मीर के अलगाववादी पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ गलबहियां करते थे तथा इस्लामाबाद से आने वाले विशिष्ट अतिथियों से मिलने जाते थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 2014 में बनी सच्ची राष्ट्रवादी सरकार ने संप्रभुता के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया और इस जहरीले गठजोड़ का अंत कर दिया। मोदी सरकार आने के बाद और अनुच्छेद 370 समाप्त करने से पहले भी जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों तथा जिहादी आतंकी समर्थकों और पाकिस्तानी राजनयिकों के बीच यह गठजोड़ तोड़ दिया गया। इसके उलट कांग्रेस हमेशा मुस्लिम-समर्थक दृष्टिकोण अपनाती रही। यह इस बात से स्पष्ट है कि आज भी वक्फ और मुस्लिम पर्सनल ला विधि संहिता का हिस्सा बने हुए हैं। ईमानदारी से कहें तो सामूहिक रूप से वक्फ संपत्तियां भारत की सबसे बड़ी शहरी जमींदार बनी हुई हैं।

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा ताज महल तथा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा औरंगाबाद में 'बीबी का मकबरा' की मांग इस आधार पर की जाती है कि वहां कुछ कब्रे हैं। एक संप्रभु राज्य को इन सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए क्योंकि इनका संबंध अल्लाह से है जो सर्वोच्च तथा किसी देश से ऊपर है। इसी प्रकार विडंबना है कि सुन्नी पर्सनल ला ऐसे देश में अभी बने हुए हैं जिसका संविधान स्वयं को एक 'पंथनिरपेक्ष' देश घोषित करता है। मुस्लिम समुदाय की ओर से बार-बार मांगें की जाती हैं कि 'दारुल कज़ा' नामक शरीया अदालतों की स्थापना की जाए जो मुस्लिम समुदाय में विवाह, तलाक, आदि से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकें। मुस्लिम समुदाय के इन सभी तर्कों तथा अतीत की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह नतीजा निकाला जा सकता है कि भारत एक अर्ध-संप्रभु देश है। इस अवधारणा की खोज 18वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ जर्मन विधिवेत्ता जे.जे. मोज़र ने की थी। भारत में संप्रभुता की अवधारणा भी उपरोक्त फ्रांसीसी संविधान तथा 'अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा' के अनुरूप है। भारत में संप्रभुता के तत्वों का संबंध राष्ट्र से है, किसी व्यक्ति से नहीं। इसके साथ ही संप्रभुता की अवधारणा अवर्णनीय भी है। लेकिन जब तक शरीया, पर्सनल ला और वक्फ के अस्तित्व को कानून के रूप में अनुमति दी जाती है, तब तक संप्रभुता संपूर्ण होने के बजाय इसका कुछ तत्वों से साझा होगा।

भारत में 2014 से पहले मोटेतौर से संप्रभुता के बारे में यही भ्रामक स्थिति बनी हुई थी। संप्रभुता का साझा किसी अन्य से नहीं हो सकता है। अनेक मुस्लिम देशों ने अपने वक्फों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। सौभाग्य से भारत में 2014 के बाद ऐसी सरकार आई है जिसका विश्वास संपूर्ण राष्ट्रीय संप्रभुता में है और वह इसी दृष्टिकोण पर कठोरता से अमल करते हुए आगे बढ़ रही है।

महिला मतदाता निर्णायक भूमिका: मोदी और महिला सशक्तीकरण

-डॉ. सौरभ मालवीय

"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नारी शक्ति को अधिक से अधिक अवसर देना अत्यंत आवश्यक है"

2024 लोकसभा चुनाव सिर पर है। इस बार भी चुनाव में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे के साथ- साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर चुनाव प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण आशा है कि उसे महिलाओं का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इसके अनेक कारण हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दस वर्ष के शासन काल में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किए, अपितु उनके मान- सम्मान को भी विशेष महत्व दिया। वे दावे से कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण - ये मोदी की गारंटी है। उनका कहना है कि मोदी ने बहन- बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी। वह पूर्ण हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को तीन तलाक की कुरीति से मुक्ति दिलाने की गारंटी भी दी थी। ये गारंटी भी मोदी ने पूर्ण की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के कार्यों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए सदैव से ही प्रतिबद्ध रही है। मोदी सरकार ने समय- समय पर दोहराया है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी प्रयास का ही परिणाम है। सितम्बर 2023 पारित यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। इसके पारित होने से महिलाओं की एक लम्बित मांग पूर्ण हुई है। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने केवल टाल- मटोल का व्यवहार ही किया था। उन्होंने इस विधेयक को लेकर केवल महिलाओं के वोट हथियाने का ही प्रपंच रचा। उन्होंने इस संबंध में कभी गंभीरता से कार्य नहीं किया। किन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस विधेयक के संबंध में पूर्ण निष्ठा एवं गंभीरता से कार्य किया तथा इसे पारित करवाया। इसी प्रकार बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम महिलाओं के हित में भी निर्णय लेते हुए उन्हें तीन तलाक की कुरीति से मुक्ति दिलवाई। इस पर भी उन्हें निशाना बनाया गया, परन्तु उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मुस्लिम बहनों के हित में निर्णय लिया। इन सब निर्णयों के कारण ही महिलाओं में मोदी सरकार विशेषकर श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसीलिए उन्हें महिलाओं का भरपूर जनसमर्थन प्राप्त होता रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नारी शक्ति को अधिक से अधिक अवसर देना अत्यंत आवश्यक है। भाजपा सरकार के प्रयास से आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। मोदी सरकार महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार आदि से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए युद्धस्तर पर शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। इससे एक ओर महिलाओं को मान मिल रहा है, दूसरी ओर उन्हें अपराधों से भी मुक्ति मिल रही है। महिलाएं शौच के लिए अंधेरे में ही निर्जन स्थानों पर जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अपराधी तत्वों का शिकार बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त समय पर नित्य कर्म से न निपटने के कारण वे अनेक रोगों की भी चपेट में आ जाती हैं। किन्तु शौचालयों के निर्माण से उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल रहा है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार देश में विगत नौ वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्ति मिली है।

वास्तव में मोदी सरकार महिलाओं के हित के अनेक कार्य कर रही है। वह उनकी प्रत्येक छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रख रही है। महिलाओं का स्वप्न होता है कि उनका भी अपना निजी मकान हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार निर्धन लोगों को पक्के आवास उपलब्ध करवा रही है। इनके पंजीकरण में महिलाओं का नाम सम्मिलित किया जा रहा है। इसके कारण अब महिलाएं भी अपने घर की स्वामिनी बन रही हैं। उनका स्वयं के घर का स्वप्न पूर्ण हो रहा है। इतना ही नहीं मोदी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी तीव्र गति से कार्य कर रही है। महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार अर्जित करने के लिए ऋष्टा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे वे कुटीर उद्योग चालू कर रही हैं। जो महिलाएं सिलाई का कार्य जानती हैं तथा उनके पास सिलाई मशीन क्रय करने के लिए धन नहीं हैं उन्हें निशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की जा रही हैं। ये महिलाएं अब घर पर ही सिलाई का कार्य करके धन अर्जित कर रही हैं। आत्मनिर्भरता के कारण उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब वे अपनी इच्छा से अपना धन व्यय कर रही हैं। उनके जीवन यापन की शैली में परिवर्तन आया है। यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महिला हितैषी योजनाओं का ही परिणाम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि भारत की नारी शक्ति, विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते दस वर्षों में बीजेपी सरकार ने निरंतर कार्य किया है। जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं। इन दस वर्षों में देश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की संख्या दस करोड़ को पार कर गई है। देश में दस वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए आठ लाख करोड़ रुपए की सहायता बैंकों से दिलवाई गई है। श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में कहा था कि आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें देश की नारी- शक्ति पीछे रह गई हो। एक और क्षेत्र, जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वह है- प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता। केमिकल से हमारी धरती मां को जो कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है - हमारी धरती मां को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने- कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही हैं। आज अगर देश में 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। इसके अलावा भी बहनें-बेटियां, जल संरक्षण के लिए चौतरफा प्रयास कर रही हैं।

मोदी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सशक्तिकरण के लिए किए गये कार्यों की सफलता ही है कि आज महिलाएं आत्मविश्वास के साथ निर्भीक होकर घर से बाहर जाकर कार्य कर रही हैं। कहा जाता है कि महिला मतदाता साइलेंट वोटर होती हैं। महिला मतदाता जिस दल को अपना समर्थन देती हैं, उसे ही बहुमत प्राप्त होता है तथा सरकार उसी दल की बनती है। विशेष बात है कि भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध विरोधियों द्वारा दुष्प्रचार करने के पश्चात भी मुस्लिम महिलाएं इन्हें अपना भरपूर समर्थन दे रही हैं। इस बार यह देखना अत्यंत रोचक होगा कि महिलाएं उन्हें कितना समर्थन देती हैं।

उनका कहना है कि उन्हें उन निर्णयों पर गर्व है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि उनका तृतीय कार्यकाल भी विकास एवं महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहेगा।

आप की बात

विपक्ष की चुनौतियां

भाजपा की प्रगति को देखते हुए विपक्ष की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। विपक्षी दलों में संगठन और राजनीतिक विचारधारा की कमी के कारण वे भाजपा के खिलाफ विरोध की रणनीति बनाने में विफल हो रहे हैं। विपक्ष को ध्यान में रखना होगा कि केवल भाषण देकर ही वे चुनाव नहीं जीत सकते। उनको भी सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए जो समाज के हित में हो। विपक्ष को समय पर विचारशील और सकारात्मक रणनीतिक उपाय करने की आवश्यकता है ताकि वे भाजपा के खिलाफ प्रभावी विरोध विकसित कर सकें। विपक्ष को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे कि वे आम जनता की समस्याओं का हल प्रस्तुत कर सकें। विपक्ष की चुनौतियां उसकी दिशाहीनता तथा पुरानी जातिवादी, वंशवादी व विघटनवादी सोच के कारण हैं। आज का नौजवान देश की प्रगति के बारे में आशा से भरा है और विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प तैयार करने की स्थिति में नहीं है। भ्रष्टाचार के भयानक आरोपों में फंसे, जेल के सीखचों के पीछे या जमानत पर रिहा विपक्षी नेता जनता से हमदर्दी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके ये प्रयास सफल होने वाले नहीं हैं। इसलिए अनेक विपक्षी दलों के सामने अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

योगी आदित्यनाथ का बयान

अयोध्या में राम आज भव्य रूप में आ गए हैं। अत: अयोध्या व काशी के बाद अब प्रदेश सरकार का पूरा फोकस मथुरा वृंदावन पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ मामले न्यायालय में लंबित है। इससे कुछ देरी हो रही है वरना मथुरा में कृष्ण मंदिर को भव्यता प्रदान करने की हमारी पूरी तैयारी है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से पूछा कि क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा, बसपा या कांग्रेस ने किया है? वे तो रामभक्तों पर गोलियां चलवाते थे। उनके समय अयोध्या में कुछ भी विकास नहीं हुआ मगर अब अयोध्या जाने वालों के मन में वहां के वर्तमान दृश्य देखकर त्रेता युग की कल्पना पैदा होती होगी। भाजपा, जनसंघ, आरएसएस व अन्य हिंदुत्ववादी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि मुसलमानों को हिंदू आस्था के तीन केन्द्र-अयोध्या, काशी और मथुरा उनको सौंप देने चाहिए ताकि समाज को अन्य परिवर्तित धर्मस्थलों के बारे में शांति धारण करने के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन विडंबना है कि ऐसा नहीं हुआ। अब भी समय है कि देश की पंथनिरपेक्ष पार्टियां तथा मुस्लिम संगठन देश की बहुसंख्य व सच्चे मन से पंथनिरपेक्ष हिंदू जनता की भावनाओं के अनुकूल व्यवहार करें।

- **एमएम राजावत,** शाजापुर

मोदी का मंत्र

मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर देश के स्वर्ग कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे देश व देशवासियों को राहत दिलाई है। मोदी का 370 का मिशन मंत्र चुनावी शंखनाद के साथ आरम्भ हो गया है। उन्होंने कहा है कि 370 के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमारे हर कार्यकर्ता को हर बूथ पर पिछले लोकसभा चुनाव से 370 वोट अधिक लाने होंगे। मोदी मन्त्र के अनुसार कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण तक प्रत्येक चुनावी बूथ पर कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करके पिछली बार से इस बार 370 वोट अधिक लाएं ताकि अबकी बार हम आसानी से 400 सांसदों की संख्या पार कर लें। वैसे भी कंकड़ पत्थर जोड़ कर भानुमती का कुनबा बनाने वाला विपक्ष लगातार बिखरता जा रहा है। चुनाव निकट आने के साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में निराशा बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र के तेजतर्रार नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस में पांच सत्ता केन्द्र होने का दावा किया है। अब यदि कांग्रेस प्रियंका के पति और सोनिया के दामाद को अमेठी या रायबरेली से मैदान में उतार देती है तो उसकी छवि एकदम मिट्टी में मिल जाएगी। शायद यह भगवान राम का प्रताप है कि मोदी-विरोधियों की बुद्धि नष्ट हो गई है और वे दारुण दु:ख की ओर बढ़ रहे हैं।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

राजनीतिक कलह

लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीखें निकट आने के साथ ही राजनीतिक गठबंधनों के बीच का अंदरूनी कलह बंद कमरे से बाहर निकल कर सड़कों पर आता जा रहा है। महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले एकदम नई तरह की परिस्थितियां सामने आ गई है। महाअघाड़ी में शामिल शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद तो प्राप्त कर लिया है। मगर उसके बाद अजीत पवार गुट के सत्ता में शामिल होने से उनकी अहमियत घटती जा रही है। चूंकि बीजेपी की पूरे महाराष्ट्र पर अच्छी पकड़ है इसलिए वह अपनी शर्तों पर सहयोगी दलों को सीटें आवंटित कर रही है। इसे लेकर एनडीए में शामिल कुछ नेता कसमसा रहे हैं। मगर अब इतना वक्त नहीं बचा है कि वह स्वतंत्र रूप से अपना दम-खम दिखा सके। बीजेपी कुछ अन्य प्रदेशों में भी अच्छी स्थिति में है जहां एनडीए की सरकारें नहीं हैं। इसके चलते वह आधिकाधिक सीटों पर अपने अनुकूल लोगों को टिकट वितरण कर रही है। इस प्रकार एनडीए फिर भी बेहतर स्थिति में है। ऐसे में नाम वापसी के बाद भी 4 जून को नतीजों की प्रतीक्षा बनी रहेगी।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 6 अप्रैल 2024

OPS पर बदला रुख?

विपक्षी दल ने साफ की वैकल्पिक दिशा

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणापत्र जारी कर उन प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट किया, जहां उसके मुताबिक सत्ता पक्ष का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है और अगर मतदाताओं ने मौका दिया तो सत्ता में आने पर वह उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। इस लिहाज से कांग्रेस के इस 'न्याय पत्र' की कुछ बातें खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं।

कास्ट सेंसस | जातिगत जनगणना इस घोषणापत्र का अहम हिस्सा है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी परीक्षा होनी है। माना जा सकता है कि अगर इस बार की वोटिंग में इस मुद्दे की खास भूमिका नहीं दिखती है तो बहुत संभव है कि आने वाले दौर में आरक्षण जैसे मुद्दे की राजनीतिक अहमियत कम होती नजर आए।

कांग्रेस का घोषणापत्र

विकास का दावा | घोषणापत्र में कहा गया है कि 10 वर्षों का NDA शासन 10 साल के UPA राज के मुकाबले विकास दर की कसौटी पर कमजोर साबित हुआ है। यह केंद्र की BJP सरकार के डिवेलपमेंट के नैरेटिव को चुनौती है। इन परस्पर विरोधी दावों की प्रामाणिकता के सवाल में उलझे बगैर यह देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि मतदाता किसके दावे पर अपनी मुहर लगाते हैं। हालांकि, कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और BJP, दोनों ही ओर से लोकलुभावन वादे हुए थे। तब अधिक लोगों का झुकाव केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर दिखा।

OPS पर चुप्पी | कल्याणकारी घोषणाओं पर जोर देने के बावजूद कांग्रेस का यह घोषणापत्र ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर चुप्पी साधे हुए है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का इस पर जोर था। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मिली कामयाबी के पीछे इस वादे की भी भूमिका बताई गई थी। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों की राय थी कि यह वित्तीय समझदारी के खिलाफ है। ऐसे में कांग्रेस ने अगर सोच-समझे ढंग से इस मुद्दे पर कदम पीछे खींचने का जोखिम उठाया है तो इसकी सराहना होनी चाहिए।

विवादित मुद्दे | सत्तारूढ़ BJP की नीतियों से खुद को अलग दिखाने के प्रयास में पार्टी ने उन विवादित मुद्दों से भी परहेज नहीं किया है, जो खास तौर पर हाल के वर्षों में राजनीतिक और चुनावी लिहाज से हानिकारक करार दिए जाने लगे हैं। उदाहरण के लिए पार्टी ने खानपान, वेशभूषा, भाषा और पर्सनल लॉ के मामले में अल्पसंख्यकों समेत सभी नागरिकों के लिए चयन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात खास तौर पर कही है।

वैकल्पिक दिशा | कुल मिलाकर, मुख्य विपक्षी दल के इस घोषणापत्र को इस मामले में साहसिक कहा जाएगा कि इसने नीतियों की वैकल्पिक दिशा स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब इस पर वह वोटरों को कैसे और किस हद तक आश्वस्त कर पाती है यह देखने वाली बात होगी।

अंतर्दृष्टि

ताकि आपका मूड बना रहे बदस्तूर बेमिसाल

सुंदर चंद ठाकुर

अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या रहता है? आप सहज ही कहेंगे कि हम सब कुछ अपनी खुशी के लिए करते हैं। अगर हम खुद को तकलीफ भी देते हैं, तो वह खुशी के लिए ही होता है। अगर कोई जिम में जाकर भारी वजन उठाने की पीड़ा सहता है, तो वह भी अपनी खुशी के लिए ही करता है। कोई छात्र पूरी एकाग्रता के साथ घंटों तक पढ़ाई करने का कष्टसाध्य काम करता है, तो वह भी अपनी खुशी के लिए ही करता है। अगर हम नौकरी के लिए खून-पसीना एक करते हैं, तो यह भी खुशी के लिए ही करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम किन वजहों से खुश होते हैं? जब तब आपके दिमाग में और आपके गट में खुशी के हार्मोंस रिलीज नहीं होते, आप खुश नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपका मकसद खुश होना है, तो आप इन चार हार्मोंस को ठीक से समझ लें कि ये क्या काम करने से रिलीज होते हैं और फिर सुनिश्चित करें कि आप वे सभी कार्य नियमित करते रहें।

सबसे पहला हार्मोन है डोपामीन। इसे फील गुड और रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं। जब भी आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसे हासिल करने पर इनाम के तौर पर आपको यही होर्मोन मिलता है। आप जब भी आनंद देने वाले काम करते हैं, जैसे पसंदीदा भोजन करना या एक्सरसाइज करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, संगीत सुनते हैं, तो इन कामों को करते हुए भी दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और आपको खुशी जैसी महसूस होती है। आप जो बार-बार मोबाइल देखते हो और किसी पसंद के व्यक्ति का कमेंट पढ़ते हो, लाइक देखते हो, तो भी आपका माइंड डोपामीन रिलीज करता है। दूसरा हार्मोन है सिरोटोनिन, जिसे मूड रेग्युलेट करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ये लेकिन हार्मोन दिमाग में नहीं, हमारी गट यानी आंत में रिलीज होता है। यह हमारे मूड को सही करता है, हमें भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरता है और हमारी नींद को भी बेहतर बनाता है। हेल्दी और संतुलित भोजन लेने, प्रकृति के बीच लंबे वॉक पर जाने, धूप लेने और ध्यान में बैठने से सिरोटोनिन रिलीज होता है। तीसरा खुशी का हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। इसे प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें सुरक्षा और सामीप्य की फीलिंग देता है और भरोसे को बढ़ाता है। अगर आप अपने जीवन में खुशी के इस हार्मोन को चाहते हैं तो आपको जीवन में प्रेम को जगह देनी होगी, दोस्तों से अपनत्व को बढ़ाना होगा, करीबियों के गले लगना-लगाना होगा, अपने प्रियजनों का हाथ पकड़ना होगा। जीवन में लंबे समय के लिए खुशी चाहिए, तो आपके लिए यह काम ऑक्सीटोसिन ही करेगा। खुशी के लिए चौथा जरूरी हार्मोन एंडोर्फिंस है। इसका काम आपके दर्द को कम करना होता है। एक तरह यह शरीर द्वारा प्राकृतिक तरह से पैदा किए जाने वाला पेनकिलर है। दर्द कम करने के अलावा यह स्ट्रेस को भी कम करता है और अच्छा होने की फीलिंग को बढ़ाता भी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, हंसते हैं, संगीत सुनते हैं और डार्क चॉकलेट खाते हैं, तो ऐसा करके आप अपने शरीर में एंडोर्फिंस को ही बढ़ाते हैं।

अगर आप चारों हार्मोंस को किसी एक एक्टिविटी की मदद से रिलीज करना चाहते हैं, तो वह है शारीरिक व्यायाम। ऐसा व्यायाम जिससे आपको शरीर को हिलाना पड़े, पसीना निकले। अगर आप यह सुनिश्चित कर सकें कि रोज सुबह उठने के बाद आप एक-डेढ़ घंटे योग, रनिंग, जिम वर्कआउट आदि जैसे काम करें और शरीर का पसीना निकालें, तो इस तरह आप अपने दिमाग और आंत में खुशी के इन हार्मोंस को रिलीज करवाएंगे और जब खुशी-खुशी आप अपने काम करेंगे, तो काम पर ज्यादा सहजता से फोकस कर पाएंगे। इस तरह एक सकारात्मक घटनाओं का चक्र आपके कदमों के आगे खुलता हुआ आपको एक हेल्दी और हैपी जिंदगी की ओर ले जाएगा। आपका मूड भी बदस्तूर बेमिसाल बना रहेगा।

ऑफ दि ट्रैक

पौधे वाला प्लास्टिक है न

दिलीप लाल

पर्यावरण को संकट में डालने में प्लास्टिक की बड़ी भूमिका है। अनुमान है कि सालाना 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसका केवल दसवां हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी समुद्रों में पहुंच जाता है या मिट्टी को प्रदूषित कर फूड चेन के जरिए मनुष्य सहित तमाम जीवों को बीमार करता है। प्लास्टिक कचरा जब पर्यावरण के संपर्क में आता है, तो यह छोटे कणों में टूट जाता है जिनका आकार 5 मिमी से कम होता है। इन कणों को हम माइक्रोप्लास्टिक के तौर पर जानते हैं। इंग्लैंड की Portsmouth यूनिवर्सिटी और बेल्जियम के मरीन इंस्टिट्यूट के एक हालिया रिसर्च से यह सुकून भरी जानकारी मिली है कि पौधों से तैयार होने वाला प्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक से नौ गुना कम माइक्रोप्लास्टिक छोड़ता है। पौधे से तैयार होने वाले प्लास्टिक को बायोप्लास्टिक या बायोबेस्ड प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। इसके स्रोत शैवाल, गन्ना या खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल हैं। पारंपरिक प्लास्टिक का 99% स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन हैं। इसका अर्थ है कि आज हम जिस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं वह कचरा बनने से बहुत पहले ही हमारे ग्रह को बर्बाद करना शुरू कर देता है। एक दशक से पहले ही पौधे-आधारित प्लास्टिक पर चर्चा शुरू हो गई थी और वर्ष 2012 में हुई एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में यह निष्कर्ष निकला था कि पारंपरिक प्लास्टिक का यह विकल्प प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य सबके लिए बेहतर है और इसका उपयोग जहां तक हो सके, बढ़ाना चाहिए। ताजा शोध ने इस निर्णय को नई दिशा दी है।

ऊंचे रिटर्न का लालच देकर आम लोगों को चूना लगा रहे हैं ठग

आज के नटवरलालों से कैसे बचें

उमेश्वर कुमार

शेयर बाजार में तूफानी तेजी है, जिसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती को बताया जा रहा है। GDP की रफ्तार 8% के दायरे में है। देशी-विदेशी रेटिंग एजेंसियां सिरे से इसकी तस्दीक कर रही हैं। रिजर्व बैंक का भी आकलन इसी के अनुरूप है। ऐसे में बड़ी कंपनियों के साथ छोटी कंपनियों के शेयर भी तेजी की लहर पर सवार हैं।

बेतहाशा रिटर्न का दावा : आजकल सोशल मीडिया पर कथित सलाहकारों की फौज खड़ी हो गई है। गजब के दावे हैं इनके, कोई दैनिक आधार पर 20% की रिटर्न का सब्जबाग दिखा रहा है, तो कई 60% मासिक कमाई की एक तरह से गारंटी दे रहे हैं। फेसबुक, वट्सऐप और टेलीग्राम पर इस तरह के ग्रुप्स की बाढ़ आ गई है। इनमें से कुछ के नंबर तो देश के हैं, लेकिन अधिकांश विदेश के।

निवेशकों को फंसाने वालों की एक कैटिगरी ऐसी है, जो सलाह के नाम पर ठगी के लिए उतरी है। ये पहले निवेशकों को लुभाकर शुरुआती सौदों में उन्हें फायदा भी कराते हैं। जब निवेशक उन पर भरोसा करने लगता है, तब वे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उन्हें निवेश कराते हैं और फिर उनकी रकम लेकर गायब हो जाते हैं।

दूसरी कैटिगरी है अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर शेयर के दाम को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने वालों की। भारतीय शेयर बाजार में 'ऑपरेटरों' का यह खेल बरसों से चलता आया है। शायद कुछ लोगों को याद हो कि हर्षद मेहता के समय में एक कंपनी होती थी सिल्वरलाइन। 5-7 रुपये के इसके शेयर को 1300 रुपये के पार ले जाया गया, बाद में तीन रुपये में भी इसका कोई लेनदार नहीं था। अब तो कंपनी का नामोनिशान तक मिट गया है। इस तरह का खेल सैकड़ों कंपनियों के साथ हुआ।

कैसे होता था यह खेल? इसमें कंपनी एक छोटे ब्रोकर समूह को शेयर का भाव बढ़ाने का ठेका देती थी। इनकी बाजार के इन्फ्लुएंसर्स से मिलीभगत होती थी। तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जिस कंपनी के शेयर में खेल करना होता था उसके शेयर समूह से जुड़े लोग कम भाव पर पहले ही भारी मात्रा में खरीद लेते थे। फिर कंपनी से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें बाजार में फैलाई जातीं। आम निवेशक अक्सर इस झांसे में आकर इनके शेयर खरीद लेते थे। जब दाम काफी ऊपर चला जाता तब समूह के शातिर अपने शेयर बेचकर निकल जाते और छोटे निवेशक इस जाल में फंसकर अपनी रकम गंवा बैठते।

ऐसा खेल तब ज्यादा होता था, जब बाजार में तेजी हो। ऐसे शेयरों की एक और पहचान यह है कि जब ये चलाए जाते हैं, तब इन पर लगातार कई दिनों तक अपर सर्किट लगता रहता है। जिस दिन सर्किट खुलता है, तब रिटेल निवेशक इनमें निवेश करते हैं। फिर कुछ और चढ़ने के बाद ऑपरेटर उनमें मुनाफावसूली करने लगते हैं। उस वक्त शेयर में लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू होता है। इसलिए समय की कसौटी पर खरे उतरे अच्छी और मजबूत कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए। बाजार में फंसने का मूल कारण लालच है और नटवरलाल ने भी कहा था कि जब तक लोगों में लालच है ठग भूखे नहीं मरेंगे।

AI Image

आजमाते हैं नए-नए तरीके

- सोशल मीडिया के युग में बढ़े ठग शेयर सलाहकार
- निवेशकों को फंसाने वाले कई हथकंडों का इस्तेमाल
- ऑपरेटरों के जाल से बचें, जो शेयरों तेजी लाते हैं

आज बाजार तेजी में है और ठगों के पास सोशल मीडिया जैसा शानदार मीडियम है। इनमें अधिकांश तो छुटभैये हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम भी हैं, जिनके सदस्यों की संख्या मिलियन में है। सोचिए इनके लिए किसी शेयर के दाम में तेजी लाना कितना आसान है। एक तरह से वैसा ही खेल चल रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया के आने से पहले चला करता था।

अब सवाल है कि आम निवेशक को क्या करना चाहिए:

- सबसे पहले तो शेयर अपने चुने हुए प्लेटफॉर्म से अपने डीमैट खाते में खरीदें, भले ही उसकी सलाह कहीं से मिली हो। इससे आप उन ठगों से बच जाएंगे जो निवेश का झांसा देकर गायब हो जाते हैं।
- निवेश करने से पहले संबंधित कंपनी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें। अगर आपके पास इसके लिए समय या सूझबूझ नहीं है तो BSE और NSE के विभिन्न इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों में निवेश कीजिए। ये स्थापित कंपनियां होती हैं। इसलिए इनमें तुलनात्मक रूप से जोखिम कम होता है।
- शेयर बाजार निवेश के लिए है न कि सट्टेबाजी के लिए। सलाहकारों की जो फौज अभी मैदान में उतरी है, वह एक तरह से सट्टेबाजी के लिए प्रेरित कर रही है। निवेश 10 या 15 दिनों के लिए नहीं होता। अपने निवेश की अवधि तय करिए और फिर अच्छी गुणवत्ता वाले शेयर खरीदिए।
- अभी बाजार तेज है क्योंकि अर्थव्यवस्था की रेटिंग अच्छी है। सोना ऑल टाइम हाई पर है। इसके कारण अलग हैं। अमेरिकी ब्याज दरों में गिरावट का आकलन है और आशंका है कि वैश्विक मंदी पसर सकती है। दुनियाभर में सोना को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसलिए सोने में निवेश बढ़ा है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर मंदी की आहट और अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी। एक तरह से विरोधाभासी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और शेयर बाजार को विरोधाभास पसंद नहीं। ऐसे में और भी अधिक सतर्कता के साथ निवेश की जरूरत है।
- एक बात और फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। सेबी से लगातार यह चेतावनी आती है कि इस तरह की ट्रेडिंग में 10 में से 9 निवेशक घाटे में रहते हैं, इनमें निवेश न करें।

इस आलेख का मकसद आपको शेयर बाजार से डराना नहीं है बल्कि सावधान करना है। जोखिम कहां नहीं है, कमाई करनी है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा लेकिन जोखिम को जानकर और समझदारी के साथ, ठगों के जाल में फंसे बगैर उठाएं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्या है हवाना सिंड्रोम

अमेरिका की राजनीति में 'हवाना सिंड्रोम' का भूत फिर उठ खड़ा हुआ है। कुछ नई जानकारी सामने आने के बाद गुत्थी और उलझती दिख रही है। क्या है यह रहस्य और क्या इससे कभी उठ पाएगा पर्दा?

AI image

कानों में सीटी, सिर में दर्द

हवाना सिंड्रोम कई सारे लक्षणों का समूह है। इसमें कानों में अचानक तेज आवाज बजती है, नींद उड़ जाती है। सिरदर्द और मितली, साथ में मेमरी लॉस भी देखी गई। 2016 में क्यूबा के हवाना में सबसे पहले अमेरिकी राजनयिक इसका शिकार बने थे।

क्या रूस की साजिश?

कोल्ड वॉर के समय से ही अमेरिका और रूस के बीच जंग का मैदान रहा है क्यूबा। ऐसे में माना जा रहा कि इसके पीछे रूस की साजिश है। कनाडा के कुछ डिप्लोमैट भी इससे प्रभावित हुए हैं। हवाना सिंड्रोम के पीड़ितों की संख्या करीब 1000 है।

कार वाले का कनेक्शन

जून 2020 में फ्लोरिडा में एक रूसी नागरिक Vitalii Kovalev को गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगा कि वह रूस का एजेंट है। उससे FBI एजेंट्स ने पूछताछ की थी। उनमें से एक एजेंट ने पिछले दिनों खुलासा किया कि Kovalev से पूछताछ के कुछ वक्त बाद उसे हवाना सिंड्रोम के लक्षणों जैसी तकलीफ से गुजरना पड़ा। Kovalev की मौत हो चुकी है।

क्या बायलॉजिकल अटैक है?

निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ थिअरी हैं कि किसी सीक्रेट वेपन के जरिये अमेरिकी अफसरों को निशाना बनाया जा रहा। यह वेपन माइक्रोवेव या फिर अल्ट्रासाउंड की हाई-एनर्जी बीम छोड़ता है, जिसका असर सीधे दिमाग पर होता है। कुछ रिसर्चर्स ने Psychogenic और Environmental फैक्टर्स को भी संभावित कारण माना है।

डिप्लोमैसी पर असर

रूस के अलावा कुछ एक्सपर्ट चीन का भी नाम ले रहे इस केस में। इन दोनों ही देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते इस समय बेहद खराब दौर में हैं। ऐसे में हवाना सिंड्रोम को लेकर लगाए गए आरोपों से बात और बिगड़ेगी। क्यूबा ने तो पूरे मामले को लेकर अमेरिका की आलोचना की है। FBI और दूसरी अमेरिकी एजेंसियों पर किसी नतीजे तक पहुंचने का दबाव पड़ रहा है

जेल जाने वाली औरतों को छोड़ देती है फैमिली

जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और शिक्षाविद सुधा भारद्वाज ने अपनी चर्चित जेल यात्रा के दौरान एक किताब लिखी 'फांसी यार्ड'। जेल की महिला कैदियों पर केंद्रित इस किताब को टाइम्स ग्रुप के AutHer Awards 2024 से नवाजा गया है। सुधा भारद्वाज से इस किताब, इसे लिखे जाने के हालात और इसके पीछे के मकसद पर ***नाइश हसन*** *ने बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश :*

सप्ताह का इंटरव्यू

सुधा भारद्वाज

■ अपनी किताब का नाम आपने 'फांसी यार्ड' रखा है। इस नाम की कोई खास वजह...

मैं लगभग सवा तीन साल पुणे की यरवदा जेल और मुंबई की भायखला जेल में रही। यरवदा जेल में एक फांसी यार्ड है, वहां अलग-अलग सेल हैं, बैरक नहीं है। ऐसे समझिए कि चार सेल हैं, उसके अंदर एक पिंजरानुमा जगह है। वह पिंजरा वहां फांसी यार्ड कहलाता है। वहां फांसी की सजा पाई दो बहनें करीब 24-25 साल से रह रही थीं। उन्हीं के साथ हमें रखा गया। जब मैंने वहां बैठकर औरतों की कहानियां लिखनी शुरू कीं तो मुझे इससे अच्छा कोई नाम नहीं लगा।

■ अक्सर देखा जाता है कि जब पुरुष कैदी ट्रकों में भरकर पेशी पर लाए जाते हैं तो उनकी पत्नियां ट्रक के पास आकर उनके लिए बीड़ी, तंबाकू, खाने का डिब्बा लेकर खड़ी रहती हैं, लेकिन जब वे औरतें जेल में होती हैं तो उनके पति या घर वाले उन्हें लगभग त्याग देते हैं। उनसे मुलाकात करने तक कोई नहीं आता। आप की कहानियों में ऐसी औरतें भी हैं। इन महिलाओं के बारे में क्या कहेंगी आप?

जी, मैंने ऐसी बहुत सी महिलाएं देखीं। अगर मामूली अपराध में भी वे जेल आ गईं तो उन्हें परिवार सबसे पहले तिरस्कृत करता है। उनसे कभी कोई मुलाकात करने, उनकी खोज0खबर लेने भी नहीं आता। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन महिलाओं के पुनर्वास का काम गंभीरता से किया जाए जिससे वह वापस लौटकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे अभी सही ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा है।

■ और जिन महिला कैदियों के बच्चे हों, उनका क्या हाल होता है?

नियम यह है कि बच्चे 6 साल से ज्यादा जेल में नहीं रह सकते। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म ही जेल में होता है। उन्होंने तो औरतों के अलावा कोई मर्द देखा ही नहीं होता। किसी नाते-रिश्तेदार से उनका परिचय नहीं होता। ऐसे में जब उन्हें 6 साल बाद उनकी मां से अलग किया जाता है तो मां और बच्चा दोनों के लिए यह बड़ा दुखद होता है।

■ आपने यह भी लिखा है कि जेल में जेंडर आधारित भेदभाव बहुत ज्यादा है। किस तरह के होते हैं ये भेदभाव?

जेल में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, वह बहुत ही खराब होता है। मर्द अपराधियों से कहीं ज्यादा बुरी नजरों से उन्हें देखा जाता है, चाहे वे अपने पति के कारण ही जेल पहुंची हों। उसे कोई नहीं समझता, इसलिए भी औरत को वहां कुछ ज्यादा ही भुगतना पड़ता है।

■ आप एक जगह लिखती हैं कि वहां औरतों को कानूनी सहायता मिलना मर्दों के मुकाबले मुश्किल होता है, ऐसा क्यों ?

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिवार ही औरत को तिरस्कृत कर देता है। बिना परिवार की कोशिशों के कानूनी सहायता मिल पाना मुश्किल होता है। लीगल एड (legal aid) के जो वकील हैं, वे औरतों के केस को प्राथमिकता नहीं देते। वे अपने क्लाइंट से पूछने भी नहीं आते कि आपका क्या पक्ष है, अक्सर इन औरतों को पता ही नहीं होता कि उनके केस में क्या चल रहा है। यहां तक कि वे इस बात से भी अनजान होती हैं कि उनकी कब पेशी है, उनकी बेल एप्लिकेशन लगी है या नहीं लगी है।

■ आप खुद इतनी परेशान थीं तो इस किताब का आइडिया कैसे आया?

देखिए, मैंने जो 76 छोटी कहानियां लिखी हैं, ये सब ऐसे ही लिखी गईं कि जब भी मौका मिला बातचीत का, कर ली और उसे लिख लिया। मैं जब बाहर निकली तो उस दस्तावेज के साथ निकली। कुछ लोग दुआ/प्रार्थना से अपना समय काटते थे, मैं लिख कर अपना समय काटती थी।

> “ legal aid का काम भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह काम जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। जरूरी है कि इस तरह का केस लड़ने वाले वकील खुद को लीगल एड सिस्टम के साथ ही क्लाइंट के प्रति भी जिम्मेदार समझें, चार्जशीट बने तो क्लाइंट को बताएं कि उसमें क्या लिखा है। उनसे निरंतर संवाद बनाए रखें

■ जिन औरतों की जिंदगियों को वहां आपने नजदीक से देखा और अपनी किताब में दर्ज किया, उन औरतों के लिए कुछ करने का प्लान रखती हैं?

हंसते हुए.... क्यों नहीं। अभी भी मैं जितना कर सकती हूं, करती हूं, आगे भी करूंगी। कुछ लोग वहां से चिट्ठी लिख कर मदद मांगते हैं, उन लोगों की बेल कराने, उन्हें अच्छे वकील दिलवाने की मैं आज भी पूरी कोशिश कर रही हूं।

■ आपकी निगाह में कैदियों की लीगल एड में अभी क्या बदलाव आना जरूरी है?

पहली बात तो यह कि लीगल एड वकीलों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। यह अभी नाकाफी है। इसके अलावा लीगल एड को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लीगल एड वकील अपने को लीगल एड सिस्टम से ज्यादा क्लाइंट के प्रति जिम्मेदार समझें।

■ आपने अमेरिका से शिक्षा ली, IIT से गणित की पढाई की, फिर वकील बनीं। 2013-14 में जब आपको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद मिलने की बात उठी तो उसे भी आपने ठुकरा दिया, ऐसा क्यों?

देखिए, लोगों को ये बातें बड़ी एक्साइट करती हैं लेकिन मेरे लिए यह स्वाभाविक था। मैं चालीस साल की उम्र में वकील बनी। मुझे मजदूरों ने वकील बनाया। उनके पास वकील नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वे एक अच्छा वकील रख पाते जो कॉरपोरेट वकीलों को टक्कर दे सके। बेंच में और बार में दोनों तरफ अच्छे लोगों की जरूरत है। मजदूरों ने इसी तरफ रहने के लिए मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं इस तरफ रहकर ही सेवा करूंगी।

पतझड़ की यादें वापस लौट आईं

खुद अपनी आंख से

क्षमा शर्मा

आमों पर बौर आ गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में– आम फिर बौरा गए हैं। हवा में हलकी सी गर्मी आ गई है। लेकिन कभी-कभी ठंड भी महसूस होती है। मौसम का बदलता मिजाज जैसे कुछ थाह ही नहीं लगने देता। हम खुद को गर्मी के लिए तैयार कर रहे होते हैं और ठंड पलटकर चौंका देती है। समाचारों से पता चलता है कि पहाड़ों पर कहीं फलां जगह बर्फ पड़ी और यहां गरमी होते–होते ठंड बढ़ गई। लेकिन पेड़-पौधों पर मौसम अपना असर खुलकर दिखा रहा है। सोसाइटी के पूरे परिसर में डालों से झरे पत्ते इधर-उधर उड़ते फिर रहे हैं। कल किसी काम से बाहर निकलना हुआ तो बार-बार पैरों के नीचे आते पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी।

कई साल पहले शेरों पर एक किताब पढ़ रही थी, तो उसमें मां शेरनी बच्चों को किस तरह से पालती है और शिकार करना सिखाती है, इसका वर्णन विस्तार से था। उसमें बताया गया था कि मां शेरनी बच्चों को सूखे पत्तों पर चलना सिखाती है। अगर चलने पर जरा सी भी आवाज हो तो बच्चों को सजा देती है, क्योंकि आवाज सुनकर हाथ में आया शिकार निकल सकता है। मेरे पैरों के नीचे जो पत्ते चरमरा रहे थे, उनकी आवाज सुनकर मन में सवाल उठा कि अगर जंगल में चल रही होती तो क्या इस आवाज पर कोई जानवर यही समझता कि मैं उसका शिकार करने आ रही हूं?

रास्ते भर पेड़ों पर नजर पड़ रही थी। शहतूत के नए पत्ते, पीपल की तरह ही तांबई रंग के हैं। थोड़े दिनों में हरे हो जाएंगे। नीम की कोंपलें अलग से दिखाई दे रही हैं। पेड़ों के नए पत्ते हवा में लहरा रहे हैं। जैसे कह रहे हों– आओ, आओ। ये चमकीले पत्ते कितने आकर्षक लगते हैं और खुशी देते हैं। जीवन में नई आमद का संकेत भी। लेकिन पिछले साल भी इन पत्तों को देखकर इतनी ही खुशी हुई होगी। पर, आज उनका घर (यानी इन पेड़ों की डालें) छूट चुका है। वे बेघर-बार हो चुके हैं। वे पैरों तले कुचले जा रहे हैं। और यहां से कूड़े के ढेर में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। एक दुख सा होता है।

हर पुरानी चीज, जिसकी उम्र बीत गई संसार में उसकी नियति यही है। प्रकृति का यही नियम है। उसके चक्र में कोई दया-माया या सहानुभूति नहीं है। उम्र के गुमान में हम ये बातें भूले रहते हैं। पर जीवन सिर्फ दुख ही तो नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो आशा से भी भरा है। आम पर कूकती कोयल की मीठी आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। यों कोयल को हम अक्सर स्त्रीलिंग के रूप में पुकारते हैं, मगर सच तो यह है कि जो कूकता है वह मादा कोयल नहीं, नर कोयल होता है। वह मीठी तान सुनाकर अपनी साथिन को पुकारता है। उधर, तेज सुर में बोलती फाख्ता गर्मी आने की घोषणा कर रही है। थोड़े दिनों में वह अपने घर भी बनाएगी, जिसमें अंडे दे सके। क्या पता बना भी लिया हो। गौरैया भी तिनकों के साथ इधर-उधर उड़ रही हैं। बहुत से पक्षियों का यह प्रजनन का समय है। जिस तरह पेड़ों पर नए पत्ते उनके शिशु ही हैं, उसी तरह पक्षी जिन घोंसलों को बना रहे हैं थोड़े दिनों में वहां भी उनके शिशुओं की आवाजें सुनाई देंगी। माता-पिता इन्हीं पेड़ों और शाखाओं पर लगे पत्तों के पर्दों के बीच उन्हें पालेंगे। शत्रुओं से छिपाएंगे। उन्हें उड़ना और भोजन तलाशना सिखाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये शिशु अपनी–अपनी दुनिया में उड़ जाएंगे। उन्हें न मां याद रहेगी न पिता, कहते हैं, चिड़ियों में एक वक्त के बाद संबंधों की स्मृति रखने वाले सेल्स मर जाते हैं, इसलिए वे किसी परिजन को याद नहीं रख पाते। कई बार लगता है, सचमुच हम मनुष्य अनोखे हैं। हमें जीवन भर अपने संबंध याद रहते हैं।

चलते-चलते...

दाएं हाथ से लिखने वालों के मन में हमेशा से यह सवाल उठता रहा होगा कि कुछ लोग बाएं हाथ से क्यों लिखते हैं। नीदरलैंड स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टिट्यूट फॉर साइकोलिंग्विस्टिक्स के शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक डेटा पर किए गए एक अध्ययन में पाया कि कुछ जीन बाएं हाथ से काम करने से संबंधित हैं। टीम ने निष्कर्ष निकाला कि बाएं हाथ के लोगों में TUBB4B नाम का जीन होता है। यह जीन 1 प्रतिशत लोगों में आनुवंशिक है।

रीडर्स मेल

■ आओ हिंदुस्तान को संवारें हम

कई साल बाद यानी 1975-76 के बाद अब फिर से राजनीति का घिनौना और शर्मनाक रूप देखकर हर सच्चा हिन्दुस्तानी शर्मशार है। ये नेता सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, यह हम भलीभांति देख सकते हैं। इस दौर में धर्म व इंसानियत तक को गिरवी रखकर सत्ता पाने के लिए नेता दल बदलने लगे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। राजनीति और देश को बचाने के लिए हमको धर्म-जाति से ऊपर उठकर अच्छे और ईमानदार लोगों को ही चुनना होगा, तभी अच्छे दिन आएंगे। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे दिन देश और जनता के तो नहीं ही आ पाएंगे। यह समझ लेना होगा। तो अब हमें अच्छे लोगों को संसद में लाना है, ताकी प्यारे हिन्दुस्तान को संवारा जा सके। जय हिंद।

-शकील खिलजी, ईमेल से

■ कुर्सीबाज़ नेताओं की कालिख

जिस तरह बीजेपी हर पार्टी के नेता को अपने साथ मिलाए जा रही है, उनके पूर्व कार्य, वक्तव्य और चरित्र को नजरअंदाज करते हुए, उससे दस वर्षों के सरकार के किए गए कामों पर पानी फिर रहा है। बीजेपी की छवि तेजी से अब कुर्सीबाज़ नेताओं की कालिख से काली हो रही है। मन खिन्न हो गया है। अब मतदाताओं को सोचना होगा, दागदारों का बोझ ढोनेवाली पार्टी भी अगर बाकियों जैसी है, तो वोट किसे दें? हम किसी को भी वोट दें, भला क्या अंतर पड़ेगा? वही 'नागनाथ नहीं, तो सांपनाथ' वाला खेल बन गया है लोकसभा चुनाव। बीजेपी को अपने किए विकास कार्यों पर जरा भी आत्मविश्वास नहीं है।

-चंद्रा देवत (मुंबई), ईमेल से

■ विवाद जल्द खत्म हो

4 अप्रैल का संपादकीय 'यात्रियों को न हो परेशानी' पढ़ा। विस्तारा एयरलाइंस के पायलटों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा। मामला यह है कि पायलट एयरलाइन की तरफ से पेश किए गए नए कॉन्ट्रैक्ट से परेशान हैं। विस्तारा के एयर इंडिया में विलय की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में तय हुआ है कि विस्तारा के पायलटों पर भी एयर इंडिया का सैलरी स्ट्रक्चर लागू होगा। इससे उनका वेतन कम होने की नौबत आ गई है। देखा जाए तो विस्तारा के पायलटों की मांग उचित है। विलय के पीछे जो भी कारण रहे हों, उसका खामियाजा पायलटों को भुगतने पर मजबूर क्यों किया जाना चाहिए? इस हड़ताल की वजह से यात्रियों को जो परेशानी हो रही है वह अलग। सबके हित में यही है कि जल्द से जल्द इस विवाद को खत्म किया जाए और पायलटों की शिकायत दूर कर उन्हें काम पर बुलाया जाए।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

कांग्रेस की घोषणाएं

देश की सबसे पुरानी पार्टी ने चुनावी घोषणापत्र जारी करने के साथ ही अपना आगामी एजेंडा सामने रख दिया है। कांग्रेस के घोषणापत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, संविधान, अर्थव्यवस्था, संघवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश हुई है। पिछड़ी जातियों के उत्थान के प्रति कांग्रेस की घोषणाएं विशेष रूप से चर्चा का विषय बन रही हैं। बेशक, संविधान लागू होने के इतने साल बाद भी जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इसे खत्म करने के लिए देश की आने वाली सरकारों को सकारात्मक उपायों के साथ काम करना होगा। अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने इस मंशा को जाहिर करने की कोशिश की है। विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों के लिए हर पार्टी को पहल करनी ही चाहिए।

एक बड़ी घोषणा यह है कि संविधान संशोधन के जरिये आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा। यदि अगली सरकार इस दिशा में विधायी कदम उठाती है, तो यह स्वागतयोग्य है। वास्तव में, बिहार की जातिगत जनगणना से साफ हो गया है कि पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। अतः आबादी के अनुपात के साथ आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने को कांग्रेस ने जरूरी माना है। पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का वादा किया है। कांग्रेस ने भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए संविधान में दिए गए अधिकारों को बनाए रखने का वचन दोहराया है। यह एक ऐसा मोर्चा है, जहां कांग्रेस निरंतर भाजपा को चुनौती दे रही है। नई बात यह है कि चुनाव जीतने पर पार्टी संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से 'पर्सनल लॉ' में सुधार को प्रोत्साहित करेगी। मतलब, समान नागरिक संहिता का विषय आने वाले समय में प्रासंगिक बना रहेगा। यहां हम सभी पार्टियों से समझदारी की उम्मीद करेंगे। वाकई, समाज को समग्रता में देखने की जरूरत है और यहां किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उन सभी विवादित और चर्चित मुद्दों को अपने चुनावी घोषणापत्र में जगह दी है, जिनकी चर्चा हमारी राजनीति में लगातार होती आई है।

कांग्रेस का एलजीबीटी समूह से किया गया वादा भी उल्लेखनीय है, पर उससे भी खास है रोजगार संबंधी वादा। कांग्रेस रोजगार की बात लगातार कर रही है और इससे वोट जुटाने में उसे सुविधा होगी। उसने युवा न्याय कार्यक्रम के साथ बेरोजगारी से युद्ध स्तर पर निपटने का वादा किया है। प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को सालाना एक लाख रुपये देने के लिए महालक्ष्मी योजना की भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस महिलाओं को भी लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को तत्काल लागू करेगी। खास यह भी है कि कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का वादा किया है। इतना ही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का भी वादा किया गया है। बुनियादी रूप से लोकतंत्र को बचाने, भय दूर करने और स्वतंत्रता बहाल करने का वादा तो वह लगातार करती आई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व्यवस्था में सुधार, चीन से जमीन वापस लेने, अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा भी प्रत्याशित है। कुल मिलाकर, कांग्रेस के वादे समकालीन राजनीति और भाजपा को संबोधित हैं। अब हम इससे भी व्यापक घोषणापत्र की उम्मीद सत्तारूढ़ पार्टी से कर सकते हैं। जब सारी घोषणाएं सामने आ जाएंगी, तब घोषणाओं की तुलना का रोचक होना तय है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 06 अप्रैल, 1949

राष्ट्रीय सप्ताह

काल तीव्र गति से आगे बढ़ता है और घटनाएं इतिहास का रूप लेती जाती हैं। जलियांवालाबाग-हत्याकांड लगभग दो दशक पुरानी बात हो गई और आज हम परतन्त्र नहीं स्वतन्त्र हैं। किन्तु तब शुरू हुआ राष्ट्रीय सप्ताह (६ अप्रैल से १३ अप्रैल) आज भी हमें उद्बोधित करता और प्रेरणा देता है। आज जब हम इस सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, हमें उसी श्रद्धा और पवित्रता के साथ इसे मनाना चाहिए। राष्ट्रीय सप्ताह के प्रारम्भिक और अन्तिम दिन उपवास तो उसका ऊपरी रूप है और वह अपेक्षाकृत आसान है, किन्तु उसे मनाने की सार्थकता इसमें है कि हम उपवास-शुद्धि के साथ आत्म-निरीक्षण करें और कर्तव्य-पालन के लिए संकल्पबद्ध हों। आत्म-निरीक्षण इस बात की कि राष्ट्रीय सप्ताह के समय हमने जिस स्वराज्य का व्रत लिया था वह जब पूरा हो गया है तो उसे सु और स्थिर बनाने में हमारा योग कितना है। इस दिशा में हमारा योग है तो हम धन्य हैं और हमें संकल्प करना चाहिए कि आगे भी वह जारी रहेगा; यदि ऐसा नहीं है तो हमें सोचना है कि हमारा योग क्यों नहीं है और संकल्प करना चाहिए आगे इस दिशा में हमारी लापरवाही नहीं होगी। साथ ही यह आत्म-निरीक्षण भी हमें करना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में नैतिकता का जो पुट हमने स्वीकार किया है उस पर हम कायम हैं या नहीं- यदि उससे हमारा स्खलन हुआ है तो क्यों, और कैसे हम अपनी शुद्धि करके फिर से सही रास्ता पकड़ें? ऐसा हम करें तो हम पायेंगे कि बुराई दूसरे में नहीं हमीं में है और हम चाहें तो उसे सुधार सकते हैं। ऐसा बोध हो तो आत्म-सुधार के लिए संकल्पबद्धता स्वयं आती है और वही कर्तव्य-पालन की प्रेरणा है। राष्ट्रीय सप्ताह में हम यह कर सकें, तभी उनका मानना सार्थक है।

काल और परिस्थिति के अनुसार, कर्तव्य भी नये कलेवर धारण करता है। आज की स्थिति में स्वराज्य को मजबूत बनाने का बड़ा कर्तव्य तो हमारे सामने है ही, स्थूल रूप में दो कर्तव्य हमारे लिए सुझाये गये हैं। एक यह कि जो खराबियां सत्ता-प्राप्ति के बाद हमारे अन्दर आ गई हैं उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करें और दूसरा यह कि अपने राष्ट्रपिता की स्मृति के रक्षार्थ जिस निधि के संग्रह का हमने निश्चय किया है, उसे पूरा करने में दृढ़ता से लग जायें।

अमेरिका की भारत विरोधी टिप्पणी और इस पर भारत का तीखा जवाब आजकल चर्चा में है। सवाल-जवाब का यह शगल पुराना है। साल 1985 में भी 18 अप्रैल को लोकसभा में अमेरिकी हस्तक्षेप की जमकर आलोचना हुई थी और सरकार को तब भी तल्खी से जवाब देना पड़ा था।

आमने-सामने

वहां किस काम में लगा रहा हमारा दूतावास

यहां स्कैन करें

जी जी स्वैल | तत्कालीन वरिष्ठ सांसद

यह सभा हमारे प्रभुसत्ता संपन्न देश के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप और विश्व में कतिपय सामरिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से हमारे देश का विकृत चित्र प्रस्तुत करने के घृणित प्रयास से चिंतित और व्यथित है। ... हमें यह देखना होगा कि इस संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है?

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तथाकथित सुनवाई का आयोजन मानव अधिकार संबंधी (अमेरिकी) कांग्रेस गुट के तत्वावधान में किया गया था। इन व्यक्तियों ने भलाई की भावना से प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया, आपको इस प्रकार के व्यक्ति अमेरिका, यूके अथवा कहीं भी मिल जाएंगे, जो जानने तथा मंच प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ... उन्होंने जो किया है, वह घृणित बात है। दूसरा, बैठक का स्थान अमेरिकी कांग्रेस भवन था और इसलिए इसे कांग्रेस की स्वीकृति अथवा समर्थन प्राप्त था। इससे भी अधिक विचलित करने की बात है कि ...ऐसी अन्य बैठकें भी होंगी, ताकि ऐसी स्थिति तैयार की जा सके कि अमेरिकी कांग्रेस स्वयं भारत के आंतरिक मामलों पर सुनवाई करे।

महोदय, मैं कहता हूं कि यदि कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, तो मेरे विचार से अमेरिका से संबंध विच्छेद की स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें हमारे आंतरिक मामलों में किसी के हस्तक्षेप को कभी सहन नहीं करना चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि यदि भारत की संसद अमेरिकी कांग्रेस अथवा अमेरिकी सरकार के आंतरिक मामलों पर सुनवाई का आयोजन करती है, तो कोई भी अमेरिकी व्यक्ति इस बात को एक दिन भी सहन नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर, हम पाकिस्तान की जनता के मानवीय अधिकारों के मामले में सुनवाई का आयोजन कर सकते हैं। ... मैं अमेरिकी लोगों से कहता हूं कि जैसा हमारा इतिहास रहा है, गरीबी की समस्याएं हैं, विविधता की समस्या है, समाज में विरोधाभास है, यदि अमेरिका को उसका चौथा या दसवां हिस्सा भी मिलता, तो अमेरिकी लोकतंत्र कब का ध्वस्त हो चुका होता। वे लोकतंत्र की कसमें उठाते हैं, किंतु वे इस बात को नहीं देखते कि भारत में क्या किया जा रहा है।...

मैं विदेश राज्य मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। अमेरिका में हमारा दूतावास क्या कर रहा है? आप कहेंगे कि आपने विरोध प्रकट कर दिया है। अच्छी बात है कि आपने अपना विरोध प्रकट कर दिया है, किंतु आपने इस प्रकार की बात की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्य किया है?...

क्या इस प्रकार अंधता और अज्ञानता से ये अमेरिकी अमेरिका का कुछ भला कर रहे हैं? क्या वे विश्व को यह नहीं बता रहे हैं कि अमेरिका अंधों और बेईमानों का राष्ट्र है। ...वे तो स्वयं अपने इतिहास को झुठला रहे हैं। ...आज से 120 साल पहले अमेरिका ने गृह युद्ध लड़ा था और जिस व्यक्ति ने उस युद्ध का नेतृत्व किया था, उसको अमेरिकी आज भी और शेष विश्व के लोग भी अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति मानते हैं - अब्राहम लिंकन...। हमारी (दिवंगत) प्रधानमंत्री ने क्या किया था? मंदिर में सेना भेजने में उन्हें कोई खुशी नहीं हुई थी। ...मेरे विचार से जब उन्हें ऐसा करना पड़ा था, तब उन्होंने आंसू बहाए होंगे, जैसा अब्राहम लिंकन ने दक्षिण में सेना भेजते समय बहाए थे।...

आज वे नागरिकों के मानवाधिकारों की बात करते हैं। हम विश्व में हर कहीं लोगों के मानवाधिकारों हेतु प्रवक्ता बनकर आगे ही आगे रहे हैं, परंतु मैं अमेरिकियों से पूछता हूं कि उस गैर-सिख जनसंख्या के बारे में उन्हें क्या कहना है, जो यह सब होने से पहले मौत के कगार पर खड़ी थी? बहुत से हिंदुओं ने क्या अपनी जान नहीं गंवाई? जब डाकुओं, जलदस्युओं और मतिभ्रम लोगों या कुछ ताकतों द्वारा कठपुतली बनाए गए स्वार्थी लोगों का यह ग्रुप हत्याओं का तांडव नृत्य कर रहा था, तो क्या उन्होंने मानवाधिकारों के बारे में एक भी शब्द बोला था? यह पाखंड है। यह मिथ्याचार है।

...हमें आपे से बाहर तो नहीं होना चाहिए, परंतु उन्हें बता देना चाहिए कि हम ऐसी बातों को समझते हैं और ऐसी हरकतों से निपटने के लिए हम सब एक हैं। ...हमें तोप से मक्खी मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ...आपको अपने दूतावासों को थोड़ा और सक्रिय करना होगा। आपको अपने दूतावास में शीर्षस्थ स्थानों पर कल्पना शक्ति से भरपूर गतिशील लोगों को बिठाना होगा, उनको नहीं, जो वहां पर मौज उड़ाते हैं...।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

हमने अमेरिका को कड़े शब्दों में दिया जवाब

यहां स्कैन करें

खुर्शीद आलम खान | तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री

उपाध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में मैं इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूं। केवल मैं ही नहीं, बल्कि मेरे विचार से प्रत्येक भारतीय इन भावनाओं का समर्थन करेगा। यह स्वाभाविक है कि जहां देश की प्रतिष्ठा, एकता और सम्मान का प्रश्न निहित होगा, तो कोई भी भारतीय किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं होगा।...

हम सभी देशों से मैत्री और सौहार्दपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं, परंतु हम अपनी स्थिति से समझौता नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी पसंद से और मर्जी से संबंध रखेंगे और ऐसे संबंध रखेंगे, जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद होंगे। यदि कोई देश इन संबंधों से लाभ उठाना चाहे, तो उसे निस्संदेह निराशा होगी और हम इसकी अनुमति भी नहीं देंगे, चाहे वह अमेरिका हो या पाकिस्तान या अन्य कोई देश हो, हम अपनी पसंद के अनुसार संबंध रखेंगे।

...ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका जैसे कुछ देशों में इन आतंकवादियों के प्रति विशेष स्नेह दिखाया गया है। यह वास्तव में अत्यंत खेदजनक है और हमने इन देशों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत की मित्रता इन लोगों के साथ किए गए व्यवहार पर निर्भर करेगी। जब तक इन लोगों की गतिविधियों को नहीं रोका जाता, तब तक इन लोगों की सहायता करने वाले देशों के आगे भारत मैत्री का हाथ नहीं बढ़ाएगा।

महोदय, मैं अब यह स्पष्ट करना चाहता हूं। अमेरिका द्वारा यह कहा गया है कि सुनवाई करने वाला संगठन सरकारी नहीं था। यह सरकारी हो या गैर-सरकारी, परंतु मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, उनकी किस प्रकार के लोगों के साथ मित्रता है। ... वे गलती पर हैं, वे उन लोगों को, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, उन्हें अमेरिका जाकर देखना चाहिए, कंपूचिया जाकर देखना चाहिए, उन्हें और भी कई स्थानों पर जाकर देखना चाहिए। वे पाएंगे कि केवल हमारे देश और हमारे नेताओं ने मानव अधिकारों की रक्षा हेतु आवाज उठाई है। हम आवाज उठाना जारी रखेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। ...मैं इस सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी देश इसे सहन नहीं करेगा।

प्रत्यर्पण और अन्य मामले कानूनी हैं। इसके संबंध में मेरे लिए इस समय कुछ कहना संभव नहीं होगा, परंतु मैं ... यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी सभी संस्थाएं जो अधिकार का केंद्र हैं, पवित्र हैं, सम्मानित हैं और निस्संदेह उस पवित्रता, उस सम्मान को सुनिश्चित करना होगा और बनाए रखना होगा और इसलिए इस संबंध में किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

...हमने अमेरिका को अत्यंत कड़े शब्दों में कहा है कि भारत ऐसी बातें और इस प्रकार की सुनवाई सहन नहीं करेगा, क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि कोई भी देश अगर वास्तव में हमारा मित्र है, तो ऐसी बातें नहीं होने देगा। ...आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई बात हो, जिस पर सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की जरूरत हो, तो सरकार कभी पीछे नहीं रहेगी। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी शक्ति हो, सरकार कभी नहीं डरेगी। ... यह ठीक है कि श्री स्वैल ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने अपने अनुभव का सदा अच्छा उपयोग किया है। वह वर्मा में हमारे राजदूत थे, उन्होंने अनुभव का अत्यंत लाभकारी ढंग से उपयोग किया है, परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह कहा है कि भारतीय अत्यंत परिपक्व हैं, वे जल्दी में कोई कार्रवाई नहीं करते, वे भावुकता में कार्रवाई नहीं करते, निस्संदेह ठीक है।...

माननीय सदस्यों ने यह पूछा था कि सुनवाई करने वाले लोगों को वॉशिंगटन स्थित हमारे दूतावास ने क्या लिखा था। उन्होंने अत्यंत कड़ा पत्र लिखा था। हमारे राजदूत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय प्रतिनिधि स्वयं को इस प्रकार की हरकत से नहीं जोड़ सकते, जो उनकी राय में नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने अमेरिकी सरकार से विरोध प्रकट किया था।

मैं यहां अपने सिख भाइयों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि उन्हें अपनी तथाकथित समस्याओं का समाधान कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन में नहीं मिल सकता। उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान केवल इस देश में और इसके नेताओं से मिल सकता है।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

सेहत के पैमानों पर कैसे और कहां खड़ी दुनिया

यहां स्कैन करें

चंद्रकांत लहारिया | वरिष्ठ चिकित्सक

इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है- 'मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार।' निजी और सामाजिक स्तर पर यह हमारे चिंतन का एक अहम अवसर है कि स्वास्थ्य क्या है? हालांकि, कई लोग तर्क देते हैं कि देश और क्षेत्र के हिसाब से इसकी परिभाषा अलग-अलग होती है, पर इसके मूल में विश्व स्वास्थ्य संगठन की यही परिकल्पना है कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति ही स्वस्थ जीवन का आधार है, न कि बीमारी की अनुपस्थिति या दुर्बलता।

इस पैमाने पर आज के देश कहां खड़े हैं? दरअसल, तमाम देशों में सरकारों ने जन-स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले रखी है। ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ कार्यबल का अर्थ है, कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की उपस्थिति व उत्पादकता। 2015 में अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले एंगस डीटन ने अपनी पुस्तक *द ग्रेट एस्केप : हेल्थ, वेल्थ ऐंड द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वलिटी* में लिखा है, यूरोप के देशों में ज्यादातर आर्थिक तरक्की इसलिए हुई, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया, जिससे नागरिकों की सेहत बेहतर हुई। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मानव विकास में सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों, विशेषकर यूरोप में नागरिकों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं मुफ्त हैं।

दुनिया भर के देश अब अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। इसका एक पैमाना यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से सुलभ और सस्ती होनी चाहिए। ऊंची आय वाले कई देशों ने दशकों पहले इसे अपना लिया था। थाइलैंड जैसे देशों की सफलता तो एक शानदार उदाहरण है। अपने प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के संकल्प के साथ वह आगे बढ़ रहा है। थाइलैंड सरकार इनमें नए-नए उपचार और सेवाएं जोड़ने का काम करती है। कुछ देश, विशेषकर यूरोपीय राष्ट्र अस्पताल-आधारित सेवाओं से अधिक बाह्य रोगी आधारित सेवाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहां के कुछ अस्पताल अपनी व्यापक सेवाओं में कटौती करके बाह्य रोगी सेवाओं पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। इन दिनों एक अन्य प्रवृत्ति देखी जा रही है। विशेषज्ञ आधारित सेवाओं से हटकर अब परिवार-चिकित्सा आधारित नजरिया अपनाया जा रहा है। इसमें एक ही प्रदाता पूरे परिवार को अपनी सेवाएं देता है। केन्या, ट्यूनीशिया और कई अन्य देश अपने स्नातक डॉक्टरों को परिवार-चिकित्सा में प्रशिक्षित कर रहे है। इससे विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता कम हो जाएगी और डॉक्टरों के समय का सदुपयोग हो सकेगा। इसी तरह, ब्रिटेन में एनएचएस सार्वभौमिक व मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का बेहतर उदाहरण है। हालांकि, कुछ वजहों से इसकी आलोचना हो रही है, पर गुणवत्ता के मामले में यह बेजोड़ है। वास्तव में, जो देश पहले से अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, उनकी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे, कनाडा में प्रत्येक नागरिक को मुफ्त सेवाएं मिलती हैं, बल्कि उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी सेवाएं भी शामिल हैं, लेकिन लंबे समय तक रोगियों के इंतजार को लेकर इसकी आलोचना भी होती है।

स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से सुलभ और सस्ती होनी चाहिए। ऊंची आय वाले देशों ने दशकों पहले इसे अपना लिया था। थाइलैंड की सफलता एक शानदार उदाहरण है।

यह सही है कि जांच के अत्याधुनिक तरीकों के कारण आज जो व्यक्ति स्वस्थ दिखते हैं, वे कल रोगी पाए जा सकते हैं, इसलिए अब सिर्फ रोगियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि रोगों की रोकथाम, स्वस्थ जीवन-शैली को बढ़ावा देने और आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपचार पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए जरूरी यह भी है कि सभी आयु-समूहों के लिए टीकाकरण की उचित व्यवस्था गढ़ी जाए। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाना, उसे गुणवत्तापूर्ण बनाना और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

बांग्लादेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत समुदाय-आधारित संगठन है, भारत में आशा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है। ऐसे प्रयास चौतरफा किए जाने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण की भी आवश्यकता है, जिसका एक उदाहरण यूरोप है, जहां डेढ़ सदी (1830-1980) के दौरान यूरोपीय आबादी की लंबाई 15 सेंटीमीटर बढ़ी। हालांकि, भारतीय बच्चों की वर्तमान पीढ़ी भी अपने माता-पिता से पांच सेंटीमीटर लंबी है, पर अब भी यहां काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

जन्नत का हकदार

एक बार मैंने रमेश से पूछा, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जटिल से जटिल समस्या से भी आसानी से निपट लेते हैं, उससे बाहर निकल आते हैं, जबकि ज्यादातर लोग छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी आसमान सिर पर उठा लेते हैं? रमेश मुस्कराया और उसने मुझे एक कहानी सुनाई।

'एक बार की बात है। प्यार, करुणा और परोपकार भरी जिंदगी बिताने के बाद एक शख्स की मौत हुई, तो सभी ने उससे स्वर्ग जाने को कहा। उसके जैसा परोपकारी व्यक्ति स्वर्ग ही जा सकता था। स्वर्ग जाना उस आदमी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी वह वहां गया। स्वर्ग के प्रवेश-द्वार पर खड़ी परिचारिका ने उसका खास स्वागत नहीं किया। उसने लिस्ट देखी और कहा, स्वर्गारोहण करने वालों की सूची में आपका नाम नहीं है, कृपया नरक में जाएं। नरक के द्वार पर कोई जांच-पड़ताल नहीं थी। जो भी पहुंचता, सीधे अंदर चला जाता। कुछ दिनों के बाद लूसिफेर (शैतान) स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा और क्रोधित होते हुए स्वर्ग के प्रभारी देव से बोला- आप जो कर रहे हैं, वह विशुद्ध आतंकवाद है! आपने किस शख्स को नरक में भेज दिया, जो मेरा मनोबल गिराए जा रहा है? वह नरकवासियों की सारी बातें सुकून से सुनता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। वहां हर कोई अब एक-दूसरे से बातें करने लगा है, एक-दूजे को गले लगाने लगा है, एक-दूसरे को चूमने लगा है। नरक नरक ही न रहा। उसे फौरन वहां से यहां ले आएं!'

कहानी खत्म करते हुए रमेश ने मेरी तरफ स्नेह से देखा और कहा, 'अपने भीतर इतना प्रेम भरकर जियो कि यदि गलती से दोजख भी पहुंच गए, तो शैतान तुम्हें खुद जन्नत तक छोड़ जाए!'

पाउलो कोएल्हो

पी चिदंबरम | पूर्व गृह मंत्री

भारत-श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाले बयान देने से पहले तमाम जिम्मेदार लोगों को यह याद रखना चाहिए कि श्रीलंका में 25 लाख श्रीलंकाई तमिल और 10 लाख भारतीय तमिल रहते हैं।

अनुलोम-विलोम
कांग्रेस पार्टी

आज एक डूबती नैया हो गई कांग्रेस

कहावत है कि डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता। यही स्थिति आजकल कांग्रेस की हो गई है। केवल एक परिवार के इर्द-गिर्द परिक्रमा करने की परंपरा के कारण देश की इस सबसे पुरानी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, इसी कारण यह अब अपने अस्तित्व के संकट के दौर से गुजर रही है। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विशाल संगठन के विरोध में गठित 'इंडिया' ब्लॉक का नेतृत्व जिस कांग्रेस को सिरमौर बनकर करना चाहिए था, आज वह स्वयं दयनीय अवस्था में है और विभिन्न क्षेत्रीय दलों की कृपा पर निर्भर रहने को विवश है। उसके नेतागण एक-एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपने नेताओं को रोकने का कोई प्रयास तक कांग्रेस नहीं कर पा रही है।

पश्चिम बंगाल हो या पंजाब, महाराष्ट्र हो या बिहार, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली या फिर अन्य कोई राज्य, आज कहीं पर कांग्रेस मोल-भाव की स्थिति में नहीं है। छोटे-छोटे दल उसे आंखें दिखाने लगे हैं। जिसे देखो, वही कांग्रेस को नसीहत देने लगता है। इससे आम लोगों में कांग्रेस की छवि काफी दयनीय बन गई है। वस्तु स्थिति यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही आत्मविश्वास खो चुका है। उसके पूर्व अध्यक्ष ने देश भर में न्याय यात्राएं निकालीं, लेकिन ऐसा लगता है, उससे भी बात नहीं बनी और वह लोगों का भरोसा नहीं जीत सके, तो थक-हारकर उन्होंने दक्षिण की अपनी सीट पर ही ध्यान लगाना मुनासिब समझा। इन दिनों तो कांग्रेस व राहुल गांधी से ज्यादा खबरें आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की आती हैं। कांग्रेस छोड़ रहे लोगों का यह भी कहना है कि पार्टी नेतृत्व की सनातन विरोधी व राष्ट्र विरोधी सोच को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी नेताओं के बड़बोलेपन से रही-सही कसर भी पूरी हो जाती है। ऐसे में, कोई भला कब तक पार्टी से जुड़ा रह सकता है?

आज जब भारतीय राजनीति की तस्वीर कहीं ज्यादा स्पष्ट है और पार्टियां अपनी विचारधारा खुलकर जनता के सामने रखती हैं, तो बहुसंख्यक आबादी की अवहेलना करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। भाजपा को इसी का फायदा मिला है और वह आज सत्ता में है। चूंकि कांग्रेस अब भी अपनी पुरातन सोच से उभर नहीं पाई है, इसलिए वह डूबने के कगार पर पहुंच गई है। जिस तरह से उसके नेतागण पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे लगता यही है कि जल्द ही यह पार्टी खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा दिनों तक इसे संभालना अब मुश्किल जान पड़ता है।

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

जनादेश बताएगा इस दल का दमखम

कांग्रेस के दिन लदने के बार-बार दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस पार्टी में लोगों का अब विश्वास नहीं रहा और वे इसे छोड़कर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर नेताओं के नाम भी गिनाए जाते हैं। मगर ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि कोई भी पार्टी अपने नेता से नहीं बनती, बल्कि समर्थकों से बनती है। देश में भले ही भाजपा का दबदबा हो, लेकिन कांग्रेस के समर्थकों की संख्या अब भी करोड़ों में हैं। 2019 के आम चुनाव में ही इसे 11 करोड़ से अधिक मत प्राप्त हुए थे, जो डाले गए कुल वोट का करीब 19 प्रतिशत था। समझने की बात यह भी है कि इसके वही नेतागण पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनका कांग्रेस के सिद्धांत से कोई लेना-देना नहीं है। वे सिर्फ अपना हित साधने के लिए राजनीति में आए हैं। जब उनका हित कांग्रेस से पूरा हो गया, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अन्य दलों से हित सधने के बाद उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य दिखाई देने लगेगा, तो वे फिर से पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे मौकापरस्त नेताओं से पार्टी ही नहीं, लोगों को भी दूर रहना चाहिए।

इस बार के आम चुनाव की ही बात करें, तो कांग्रेस पिछली बार की तुलना में काफी मजबूत नजर आ रही है। दक्षिण भारत में तो वह मतदाताओं की पहली पसंद है ही, उत्तर भारत में भी वह इस बार कई सीटें फिर से झटकती नजर आ रही है। यहां तक कि उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के कारण उसकी ताकत बढ़ी दिखती है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर और दक्षिण के कुछ इलाकों में दूसरे दलों का दामन छोड़कर नेतागण कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनाव अभियान पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक और 'फोकस्ड' है। वह एक सोची-समझी रणनीति के तहत वह काम कर रही है, उसके घोषणापत्र का असर मतदाताओं पर जरूर पड़ेगा।

कांग्रेस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वह धर्म की राजनीति नहीं करती। इसके कारण देश का एक बड़ा तबका उसकी नीतियों को पसंद करता है। ये वैसे लोग हैं, जो धर्म को निजी आस्था का विषय मानते हैं और इसके सार्वजनिक प्रदर्शन को धर्मनिरपेक्ष राज्य के खिलाफ समझते हैं। इनमें से काफी 'स्विंग वोटर' माने जाते हैं, यानी वे ऐसे मतदाता हैं, जिनका मूड चुनाव प्रचार के दौरान बनने वाली हवा से प्रभावित होता है। चूंकि राहुल गांधी ने दो-दो यात्राओं से एक सकारात्मक माहौल बनाया है, इसलिए ऐसे लोग इस बार कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं।

विमलेंदु अस्थाना, टिप्पणीकार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 43

एक विशिष्ट करियर

इस सप्ताह राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का लंबा सार्वजनिक करियर समाप्त हो गया। डॉ. सिंह ने कई तरह से देश की सेवा कीः अर्थशास्त्री, अफसरशाह, नियामक, सांसद, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी। आजाद भारत में कम ही लोग होंगे जिनका करियर उनके समान लंबा, विविधतापूर्ण और प्रभावशाली रहा हो। जैसे-जैसे समय व्यतीत हो रहा है, इस बात की संभावना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल (जब उन्होंने 1991 के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की) को इतिहासकार अलग से चिह्नित करेंगे। यह उस दृष्टि से अलग होगा जिससे कि 7 रेसकोर्स में बतौर प्रधानमंत्री उनके एक दशक के कार्यकाल से अलग होगा। उस दौर में कोई अन्य अर्थशास्त्री या राजनेता भी वित्त मंत्री हो सकता था और उस समय जिस सुधार की तत्काल आवश्यकता थी उनके मानक भी व्यापक तौर पर ज्ञात ही थे और उसके लिए डॉ. सिंह की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद वित्त मंत्री ने जिस गंभीरता के साथ सुधारों के शुरुआती चरणों का प्रबंधन किया और बचाव किया, उसने भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य और उसके विकास की कहानी में विश्वास बहाल करने में बहुत अधिक सहायता की।

डॉ. सिंह के करियर की सबसे बड़ी कमजोरी को भी इस बात से महसूस किया जा सकता है कि वह राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए। भारत में जहां चुनावी लोकतंत्र हमेशा तकनीकी लोकतंत्र पर भारी पड़ता है और पड़ना ही चाहिए, वहां इस बात ने डॉ. सिंह के राजनीतिक प्रभाव को सीमित किया कि वह कभी जनता का सीधा समर्थन हासिल नहीं कर सके। कई लोग इसे ही 2004 से 2014 तक बतौर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री उनकी कमजोरी की वजह बताते हैं। सरकार के संवैधानिक मुखिया डॉ. सिंह, पार्टी और राजनीतिक संगठन जो सोनिया गांधी को रिपोर्ट करता था, के बीच शक्ति विभाजन साफ था। यह तथ्य है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साझेदार चाहते थे कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनें लेकिन उन्होंने इससे इनकार करके मनमोहन सिंह को चुना। इसका मतलब यही था कि वह हमेशा उनकी राजनीतिक छाया में रहेंगे। परंतु यह भी कहना होगा कि इनकी असहमतियां कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आईं। जब सोनिया गांधी के बेटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के बनाए कुछ कानूनों को कैमरे के सामने फाड़ दिया तो यह अपने आप में एक स्तब्ध करने वाली घटना थी क्योंकि ऐसे विवादों का सामने आना एक दुर्लभ अवसर था।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने गरीबी में कमी लाने, पात्रता योजनाओं के विस्तार और अधोसंरचना निवेश के क्षेत्र में जो कुछ हासिल किया उसका श्रेय शायद डॉ. सिंह को नहीं दिया जाए, खासकर यह देखते हुए कि उनके कार्यकाल के कई वर्ष ऐसे संकटों से निपटने में गुजर गए थे जो नीतिगत और प्रशासनिक पंगुता के कारण उत्पन्न हुए थे। इस पंगुता के पीछे अफसरशाही और मध्य वर्ग का असंतोष था। बहरहाल वृद्धि के क्षेत्र में उस सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल कीं वे मामूली नहीं थीं, भले ही उनमें पिछली सरकारों का भी योगदान हो। वैसे ही जैसे मौजूदा सरकार जो कल्याणकारी सुधारों और डिजिटल अधोसंरचना विकास को लेकर गर्व कर सकती है लेकिन इस कामयाबी का काफी श्रेय आधार जैसे नीतिगत निर्णयों को जाता है जो डॉ. सिंह के कार्यकाल में लिए गए। आंतरिक राजनीतिक अपील के मामले में उनकी सरकार काफी कमजोर थी और उसे अपने कदमों के लिए बाहरी मंजूरी की दरकार रहती थी। परंतु दूसरी ओर इसमें भी बहुत कम संदेह था कि उस सरकार में क्षमता संपन्न लोगों, तकनीकी जानकारों और विशेषज्ञता रखने वालों का सम्मान भी था। एक अर्थशास्त्री के रूप में डॉ. सिंह का प्रशिक्षण बतौर प्रधानमंत्री उनके बहुत काम नहीं आया लेकिन अब लगता है कि उन्होंने जिस दौर में काम किया वह एक अलग दौर था।

विनय सिन्हा

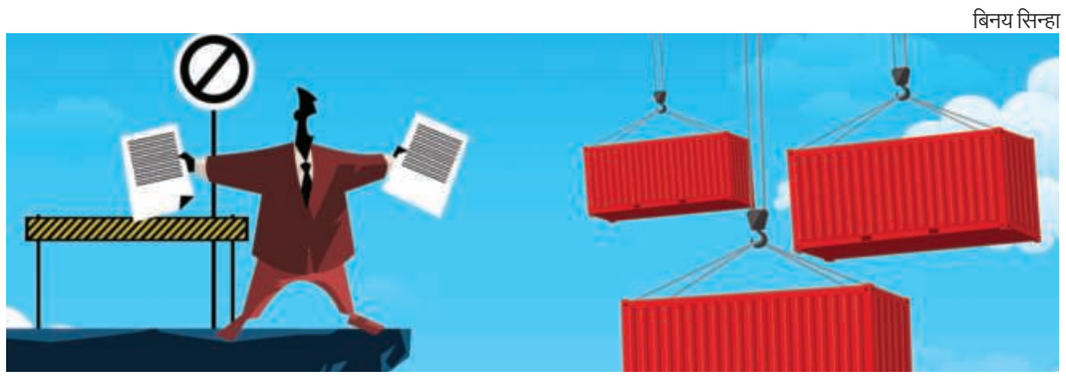

विश्व व्यापार संगठन का क्या होगा भविष्य

वैश्विक समृद्धि के लिए विभिन्न लाभ के बावजूद अगर कोई नाटकीय बदलाव नहीं हुआ तो डब्ल्यूटीओ शायद अपने अंतिम दौर में है। बता रहे हैं अजय छिब्बर

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को की गई थी। इसे दूसरे विश्वयुद्ध के अंत के बाद सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक सुधार बताया गया था। ऐसा इसलिए कि इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऐंड ट्रेड (जीएटीटी) का विस्तार करते हुए सेवाओं और बौद्धिक संपदा को व्यापार में शामिल कर दिया था। डब्ल्यूटीओ की शुरुआत के बाद विवाद निस्तारण की नई प्रक्रिया शुरू हुईं। इससे तीन मसले उत्पन्न हुए। पहला, चीन को लगातार 'विकासशील अर्थव्यवस्था' दिखाए रखना। दूसरा चीन द्वारा विशेष सब्सिडी वाले सरकारी उपक्रमों का इस्तेमाल करना जिससे उसे अनुचित लाभ मिला और बाजार अर्थव्यवस्था बनने की उसकी प्रगति धीमी हुई। तीसरा, आरोप है कि डब्ल्यूटीओ अपील संस्था हद से आगे बढ़ गई है और कुछ देशों ने इसकी विवाद निस्तरण व्यवस्था का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ हासिल किया है। दोहा दौर की वार्ता पर सहमति नहीं बन पाने के बावजूद वैश्विक व्यापार का आकार दोगुना से अधिक हो गया और वैश्विक टैरिफ में 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट तक गिरावट आई। तब से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और अटलांटिक पार साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौते आगे बढ़े हैं। परंतु इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अमेरिका और चीन अब समांतर और प्रतिस्पर्धी कारोबारी क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। इस बीच एक दूसरे के साथ उनका कारोबार जारी है। अमीर देशों में विनिर्माण कमजोर होने तथा भारत समेत कई विकासशील देशों में समय से पहले ही औद्योगीकरण की प्रक्रिया समाप्त होने से मुक्त व्यापार का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। रिचर्ड बाल्डविन का कहना है कि वैश्वीकरण का अगला दौर सेवा व्यापार से उत्पन्न होगा जिसे वैश्वीकरण 4.0 का नाम दिया जाएगा। परंतु 2020 से व्यापार में सुधार, खासकर सेवा क्षेत्र और सीमा पार के वित्तीय प्रवाह से यही संकेत मिलता है कि वैश्वीकरण जारी रह सकता है लेकिन उसकी गति काफी धीमी हो सकती है। यह गति वैश्विक वित्तीय संकट से पहले की तुलना में धीमी रहने वाली थी और भूआर्थिक कारणों से इसकी प्रकृति क्षेत्रीय रह सकती है।

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सेवा व्यापार में वृद्धि को लेकर चौंका सकती है लेकिन अब तक इसका प्रभाव अस्पष्ट है। मौजूदा वैश्विक व्यापार व्यवस्था में संरक्षणवाद बढ़ रहा है और कोविड तथा यूक्रेन युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखला को झटका दिया है। अपने देश में तथा मित्र देशों में उत्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं खासतौर पर अहम रणनीतिक क्षेत्रों मसलन सेमीकंडक्टर चिप आदि के मामले में। हालांकि जिंस के मामले में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार बढ़ रहा है। रूसी तेल पर प्रतिबंध की नाकामी यही दिखाती है।

डब्ल्यूटीओ ने विवाद निपटाने के लिए अधिक औपचारिक प्रणाली पेश की। इसमें विशेषज्ञों की एक अपील संस्था शामिल है जो विवादों पर निर्णय करती है लेकिन अब वह व्यवस्था अब सही नहीं रही। उसने विकासशील देश जैसे दर्जे की इजाजत दी जिसने खास अवधि के लिए विशेष प्रकार की रियायतों की व्यवस्था की। दोहा दौर की वार्ता में समझौते के अभाव के बावजूद डब्ल्यूटीओ व्यवस्था ने सही ढंग से काम किया। हालांकि बाद में दिक्कत होने लगी। चीन जैसे कुछ देशों खुद ही खुद को विकासशील देश बताया जाना अनुचित था क्योंकि उनके पास भारी भरकम व्यापार अधिशेष था। ध्यान रहे अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। विशेष सब्सिडी वाले सरकारी उपक्रमों का इस्तेमाल भी एक मुद्दा था खासकर चीन के मामले में क्योंकि यह अनुचित लाभ देता है। अमेरिका ने अपील संस्था में नए सदस्यों की नियुक्ति को रोक दिया है जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। चीन और यूरोपीय संघ समेत 26 देशों के समूह ने एक वैकल्पिक प्रणाली तैयार की है जिसे बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता समझौते (एमपीआईए) का नाम दिया गया है लेकिन उनके निर्णय उन पर लागू नहीं हैं जो इसके पक्ष नहीं हैं। उसने हाल के वर्षों में एकतरफा ढंग से शुल्क बढ़ा दिया गया और बाकियों ने प्रतिरोध किया जिसका असर डब्ल्यूटीओ की कार्यप्रणाली पर पड़ा।

बहुपक्षीय समझौतों पर प्रगति नहीं होने को लेकर हताशा का माहौल है। इसके लिए सहमति की आवश्यकता है इसलिए मतदान की व्यवस्था बनाने की मांग उठ रही है। भारत तथा कई विकासशील देशों ने ऐसे रवैयों का विरोध किया है। ई-कॉमर्स, निवेश संरक्षण और पर्यावरण तथा श्रम मानकों को लेकर भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है।

बारहवीं मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी मसलन मछलीपालन की सब्सिडी, महामारी को लेकर प्रतिक्रिया, खाद्य असुरक्षा और ई-कॉमर्स आदि अहम थे क्योंकि वे बहुपक्षीय थे और इन्होंने सबसे कठिन मुद्दों को हल करने की उम्मीद दी। परंतु तेरहवें सम्मेलन में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। सेवा क्षेत्र का व्यापार तेजी से बढ़ा और इसमें आगे और इजाफा होने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स में टैरिफ पर 25 वर्ष की रोक को तेरहवें सम्मेलन में 2026 तक दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके जारी रहने की उम्मीद है।

अतीत में भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों को बिगाड़ने वाला माना गया है जबकि उसने खुद को विकसित देशों के अनुकूल व्यवस्था में अपने तथा विकासशील देशों के हितों का बचाव करने वाले देश के रूप में देखा। वैश्विक व्यापार में धीमापन आने के बावजूद भारत का विकास विश्व निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यह 1990 के 0.5 फीसदी से बढ़कर 2022 में 2.5 फीसदी हो गया और 2030 तक इसके चार फीसदी होने की उम्मीद है। करीब दो अरब डॉलर के इस अनुमानित निर्यात में सेवा निर्यात की हिस्सेदारी आधी होगी। देश में संरक्षणवादी लॉबी के बढ़ने के बावजूद हमारे हित अधिक खुली विश्व व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

संभव है कि डब्ल्यूटीओ अधिक खुली व्यापार व्यवस्था का उत्तर न रह जाए। भारत को मुक्त व्यापार समझौतों पर अधिक यकीन करना होगा। यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ समझौते जरूरी होंगे। आरसेप में शामिल होना भी एक विकल्प है लेकिन तब भारतीय बाजार चीन के आयात से पट जाएगा। यूरोपीय संघ की कार्बन बॉर्डर समायोजन प्रणाली तथा अमेरिका के उच्च टैरिफ के कारण बढ़ते संरक्षणवाद की आशंका के बीच और चीन के सब्सिडी आधारित निर्यात मॉडल पर काम करते रहने के कारण व्यापार नियमों पर वैश्विक सहमति बन पाने की संभावना बहुत कम है।

वैश्विक समृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद डब्ल्यूटीओ बड़ी कारोबारी शक्तियों के लिए अनुकूल नहीं रह गया है और अगर कुछ नाटकीय नहीं घटित होता है तो यह अपने अंतिम पड़ाव पर है।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी के प्रतिष्ठित विजिटिंग स्कॉलर हैं)

राजनीतिक बदलाव की दो कहानियां

जब 9 फरवरी को संतृप्त मिश्र ने औपचारिक घोषणा कर दी कि वह बीजू जनता दल (बीजद) के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पार्टी से जुड़ रहे हैं तो अटकलें तेज हो गईं कि आदित्य बिड़ला समूह के इस दिग्गज को राज्यसभा के लिए नामित किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकती है।

वहीं दूसरी ओर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में मनीष खंडूड़ी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए स्थानीय उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही हफ्ते पहले तक खंडूड़ी उसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट पाने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहे थे, जब तक कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा नहीं दे दिया। बाद में उन्होंने भाजपा से जुड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने भाजपा से पार्टी का टिकट नहीं मांगा और न ही इसकी पेशकश उन्हें की गई। लेकिन उन्हें भविष्य में दिल्ली में पार्टी में संगठनात्मक भूमिका देने की चर्चा जरूर हुई।

खंडूड़ी के कांग्रेस से इस्तीफे की खबर से हम पत्रकार समुदाय में गहरी निराशा छाई खासतौर पर हममें से कुछ उन लोगों में जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया था और1990 के दशक की शुरुआत में इसी अखबार से अपना करियर शुरू करना भी शामिल था।

मिश्र और खंडूड़ी की राजनीतिक यात्रा की तुलना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती। मिश्र कॉरपोरेट जगत के एक दिग्गज हैं, जिनके खाते में बदलाव का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी ओर, खंडूड़ी ने एक वित्तीय पत्रकार के रूप में और बाद में केलॉग से एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद, सीएनएन और मेटा जैसी वैश्विक मीडिया कंपनियों में एक वरिष्ठ कारोबारी अधिकारी के रूप में एक सफल करियर बनाने के बाद 2019 में राजनीति में कदम रखा।

आखिर इन बातों का सार क्या है? पार्टी बदलने की घोषणा के कुछ ही समय बाद ही मिश्र से कॉरपोरेट जगत के उनके साथियों ने सवालों की बौछार कर दी। दरअसल वे जानना चाहते थे कि सार्वजनिक जीवन में आने के लिए क्या करना होगा। इन सवालों को लेकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर इस वजह से कि कॉरपोरेट जीवन एक निश्चित बिंदु के बाद बेहद उथला सा और अधूरा मालूम पड़ सकता है।

राजनीति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव बनाने का भी अपना एक कथित रोमांच है। इसके बावजूद लोगों को क्या चीजें पीछे खींच रही हैं? देश के अधिकांश मध्यम वर्ग का भारतीय राजनीति को लेकर बेहद उत्साहहीन दृष्टिकोण है।

रणनीति कदम

इंद्रजित गुप्ता

मैं यह बात सुनता रहता हूं कि भारत की राजनीति में ईमानदार और नैतिकता को बढ़ावा देने वाले कॉरपोरेट जगत के उन दिग्गज अगुआई करने वालों की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार को दूर करने के साथ ही एक बेहतर भविष्य को बढ़ावा देने का बेहतर मौका मिल सके। यह और बात है कि ज्यादातर लोग यह चाहेंगे कि उनके बजाय कोई और सार्वजनिक जीवन में जाने का बीड़ा ले और जोखिम उठाए। हालांकि कुछ लोगों का इरादा है और वे गंभीर हैं, लेकिन अपनी वास्तविक हैसियत, पोजिशन और पूंजी से दूर होना शायद ही कभी आसान होता है।

खंडूड़ी और मिश्र दोनों की राजनीति में पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, खासतौर पर तब जब वे युवा थे। खंडूड़ी ने अपने पिता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के लिए प्रचार किया, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री के रूप में काम किया था। इसके अलावा इस दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के निर्माण में उनकी छवि भी साफ-सुथरी थी। उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया।

मिश्र का परिवार भी सार्वजनिक जीवन से जुड़ा था। उनके पिता के बड़े भाई देश की एक प्रमुख ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे जो भाकपा से संबद्ध थी। वह खुद भी युवा छात्र के रूप में श्रमिक संगठन का चुनाव लड़े। बीजद में शामिल होने के उनके फैसले में एक दशक से अधिक की देरी हुई क्योंकि कॉरपोरेट जगत से जुड़ी उनकी प्रतिबद्धताओं ने उन्हें एक बार वर्ष 2013 में और फिर 2019 में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी।

खंडूड़ी को उम्मीद थी कि वह अपना राजनीतिक आधार बनाने के लिए अपने पिता की समाज में बनी प्रतिष्ठा को ही बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 2019 में वह कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन इसके बावजूद वह रुके नहीं। उन्होंने अपने जमीनी स्तर के काम को जारी रखा और राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान एक महत्त्वपूर्ण संचारक की भूमिका निभाई और लगभग पूरी यात्रा के दौरान पैदल चले।

जैसे-जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा था खंडूड़ी को पता चल गया था कि उनके पास सीट जीतने का कोई रास्ता नहीं है। भाजपा वास्तव में अजेय प्रतीत हो रही है जिसके पास शक्तिशाली और अनुशासित काडर का समर्थन है। खास बात यह है कि जब वह 'भारत जोड़ो यात्रा' के लिए प्रचार कर रहे थे, तब राज्य में स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व उनका पत्ता काटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा था।

उन्होंने दिल्ली में पार्टी प्रबंधन से जुड़े लोगों से एक मध्यम स्तर की भूमिका के लिए कहा ताकि अगर वह दूसरी बार हार भी जाएं तो उनका थोड़ा सम्मान बना रहे। इसके लिए उनसे वादा भी किया गया लेकिन इस मोर्चे पर वास्तव में कोई प्रगति नहीं हुई। वह पूरी तरह से निराश थे और आखिरकार उन्होंने 8 मार्च को पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया। अब उन्हें एक नए माहौल में अपनी प्रतिष्ठा कायम करनी है। अच्छी खबर यह है कि कांग्रेस के विपरीत भाजपा नए चेहरों को लाने और पार्टी में बेहतर प्रदर्शन न करने वाले नेताओं से निपटने के लिए तैयार है।

दूसरी ओर, बीजद कोई बड़ी पार्टी नहीं है। नवीन पटनायक केवल चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करने से पहले अपनी विनम्र नेतृत्व शैली के जरिये विकास को प्राथमिकता देने वाली संस्कृति बनाने में सक्षम रहे हैं। अपने शुरुआती कुछ हफ्ते के भीतर ही मिश्र ने पार्टी की डिजिटल पहचान और उसकी वेबसाइट में बड़े सुधार करने के लिए अपने कारोबारी कौशल का इस्तेमाल किया। टीम को दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक पार्टी वेबसाइटों की समीक्षा करने, बीजद सांसदों और अन्य हितधारकों को इससे जोड़ने और समय पर इस काम को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया।

अब जब उनकी भूमिका खुली हुई है तब पार्टी ने बेहद बुद्धिमानी से उनका इस्तेमाल चुनिंदा और उच्च-गुणवत्ता वाले कार्यों के लिए किया है। निश्चित रूप से किसी भी बदलाव के तहत जुड़ने और निकलने की एक प्रक्रिया होती है। मिश्र का कहना है कि उन्हें पता है कि वह अपने कॉरपोरेट कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक विविध हितधारकों के साथ काम करेंगे। इसके अलावा, उन्हें सूची बनाकर नियत समय पर काम करने के अपने जुनून को छोड़ने और अस्पष्टता तथा अनिश्चितता से निपटने के लिए सीखने की जरूरत है। उन्होंने सलाहकारों का एक समूह बनाया है जो उनके पांव जमीन पर ही टिकाए रहने देते हैं और उन्हें किसी तरह कोई गलती करने से रोकते हैं।

(लेखक फाउंडिंग फ्यूल पब्लिशिंग के सह-संस्थापक हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

भूकंप से निपटने के लिए कितना तैयार भारत

बीते दिनों कुदरत का कहर ताइवान में बरपा। वहां लगभग 7 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई। हमारे देश में भी समय-समय पर कम-ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं। एक तरफ तो विज्ञान के कारण आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुपके से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं यह सवाल खड़े करती हैं कि क्या इंसान आज भी प्रकृति के आगे बौना ही है? भूकंप की सटीक भविष्यवाणी विज्ञान क्यों नहीं कर पा रहा? हमारे देश में भूकंप से भारी जानमाल का नुकसान भी इतिहास में दर्ज है। इनमें मुख्यतः हिमाचल के कांगड़ा में साल 1905 में सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया था। उस वक्त 20 हजार से ज्यादा लोगों की जान जाने और लगभग एक लाख से अधिक घरों आदि को नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था। इसी तरह 2001 में गुजरात में आए भूकंप ने भारी

बीते दिनों ताइवान की राजधानी ताइपे में 7 तीव्रता का भूकंप आया था जलजला ऐसा था कि बिजली-पानी के साथ रेलसेवा भी प्रभावित हुई

तबाही मचाई थी। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, लाखों लोग घायल हुए थे और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ था। यहां के लगभग 24 जिले तो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर और राधनपुर मुख्य हैं और लगभग 7900 से ज्यादा गांव बरबाद हो गए थे। भूकंप प्राकृतिक आपदा कब अपना कहर बरपा दे, यह समझना मुश्किल है लेकिन फिर भी इस आपदा से जानमाल को होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है यह भी यक्ष प्रश्न है। अक्सर यह भी देखा गया है कि कभी कभी इसके झटके इतने तेज होते हैं कि वह मजबूत इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। भूकंप से निपटने के लिए सभी को प्रयास करना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

भारतीय नीति की लोकप्रियता

भारत की शांति नीति की सफलता इसी बात से समझी जा सकती है कि दुनिया के युद्धरत देश मध्यस्थता के लिए भारत को अगुआ बनने की बात कह रहे हैं। रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे संघर्ष में शांति के लिए भारत की भूमिका को जिस तरह रेखांकित किया गया है, वह भारत के वैश्विक शांति के प्रयासों का ही नतीजा है। भारत के रूस-यूक्रेन दोनों से मजबूत संबंध है ऐसे में केवल शांति मार्ग से ही इसका समाधान निकल सकता है। यूक्रेन ने इसकी जरूरत महसूस की है। रूस की मनःस्थिति यूक्रेन को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की है ताकि वह न केवल उसके दबाव में रहे बल्कि भविष्य में उसका उपनिवेश भी बना रहे। ऐसे में यूक्रेन के लिए जरूरी हो जाता है कि वह सैन्य और शस्त्र रूप से मजबूत तो रहे ही, भारत जैसा देश उसके लिए मध्यस्थ भी बने ताकि रूस की किसी भी नाजायज मंशा को वैश्विक मंच पर गैरजरूरी ठहराया जा सके। यहां उल्लेखनीय यह भी है कि दुनिया युद्ध से थक चुकी है और अब शांति ही एकमात्र रास्ता बचा है। चूंकि भारत ने कभी भी शस्त्रों से शांति की बात नहीं कही है और वार्ता के माध्यम से ही शांति कायम करने का प्रयास किया है। ऐसे में विश्व शांति के लिए हमारा अभियान कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है, समझा जा सकता है।

अमृतलाल मारू 'रवि', इन्दौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में शुक्रवार को 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रोफेशनल कोर्स के पहले चरण के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे।

कल्पमेधा

लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत का फैसला अंतिम होता है, परंतु इस व्यवस्था में सबसे बड़ा खतरा यही है कि इसमें बहुमत की तानाशाही हो जाती है।

– जान स्टुअर्ट मिल

वादा बनाम अमल

लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने समीकरणों के साथ प्रचार अभियान में लग चुकी हैं। रैलियों और भाषणों में अनेक मुद्दों पर बात की जाती है, लेकिन किसी पार्टी का रुख इस बात से आंका जाता है कि चुनाव में जनता को अपने पक्ष में मत देने के लिए घोषणा पत्र में वह क्या वादे करती है। इस क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे 'न्यायपत्र 2024' का नाम दिया गया है। इसमें कांग्रेस ने जनता से वादा किया है कि वह सत्ता में आने पर अलग-अलग सामाजिक वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए नई योजनाएं लाएगी। मसलन, उसने अपने घोषणापत्र की पच्चीस गारंटियों को ठोस बताया है। हर गरीब महिला को हर वर्ष एक लाख रुपए, किसानों को कर्जमाफी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, मनरेगा में कम से कम मजदूरी चार सौ रुपए की गारंटी के अलावा सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए जाति आधारित जनगणना कराने जैसे कई वादे किए गए हैं।

इसमें एक तरह से भाजपा की ओर से जारी एक नारे 'मोदी की गारंटी' का जवाब देने की कोशिश है कि अगर मतदाता केंद्र में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो वह अपने घोषणापत्र में दर्ज जनता के कल्याण कार्यक्रमों को 'गारंटी' के स्तर पर लागू करेगी। यह छिपा नहीं है कि चुनाव आने पर राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की ओर से कितने बड़े-बड़े और कैसे वादे किए जाते हैं। पिछले कुछ समय से तो लोगों को कोई सामान, उपहार या सुविधा मुफ्त में मुहैया कराने के वादे करके वोट मांगने का चलन हावी होता दिख रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि किन्हीं हालात में अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिल जाता है तो उसके बाद वे या तो उन वादों को भूल जाते हैं या फिर उन्हें पूरा करने को लेकर वे अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। जबकि जनता आमतौर पर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की ओर से अपने भाषणों में दिए गए भरोसे, घोषणापत्र में दर्ज वादों के आधार पर किसी पार्टी को अपना समर्थन देकर सत्ता में पहुंचाती है और उसके बाद अपने लिए किसी कल्याण कार्यक्रम का इंतजार करती रह जाती है।

अव्वल तो जनता को ऐसे वादों के प्रति जवाब मांगने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि चुने जाने के बाद बहुत कम जनप्रतिनिधि जनता के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। दूसरे, अगले चुनाव तक फिर से राजनीतिक दलों के वादों का एक नया संजाल खड़ा हो चुका होता है। वादे करके उसे पूरा नहीं करने को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले चुनाव लड़ने वाले दलों और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने और चुनाव प्रक्रिया की शुचिता खराब न होने देने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने को कह चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी यह स्पष्ट कर रखा है कि राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए, जिनसे चुनाव प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित हो या मतदाताओं पर उनके मताधिकार का प्रयोग करने में अनुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो। ऐसे में स्वाभाविक ही यह सवाल उठता है कि इस आम चुनाव के मद्देनजर अपने-अपने घोषणा पत्रों में किए गए वादों को पूरा करने को लेकर कांग्रेस या अन्य सभी पार्टियां कितनी गंभीर और जिम्मेदार होंगी!

स्थिर मुद्रा

यह सातवीं बार है, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में कोई बदलाव करने से परहेज किया है। उसने रेपो दर को 6.5 फीसद पर यथावत बनाए रखा है। ऐसा महंगाई पर काबू पाने के मकसद से किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्तवर्ष में महंगाई की दर घट कर 4.5 फीसद पर आ जाएगी। पिछले वर्ष इसके 5.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया था। अब भी महंगाई काबू में नहीं आ रही। थोक और खुदरा महंगाई तथा विकास दर में कोई तार्किक संतुलन नजर नहीं आता। खुदरा वस्तुओं में फल और सब्जियों के दाम उस मौसम में भी ऊंचे देखे गए, जब बाजार में नई फसल की आवक बढ़ जाती है। इस समय भी बाजार में आलू, प्याज, टमाटर जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमत बाईस से चालीस फीसद तक बढ़ी हुई है, जबकि इस वक्त इनकी नई फसल बाजार में आती है। दाल, चावल, आटे जैसी चीजों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक रेपो दर में बदलाव करके किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता था।

रेपो दर ऊंची रहने पर बाजार में पूंजी का प्रवाह काबू में रहता है, इस तरह महंगाई पर भी अंकुश होता है। मगर इससे घर, वाहन, कारोबार आदि के लिए कर्ज लेने वालों पर ब्याज का बोझ बढ़ जाता है। उद्योग जगत लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठा है कि रेपो दर में कमी आए, तो उन्हें कारोबार के लिए लिए कर्ज पर कम बोझ उठाना पड़े। मगर महंगाई की मार ने रिजर्व बैंक को ऐसा कोई फैसला करने से रोक रखा है। मगर केवल रेपो दर ऊंची रख कर महंगाई पर काबू पाने का फार्मूला कहां तक कारगर साबित होगा, कहना मुश्किल है। महंगाई के लिए जिम्मेदार पेट्रोल-डीजल की कीमतें, खेती में बढ़ती लागत, उद्योगों में उत्पादन लागत आदि पर काबू पाए बिना महंगाई पर लगाम कसना कठिन ही बना रहेगा। फिर, लोगों की क्रयशक्ति घटने से महंगाई की मार आम लोगों पर बहुत भारी पड़ रही है। रेपो दर के अलावा महंगाई के कुचक्र से बाहर निकलने का व्यावहारिक रास्ता निकालना होगा।

जमीन से उठा एक दल

6 अप्रैल, 1980 को फिर देश भर के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। चुनाव चिह्न कमल का फूल घोषित किया गया।

प्रभात झा

जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर, मोहन धारिया और मधु लिमये जनता पार्टी के जनसंघ घटक से बार-बार कह रहे थे कि आपकी दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी सदस्यता खत्म करनी होगी। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सूचना प्रसारण राज्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी लगातार समझाते रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृसंस्था है। संघ में कोई सदस्यता नहीं होती, यह एक सांस्कृतिक संगठन है, जो देश की संस्कृति, भारतीय परंपरा, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के लिए काम करता है। बावजूद इसके, जनता पार्टी के अन्य घटक दल नहीं माने, जबकि सच्चाई यह थी कि आपातकाल के बाद जनसंघ ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने दल का नाम और चुनाव चिह्न 'दीपक' भी मिटा दिया था। अटलजी और आडवाणीजी की बात जनता पार्टी नेताओं ने, यहां तक कि मोरारजी देसाई जो उस समय प्रधानमंत्री थे, ने भी इस विषय पर चुप्पी साध ली। तब अटलजी और आडवाणीजी ने तत्कालीन पूर्व संगठन मंत्री सुंदर सिंह भंडारी से आग्रह किया कि 4 अप्रैल, 1980 को देश के अपने सभी प्रांतों और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं की आपात बैठक बुलाई जाए।

बैठक में पहले आडवाणीजी ने जनता पार्टी से उत्पन्न सभी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि दोहरी सदस्यता के नाम जनता पार्टी के अन्य घटक हमें संघ के 'स्वयं सेवक' नहीं रहने और उनके कार्यक्रमों के साथ-साथ संघ की सदस्यता छोड़ने की बात कर रहे हैं। वहां उपस्थित जगन्नाथ राव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, सुंदर सिंह भंडारी, केदारनाथ साहनी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, विजय कुमार मल्होत्रा, कुशाभाऊ ठाकरे, जेपी माथुर, कैलाशपति मिश्र, उत्तम राव पाटिल, विष्णुकांत शास्त्री, ओ राजगोपाल, यज्ञदत्त शर्मा, मदनलाल खुराना, अश्विनी कुमार, केशुभाई पटेल, येदियुरप्पा सहित देश के सौ से अधिक नेताओं ने एक साथ कहा कि हम सबसे पहले स्वयंसेवक हैं और संघ से हमारा नाता मरणोपरांत भी नहीं छूट सकता, चाहे इसके लिए जनता पार्टी क्यों न छोड़ना पड़े।

अंत में अटलजी ने उद्बोधन में कहा कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं और सदा रहेंगे, लेकिन अब जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे। उपस्थित सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि हमने जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाया था, पर जनसंघ के कार्यकर्ता तो आज भी गांव-गांव में हैं। जनसंघ के कार्यकर्ताओं और संघ के सहयोग के कारण ही जनता पार्टी को देश में इतनी सीटें सन 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद मिलीं। बैठक में एक समिति सुंदर सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बनाई गई, और इस समिति को नया दल, नया चुनाव चिह्न और नया संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया।

6 अप्रैल, 1980 को फिर देशभर के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। चुनाव चिह्न कमल का फूल घोषित किया गया और दल का संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ। भाजपा बन गई। इसका पहला अधिवेशन मुंबई के माहिम क्षेत्र में आयोजित किया गया। सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने एक स्वर में जनसंघ के तीन बार अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी को लाखों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में अटलजी ने कहा, 'अंधेरा छंटेगा सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा'।

> एक स्थिति यह आई कि सन 1996 के चुनाव में भाजपा को 182 सीटों पर जीत मिली। सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण अटलजी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई, लेकिन वह सरकार मात्र तेरह दिन तक चली। फिर चुनाव हुए, और भाजपा को उस समय के एनडीए के साथ, अच्छी सीटें मिलीं। अटलजी फिर तेरह महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। सहयोगियों ने धोखा दिया और अटलजी की सरकार एक वोट से गिर गई। अटल जी ने इस्तीफा देने से पहले संसद में अपने भाषण में कहा, 'सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन हम खरीद-फरोख्त से बनी सरकार को चिमटी से भी नहीं छूएंगे'।

सन 1984 में चुनाव हुए। तब इंदिराजी की हत्या हो गई। भाजपा को देश में सिर्फ दो सीटें मिलीं। यहां तक कि अटलजी ग्वालियर से चुनाव में माधवराव सिंधिया से हार गए। मगर अटलजी उठे और कहा कि हम चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं। हम दुगुनी ताकत से पूरे देश में कमल खिलाएंगे। कार्यकर्ता तो देश भर में थे। राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व ने पूरे भारत का अखंड प्रवास कर छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं और भारत की जनता को जगाने का कार्य जारी रखा। धीरे-धीरे हर लोकसभा चुनाव में भाजपा की संख्या बढ़ती गई। सन 1989 में 85 सीटें और सन 1991 में भाजपा को 120 सीटें मिलीं।

एक स्थिति यह आई कि सन 1996 के चुनाव में भाजपा को 182 सीटों पर जीत मिली। सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण अटलजी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई, लेकिन वह सरकार मात्र तेरह दिन तक चली। फिर चुनाव हुए, और भाजपा को उस समय के राजग के साथ, अच्छी सीटें मिलीं। अटलजी फिर तेरह महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। सहयोगियों ने धोखा दिया और अटलजी की सरकार एक वोट से गिर गई। अटलजी ने इस्तीफा देने से पहले संसद में अपने भाषण में कहा, 'सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन हम खरीद-फरोख्त से बनी सरकार को चिमटी से भी नहीं छूएंगे'।

सन 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी और अटलजी तीसरी बार पांच साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। फिर सन 2004 में लोकसभा चुनाव में भाजपा पराजित हुई और यूपीए की सरकार बनी। उसके बाद यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। यह सरकार दस साल चली। इन दस सालों में यूपीए सरकार घोटालों में डूब गई। पूरे देश में यूपीए से देश के लोग निराश हो चुके थे।

मगर इतिहास करवट लेता है। गुजरात में बारह वर्ष शानदार सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का संयोजक और कुछ दिनों बाद उन्हें भाजपा की ओर से देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने की दलीय घोषणा की। नरेंद्र मोदी का नाम आते ही देश में एक नए राजनीतिक युग का संचार हुआ। नई आशाएं जगीं, उम्मीदों की नई किरणें दिखने लगीं। गुजरात के विकास की अमिट छाप देश ने देखा था। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का विश्वास जीता और तीस वर्ष बाद किसी पार्टी (भाजपा) की बहुमत की सरकार बनी। कुल सीटें भाजपा की 282 और राजग की 336 आईं। उसके बाद प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं रुके। उनके कदम बढ़ते गए। इसी बीच में राजनाथ सिंह देश के गृहमंत्री बने और भाजपा के नए अध्यक्ष अमित शाह बने। संगठन का कार्य संभालते ही अमित शाह ने अपने अखंड प्रवास और अनेकानेक कार्यों और कार्यक्रमों से पूरे भारतवर्ष में भाजपा को खड़ा कर विश्व में भाजपा को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर इतिहास रचा। हर जिले में भाजपा कार्यालय सहित बारह ऐसे कार्य सौंपे, जिसे भाजपा के हर जिलों में होना ही था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति और गरीब, महिला, किसान, युवा के लिए अपनी सरकार समर्पित कर दी। भारत के गांव गरीबों की ही नहीं, बल्कि विकास के इतने आयाम तय किए कि सन 2019 में भाजपा को 303 सीटें अकेले मिलीं और एनडीए को कुल 352 सीटें। जनसंघ के जमाने से घोषणा-पत्र में जो बातें आज तक कही जा रही थीं, मोदी जी ने उसे साकार करने की दिशा में एक पल भी नहीं गंवाया।

(लेखक भाजपा के पूर्व सांसद हैं)

चरित्र के सोपान

पूजा खिल्लन

मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्त्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्त्व है। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जिसके पास चरित्र है, वही नायक हो सकता है, अन्यथा मनुष्य पद, पैसा और अन्य भौतिक आकर्षणों में खुद की पहचान खो बैठता है। जबकि खुद को पहचानना एक सच्चा और प्रामाणिक जीवन जीने की पहली शर्त है। 'स्व' की पहचान या खोज मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लिए जरूरी है। 'स्व भाव' का तात्पर्य किसी चीज की उस विशिष्टता से है, जिसे निकाल देने पर उस चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे दाहकता को निकाल देने पर 'आग' का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का 'स्व भाव' क्या माना जाएगा? निश्चित तौर पर दया, परोपकार, विनम्रता, सदाचार, परस्पर प्रेम की भावना... मनुष्य का स्व भाव होना चाहिए। अगर ये गुण न हों, तो वह शरीर मात्र रह जाएगा, जो सांसारिक सुखों और बाह्य आकर्षणों की मृग-मरीचिका में फंसकर खुद का सर्वनाश कर डालेगा। बुद्ध ने 'स्व' की खोज की और जीवन भर घर नहीं लौटे। उनके उदाहरण से पता चलता है कि सच्चा ज्ञान हमें जीवन-पर्यंत बेचैन करता है और भटकने के लिए बाध्य करता है। जैनेंद्र ने लिखा है 'मेरे भटकाव'। बहरहाल, चरित्र की अगर बात करें तो बेशक एक प्रामाणिक चरित्र वाला व्यक्ति जिज्ञासु और अंत तक बेचैन रहने के लिए विवश होता है, क्योंकि वह ज्ञान की खोज में लगा हुआ होता है और स्वयं को भी पाना चाहता है। जिन लोगों मे यह बेचैनी नहीं होती, वे अंत तक जीवन के सच्चे लक्ष्य तक नहीं पहुंचते और उन पर चारित्रिक दुचित्तापन हावी रहता है। यानी उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। वे बोलते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं। अच्छी पोशाक पहनने वाला और अच्छी किताब पढ़ने वाला व्यक्ति भी कभी-कभी अपनी प्रकृति में खराब होता है। 'रामायण' और 'महाभारत' हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें राम और कृष्ण के चरित्रों की तुलना होती है। राम को एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, वहीं कृष्ण रसिक और छलिया माने गए हैं। कृष्ण अपनी लीलाओं से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और राम अपने चरित्र के कारण। एक प्रसंग रामायण में आता है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और रावण ने कहा कि मैं शिव का पुरोहित हूं, मेरे पास इतना सैन्य बल और न जाने क्या-क्या है..! इस पर राम ने प्रश्न किया कि फिर यह युद्ध जीतेगा कौन, तो रावण ने कहा, राम तुम जीतोगे, क्योंकि एक चीज जो मेरे पास नहीं है और तुम्हारे पास है, वह है 'चरित्र बल'।

चरित्र मनुष्य का सबसे संवेदनशील और सशक्त पक्ष है। इसलिए दुष्ट सबसे पहले सज्जन के शील और चरित्र पर ही वार करता है। उस पर आघात करता है। इस पर बहुत लिखा गया है। शरतचंद्र की जीवनी विष्णु प्रभाकर ने 'आवारा मसीहा' के नाम से लिखी है। उसमें शरतचंद्र के वेश्याओं वाले इलाके में जाने पर समाज की प्रतिक्रिया आदि प्रसंगों में यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर मसीहा किसी बदनाम गली तक जाता है तो समाज उसे भी बदनाम कर देता है। 'अमर प्रेम' फिल्म का गीत है- 'कुछ तो लोग कहेंगे... लोगों का काम है कहना', मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग उसके बारे में ही बातें करते हैं, जो चरित्रवान है। वे सबसे पहले उजले को ही गंदला करते हैं। वरना सीता जैसी देवी को ही क्यों अग्नि परिक्षा देनी पड़ती? यह एक सामाजिक मनोवृत्ति है जिससे हर युग में एक सच्चे और चरित्रवान व्यक्ति का सामना होता है।

अंग्रेज जब देश की संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे तो वे देश के सम्मान का ही हरण कर रहे थे, क्योंकि ऐसा करना उन्हें सबसे सरल और अपने लिए हितकर लगा। तब से चालाक लोग चरित्र का सौदा करने लगे और व्यक्तित्व के दुचित्तेपन के शिकार होने लगे। अनैतिक और चरित्रहीन लोगों का गिरोह होता है, जबकि नैतिक और चरित्रवान व्यक्ति आमतौर पर अकेला होता है। कई बार उसे अकेला होना पड़ता है। नैतिकता को धर्म की मां माना जा सकता है। नैतिक हुए बगैर व्यक्ति मानवीय और धार्मिक नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि अनैतिक लोगों ने दुनिया को बांटने के लिए अक्सर धर्म का इस्तेमाल किया है। धर्म की आड़ लेकर या धर्म के नाम पर लोगों में वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की जाती है। जबकि नैतिक और चरित्रवान लोग अपने स्वभाव और नैतिक बल के साथ मानवता के मूल्यों को निबाहते हैं। सीता ने रावण को तिनके की ओट से अपना पति-परायण होना ज्ञात कराया। चरित्रवान को अपने चरित्र का प्रमाण देने की कभी आवश्यकता नहीं होती। 'प्रत्यक्षम् किम प्रमाणम्' वाली बात यहां सिद्ध होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आमतौर पर सच्चे व्यक्ति से ही प्रमाण की मांग की जाती है। हालांकि यह भी सही है कि जो व्यक्ति सत्य के पक्ष में होता है, वह खुद को प्रमाणित करने के प्रश्न पर परेशान नहीं होता। निर्भीकता उसकी ताकत होती है। संसार और समाज अगर निरंतर आगे की ओर प्रवहमान है तो इसका आधार सत्य ही है। आज समय जिस तरह की जटिलता से गुजर रहा है, उसमें साहसी और निर्भीक चरित्रों की आवश्यकता है जो समाज के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे सकें। अन्यथा इतिहास की सार्थकता समाप्त हो जाएगी और मनुष्य केवल वर्तमान में विचरण करने वाला सुविधाभोगी जीव मात्र रह जाएगा।

दुनिया मेरे आगे

> अनैतिक और चरित्रहीन लोगों का गिरोह होता है, जबकि नैतिक और चरित्रवान व्यक्ति आमतौर पर अकेला होता है। कई बार उसे अकेला होना पड़ता है। नैतिकता को धर्म की मां माना जा सकता है। नैतिक हुए बगैर व्यक्ति मानवीय और धार्मिक नहीं हो सकता।

बीती ताहि बिसार दे

आजकल के जीवन में हर कोई कहता मिल जाता है कि अगर उस समय ऐसा कर लेते तो ठीक होता। जैसे किसी से शादी करने के बाद मलाल करना या बीत चुके दिनों में अच्छे से पढ़ाई करना, पिता की बात मान कर व्यवसाय संभाल लेना आदि। इस मलाल के साथ जीने वाले दुनिया में तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। मगर इस मलाल का कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। हमने जो भी निर्णय लिए हैं, उनमें और भी ज्यादा नकारात्मकता दिखने लगेगी। इस मलाल के जाल में फंस कर लोग अवसाद का शिकार भी हो जाते हैं।

निर्णय प्रक्रिया में जरूरी तो नहीं कि प्रत्येक निर्णय शत-प्रतिशत ठीक हो। मानवीय प्रक्रिया में कुछ भूलवश त्रुटियों से निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों में सुधार करना चाहिए। अच्छा यह है कि आगे जीवन में बेहतर निर्णय निर्णय लिए जाएं, जो पहले की अपेक्षा और अधिक सुलझे हुए हों। हमें बीती बातों और गलतियों पर मलाल करने के बजाय उनसे सीखकर जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए।

– मधुसूदन बैरागी, इंदौर

शहर और गांव

'जागरूक बच्चे' (संपादकीय, 2 अप्रैल) पढ़ा। निस्संदेह इन बच्चों की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। पर हमें इस कुरीति को जड़ से मिटने के बारे में सोचना पड़ेगा। वह जगह नोएडा थी, इसलिए शायद हमें यह देखने को मिला कि कक्षा आठ की बच्ची को बाल विवाह से बचाया जा सका, लेकिन ऐसा हम किसी ग्रामीण अंचल में शायद नहीं देख सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह कुरीति बेहद जटिल समस्या है और बच्चियों के मां-बाप कभी पैसे की वजह से तो कभी ज्यादा बच्चे होने के कारण तो कभी किसी और कारण से बाल विवाह की आग में अपनी मासूम बच्ची को झोंक देते हैं। वहां की बच्चियों में इतना सहस भी नहीं है कि वे अपनी सहपाठी का जीवन बचाएं। इसलिए इस कुरीति पर समूचे समाज की सोच में बदलाव की जरूरत है। लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से एक कदम भी पीछे नहीं है और उतनी ही सक्षम हैं, जितने की पुरुष तो हमें उन्हें भी पढ़ाई और आगे बढ़ने के उतने ही अवसर देने चाहिए।

– बाल गोविंद, सेक्टर-44, नोएडा

चीन की भाषा

हालांकि अरुणाचल को लेकर चीन के दावों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक और कड़े शब्दों में खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन के अड़ियल रवैये के दृष्टिगत उनकी यह प्रतिक्रिया काफी नहीं है। ज्ञातव्य है कि विस्तारवादी चीन ने पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के तीस विभिन्न स्थानों के नए नामों की चौथी सूची जारी कर दी। चीन की ओर से अरुणाचल के क्षेत्रों के नाम बदलने का यह आपत्तिजनक क्रम निरंतर जारी है। हालांकि यह सही है कि चीन द्वारा नाम बदलने से भारत का क्षेत्र चीन का नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी चीन की इस जुर्रत का माकूल जवाब अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया देना चाहिए। वरना चीन की नापाक हरकतें बढ़ती रहेंगी। इन दिनों भारत के पड़ोसी देशों से भी चीन के आपत्तिजनक संबंध विकसित हो रहे हैं। हमें इस मामले में सतर्क रहना भी अत्यंत आवश्यक है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

प्रदूषण के वाहक

आज गांव से लेकर शहर तक प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक का सही विकल्प उपलब्ध न होने से सरकारी प्रतिबंध विफल साबित हो रहे हैं। प्लास्टिक से पिंड छुड़ाना बेहद मुश्किल कार्य है। पालिथीन की थैलियां, प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, झंडा सजावट की सामग्रियां हमारे दैनिक इस्तेमाल में शामिल हो चुकी हैं। आज भी मिट्टी के कप और प्लेट बनाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक की तुलना में उनका उपयोग कम हो रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ताड़ के पत्तों की टोकरी बनाई जाती है, जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कागज की थैलियां और कपड़े की थैलियों को इस्तेमाल में अधिक लाना चाहिए। आम जनों के बीच प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के विषय में जागरूकता फैलाने की जरूरत है और लोगों को प्लास्टिक का न्यूनतम इस्तेमाल करने की आदत विकसित करनी चाहिए।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

www.readwhere.com

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 6 अप्रैल, 2024

दैनिक जागरण

जिसके अंदर नफरत है उसे किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं

कांग्रेस के वादे

चुनावी तैयारियों और सहयोगी दलों से सीटों के तालमेल में पिछड़ी कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी करने में तो बढ़त हासिल कर ली, लेकिन उसने उसमें जो तमाम लोक-लुभावन वादे किए, वे यही रेखांकित कर रहे हैं कि वह समाजवादी सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना कराने के साथ आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक करने का वादा किया है। साफ है कि वह यह समझने को तैयार नहीं कि जाति एवं आरक्षण की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और यह समय आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा का है, ताकि यह जाना जा सके कि उन वर्गों का उत्थान कैसे हो, जो इतने वर्षों से आरक्षण जारी रहने के बाद भी अभी तक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर बने हुए हैं। यह निराशाजनक है कि कांग्रेस को अभी भी यह लगता है कि कर्ज माफी के जरिये खेती और किसानों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। यह तब है, जब यह बार-बार प्रमाणित हो चुका है कि कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होता। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने का भी वादा किया है। क्या यह वही कांग्रेस नहीं, जिसने मनमोहन सरकार के समय इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इन्कार करने के साथ एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझी थी?

कांग्रेस ने एक बार फिर गरीबी हटाओ पर जोर दिया, लेकिन उसका घोषणा पत्र निर्धनता निवारण के कारगर उपायों पर मौन है। इसके बजाय उसने जिस तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां करने और मौजूदा संविदा कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन दिया है, उससे तो यही लगता है कि वह सार्वजनिक उपक्रमों को नौकरियां बांटने का माध्यम बनाना चाहती है। कांग्रेस यह समझे तो अच्छा कि यह युग घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने का नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र को सशक्त करने का है, ताकि वे उत्पादकता बढ़ाने के साथ रोजगार देने का जरिया बन सकें। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा तो कर दिया कि केंद्र सरकार में 30 लाख पदों को भरने का काम किया जाएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या इतनी नौकरियां पर्याप्त होंगी? क्या यह उचित नहीं होता कि वह अपने घोषणा पत्र के जरिये यह भी बताती कि वह निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि पर जरूरत से ज्यादा निर्भर लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाएगी? यह अच्छा है कि कांग्रेस को यह समझ आ गया कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना मुश्किल है, लेकिन और भी अच्छा होता कि वह यह समझती कि वादों को न्याय कहना ही पर्याप्त नहीं होता। उन्हें पूरा करने की ठोस रूप रेखा भी चाहिए होती है। इसका घोषणा पत्र में अभाव ही दिखता है।

मतदान से दूरी उचित नहीं

लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद हो चुका है। सभी बड़े राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतर चुके हैं। चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। उत्तराखंड की पांचों सीटों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लोकसभा चुनाव कराने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इन तैयारियों के बीच कई स्थानों पर व्यवस्था से नाराज मतदाताओं की मतदान से दूरी बनाने के निर्णय लेने की बात सामने आ रही है। ऐसा कर क्षेत्र विशेष की जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इस कदम को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में क्षेत्रवासियों को यह सोचने की जरूरत है कि जिस कार्य के लिए वे यह कदम उठा रहे हैं, उसका समाधान सक्षम जनप्रतिनिधि चुन कर उसके माध्यम से कराया जा सकता है। किसी समस्या का समाधान न होने पर तंत्र के प्रति नाराजगी तो हो सकती है, लेकिन इसका हल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना कतई नहीं है। देखा जाए तो यह सबसे अच्छा मौका है जब मतदाता प्रत्याशियों के सामने अपने विषयों, मांगों को रख सकते हैं। सभी प्रत्याशियों से बातचीत कर यह देखें कि कौन उनकी मांगों का समाधान कराने में सक्षम है या उनकी मांगों को उस सक्षम स्तर तक ले जा सकता है, जहां इनका समाधान होना है। ऐसे प्रत्याशियों को मत देकर न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, बल्कि अपने विषयों को सही प्लेटफार्म पर भी रखा जा सकता है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लोकतंत्र के इस महापर्व पर अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा है। यह समझने की जरूरत है कि अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग न करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी में ही समस्या का समाधान निहित है।

जनतांत्रिक राजनीति की नई शैली

बद्री नारायण

विपक्ष को यह समझना होगा कि पीएम मोदी जनतांत्रिक राजनीति को एक नया रूप-स्वरूप प्रदान कर रहे हैं

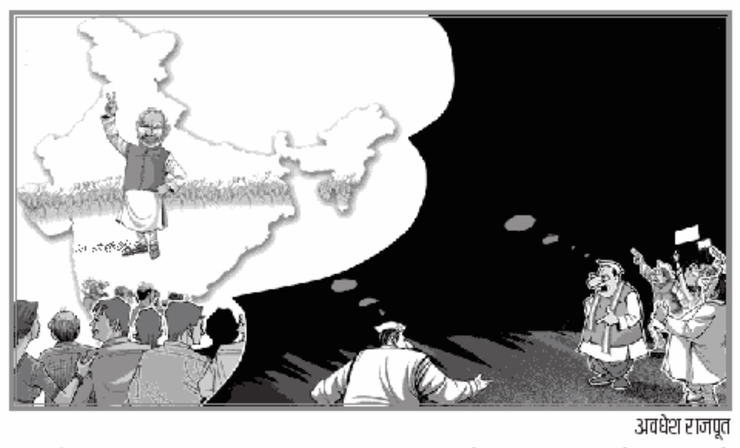

अवधेश राजपूत

लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। विभिन्न दलों द्वारा चुनाव क्षेत्रों के टिकट निर्धारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तो रैलियों के साथ रोड शो भी शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार में भाजपा ने बढ़त ले ली है। मोदी एक लोकप्रिय नेता ही नहीं, बल्कि आज की जनतांत्रिक राजनीति के शिल्पकार के रूप में उभर रहे हैं। देश की जनतांत्रिक राजनीति में अनेक बड़े नेता हुए, किंतु उनमें से कई बनी-बनाई लीक पर ही चलते रहे। कुछ ही हुए, जिन्होंने अपनी राजनीति के लिए नया रास्ता बनाया। यदि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को गहराई से विश्लेषित करें तो प्रतीत होगा कि उन्होंने अपनी राजनीति की एक नई शैली विकसित की है। वह राजनीति के ऐसे शिल्पकार के रूप में उभरे हैं, जो भारतीय परंपरा में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इसका एक कारण उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करना है।

यदि मोदी के राजनीतिक क्रियाकलापों की व्याख्या से कोई एक सूत्र तलाशें तो वह है सतत नवोन्मेष। इस नवोन्मेष की दिशा उनकी भारत के भविष्य की अवधारणा से बनती एवं आकार लेती है। उन्होंने जिस प्रकार 2047 तक विकसित भारत एवं हजार वर्ष के बाद के भारत का सपना देखा है, उसका स्वरूप और उभर कर आना है। इस नवोन्मेष की दूसरी दिशा थके, हारे, उदासीन जन में आशा जगाने की राजनीति विकसित करना एवं उन आशाओं को पूरा करने के लिए लोगों में क्षमता निर्माण की नीति पर काम करना है।

पिछले दिनों मैं उत्तर भारत के एक गांव में एक पिछड़े सामाजिक समूह के युवाओं से बात कर रहा था। मेरी बातों में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का संदर्भ आ रहा था। उन युवाओं ने कहा-'अब देश पहले जैसी दशा में नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है। सबके आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा है। नौकरी मिली तो ठीक, नहीं तो कुछ धंधा, रोजगार कर लेंगे। बैंक लोन, स्टार्टअप की अनेक योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं।' यह सब सुनकर मुझे लगा कि आधार तल पर लोगों में एक प्रकार की आशा जगी है और जड़ता टूटी है। बनारस, अयोध्या, उज्जैन जैसे तीर्थों के आधुनिकीकरण ने बड़े पैमाने पर तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के अनुसार 2023 में उत्तर प्रदेश में 48 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें से 16 लाख बाहर के देशों के थे। पर्यटकों के आवागमन ने इन तीर्थ केंद्रों के आसपास के गांवों, कस्बों में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाया है। इससे भी लोगों में जड़ता टूटी है एवं विकास की आशा जगी है।

मोदी की राजनीतिक शैली का एक तत्व लोगों में भविष्य के प्रति आशा सृजित करना भी है। मोदी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति में भविष्य को विमर्श का विषय बनाया है। पहले के कई प्रधानमंत्री या तो समकालीन समस्याओं के दबाव में या अपनी दृष्टिगत सीमा के कारण छोटे कालखंडों यथा पंचवर्षीय विकास की योजनाओं में ही बंध कर रह गए। उनके पास दीर्घकालीन भविष्य का सोच नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को सुनें तो 'भविष्य' शब्द उनमें प्रायः आपको मिलेगा ही नहीं। राममनोहर लोहिया ने एक आलेख में भारतीय राजनीति के इस संकट की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में राजनीतिक दलों में भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक शैली में एक अन्य तत्व सत्ता की राजनीति को सामाजिक राजनीति में रूपांतरित करना है। वह बार-बार कहते हैं कि सत्ता की राजनीति के पार जाकर हमें समाज से अपनी राजनीति को जोड़ना होगा। यहां वह हमें महात्मा गांधी की शैली में संवाद करते दिखते हैं, जहां वह विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष को अछूतों के उद्धार, पंथक एकता और अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपने अभियानों से बल प्रदान करते थे। मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने के साथ अनेक छोटे-छोटे सामाजिक मुद्दों को भी अपनी व्यापक राजनीति में जगह दी है। छात्रों से संवाद, परीक्षा पे चर्चा, युवाओं में तनाव बढ़ने की चिंता, स्क्रीन टाइम के बारे में संदेश, पंच प्रण की अवधारणा, काशी-तमिल संगमम् के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने के प्रयासों को उन्होंने अपनी राजनीति से जोड़ा है। समाज के हाशिये पर रहने वालों को भी 'मन की बात' में वह जगह देते रहे हैं। ऐसे में सत्ता की राजनीति विकास, आशा एवं सामाजिक मुद्दों की राजनीति में बदल जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति में धर्म एवं अध्यात्म की उपस्थिति को भी नए ढंग से परिभाषित किया है। साधु-संतों, मंदिरों, सूफी स्थलों से अपने प्रतीकात्मक संबंध स्थापित करते हुए उन्होंने जनता के विभिन्न वर्गों के मन में प्रवेश पाया है। इसी कारण उनकी छवि आज मात्र एक राजनेता की नहीं रह गई है, बल्कि उसके पार चली गई है। इस छवि ने एक सामाजिक नेता, सांस्कृतिक कार्यकर्ता तथा लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं में शामिल रहने वाले व्यक्तित्व का प्रतीक गढ़ा है। उनकी इस छवि ने विपक्ष की कठिनाई बढ़ा दी है।

यह उल्लेखनीय है कि भाजपा ने इस बार अपने कई विवाद पैदा करने वाले नेताओं का टिकट काट दिया है। अनंत कुमार हेगड़े, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी जैसे नेता शायद यह मानते थे कि विवाद पैदा कर राजनीति की जा सकती है। इनका टिकट कटना भी प्रधानमंत्री मोदी की नई राजनीतिक शैली की तरफ इशारा कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने विजयी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विवाद से बचिए। पिछले दिनों भी उन्होंने दोहराया कि पार्टी नेता विवाद से बचें और सिर्फ विकास कार्यों की चर्चा करें। इसे हम एक प्रकार से एक ऐसे समय जनतांत्रिक राजनीति में सकारात्मक राजनीति के निर्माण की शैली के रूप में देख सकते हैं, जब अनेक नेता विवाद एवं नकारात्मक चर्चा से अपनी राजनीतिक प्रसांगिकता बनाए रखना चाहते हैं। देखना होगा कि भारतीय राजनीति में आगे चल कर यह शैली कैसे फलती-फूलती एवं विकसित होती है और विपक्ष उसका सामना कैसे करता है?

(लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)
response@jagran.com

माफिया को मसीहा मानने की मानसिकता

अंबर जैदी

शायद ही किसी सजायाफ्ता माफिया नेता को उस तरह मसीहा कहा गया हो, जैसे मुख्तार को कहा गया

मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी भीड़। प्रेट्र

माफिया डान, सजायाफ्ता अपराधी के साथ नेता रहे मुख्तार अंसारी की न्यायिक हिरासत में उपचार के दौरान मौत के बाद उसके जनाजे में जैसी भीड़ दिखाई दी, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके नाना नौशेरा के शेर कहे जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपना बलिदान दिया था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी उसके रिश्तेदार हैं। मुख्तार अंसारी पर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे थे, जिनमें से कुछ में उसे सजा भी सुनाई गई। उसके खिलाफ साधारण अपराध के मुकदमे नहीं थे। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे किसी अपराधी की मौत पर जनता की प्रतिक्रिया राहत, तिरस्कार या फिर उदासीनता वाली होती है, लेकिन मुख्तार की मौत ने आक्रामक और साथ ही भावुक प्रतिक्रिया पैदा की। उसकी मौत पर दुख जताने और सवाल उठाने वालों में कई मुस्लिम पत्रकार और नेता भी शामिल थे। स्वाभाविक रूप से इनमें वही थे, जो खुद को सेक्युलर बताते हैं। आखिर मुख्तार की मौत पर ऐसी प्रतिक्रिया देखने को क्यों मिली? चूंकि मुख्तार माफिया के साथ एक नेता भी था, इसलिए उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ काम भी किए होंगे और कुछ लोगों की मदद भी की होगी, लेकिन माफिया किस्म के नेता ऐसा ही करते हैं, ताकि उनकी राजनीतिक पकड़ बनी रहे। वैसे तो अन्य नेता भी अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लेकिन शायद ही गंभीर अपराध में लिप्त किसी नेता को उस तरह मसीहा घोषित किया गया हो, जैसे मुख्तार को किया गया।

मुख्तार अंसारी पांच बार विधायक चुना गया। मुसलमानों के साथ उसे गरीब हिंदुओं के वोट भी मिलते थे। हालांकि उसे मसीहा बताने वाले मुस्लिम अधिक हैं। मुसलमानों का एक तबका ऐसा है, जिसके लिए उनके समाज का जो कोई भी व्यक्ति अपनी आपराधिक गतिविधियों से पुलिस और सरकार को चुनौती देता है, वह उनका नायक बन जाता है। चूंकि मुख्तार अंसारी के ज्यादातर शिकार हिंदू थे, इसलिए कुछ मुसलमानों की नजर में उसकी छवि काफिरों से लोहा लेने वाले की भी थी। उसे मसीहा मानने वाले यह समझने को तैयार नहीं कि उसे सजा भाजपा सरकार ने नहीं, अदालतों ने दी और वह भी तय न्याय प्रक्रिया के तहत। एक सजायाफ्ता अपराधी को मसीहा घोषित करने वालों ने एक तरह से न्यायपालिका के प्रति अपना अविश्वास ही जताया। इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं। कई ऐसे भ्रष्ट और अपराधी नेता हैं, जिन्हें सजा मिलने के बाद भी उनके समर्थक मसीहा के रूप में देखते हैं और इस तरह के तर्कों की आड़ लेते हैं कि उसे गलत फंसाया गया। अक्सर जातीय और मजहबी कारणों से कुख्यात अपराधियों को मसीहा के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब पढ़े-लिखे और यहां तक कि पत्रकार, आरजे और बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग भी ऐसा करने लगें तो मामला गंभीर हो जाता है। इन लोगों को अच्छी तरह पता था कि मुख्तार एक माफिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मौत पर आंसू बहाए।

असदुद्दीन ओवैसी खास तौर पर मुख्तार अंसारी के घर भी गए। उन्होंने वहां जाकर उसे जहर देने की आशंका जता दी। जाहिर है कि अनेक मुसलमानों ने उनकी बात पर यकीन किया। इसका एक कारण यह है कि ऐसे मुसलमान भाजपा को अपने शत्रु के रूप में देखते हैं और यहां तक कि उससे नफरत करते हैं। भाजपा के प्रति इसी नफरत को भुनाने और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए अन्य नेता भी मुख्तार के घर गए। भाजपा के प्रति नफरत रखने वाले मुस्लिम यह देखने को तैयार नहीं कि मुख्तार के कारनामे कैसे थे? मुसलमानों का एक तबका भारत के संविधान और यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में तभी भरोसा करता है, जब सत्ता में ऐसी सरकार हो, जो उसका तुष्टीकरण करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हो। मोदी या योगी सरकार की जनकल्याण की कोई योजना ऐसी नहीं, जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह जाति, मजहब के आधार पर लोगों में भेद करती है, फिर भी मुसलमानों को यह कहकर बरगलाने वालों की कमी नहीं कि भाजपा उनकी दुश्मन है। कई बार वे मुस्लिम भी इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, जिन्होंने भाजपा सरकार की आवास, शौचालय, बिजली, पानी संबंधी योजनाओं का लाभ लिया है।

चूंकि पहले की सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, इसलिए खुद को उनके वोटों का ठेकेदार समझने वाले मुस्लिम नेता अब अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वे भाजपा के शासन को हिंदुओं के शासन के रूप में देखते हैं। इस सोच ने उनकी मानसिकता को दूषित करने का काम किया है। इस्लामवादी और भारत पर फिर से इस्लामी शासन स्थापित करने का सपना देखने वाले भी मुख्तार को अपने आदर्श के रूप में देखते थे। इस्लामवादियों का एजेंडा भारत का इस्लामीकरण करना है। यह समय की मांग है कि सरकार मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदले, क्योंकि वहीं इस्लामी कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है। इसका कोई औचित्य नहीं कि इस्लामिक शिक्षा संस्थाएं सरकारी पैसे से चलें। सरकार से पैसा पाने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्थान का चरित्र पंथनिरपेक्ष होना चाहिए। उनका पाठ्यक्रम भी सरकार से अनुमोदित होना चाहिए। शरिया आधारित व्यक्तिगत कानून खत्म किए जाने चाहिए, क्योंकि वे मुसलमानों को मुख्यधारा में शामिल होने से रोकते हैं। हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में अलगाववाद कैसे दम तोड़ रहा है। मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि भारत में कभी भी शरिया आधारित शासन नहीं होगा और वह अपनी पुरातन संस्कृति के अनुरूप पंथनिरपेक्ष बना रहेगा।

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अल्प ही पर्याप्त है

अतीत के अभावों का दुखड़ा गाने वाले वर्तमान के आनंद से वंचित रहते हैं। कुछ को मलाल है, उन दिनों मकान बड़ा होता तो परिजनों को चहलकदमी, पढ़ाई, शयन आदि का अधिक आराम रहता और जीवन बेहतर होता। दूसरों के माता-पिता, सहोदर, संबंधी या मित्र जितने भले हैं, उनके भी होते तो वे गुल खिला देते। जो, जितना, आज उपलब्ध है उससे अतृप्त रहना कुछ ने अपनी नियति बना ली है। अपनों-परायों के जैसे मकान हैं, उनके पास जितनी चल-अचल संपत्ति है, उससे बेहतर और अधिक चाहिए! विडंबना है कि भव्य मकानों या अथाह संपत्तियों के स्वामियों को नहीं पता कि अतिरिक्त स्थान, संपदा का उपयोग कैसे करें। बेहतर जीवन के लिए मनुष्य को कितना चाहिए, और उसे पाने के उपायों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को अभागा ही कहा जाएगा। अधिक की चाहत में भटकते वे बेचारे नहीं जानते कि सीमित सुविधाओं-साधनों के बावजूद सुखमय जीवन बिताया जा सकता है। सुस्वादु या अधिक भोजन का सेवन व्यक्ति को अधिक स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि यह अनेक व्याधियों का कारण बनता है। जितनी बीमारियां और मौतें अधिक खाने से हो रही हैं उतना कम खाने से नहीं होतीं। ईश्वर का आभार मानते हुए भोजन की सीमित मात्रा हमें आवश्यक पोषण प्रदान कर देती है।

भलीभांति खाने, पहनने, स्वस्थ रहने के लिए ढेर सारा नहीं चाहिए। पशु-पक्षी उससे अधिक की लालसा नहीं रखते जितना उस क्षण आवश्यक है, न ही संचित करते हैं। इसीलिए वे निश्चिंत रहते हैं। शहरी कचरादानों में डाले गए खाने योग्य भोजन से उस शहर की भुखमरी मिट सकती है। शब्द हों, धन या ऊर्जा, जहां अल्प से कार्य सध जाए वहां अधिक का उपयोग बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा करना संसाधनों का दुरुपयोग और उनकी अवमानना है, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार दंडनीय है।

हरीश बड़थ्वाल

मानव विकास को मिले प्राथमिकता

देवेंद्रराज सुथार

मानव विकास सूचकांक बताता है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच कितनी है, उनका जीवन स्तर कैसा है

मानव विकास किसी भी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। हाल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास संबंधी रिपोर्ट में 193 देशों की सूची में भारत को 134वां स्थान मिला है। देश पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन मामूली सुधार पर्याप्त प्रगति का संकेत देने में विफल है। श्रीलंका (78वें) और चीन (75वें) जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भारत काफी पीछे है। यहां तक कि भारत भूटान (125वें) और बांग्लादेश (129वें) से भी नीचे है। हालांकि सूचकांक के कुछ कारकों में भारत में सुधार हुआ है। भारत में जीवन प्रत्याशा में 67.2 से 67.7 और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 12 से 12.6 की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भी 6,542 से बढ़कर 6,951 डालर हो गई है।

मानव विकास सूचकांक हमें यह बताता है कि किसी देश में लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच कितनी है, उनका जीवन स्तर कैसा है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। यह सूचकांक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डा. अमर्त्य सेन की मानवीय क्षमता की अवधारणा पर आधारित है। मानव विकास के तीन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर इस सूचकांक का निर्माण किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, संभावित स्कूली शिक्षा और पीपीपी आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। इस प्रकार इसमें देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में बुनियादी चीजों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समुचित जीवन स्तर पाने में सक्षम हैं या नहीं।

ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत ने जो प्रगति की है वह पर्याप्त नहीं है, अभी भी सभी नागरिकों के लिए जीवन की न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने की चुनौती बरकरार है। 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब पर्याप्त मानव विकास होगा। मानव विकास रिपोर्ट में भारत की निम्न स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहां विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। अमीर-गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। श्रम बल भागीदारी में लिंग अंतर बहुत व्यापक है, जिसमें महिलाएं 28.3 प्रतिशत हैं, जबकि पुरुष 76.1 प्रतिशत हैं। घर, कार्यस्थल और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना मानव विकास में कोई भी गुणात्मक सुधार संभव नहीं है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम मौजूद हैं, लेकिन कार्यान्वयन को और बेहतर बनाने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सबसे महत्वपूर्ण मानकों पर पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जेल से सरकार

'राजनीति में नैतिकता का सवाल' शीर्षक आलेख में हरेंद्र प्रताप ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं देने पर सवाल उठाया है। इस तरह वह देश में एक गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से ही क्यों सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं यह तो वही जानते हैं, लेकिन सवाल है कि जब उनके दो मंत्री मनीष सिसौदिया और सत्येंद्र जैन जेल गए थे तब उन्होंने उनका उनके जेल जाते ही इस्तीफा क्यों मंजूर कर लिया था? भले ही देश के संविधान में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है या नहीं, लेकिन सच है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। यह व्यावहारिक भी नहीं है। जेल के लिए एक नियमावली बनी है। उसे मानना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। वह जेल में कैबिनेट बैठक बुलाने और गोपनीय फाइलों के निपटारे की अनुमति नहीं देती। अगर अरविंद केजरीवाल अपने आपको बेगुनाह मानते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरफ तो वह भ्रष्ट और दागदार नेताओं के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उनकी जांच ईडी और सीबीआइ से करवाने की मांग करते हैं, लेकिन खुद ही ईडी की जांच को शक की नजर से देख रहे हैं। उनकी जेल से सरकार चलाने की जिद दूसरे भ्रष्ट और दागदार राजनेताओं को भी जेल से ही अपनी गतिविधियां चलाने के लिए प्रेरित कर रही है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

विरासत की सियासत

आजादी लोकतंत्र की बुनियादी शक्ति है। अफसोस इस बात का है कि हर शख्स अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज फायदा उठा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी का कारण वंशवाद और भ्रष्ट नेता हैं। विपक्षी दलों के नेतागण चुनावी अभियान के समय अक्सर ओछी, विवादित, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देखना यह है कि वंशवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अभियान कितना सफल होता है। बहरहाल नेताओं की गतिविधियों का कच्चा चिट्ठा जनता जनार्दन से छुपा नहीं है। विरासत में मिली नेतागिरी लोकतंत्रिक प्रणाली के लिए खतरा है। परिवारवाद की जड़ें कब काटेंगी, यह तो वक्त बताएगा।

कृष्ण खन्ना, नई दिल्ली

संकट में कांग्रेस और विपक्ष

अग्रलेख ''कांग्रेस की बीमारी'' लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस में मची भगदड़ और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी पर गंभीर चर्चा करता है। यह भगदड़ अन्य दलों में भी है, परंतु चर्चा में कम है। ऐसा लगता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए बना बेमेल विपक्षी गठबंधन इसके लिए दोषी है। आइएनडीआइए के विभिन्न दल अपनी-अपनी चुनौतियों, क्षेत्रीय विषमताओं, भ्रष्टाचार के आरोपों, सनातन के अपमान, हिंदुओं के प्रति हिंसात्मक गतिविधियों, नागरिकता संशोधन कानून और समान नागरिक संहिता के विरोध, अनुच्छेद-370 को हटाने के विरोध के कारण जन-मानस में भारी असंतोष का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो अनर्गल बयानबाजी की सीमाएं लांघ दी हैं। उनको हर समय संविधान खतरे में और देश में तानाशाही दिखाई देती है। जबकि संविधान के अंतर्गत ही वर्तमान में आम चुनाव हो रहे हैं। गठबंधन के विभिन्न दल एक-दूसरे को अपने क्षेत्र से बाहर करने पर तुले हैं। राहुल गांधी की बायनाड रैली में कांग्रेस के झंडे गायब दिखे। विपक्षी दलों का यह कैसा विचित्र चुनावी प्रबंधन है जिसमें कोई दूसरे दल का नेता समर्थन के लिए नहीं पहुंचता। नेताओं के पार्टी छोड़ने और भाजपा में आने से विपक्षी दलों को डबल नुकसान हो रहा है। अब कांग्रेस की बीमारी लाइलाज हो चुकी है। ओपिनियन पोल के अनुसार परिणाम आए तो कांग्रेस फिर आइसीयू में दिखाई देगी और अन्य छोटे और क्षेत्रीय दल वेंटिलेटर पर।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

जिसके अंदर नफरत है उसे किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं

कांग्रेस के वादे

चुनावी तैयारियों और सहयोगी दलों से सीटों के तालमेल में पिछड़ी कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी करने में तो बढ़त हासिल कर ली, लेकिन उसने उसमें जो तमाम लोक-लुभावन वादे किए, वे यही रेखांकित कर रहे हैं कि वह समाजवादी सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना कराने के साथ आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक करने का वादा किया है। साफ है कि वह यह समझने को तैयार नहीं कि जाति एवं आरक्षण की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और यह समय आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा का है, ताकि यह जाना जा सके कि उन वर्गों का उत्थान कैसे हो, जो इतने वर्षों से आरक्षण जारी रहने के बाद भी अभी तक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर बने हुए हैं। यह निराशाजनक है कि कांग्रेस को अभी भी यह लगता है कि कर्ज माफी के जरिये खेती और किसानों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। यह तब है, जब यह बार-बार प्रमाणित हो चुका है कि कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होता। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने का भी वादा किया है। क्या यह वही कांग्रेस नहीं, जिसने मनमोहन सरकार के समय इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इन्कार करने के साथ एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझी थी? कांग्रेस ने एक बार फिर गरीबी हटाओ पर जोर दिया, लेकिन उसका घोषणा पत्र निर्धनता निवारण के कारगर उपायों पर मौन है। इसके बजाय उसने जिस तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां करने और मौजूदा संविदा कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन दिया है, उससे तो यही लगता है कि वह सार्वजनिक उपक्रमों को नौकरियां बांटने का माध्यम बनाना चाहती है। कांग्रेस यह समझे तो अच्छा कि यह युग घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने का नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र को सशक्त करने का है, ताकि वे उत्पादकता बढ़ाने के साथ रोजगार देने का जरिया बन सकें। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा तो कर दिया कि केंद्र सरकार में 30 लाख पदों को भरने का काम किया जाएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या इतनी नौकरियां पर्याप्त होंगी? क्या यह उचित नहीं होता कि वह अपने घोषणा पत्र के जरिये यह भी बताती कि वह निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि पर जरूरत से ज्यादा निर्भर लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाएगी? यह अच्छा है कि कांग्रेस को यह समझ आ गया कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना मुश्किल है, लेकिन और भी अच्छा होता कि वह यह समझती कि वादों को न्याय कहना ही पर्याप्त नहीं होता। उन्हें पूरा करने की ठोस रूप रेखा भी चाहिए होती है। इसका घोषणा पत्र में अभाव ही दिखता है।

संवाद और धैर्य की कमी

यह सचमुच डर पैदा करने वाली घटना है। राजधानी के कंकड़बाग में गुरुवार को रसोई गैस के एक वेंडर की हत्या कर दी गई। डराने वाली बात यह है कि हत्या के लिए भाड़े के अपराधियों से तीस हजार रुपये का सौदा किया गया। महज पांच हजार की पेशगी लेकर वेंडर की जान ले ली गई। जान किसी की हो, उसकी अधिकतम या न्यूनतम कीमत नहीं तय की जा सकती है। लेकिन, दुखद यह है कि कम या अधिक रुपया लेकर जान का कारोबार हो रहा है। असल में यह कानून व्यवस्था की समस्या तो है ही, उससे कहीं अधिक सामाजिक समस्या भी है। कानून व्यवस्था की समस्या इस हद तक है कि रुपया लेकर हत्या करने वाले अपराधियों के मन में सजा का डर नहीं है। यह भी नहीं है कि हत्या करने के बाद अपराधी बच जाते हैं। कंकड़बाग में जिस दिन वेंडर की हत्या हुई, उसके अगले ही दिन हत्यारे पुलिस की पकड़ में आ गए। संभव है कि हत्या के प्रमाण जुट जाएं और सजा के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। यह हरेक अपराध में होता है। लेकिन, दुखद यह है कि लंबी अदालती कार्यवाही के दौरान सभी अपराधियों को उसके किए की सजा नहीं मिल पाती है। यही वह विषय है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। हालांकि, बिहार में पुलिस और न्यायपालिका की सक्रियता के कारण ऐसे उदाहरण भी भरे पड़े हैं, जिसमें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कम समय में किसी अपराधी को सजा दे दी गई है। लेकिन, हरेक मामले की स्पीडी ट्रायल संभव नहीं है। दूसरा पक्ष सामाजिक है। हम अनुभव कर सकते हैं कि शहरी जीवन में संवाद कम हो रहा है और सबसे अधिक कमी धैर्य की है। छोटी-छोटी बातों पर लोग उलझ पड़ते हैं।

> हत्या जैसी वारदात कानून व्यवस्था की समस्या तो है ही, उससे कहीं अधिक सामाजिक समस्या भी है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ना उसकी चुनावी संभावनाओं को कमजोर करेगा?

आज का सवाल
क्या दूरदर्शन पर फिल्म द केरल स्टोरी के प्रसारण को रोकने की मांग सही है?

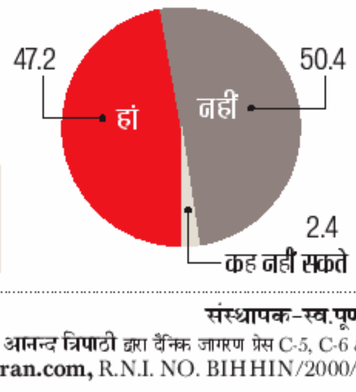

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

जनतांत्रिक राजनीति की नई शैली

बद्री नारायण

विपक्ष को यह समझना होगा कि पीएम मोदी जनतांत्रिक राजनीति को एक नया रूप-स्वरूप प्रदान कर रहे हैं

लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। विभिन्न दलों द्वारा चुनाव क्षेत्रों के टिकट निर्धारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तो रैलियों के साथ रोड शो भी शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार में भाजपा ने बढ़त ले ली है। मोदी एक लोकप्रिय नेता ही नहीं, बल्कि आज की जनतांत्रिक राजनीति के शिल्पकार के रूप में उभर रहे हैं। देश की जनतांत्रिक राजनीति में अनेक बड़े नेता हुए, किंतु उनमें से कई बनी-बनाई लीक पर ही चलते रहे। कुछ ही हुए, जिन्होंने अपनी राजनीति के लिए नया रास्ता बनाया। यदि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को गहराई से विश्लेषित करें तो प्रतीत होगा कि उन्होंने अपनी राजनीति की एक नई शैली विकसित की है। वह राजनीति के ऐसे शिल्पकार के रूप में उभरे हैं, जो भारतीय परंपरा में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इसका एक कारण उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करना है।

यदि मोदी के राजनीतिक क्रियाकलापों की व्याख्या से कोई एक सूत्र तलाशें तो वह है सतत नवोन्मेष। इस नवोन्मेष की दिशा उनकी भारत के भविष्य की अवधारणा से बनती एवं आकार लेती है। उन्होंने जिस प्रकार 2047 तक विकसित भारत एवं हजार वर्ष के बाद के भारत का सपना देखा है, उसका स्वरूप भविष्य में और उभर कर आना है। इस नवोन्मेष की दूसरी दिशा थके, हारे, उदासीन जन में आशा जगाने की राजनीति विकसित करना एवं उन आशाओं को पूरा करने के लिए लोगों में सतत क्षमता निर्माण की नीति पर काम करना है।

पिछले दिनों मैं उत्तर भारत के एक गांव में एक पिछड़े सामाजिक समूह के युवाओं से बात कर रहा था। मेरी बातों में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का संदर्भ आ रहा था। उन युवाओं ने कहा-'अब देश पहले जैसी दशा में नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है। सबके आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा है। नौकरी मिली तो ठीक, नहीं तो कुछ धंधा, रोजगार कर लेंगे। बैंक लोन, स्टार्टअप की अनेक योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं।' यह सब सुनकर मुझे लगा कि आधार तल पर लोगों में एक प्रकार की आशा जगी है और जड़ता टूटी है। बनारस, अयोध्या, उज्जैन जैसे तीर्थों के आधुनिकीकरण ने बड़े पैमाने पर तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के अनुसार 2023 में उत्तर प्रदेश में 48 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें से 16 लाख बाहर के देशों के थे। पर्यटकों के आवागमन ने इन तीर्थ केंद्रों के आसपास के गांवों, कस्बों में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाया है। इससे भी लोगों में जड़ता टूटी है एवं विकास की आशा जगी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक शैली का एक तत्व लोगों में भविष्य के प्रति आशा सृजित करना भी है। मोदी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति में भविष्य को विमर्श एवं नियोजन का विषय बनाया है। हमारे पहले के कई प्रधानमंत्री या तो समकालीन समस्याओं के दबाव में या अपनी दृष्टिगत सीमा के कारण छोटे कालखंडों यथा पंचवर्षीय विकास की योजनाओं में ही बंध कर रह गए। उनके पास दीर्घकालीन भविष्य का सोच नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को सुनें तो 'भविष्य' शब्द उनमें प्रायः आपको मिलेगा ही नहीं। राममनोहर लोहिया ने अपने एक आलेख में भारतीय राजनीति के इस संकट की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में राजनीतिक दलों में भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक शैली में एक अन्य तत्व सत्ता की राजनीति को सामाजिक राजनीति में रूपांतरित करना है। वह बार-बार कहते हैं कि सत्ता की राजनीति के पार जाकर हमें समाज से अपनी राजनीति को जोड़ना होगा। यहां वह हमें महात्मा गांधी की शैली में संवाद करते दिखते हैं, जहां वह विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष को अछूतों के उद्धार, पंथक एकता और अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपने अभियानों से बल प्रदान करते थे। मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने के साथ अनेक छोटे-छोटे सामाजिक मुद्दों को भी अपनी व्यापक राजनीति में जगह दी है। छात्रों से संवाद, परीक्षा पे चर्चा, युवाओं में तनाव बढ़ने की चिंता, स्क्रीन टाइम के बारे में संदेश, पंच प्रण की अवधारणा, काशी-तमिल संगमम् के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने के प्रयासों को उन्होंने अपनी राजनीति से जोड़ा है। समाज के हाशिये पर रहने वालों को भी 'मन की बात' में वह जगह देते रहे हैं। ऐसे में सत्ता की राजनीति विकास, आशा एवं सामाजिक मुद्दों की राजनीति में बदल जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति में धर्म एवं अध्यात्म की उपस्थिति को भी नए ढंग से परिभाषित किया है। साधु-संतों, मंदिरों, सूफी स्थलों से अपने प्रतीकात्मक संबंध स्थापित करते हुए उन्होंने जनता के विभिन्न वर्गों के मन में प्रवेश पाया है। यही कारण है कि उनकी छवि आज मात्र एक राजनेता की नहीं रह गई है, बल्कि उसके पार चली गई है। इस छवि ने एक सामाजिक नेता, सांस्कृतिक कार्यकर्ता तथा लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं में शामिल रहने वाले व्यक्तित्व का प्रतीक गढ़ा है। स्पष्ट है कि उनकी इस छवि ने विपक्ष की कठिनाई बढ़ा दी है।

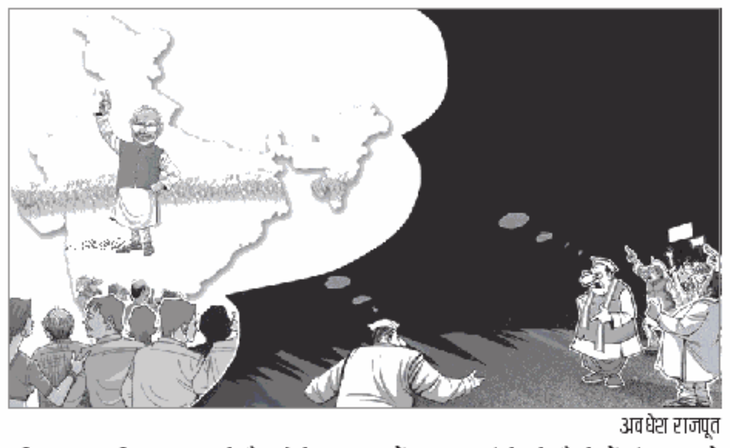

अवधेश राजपूत

यह उल्लेखनीय है कि भाजपा ने इस बार अपने कई विवादास्पद या विवाद पैदा करने वाले नेताओं का टिकट काट दिया है। अनंत कुमार हेगड़े, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी जैसे नेता शायद यह मानते थे कि विवाद पैदा कर राजनीति की जा सकती है। इनका टिकट कटना भी प्रधानमंत्री मोदी की नई राजनीतिक शैली की तरफ इशारा कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने विजयी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विवाद से बचिए। पिछले दिनों भी उन्होंने दोहराया कि पार्टी नेता विवाद से बचें और सिर्फ विकास कार्यों की चर्चा करें। इसे हम एक प्रकार से एक ऐसे समय जनतांत्रिक राजनीति में सकारात्मक राजनीति के निर्माण की शैली के रूप में देख सकते हैं, जब अनेक नेता विवाद एवं नकारात्मक चर्चा से अपनी राजनीतिक प्रसांगिकता बनाए रखना चाहते हैं। देखना होगा कि भारतीय राजनीति में आगे चल कर यह शैली कैसे फलती-फूलती एवं विकसित होती है और विपक्ष उसका सामना कैसे करता है?

(लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)
response@jagran.com

माफिया को मसीहा मानने की मानसिकता

माफिया डान, सजायाफ्ता अपराधी के साथ नेता रहे मुख्तार अंसारी की न्यायिक हिरासत में उपचार के दौरान मौत के बाद उसके जनाजे में जैसी भीड़ दिखाई दी, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके नाना नौशेरा के शेर कहे जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपना बलिदान दिया था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी उसके रिश्तेदार हैं। मुख्तार अंसारी पर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे थे, जिनमें से कुछ में उसे सजा भी सुनाई गई। उसके खिलाफ साधारण अपराध के मुकदमे नहीं थे। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे किसी अपराधी की मौत पर जनता की प्रतिक्रिया राहत, तिरस्कार या फिर उदासीनता वाली होती है, लेकिन मुख्तार की मौत ने आक्रामक और साथ ही भावुक प्रतिक्रिया पैदा की। उसकी मौत पर दुख जताने और सवाल उठाने वालों में कई मुस्लिम पत्रकार और नेता भी शामिल थे। स्वाभाविक रूप से इनमें वही थे, जो खुद को सेक्युलर बताते हैं। आखिर मुख्तार की मौत पर ऐसी प्रतिक्रिया देखने को क्यों मिली? चूंकि मुख्तार माफिया के साथ एक नेता भी था, इसलिए उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ काम भी किए होंगे और कुछ लोगों की मदद भी की होगी, लेकिन माफिया किस्म के नेता ऐसा ही करते हैं, ताकि उनकी राजनीतिक पकड़ बनी रहे। वैसे तो अन्य नेता भी अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लेकिन शायद ही गंभीर अपराध में लिप्त किसी नेता को उस तरह मसीहा घोषित किया गया हो, जैसे मुख्तार को किया गया।

मुख्तार अंसारी पांच बार विधायक चुना गया। मुसलमानों के साथ उसे गरीब हिंदुओं के वोट भी मिलते थे। हालांकि उसे मसीहा बताने वाले मुस्लिम अधिक हैं। मुसलमानों का एक तबका ऐसा है, जिसके लिए उनके समाज का जो कोई भी व्यक्ति अपनी आपराधिक गतिविधियों से पुलिस और सरकार को चुनौती देता है, वह उनका नायक बन जाता है। चूंकि मुख्तार अंसारी के ज्यादातर शिकार हिंदू थे, इसलिए कुछ मुसलमानों की नजर में उसकी छवि काफिरों से लोहा लेने वाले की भी थी। उसे मसीहा मानने वाले यह समझने को तैयार नहीं कि उसे सजा भाजपा सरकार ने नहीं, अदालतों ने दी और वह भी तय न्याय प्रक्रिया के तहत। एक सजायाफ्ता अपराधी को मसीहा घोषित करने वालों ने एक तरह से न्यायपालिका के प्रति अपना अविश्वास ही जताया। इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं। कई ऐसे भ्रष्ट और अपराधी नेता हैं, जिन्हें सजा मिलने के बाद भी उनके समर्थक मसीहा के रूप में देखते हैं और इस तरह के तर्कों की आड़ लेते हैं कि उसे गलत फंसाया गया। अक्सर जातीय और मजहबी कारणों से कुख्यात अपराधियों को मसीहा के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब पढ़े-लिखे और यहां तक कि पत्रकार, आरजे और बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग भी ऐसा करने लगें तो मामला गंभीर हो जाता है। इन लोगों को अच्छी तरह पता था कि मुख्तार एक माफिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मौत पर आंसू बहाए।

असदुद्दीन ओवैसी खास तौर पर मुख्तार अंसारी के घर भी गए। उन्होंने वहां जाकर उसे जहर देने की आशंका जता दी। जाहिर है कि अनेक मुसलमानों ने उनकी बात पर यकीन किया। इसका एक कारण यह है कि ऐसे मुसलमान भाजपा को अपने शत्रु के रूप में देखते हैं और यहां तक कि उससे नफरत करते हैं। भाजपा के प्रति इसी नफरत को भुनाने और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए अन्य नेता भी मुख्तार के घर गए। भाजपा के प्रति नफरत रखने वाले मुस्लिम यह देखने को तैयार नहीं कि मुख्तार के कारनामे कैसे थे? मुसलमानों का एक तबका भारत के संविधान और यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में तभी भरोसा करता है, जब सत्ता में ऐसी सरकार हो, जो उसका तुष्टीकरण करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हो। मोदी या योगी सरकार की जनकल्याण की कोई योजना ऐसी नहीं, जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह जाति, मजहब के आधार पर लोगों में भेद करती है, फिर भी मुसलमानों को यह कहकर बरगलाने वालों की कमी नहीं कि भाजपा उनकी दुश्मन है। कई बार वे मुस्लिम भी इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, जिन्होंने भाजपा सरकार की आवास, शौचालय, बिजली, पानी संबंधी योजनाओं का लाभ लिया है।

चूंकि पहले की सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, इसलिए खुद को उनके वोटों का ठेकेदार समझने वाले मुस्लिम नेता अब अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वे भाजपा के शासन को हिंदुओं के शासन के रूप में देखते हैं। इस सोच ने उनकी मानसिकता को दूषित करने का काम किया है। इस्लामवादी और भारत पर फिर से इस्लामी शासन स्थापित करने का सपना देखने वाले भी मुख्तार को अपने आदर्श के रूप में देखते थे। इस्लामवादियों का एजेंडा भारत का इस्लामीकरण करना है। यह समय की मांग है कि सरकार मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदले, क्योंकि वहीं इस्लामी कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है। इसका कोई औचित्य नहीं कि इस्लामिक शिक्षा संस्थाएं सरकारी पैसे से चलें। सरकार से पैसा पाने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्थान का चरित्र पंथनिरपेक्ष होना चाहिए। उनका पाठ्यक्रम भी सरकार से अनुमोदित होना चाहिए। शरिया आधारित व्यक्तिगत कानून खत्म किए जाने चाहिए, क्योंकि वे मुसलमानों को मुख्यधारा में शामिल होने से रोकते हैं। हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में अलगाववाद कैसे दम तोड़ रहा है। मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि भारत में कभी भी शरिया आधारित शासन नहीं होगा और वह अपनी पुरातन संस्कृति के अनुरूप पंथनिरपेक्ष बना रहेगा।

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं)
response@jagran.com

शायद ही किसी सजायाफ्ता माफिया नेता को उस तरह मसीहा कहा गया हो, जैसे मुख्तार को कहा गया

अंबर जैदी

मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी भीड़ ● पीटीआई

ऊर्जा

अल्प ही पर्याप्त है

अतीत के अभावों का दुखड़ा गाने वाले वर्तमान के आनंद से वंचित रहते हैं। कुछ को मलाल है, उन दिनों मकान बड़ा होता तो परिजनों को चहलकदमी, पढ़ाई, शयन आदि का अधिक आराम रहता और जीवन बेहतर होता। दूसरों के माता-पिता, सहोदर, संबंधी या मित्र जितने भले हैं, उनके भी होते तो वे गुल खिला देते। जो, जितना, आज उपलब्ध है उससे अतृप्त रहना कुछ ने अपनी नियति बना ली है। अपनों-परायों के जैसे मकान हैं, उनके पास जितनी चल-अचल संपत्ति है, उससे बेहतर और अधिक चाहिए! विडंबना है कि भव्य मकानों या अथाह संपत्तियों के स्वामियों को नहीं पता कि अतिरिक्त स्थान, संपदा का उपयोग कैसे करें। बिना विचारे ऐसी वस्तुएं बटोर ली जाती हैं, जो काम की नहीं होतीं।

बेहतर जीवन के लिए मनुष्य को कितना चाहिए, और उसे पाने के उपायों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को अभागा ही कहा जाएगा। अधिक की चाहत में भटकते वे बेचारे नहीं जानते कि सीमित सुविधाओं-साधनों के बावजूद सुखमय जीवन बिताया जा सकता है। सुस्वादु व्यंजन या अधिक भोजन का सेवन व्यक्ति को अधिक स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि यह अनेक व्याधियों का कारण बनता है। जितनी बीमारियां और मौतें अधिक खाने से हो रही हैं उतना कम खाने से नहीं होतीं। ग्राही मुद्रा में ईश्वर का आभार मानते हुए भोजन की सीमित मात्रा हमें आवश्यक पोषण प्रदान कर देती है।

भलीभांति खाने, पहनने, स्वस्थ रहने के लिए ढेर सारा नहीं चाहिए। पशु-पक्षी उससे अधिक की लालसा नहीं रखते जितना उस क्षण आवश्यक है, न ही संचित करते हैं। इसीलिए वे निश्चिंत रहते हैं। शहरी कचरादानों में डाले गए खाने योग्य भोजन से उस शहर की भुखमरी मिट सकती है। शब्द हों, धन या ऊर्जा, जहां अल्प से कार्य सध जाए वहां अधिक का उपयोग बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा करना संसाधनों का दुरुपयोग और उनकी अवमानना है, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार दंडनीय है।

हरीश बड़थ्वाल

पाठकनामा
pathaknama@pat.jagran.com

गलत परंपरा स्थापित करने की जिद

'राजनीति में नैतिकता का सवाल' शीर्षक आलेख में हरेंद्र प्रताप ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं देने पर सवाल उठाया है। इस तरह वह देश में एक गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से ही क्यों सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं यह तो वही जानते हैं, लेकिन सवाल है कि जब उनके दो मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल गए थे तब उन्होंने उनका उनके जेल जाते ही इस्तीफा क्यों मंजूर कर लिया था? भले ही देश के संविधान में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है या नहीं, लेकिन सच है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। यह व्यावहारिक भी नहीं है। जेल के लिए एक नियमावली बनी है। उसे मानना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। वह जेल में कैबिनेट बैठक बुलाने और गोपनीय फाइलों के निपटारे की अनुमति नहीं देती। अगर अरविंद केजरीवाल अपने आपको बेगुनाह मानते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरफ तो वह भ्रष्ट और दागदार नेताओं के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उनकी जांच ईडी और सीबीआइ से करवाने की मांग करते हैं, लेकिन खुद ही ईडी की जांच को शक की नजर से देख रहे हैं। उनकी जेल से सरकार चलाने की जिद दूसरे भ्रष्ट और दागदार राजनेताओं को भी जेल से ही अपनी गतिविधियां चलाने के लिए प्रेरित कर रही है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

परीक्षाओं के प्रश्न बन जाएंगे केजरीवाल

'राजनीति में नैतिकता का सवाल' शीर्षक आलेख में हरेंद्र प्रताप ने अन्ना हजारे आंदोलन से उपजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद का त्याग कर संविधानिक संकट उत्पन्न नहीं करने की सलाह दी है। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोप में अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे प्रकरण प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित या साक्षात्कार में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां पुस्तकों में यही पढ़ेंगी कि जन आंदोलन से निकले एक बड़े ओहदे वाले सरकारी अधिकारी त्याग पत्र देकर राजनीति में आते हैं। दिल्ली वासियों का विश्वास जीत कर मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल पहुंच जाते हैं, फिर भी त्याग पत्र नहीं देते। अब केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे जेल से ही शासन चलाएंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। भाजपाई इसका बड़ा कारण भव्य नव्य मुख्यमंत्री आवास का मोह बता रहे हैं। वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इस महल से सपरिवार बाहर हो जाएंगे। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास की साज सज्जा व नवीकरण में वर्ष 2015 से 2022 के बीच 29.56 करोड़ रुपये खर्च किए गए। भाजपा का आरोप है कि जब दिल्ली कोविड की चपेट में थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री करोड़ों खर्च करके अपने घर को सजा रहे थे। साल 2013 में कहते थे, सरकारी घर, सुरक्षा एवं सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने तो घर को सजाने के लिए बड़ी राशि खर्च कर दी। सरकारी संपत्ति का एक समय सीमा तक उपभोग किया जाता है। यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

हम भी अपनी अपेक्षाएं बताएं

आगामी लोक सभा चुनावों को लेकर प्रत्येक राजनीतिक दल घोषणा या संकल्प पत्र जारी करने लगे हैं। जिसमें समस्त मतदाताओं से वादा किया जाएगा कि सत्ता प्राप्त होने पर वह इन्हें पूरा करेगा। जिस तरह दल वादे करते हैं, उसी तरह हमें भी हक हैं कि हम राजनीतिक दलों को यह बताएं कि हमें अगली सरकार से पांच वर्षों में क्या क्या अपेक्षाएं हैं। यथा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बने। तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बने। सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर हो। विद्युत वाहनों का अधिकतम उपयोग हो। चांद पर उतर कर विजय पताका फहराएं। भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्णतः प्राप्त करे। मथुरा एवं वाराणसी में क्रमशः कृष्ण एवं शंकर के भव्य मंदिर बनें। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी है, अब प्रत्येक घर में बिजली हो। प्रत्येक के पास निज आवास हो। प्रत्येक घर में नल से जल प्राप्त हो। कोई भी गरीबी रेखा के नीचे न हो। सभी इतने सशक्त हों कि बिजली पानी निशुल्क पाने की इच्छा ही नहीं रखें। सभी का बैंक खाता हो। सभी सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उठा सकें। कोई भी कर्ज माफी की इच्छा नहीं रखे। किसानों की आय दोगुनी हो जाए। पूरे राष्ट्र में कामन सिविल कोड लागू हो। सीएए लागू हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और लागू हो। सभी विदेशी बाहर निकाले जाएं। सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का प्रबंध हो।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

पोस्ट

राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मोदी ने नहीं और केजरीवाल को जेल में मोदी ने डाला है, कोर्ट ने नहीं। अजीब तर्क है।

सुधीर भारतीय@seriousfunnyguy

चुनाव के शपथपत्र के अनुसार राहुल गांधी ने शेयर बाजार में करोड़ों रुपये का निवेश किया है। मजे की बात है कि एचएएल और एलआइसी के समर्थक राहुल गांधी ने एक रुपया भी पब्लिक सेक्टर में नहीं लगाया है।

साकेत@saket71

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में तब अधिक गंभीरता आएगी, जब इन मामलों को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए। अन्यथा भारत में आरोप लगाओ और खिसको की लंबी परंपरा रही है। जेल में बंद होने पर गुनहगार मान लेना और बाहर आते ही सिर पर बैठा लेना, आम चलन बन गया है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

नेताओं के दलबदल से एतराज नहीं है। यह उनका अधिकार है कि किस दल में रहें। दलबदल के साथ ही उन्हें अपने उन बयानों के लिए भी जनता से सार्वजनिक माफी जरूर मांगनी चाहिए, जिनमें उन्होंने सामने वाले दल और उसके नेताओं को जम कर कोसा था।

विनोद अग्निहोत्री@VinodAgnihotri7

जनपथ

धरती वीरों से नहीं हुई अभी तक हीन,
कहते हैं दामाद जी रहे अमेठी छीन।
रहे अमेठी छीन कमर कसि बैठे शायद,
शायद अब 'परिवार' कर रहा गुप्त कवायद!
राजनीति रॉबर्ट नहीं है स्वीट इमरती,
पकड़ न लेना आप अमेठी वाली धरती!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक पिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 24 अंक 351

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का
75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

जीवन का सबसे बेहतर उपयोग इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करना है, जो अधिक समय तक जीवित रहने वाली हो। -विलियम जेम्स

हरियाणा पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट का जो पर्दाफाश किया गया है, उससे अस्पतालों, डॉक्टरों, आदि की मिलीभगत के अलावा इसके पीछे किसी बड़े वैश्विक तंत्र के होने की आशंका पैदा होती है, जिसे तोड़े जाने के साथ-साथ गंभीर तफ्तीश की भी जरूरत है।

अंगों के सौदागर

अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा गुरुग्राम में बांग्लादेश के कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने से मानव अंगों की तस्करी का संवेदनशील मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले साल मई में विशाखापत्तनम में, अप्रैल व जून, 2022 में क्रमशः बंगलूरू तथा दिल्ली के हौजखास में और 2021 में गुवाहाटी में ऐसे मामले सामने आए थे। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से मानव अंगों की तस्करी के मामले उजागर हुए हैं, उससे पता चलता है कि ये गिरोह किस तरह से पूरे देश में अपना जाल बिछा रहे हैं। ताजा मामले में मिली जानकारी के अनुसार, यह गिरोह बांग्लादेश के मरीजों को अपने जाल में फंसाकर गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में ठहराता था। फिर जयपुर के एक बड़े अस्पताल में उनका किडनी प्रत्यारोपण किया जाता था। दाता व ग्राही, दोनों ही बांग्लादेश के होते थे। गिरोह को संचालित करने वाला सरगना झारखंड का मोहम्मद मुर्तजा अंसारी अभी फरार है।

उल्लेखनीय है कि देश में मानव अंगों की तस्करी का यह अवैध धंधा बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों, तकनीशियनों व अस्पताल प्रबंधन की मिलीभगत से बेहद गोपनीय ढंग से चल रहा है। जब भी इस तरह का कोई मामला पकड़ा जाता है, तो उसे रफा-दफा करने का रवैया ही दिखता है। वर्ष 1994 में ही देश में अवैध अंग प्रत्यारोपण रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया था, इसके बावजूद अगर ऐसे रैकेट पनप रहे हैं, तो इसलिए कि ये रैकेट एक समानांतर वैश्विक अपराध व्यवस्था के अंग हैं, जिनका नेटवर्क देश के कई राज्यों समेत, दूसरे देशों में भी फैला हुआ है। नियामक एजेंसियों की नाक के नीचे जिस तरह से ये अपराध अंजाम दिए जाते हैं, वह क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ इनके गठजोड़ की ओर इशारा करता है, जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए। गरीबी के अलावा बेरोजगारी और अंगों की मांग व पूर्ति में असंतुलन भी तस्करी को बढ़ावा देता है। कुछ वर्ष पहले सरकार ने खुद लोकसभा में बताया था कि मानव अंगों की मांग को देखते हुए आपूर्ति काफी कम है। ताजा मामले में ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश, भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी होने के साथ वहां की शेख हसीना सरकार के साथ हमारे सामरिक रिश्ते भी हैं। ऐसे में, विश्वास बनाए रखते हुए ही समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। जिस संगठित और योजनाबद्ध तरीके से ये अपराध हो रहे हैं, वे व्यवस्था के भीतर पनपती आपराधिक विकृति की ओर इशारा तो करते ही हैं, इनके पीछे किसी बड़े तंत्र के होने की आशंका भी पैदा करते हैं, जिसे तोड़े जाने की जरूरत है।

वे अपने ही देश को अस्थिर कर रहे हैं

'बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप' का विरोध करने के लिए भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का 'इंडिया आउट' अभियान, जो ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना उतना नहीं है, जितना ढाका की सरकार को अस्थिर करना।

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली विपक्षी इस्लामवादी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बहिष्कार के बावजूद जनवरी, 2024 के चुनाव में जीत हासिल करके शेख हसीना पांचवीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं। छिटपुट हिंसा के बीच व्यापक रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से 40 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ। शेख हसीना पर पश्चिमी देशों का दबाव था। लेकिन भारत ने निजी तौर पर इस हस्तक्षेप का विरोध किया।

शेख हसीना की स्वायत्त विदेश नीति, भारत से निकटता और बांग्लादेश की शानदार सफलता की वजह से पश्चिमी देश उन्हें सत्ता से बाहर करना चाहते थे। इसलिए वे भारत और बांग्लादेश के बीच दरार पैदा करने के लिए 'इंडिया आउट' अभियान चला रहे हैं। यह निराश इस्लामवादियों को सक्रिय होने का मौका देता है। अर्थव्यवस्था को धर्म के साथ मिलाने का नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। इसे पाकिस्तान, सूडान और अफगानिस्तान, आदि के हालात से समझा जा सकता है। बांग्लादेश के इस्लामवादी समूहों का मुख्य लक्ष्य बांग्लादेश में शरिया कानून से शासन चलाना है। जहां आर्थिक मंदी हसीना की मुख्य चुनौती है, वहीं देश का बढ़ता इस्लामीकरण चिंता की बात है। पहले की तुलना में अब ज्यादा बांग्लादेशी महिलाएं बुर्का और हिजाब में दिखती हैं।

दीपक वोहरा
पूर्व राजनयिक

शासन परिवर्तन आंदोलन का नेतृत्व ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कर रहा है, जिसकी स्थापना खतरनाक जॉर्ज सोरोस ने की है, जो न्याय, लोकतांत्रिक शासन और मानवाधिकारों (और दुनिया को नियंत्रित करने के अमेरिकी हित) के लिए काम करने वाले तथाकथित स्वतंत्र समूहों का सबसे बड़ा निजी वित्तपोषक है। पहला बांग्लादेशी इस्लामी उग्रवादी गुट 1989 में उभरा, जब कई दर्जन गुटों का एक नेटवर्क स्थापित और विस्तारित हुआ। भारत मुक्ति संग्राम के समय से ही बांग्लादेश की बाहरी चुनौतियों से निपटा है। भारत ने अवामी लीग का समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका उसके खिलाफ खड़े थे। ये सभी शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दक्षिण एशिया में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश के रूप में भारत कमजोरों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों का सामना करता है, लेकिन हमारे सभी छोटे पड़ोसियों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। जाहिर है, सही संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन हम संवेदनशील प्रयास कर रहे हैं। क्या 'बांग्लादेश के घरेलू मामलों में निरंतर हस्तक्षेप' का विरोध करने के लिए भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का इंडिया आउट अभियान, जो ज्यादातर सोशल मीडिया पर चल रहा है, काम करेगा? इसका जवाब है-नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना उतना नहीं है, जितना ढाका की सरकार को अस्थिर करना।

बांग्लादेश भारत से आयात पर निर्भर है, जो कुल मिलाकर 16 अरब डॉलर से ज्यादा का होता है। इसमें खाद्य, ईंधन, उर्वरक, औद्योगिक कच्चा माल जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं, जबकि उसके कॉरपोरेट सेक्टर सॉफ्टवेयर और सेवा-आधारित कुशल भारतीय श्रमिकों और विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं। भारत ने बांग्लादेश को विकास सहायता के मद में 10 अरब डॉलर से ज्यादा रकम दी है। भारत अगर बांग्लादेश से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बांग्लादेश चीन से आयात करेगा?

'इंडिया आउट' अभियान से जुड़े लाखों बीएनपी समर्थकों का झुकाव जिहादवाद और हिंदू विरोधी भावनाओं की ओर है, जो इस क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है। बांग्लादेशी मदरसे उग्रवाद के लिए खाद-पानी मुहैया कराते रहते हैं। हिंदुओं पर छिटपुट हमले और उनकी संपत्तियों को लूटने की घटनाएं होती रहती हैं।

इन सबके बावजूद बांग्लादेश भारत के लिए और भारत बांग्लादेश के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। नदी जल का बंटवारा, जलवायु परिवर्तन से लड़ना, अधिक आयात, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर सीमा प्रबंधन-ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। कई दक्षिण एशियाई देश यह सबक ले रहे हैं कि चीन वास्तव में उन्हें अपने बराबर नहीं मानता।

बांग्लादेश का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में अपने 16.7 करोड़ लोगों के लिए उच्च-मध्यम आय का दर्जा प्राप्त करना है, जो भारत के समर्थन के बिना संभव नहीं है। कुछ ही महीने पहले ढाका ने अपनी भुगतान संतुलन की लड़खड़ाती स्थिति को देखते हुए आईएमएफ से ऋण मांगा था। बांग्लादेश का कर-जीडीपी अनुपात दुनिया में सबसे कम है। ईंधन की कीमतों में रातों-रात 50 फीसदी की वृद्धि हुई और लोग सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश को भारत से पैसा, निवेश, तकनीक और खाद्यान्न चाहिए। जबकि भारत चाहता है कि वहां भारत-विरोधी गुटों को पनाह नहीं मिले, गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो और चीन को इतना तवज्जो न दिया जाए कि हमारे सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचे।

कोई भी अर्थव्यवस्था तब संकट में होती है, जब उसे बढ़ती ऊर्जा लागत, बढ़ती मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल और सिकुड़ते निर्यात बाजारों का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश को इन सबके साथ-साथ और भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है। वस्त्र उद्योग बांग्लादेश का गौरव है, लेकिन कारखाने पहले से ही अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के ऑर्डर में मंदी, तैयार माल की कम कीमतों, वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की ऊंची कीमतों और लगातार बिजली कटौती के कारण जूझ रहे हैं। महंगी प्राकृतिक गैस की कमी के कारण 2026 तक बिजली कटौती का खतरा मंडरा रहा है, जिससे निर्माताओं को नुकसान हो रहा है। इसका बुरा प्रभाव हो सकता है।

बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 17 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है, क्योंकि इसका केंद्रीय बैंक मुद्रा का बचाव करने में नाकाम रहा है, जो अब डॉलर के मुकाबले लगभग 110 टका है। मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग तीन महीने के आयात बिल का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे में, कौन उनकी मदद कर सकता है? जाहिर है, पहले भी भारत ने ही 4.5 अरब डॉलर का अनुदान एवं ऋण देकर उसकी मदद की थी।

जीवन धारा

दादा भगवान

तुम अपने से ऊपर, जितने ऊपर प्रीति करोगे, उतने ही तुम ऊपर जाने लगोगे, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। इसलिए तो हमने श्रद्धा को बड़ा मूल्य दिया है सदियों से, क्योंकि श्रद्धा आदमी को बदलती है।

जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं उसका विकास नहीं

कोई आदमी धन कमाने में लगा है--धन से उसकी प्रीति है। कोई आदमी पद के पीछे पागल है; पद तो गौण है, प्रतिष्ठा की प्रीति है। जहां भी खोजोगे, तुम प्रीति को ही पाओगे। पापी में और पुण्यात्मा में, तुम एक ही तत्व को पाओगे, वह तत्व प्रीति है।

प्रीति बड़ा बुनियादी सत्य है; इसे हृदय में सम्हाल कर रखना। प्रीति महंगा सौदा है, हर किसी से मत लगा लेना। जिससे लगाई, वैसे ही हो जाओगे। प्रीति का अर्थ ही यही होता है कि मैं यह होना चाहता हूं। राजनेता गांव में आया और तुम भीड़ लगाकर पहुंच गए। तुम गहरे में चाहते हो कि मेरे पास भी पद हो, प्रतिष्ठा हो; इसलिए पद और प्रतिष्ठा की पूजा है। कोई संगीत सुनता है, तो धीरे-धीरे उसकी चेतना में संगीत की छाया पड़ने लगती है।

फिर प्रीति के बहुत ढंग हैं, वे समझ लेने चाहिए। एक प्रीति है, जो तुम्हारी पत्नी में होती है, मित्रों में होती है, पति में होती है, भाई-बहन में होती है। उस प्रीति को हम प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ होता है: उसके साथ, जो बराबर है। तुमसे ऊपर भी नहीं, तुमसे नीचे भी नहीं; तुम्हारे जैसा है; जिससे आलिंगन हो सकता है; उसको प्रेम कहते हैं। समतुल्य व्यक्तियों में प्रीति होती है, तो प्रेम कहते हैं।

फिर एक प्रीति होती है माता, पिता या गुरु में; उसे श्रद्धा कहते हैं। कोई तुमसे ऊपर है; प्रीति को पहाड़ चढ़ना पड़ता है। इसलिए श्रद्धा कठिन होती है। श्रद्धा में दांव लगाना पड़ता है। बहुत कम लोगों में वैसी प्रीति मिलेगी, जिसको श्रद्धा कहें। माता-पिता से कौन प्रीति करता है! कर्तव्य निभाते हैं लोग। अपने से ऊपर प्रीति करने में पहाड़ चढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और ध्यान रखना, तुम अपने से ऊपर, जितने ऊपर प्रीति करोगे, उतने ही तुम ऊपर जाने लगोगे, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। इसलिए तो हमने श्रद्धा को बड़ा मूल्य दिया है सदियों से, क्योंकि श्रद्धा आदमी को बदलती है। तुम्हारे हाथ तुमसे ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और तुम्हारे पैर किसी ऊर्ध्वगमन पर गतिमान होते हैं। तुम्हारी आंखें ऊंचे शिखरों से टकराती और चुनौती लेती हैं। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, उसके जीवन में विकास नहीं है।

अपने से छोटे के प्रति जो प्रीति होती है उसका नाम स्नेह है। मेरे देखे, अपने से छोटे के प्रति सच्ची प्रीति और ठीक प्रीति तभी होती है, जब अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा हो; अन्यथा नहीं होती। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने से छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है। और उस व्यक्ति के जीवन में एक और क्रांति घटती है- अपने से सम के प्रति सम्यक प्रेम होता है। उसके जीवन में प्रेम का छंद बंध जाता है। छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है, धारा की तरह बहता है उसका प्रेम। वह कोई शर्तबंदी नहीं करता कि तुम ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, कि तुम ऐसे होओगे, तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा।

भीतरी रसायन...

सूत्र

प्रीति का तत्व रूपांतरकारी है। प्रीति का तत्व भीतरी रसायन है। और बिना प्रीति के कोई भी नहीं रह सकता। जैसे शरीर सांस से जीता है, आत्मा प्रीति से जीती है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रीति न हो, तो तुम आत्महत्या करने पर उतारू हो जाओगे। या कभी तुम्हारी प्रीति का सेतु टूट जाए, तो तुम टूट जाओगे। हम प्रीति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं।

दूसरा पहलू

आगरा किले के शाह बुर्ज से बाहर तक जाने वाली बादशाह जहांगीर की बनवाई सोने की 30 गज लंबी जंजीर में 60 घंटियां थीं।

जब बूढ़े घोड़े ने घंटी बजाकर मांगा इंसाफ

आज इंसाफ की वह सोने से बनीं जंजीरें और घंटियां कहीं मौजूद नहीं हैं, पर आगरा किले में वह जगह जरूर मौजूद है। किले के शाह बुर्ज पर लगी यह 30 गज लंबी जंजीर एक खंभे से बांधी गई थी। मुगल बादशाह जहांगीर की बनवाई इस जंजीर में कुल 60 घंटियां थीं। ...और अब सिर्फ वे किस्से मौजूद हैं, जिनसे क्रूर बादशाह को न्यायप्रिय बताने की छवि गढ़ी जाती थी।

भूपेंद्र कुमार

1605 में राजपाट संभालते ही जहांगीर ने सबसे पहले जंजीर-ए-अदल यानी इंसाफ की जंजीर लगाने का फैसला लिया। इसकी प्रेरणा ईरान और तुर्की के राजाओं की न्यायप्रियता से मिली थी।

बताया जाता है कि किसी को कहीं न्याय न मिले, तो वह किले के बाहर मौजूद उस रस्सी को खींच सकता था, जिससे जुड़ी घंटियों की आवाज सुनते ही जहांगीर तत्काल न्याय करता था। पर्यटकों को जब गाइड इस जंजीर का ब्योरा देते हैं, तो उनके चेहरे पर विस्मय दिखता है कि ऐसा कैसे होता होगा!

अब आते हैं बूढ़े घोड़े के इंसाफ पर। किस्सा कुछ ऐसा है कि जंजीर एक जगह से टूट गई थी, तो वहां घास की रस्सी बांध दी गई। एक दिन अचानक घंटी बजी, जहांगीर ने कारण पूछा, तो पता चला कि एक बूढ़े घोड़े ने उसे बजाया है। घोड़ा शायद जंजीर में फंसी घास खाना चाहता था। वह घोड़ा बादशाह ने ही सेनापति को भेंट किया था। बूढ़ा हो जाने पर सेनापति ने उसे यों ही छोड़ दिया था, जो भूखा होने के कारण इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा था। जहांगीर ने सेनापति को फटकारा और उसे पद से हटा दिया।

इंसाफ की जंजीर का विचार इतना लोकप्रिय हुआ कि वर्ष 1955 में इस पर एक फिल्म बनी, अदल ए जहांगीर, जो काफी हिट हुई।

दरअसल, 1605 में राजपाट संभालते ही जहांगीर ने सबसे पहले जंजीर-ए-अदल यानी इंसाफ की जंजीर लगाने का फैसला लिया। इतिहासकारों के मुताबिक, जहांगीर ने ईरान और तुर्की के राजाओं की न्यायप्रियता के बारे में जाना, तो उसने अपने यहां भी ऐसा प्रयोग करने का मन बना लिया। ब्रिटिश राजदूत सर टामस रो ने लिखा है, यह जनता के लिए बहुत ही कारगर व्यवस्था थी।

जहां जहांगीर की न्यायप्रियता के किस्से आम थे, वहीं इसका दूसरा पहलू भी था। पिता बादशाह अकबर अपने प्रिय शहजादे सलीम (जहांगीर के बचपन का नाम) की क्रूरता से परेशान थे। जहांगीर ने एक बार नाराज होकर एक जिंदा आदमी की खाल खिंचवा दी थी। तब बादशाह अकबर काफी विचलित हुए थे। जहांगीर ने अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की भी हत्या कराई, जिससे अकबर को भारी धक्का लगा। पर कोई दूसरा वारिस नहीं होने की वजह से अकबर उसे माफ करता रहा। इंसाफ की जंजीर का विचार इतना लोकप्रिय हुआ कि वर्ष 1955 में इस पर एक फिल्म बनी, *अदल ए जहांगीर*। इसमें प्रदीप कुमार और मीना कुमारी ने अभिनय किया। फिल्म हिट रही। ...शायद त्वरित न्याय का फॉर्मूला हमेशा ही हिट रहा है।

आंकड़े

गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर

वर्ष 1977 में देश में 63.11 फीसदी लोग 2.15 डॉलर प्रति दिन पर गुजारा कर रहे थे, पर अब मात्र 11.9 फीसदी लोग ही अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं।

2021	11.9%
2015	18.73%
2004	39.91%
1993	47.64%
1877	63.11%

स्रोत : OWID; WB

मन में किसी की सेवा-सहायता का विचार आए, तो उसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। पर बुरे काम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

उपदेश का सुफल

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

महर्षि गौतम ने एक दिन अपने पुत्र चिरकारी को बताया कि मन में किसी की सेवा-सहायता का विचार आए, तो उसे तुरंत पूरा करना चाहिए, अन्यथा देर करने पर मन बदल सकता है। लेकिन अगर प्रतिशोध या हिंसा का विचार आए, तो कुछ देर रुककर कदम उठाना चाहिए।

महर्षि गौतम एक बार अपनी पत्नी से किसी बात पर नाराज हो गए। उन्होंने चिरकारी को तलवार देते हुए आदेश दिया कि अपनी माता की हत्या कर दो। आदेश देकर वह वन चले गए। चिरकारी को अपने पिता के उपदेश याद आ गए कि हिंसा के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तलवार एक ओर रख दी और भगवान का भजन करने लगे।

महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ, तो उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने पत्नी की हत्या का आदेश देकर गलती की है। वह भागे-भागे आश्रम में पहुंचे। चिरकारी से पूछा, क्या तुमने माता की हत्या कर दी?

चिरकारी ने कहा, आपने ही तो कहा था कि बुरे काम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हत्या नहीं की, अब कहिए तो किए देता हूं। महर्षि ने उससे तलवार छीनकर नदी में फेंक दी। उन्हें संतोष था कि वर्षों पहले दिए गए मेरे उपदेश ने चिरकारी को मातृ हत्या के पाप से बचा लिया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 25 जनवरी, 1957

ख़ुश्चेव एवं मेलिनकोव में उच्च पद के लिए खींचतान

ख़ुश्चेव व मेलिनकोव में खींचतान

रूस से आ रही खबरों के मुताबिक, सोवियत सत्ता में उच्चतम स्थान पाने के लिए ख़ुश्चेव और मेलिनकोव के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। प्रेक्षकों का मानना है कि इसलिए उम्मीद से पहले सोवियत संसद का सत्र बुलाया जा रहा है।

तपते द्वीप में बदलते शहर

कार्य अवधि में बदलाव, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण जैसे उपायों से गर्मी के असर को कम किया जा सकता है।

पंकज चतुर्वेदी | मौसम

अप्रैल शुरू होते ही एक तरफ मौसम विभाग ने चेताया कि गर्मी और लू का असर झेलने के लिए तैयार हो जाएं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने भी राज्यों को बता दिया है कि बढ़ती गर्मी पर निगाह रखें और लोगों को इससे सतर्क रहने के लिए जागरूक करें। गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, खासकर यहां शहरों में तपन का एहसास समय से पहले और सीमा से अधिक है।

खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कई छोटी-मंझोली नदियों का घर है और कभी घने जंगलों के लिए जाना जाता था, बुंदेलखंड की तरह तीखी गर्मी की चपेट में है। हरित प्रदेश कहलाने वाला यह इलाका आने वाले दशकों में बुंदेलखंड की तरह सूखे-पलायन-निर्वनीकरण का शिकार हो सकता है। जिन क्षेत्रों में शहरीकरण का विस्तार तेजी से हुआ, वहां लू और गर्मी का विस्तार अधिक हुआ।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों में अब हर साल लगभग 272 दिनों को 'लू – दिन' के रूप में दर्ज किया जा रहा है। तकनीकी भाषा में इसे 'अर्बन हीट आइलैंड' अर्थात शहरी ताप द्वीप कहा जा सकता है। जब किसी शहर में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले तापमान अधिक बढ़ जाता है, तो उसे अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। ऊंची इमारतें, छायादार पेड़ों की कमी, जल-निधियों जैसे तालाब-जोहड़ और नदी के दायरे का घटना-ऐसे कारण हैं, जो शहर में गर्मी की मार को जानलेवा बना देते हैं। इसके कुप्रभावों को चौगुना करने में कंकरीट से बनी ऊंची इमारतें, एयरकंडीशनर से निकलने वाली गर्मी, वाहनों से उत्सर्जित ऊष्मा और यातायात थमने से उपजी गैस भी शहरों को तपा रही हैं।

जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट-2022 के अनुसार, वर्ष 2021 में भीषण गर्मी के चलते भारत में सेवा, विनिर्माण, खेती और निर्माण क्षेत्रों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। गर्मी बढ़ने से 167 अरब घंटे संभावित श्रम का नुकसान हुआ, जो वर्ष 1999 के मुकाबले 39 प्रतिशत अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, तापमान में डेढ़ फीसदी इजाफा होने पर बाढ़ से हर साल होने वाला नुकसान 49 प्रतिशत बढ़ सकता है। गर्मी बढ़ेगी, तो समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा और इससे उपजने वाले चक्रवात से होने वाली तबाही में भी इजाफा होगा।

लेंसेट काउंट डाउन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में वर्ष 2000-2004 और 2017-21 के बीच भीषण गर्मी से होने वाली मौतों में 55 प्रतिशत का उछाल आया है। बढ़ते तापमान से स्वास्थ्य प्रणाली पर हानिकारक असर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने भारत में एक लाख लोगों के बीच सर्वे कर एक रिपोर्ट में बताया है कि गर्मी/लू के कारण गरीब परिवारों को अमीरों की तुलना में पांच फीसदी अधिक आर्थिक नुकसान होगा। आर्थिक रूप से संपन्न लोग बढ़ते तापमान के अनुरूप अपने कार्य को ढाल लेते हैं, जबकि गरीब ऐसा नहीं कर पाते।

शहरों का बढ़ता तापमान न केवल पर्यावरणीय संकट बढ़ाएगा, बल्कि सामाजिक-आर्थिक त्रासदी और असमानता का कारक भी बनेगा। गर्मी सिर्फ स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि इससे इंसान की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। गर्मी बढ़ने पर पानी, बिजली की मांग के साथ उत्पादन लागत भी बढ़ती है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शीर्ष वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के मुताबिक, बढ़ती आबादी और गर्मी के कारण देश के चार बड़े शहर-दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बाहरी भीड़ को नहीं रोका गया, तो तापमान तेजी से बढ़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित होगा।

ऐसे में जरूरी है कि शहरों में रहने वाले श्रमजीवियों को लू-गर्मी के कुप्रभावों से बचाने के लिए अनुकूल परिवेश और कार्य समय निर्धारित किया जाए। मजबूरी में खुले में काम करने वाले लोगों के लिए छांव, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार एवं समाज, दोनों को साथ आना होगा। उमस भरी गर्मी और लू से राहत के लिए अधिक छायादार पेड़ों को लगाना जरूरी है। शहर के बीच से बहने वाली नदियां, तालाब, जोहड़ आदि यदि निर्मल और अविरल रहेंगे, तो ये गर्मी सोखने में सक्षम होंगे। कार्यालयों के समय में बदलाव, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, बहुमंजिला भवनों को पर्यावरण अनुकूल बनाना, ऊर्जा संचयन सहित कुछ ऐसे उपाय हैं, जो कम लागत में शहरों को भट्ठी बनने से बचा सकते हैं। दूरगामी उपाय के तहत शहरों की तरफ बढ़ रहे पलायन को रोकना ही होगा।

edit@amarujala.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

सभी चिकित्सा पद्धतियों का मिले जनता को लाभ

देश में चिकित्सा की अलग-अलग पैथियों पर चर्चा होती रहती है। खासकर एलोपैथी के मुकाबले अन्य पैथियों के साथ हीन व्यवहार किए जाने का मुद्दा अक्सर चर्चा में रहता है। एलोपैथी से इतर पैथियों से जुड़े विशेषज्ञों में यह भाव घर किया हुआ है कि उन्हें एलोपैथी के चिकित्सकों जैसा महत्त्व नहीं मिलता। इसे इस वृहद परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि अन्य पैथियों को तवज्जो न देना उनके विशेषज्ञों-संचालकों के हितों पर कुठाराघात है। इन पैथियों से जो लाखों करोड़ों मरीज लाभान्वित हो सकते हैं, उन्हें इस लाभ से वंचित करना है। यह अच्छी बात है कि इस संबंध में लगातार आवाजें उठती रही हैं और इनका असर भी कालांतर में किसी न किसी रूप में सामने आता रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार को उसकी आयुष्मान भारत योजना में एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा उपचार को शामिल करने पर विचार की जो व्यवस्था दी है, उसे इसी असर के रूप में देखा जा सकता है। सरकार ने इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार का जो आश्वासन दिया है, वह स्वागतयोग्य है। इसके बाद सरकार से अपेक्षा यह होगी कि वह उन कारणों और अवरोधों की पहचान करे जो इन पैथियों को बढ़ने से रोके हुए हैं। इसकी जरूरत इसलिए है कि हम दावा करते रहे हैं कि केवल और केवल हमारे पास ही आयुर्वेद का समृद्ध खजाना है। दुनिया में इसके फैलाव की भी हम अपेक्षा करते हैं। पर, जब अपने देश में ही इसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दुनिया हमारी इस पैथी को गले लगाएगी। इसमें तो कोई संशय नहीं कि आयुर्वेद कारगर चिकित्सा पद्धति है और वह बड़ी से बड़ी व्याधियों को दूर करने में सक्षम है। एलोपैथी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश में इसमें नित नए अनुसंधान भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज ने पैरासिटामोल की तरह उतने ही समय में बुखार उतारने वाली आयुर्वेदिक गोली तैयार करने का दावा किया है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सरकार के स्तर पर ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है, जिसमें ऐसी रिसर्च और उपलब्धियों को परखा जा सके और फिर आधिकारिक दावे के साथ जनता को सहज सुलभ करवाया जा सके।

उपलब्ध परंपरागत ज्ञान व संपदा को भी आधुनिक वैज्ञानिक धरातल की कसौटी पर परखकर उसकी उपयोगिता पर मुहर लगाई जाएगी, तो उसके प्रचलित होने के आसार बढ़ेंगे। तंत्र सही तरीके से काम करे और वह किसी भी तरह के दबाव से दूर रहे, यह भी सुनिश्चित करना होगा। आम जन का इसमें विश्वास तभी बनेगा। आयुर्वेद और अन्य पैथियों के बढ़ावे के लिए यह विश्वास जरूरी है। इससे एलोपैथी पर मरीजों की निर्भरता भी कम होगी और चिकित्सा का नेटवर्क मजबूत होगा।

आकांक्षापूर्वक किया हुआ कर्म शरीर बन्धन का, नवीन योनि प्राप्ति का कारण बनता है। अतः ऐसा कामात्मा किसी न किसी शरीर के छन्द से जुड़कर ही लोकों में गमन करता है। कामना से संबंधित आत्मा की गति तय करने वाला छन्द ही कामछन्द कहलाता है।

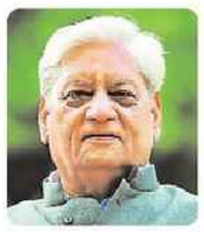

कर्मगति

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर में छन्दित (आवरित) रहता है। सूक्ष्म शरीर के कर्मानुसार दो विवर्त हो जाते हैं- अकामछन्द और कामछन्द। जो बुद्धियोगी निष्काम कर्म करते हुए संस्कार बन्धन से विमुक्त रहते हैं, वे निष्काम कर्मयोगी होते हैं।

प्रत्येक वस्तु का एक केन्द्र और परिधि (आकृति) होती है। सभी पदार्थ वयुन कहे जाते हैं। वय और वयोनाध की समष्टि वयुन है। सत्तासिद्ध तत्त्व वय है, भातिसिद्ध तत्त्व वयोनाध है। मन-प्राण-वाक् 'अस्ति' हैं, नाम-रूप-कर्म 'भाति' हैं। अस्ति आत्मा है, भाति आत्मा का शरीर है। वयोनाध को ही छन्द भी कहा जाता है। आत्म तत्त्व स्वयं में अखण्ड है, किन्तु पंचमहाभूत-त्रिगुण प्रकृति भाव से नानारूप दिखाई देता है। समस्त चौरासी लाख योनियां छन्द हैं। छन्द भेद से वस्तु भेद का ज्ञान होता है। छन्द भेद के हटते ही वस्तु पुनः अखण्ड रूप में आ जाती है।

शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर में छन्दित (आवरित) रहता है। सूक्ष्म शरीर के कर्मानुसार दो विवर्त हो जाते हैं-अकामछन्द और कामछन्द। जो बुद्धियोगी निष्काम कर्म करते हुए संस्कार बन्धन से विमुक्त रहते हैं, वे निष्काम कर्मयोगी होते हैं। तीनों शरीरों-स्थूल, सूक्ष्म और कारण में से कोई भी इनके आत्मा को बांध नहीं सकता। ये विदेह कहलाते हैं। इन आत्माओं का छन्द आकाश है और यही इनकी मुक्तिगति का निमित्त बनता है। कर्मयोगी की गति क्या होती है, इसका उपदेश देते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित (कामना रहित), ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शान्ति को प्राप्त होता है। हे पृथानन्दन ! यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अन्तकाल में भी स्थित हो जाय, तो निर्वाण (शान्त) ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है-

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः।
निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति।। (गीता 2.71)
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।। (गीता 2.72)

आकांक्षापूर्वक किया हुआ कर्म शरीर बन्धन का, नवीन योनि प्राप्ति का कारण बनता है। अतः ऐसा कामात्मा किसी न किसी शरीर के छन्द से जुड़कर ही लोकों में गमन करता है। कामना से संबंधित आत्मा की गति तय करने वाला छन्द ही कामछन्द कहलाता है। इसमें जब विद्या युक्त कर्म (यज्ञ-तप-दान) की प्रधानता रहती है तब इसका प्राण भाग प्रबल रहता है। जिससे इसका स्थूल शरीर भी प्राणमय कोश के साथ प्राणात्मक हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर का अंग बन जाता है, अतः इसे देवछन्द कहते हैं। देवछन्द ही देवयान मार्ग का प्रेरक बनता है। यदि कर्म विद्या निरपेक्ष-इष्ट, आपूर्त और दत्त होते हैं तो भूत भाग (वाक्) प्रबल रहता है। यही पितृछन्द है, जो पितृयान मार्ग का सूत्रधार बनता है। पितृछन्द से छन्दित कामात्मा आधिदेविक पितृयान की ओर ही गति करता है। यहां प्राण का अर्थ सौर दिव्य प्राण हैं तथा पार्थिव भू-भाग ही वाक् है।

सौर प्राण अमृत-मृत्यु रूप हैं। अमृत प्राण आत्म प्राण है। पूर्ण रूप से असंग है। पृथ्वी की ओर प्रवाहित प्राण मर्त्य प्राण है। ये देव प्राण भी कहलाते हैं। भूत सृष्टि से इनका गहरा सम्बन्ध (अनुशय) रहता है। विद्या युक्त प्रवृत्ति कर्म, विद्या निरपेक्ष निवृत्ति कर्म, लौकिक निवृत्ति कर्म (यज्ञ-तप-दान) में प्राज्ञ आत्मा में आत्म प्राण ही प्रधान रहता है। अतः इनकी आत्मगति का मार्ग 'ब्रह्मपथ' है क्योंकि यही क्रममुक्ति का निमित्त बनता है। यदि इन कर्मों में आसक्ति भाव आ जाता है तो ये ही देवयान प्राप्ति के कारण बनते हैं। विद्यायुक्त प्रवृत्ति कर्म में देवप्राण प्रमुख होता है। अतः इसका सूक्ष्म शरीर भी देवप्राण रूप ही रहता है और इनका पथ देवपथ कहलाता है। जो इनकी देवसर्ग गति का निमित्त बनता है। ब्रह्म पथ में पुनः आगमन नहीं है। देवगति में पुनरावर्तन, फिर से लौटना है।

दूसरा भाग पार्थिव वाग् भाग है। सूर्य सापेक्ष पृथ्वी के अदिति-दिति दो भाग माने हैं। प्रकाशित भाग अदिति है, अंधकार (छाया) भाग दिति है। अदिति का सम्बन्ध विद्या निरपेक्ष कर्मों-इष्ट, आपूर्त, दत्त से है। इसी प्रकार निरर्थक-विरुद्ध-स्वार्थ तीनों लौकिक प्रवृत्ति कर्मों का सम्बन्ध दिति से है। दोनों ही कर्म वाङ्मय हैं। पितृतत्त्व मर्त्यवाक् प्रधान हैं। अतः ये दोनों प्रकार के कर्म पितृयान पथ की प्राप्ति के निमित्त बनते हैं। अदिति-पृथ्वी से जुड़े विद्या निरपेक्ष कर्मों के संस्कार से अध्यात्म में ज्योति भाग की प्रधानता रहती है। इन ज्योति प्रधान प्रेतात्माओं का पथ पितृपथ कहा जाता है। यही पितृस्वर्ग गति का निमित्त बनता है। यदि अध्यात्म में दिति पृथ्वी से जुड़े तमोगुणी- निरर्थक-विरुद्ध-स्वार्थ कर्मों का संस्कार रहता है, तब आध्यात्मिक तम भाग विकसित हो जाता है। अतः प्रेतात्मा का सूक्ष्म शरीर भी तम प्रधान हो जाता है। यही यमपथ है। आधिदेविक यमपथ नरकगति का निमित्त बनता है।

भूत और प्राण दोनों का ही सूक्ष्म शरीर कारण-ग्रन्थि खुलने तक सुरक्षित रहता है। कारण शरीर में फलभोग के लिए कर्म का हिसाब संचित रहता है। '**अन्यन्नवतरं कल्याणतं रूपं कुरुते**' (बृहद् आ. उ 4/4/4) कर्मफलानुसार गति तय होने पर स्थूल शरीर छोड़कर जाने वाला आत्मा सूक्ष्म भूतमात्राओं के साथ युक्त होकर नये सूक्ष्म शरीर का कर्मानुसार ग्रहण करता है। अर्थात् शुभाशुभ कर्मयोग के लिए नया सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। यह केवल भोग शरीर है, जिसमें प्रेतात्मा कोई स्वतंत्र कर्म नहीं करता। मनुष्य योनि के स्थूल शरीर में स्वतंत्र कर्म संभव है।

प्रेतात्मा को कर्मानुसार सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। भूतात्मा के साथ प्राणमात्रा का भी इस शरीर में समावेश हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के भीतर ही प्राण तत्त्व रहता है। स्थूल शरीर को ही देवता का वाहन कहा जाता है। यह देवप्राण ही शरीर की स्वरूप रक्षा करता है।

ऋषि प्राण ज्ञान प्रधान है-आकाश भूत से सम्बद्ध है। ऐसे प्राणयुक्त मुक्त आत्माओं का शरीर भी आकाशात्मक बन जाता है। पंचपर्वात्मक विश्व में आगे पितर-देव-गंधर्व-वैश्वानर प्राण हैं। चन्द्रमा के गंधर्व प्राण तो परमेष्ठी के पितर प्राणों में ही समन्वित रहते हैं। शेष चार प्राणों में पितर प्राण तथा पारमेष्ठ्य आसुर प्राण का एक युग्म है तथा सौर देव प्राण तथा पार्थिव आग्नेय प्राण का एक युग्म है। पहला युग्म पितृयान तथा दूसरा युग्म देवयान का निमित्त बनता है। देवयान पथ अग्नि-वायु-आदित्य रूप है। पितृयान पथ प्राण आपः-वायु-सोम रूप है। कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर में जिस भूत का विकास रहता है, वही प्राण उस शरीर में मुख्य रूप से विकास पाता है। तीनों प्रकार के निवृत्ति कर्मों से अग्नि-वायु-आदित्य (असंग-सौर प्राण) की सूक्ष्म शरीर में प्रधानता रहती है। यही क्रम मुक्ति का निमित्त रूप ब्रह्मपथ है। सौर प्राणाग्नि (प्रवर्ग्य) ही पार्थिव प्राणाग्नि है। अतः दोनों का समान युग्म है।

विद्या निरपेक्ष प्रवृत्ति कर्म से आत्मा का सोमात्मक पितृप्राण विकसित होता है। सूक्ष्म शरीर में भी सोम-पितृप्राण का ही भाव रहता है। यही पितृपथ है। अग्नि का सोम (वीघ्र अर्थात् चिकनाई युक्त) पर प्रतिबिम्ब पड़ता है। अतः पितृप्राण आंशिक रूप से ज्योतियुक्त रहता है। यह ज्योति तत्त्व ही स्वर्ग प्राप्ति का निमित्त बनता है। इसके विपरीत निरर्थक-विरुद्ध-स्वार्थ कर्मों में पारमेष्ठ्य आसुर प्राण (दिति) प्रवृत्त रहता है। परमेष्ठी का आपः असुर प्राण की तथा सोम पितृप्राण की प्रतिष्ठा है। वायव्य प्राण गंधर्व है। आप्य प्राण भूपिण्ड से युक्त है। गंधर्व एवं पितर प्राण चन्द्रमा से युक्त हैं। आपः-वायु-सोम तीनों प्राण परमेष्ठी के हैं। अतः चन्द्र (पितृ) तथा पारमेष्ठ्य प्राण का एक युग्म है। सत्कर्म से सौम्य पितृ प्राण विकसित रहता है (विद्यानिरपेक्ष प्रवृत्ति में), तथा असत् कर्म से आप्य आसुर प्राण विकसित रहते हैं। आसुरी प्राण की सूक्ष्म शरीर में प्रधानता ही यमपथ-नरक गति का निमित्त है।

क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

स्वास्थ्य दिवस कल

हर मरीज को कैसे मिले उपचार

मरीज और उपचार के बीच साधन-संसाधन की खाई पट नहीं रही। दूरदराज क्षेत्र के साथ अशिक्षित लोग अब भी स्वास्थ्य सेवाओं से छिटके हुए हैं। शहरों तक का आलम ऐसा है कि अधिकांश लोग बीमारी में पहला इलाज मेडिकल की दुकान से ही शुरू करते हैं। सेहत को लेकर सीधे चिकित्सक या अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या एक चौथाई भी नहीं है। हालत यह है कि बढ़ती अत्याधुनिक सुविधा के बीच भी अनगिनत मरीज उपचार से छूट रहे हैं। इसके कारणों की एक लम्बी फेहरिस्त है जो मरीज के उपचार में रुकावट बन रहे हैं। हालत यह है कि इमरजेंसी फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर्स और जनरल सर्जन की शहरों में कमी होना शुरू हो गई है। बीस-पच्चीस साल पहले तक एमडी/एमएस तक का चलन था। अब सुपर स्पेशलिटी का दौर चरम पर है। अलग-अलग रोग की विशेषज्ञता की शिक्षा प्राप्त कर चिकित्सक बनना अब पहली प्राथमिकता हो गया है। मध्यम वर्ग के साथ निम्न वर्ग पर आर्थिक भार बढ़ा है और सामान्यतया जनरल प्रैक्टिशनर्स और फैमिली फिजिशियन की कमी की वजह से सही सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक तक पहुंचने की कड़ी भी खत्म होती जा रही है। देश की अधिकांश जनता को फायदा तभी होगा जब गांव में चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होगी।

डॉ. ईश मुंजाल
सदस्य, स्टेट गवर्निंग बॉडी, नेशनल हेल्थ मिशन, राजस्थान
@patrika.com

मेडिकल शिक्षा में सुधार के साथ चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने की बात तो महत्त्वपूर्ण है ही पर लोगों के खुद के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी खत्म करनी होगी। भारतीय मेडिकल छात्र ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते जो उन्हें चिकित्सकों के रूप में सामाजिक जवाबदेही प्रदान करता हो। भारत में करीब साढ़े ग्यारह हजार लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर और साढ़े चार सौ लोगों पर एक नर्स है। अगर मेडिकल शिक्षा के साथ बढ़ते परिवर्तन को बैलेंस नहीं किया जाएगा तो पर्याप्त डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता बरकरार रहेगी। सीमित बुनियादी ढांचे में सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके लिए पहले बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा।

नारी शक्ति वंदन में यूपी और पश्चिम बंगाल अव्वल

महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक संसद में पारित हो गया है, लेकिन उसे अभी लागू नहीं किया जा सका है। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह तथ्य सामने आता है कि महिलाओं को टिकट देने में राजनीतिक दल ज्यादा रुचि नहीं लेते। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी महिलाओं की भागीदारी कम रही है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 724 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और इनमें से 78 महिलाएं लोकसभा में चुनकर पहुंची। ओडिशा में 21 में से 7 महिला सांसद हैं। सीटों के अनुपात के हिसाब से यह संख्या सभी राज्यों से अधिक है। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटों पर कुल 106 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। वहीं महाराष्ट्र में 79 और बिहार में कुल 56 महिलाओं ने चुनाव में भाग्य आजमाया था। इसी तरह मध्यप्रदेश में 40, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 23-23 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। कई राज्य ऐसे हैं जहां से कोई भी महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाई।

लोकसभा चुनाव 2019 : चुनी गईं महिला सांसद — कुल 78 (महिला सांसद)

राज्य	महिला सांसद
यूपी	11
प. बंगाल	11
महाराष्ट्र	8
ओडिशा	7
गुजरात	6
आंध्र प्रदेश	4
मध्यप्रदेश	4
बिहार	3
छग	3
राजस्थान	3
तमिलनाडु	3
झारखंड	2
कर्नाटक	2
पंजाब	2

एक-एक असम, चंडीगढ़, हरियाणा, केरल, मेघालय, दिल्ली, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड से

झारखंड : सीता सोरेन को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार, 'इंडिया' गठबंधन उम्मीदवार तय करने में पीछे

'गुरुजी' के परिवार में सेंधमारी, झामुमो को पड़ रही भारी

रांची
प्रियरंजन भारती

गुरुजी इन दिनों भले राजनीति में सक्रिय ना हों, लेकिन उनकी सीट 'दुमका' जरूर झारखंड ही नहीं समूचे देश में चर्चा का केन्द्र बनी हुई है। दुमका वो सीट है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जीत की 'हैट्रिक' लगा चुके हैं। उसी दुमका सीट पर भाजपा ने इस बार सोरन परिवार में सेंध लगाकर झामुमो के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भाजपा ने सोरेन की बहू सीता सोरेन को पार्टी टिकट पर मैदान में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बंवडर ने इन दिनों झारखंड की राजनीति को गरमा रखा है। सीता, हेमंत सोरेन की भाभी हैं।

झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन उम्मीदवार तय करने में अब भी बहुत पीछे चल रहा है। कांग्रेस के तीन और भाकपा माले के एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। पूरे उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। इनके चयन के लिए मशक्कत चल रही है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, झामुमो और राजद के बीच अभी सीटों को लेकर क्लियर कट बंटवारा नहीं हो पाया है। राजद झारखंड में पलामू और चतरा की सीटों की चाहत रखता है। लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने झारखंड में एक से ज्यादा सीटें देने पर राजद को साफ मना किया है। अब इस स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा, सीट बंटवारे में कांग्रेस पलामू और चतरा दोनों सीटें राजद को देती है, या उसे एक सीट से संतोष करना पड़ता है। हालांकि बिहार में सीट बंटवारे के दरम्यान लालू प्रसाद ने कांग्रेस को यह साफ कर दिया था कि बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें इसी शर्त पर दी जा रही हैं कि झारखंड में पलामू और चतरा की सीट राजद हर हाल में लेगा।

झारखंड की राजनीति में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद सभी दलों की चिंता बढ़ गई है। मतदाता सब देख रहा है, लेकिन खामोश है।

धनबाद में उम्मीदवार को लेकर बवाल

कोयलांचल में कोयले की राजधानी धनबाद सीट पर भाजपा के उम्मीदवार ढुलू महतो को लेकर बवाल मचा हुआ है। ढुलू महतो धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। महतो का अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा धनबाद संसदीय क्षेत्र में दबदबा है। उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय व्यापारियों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से की है। इसे लेकर भाजपा उम्मीदवार खासे नाराज हैं। व्यापारियों के समर्थन में भाजपा के पूर्व विधायक और मंत्री सरयू राय धनबाद के मैदान में कूद पड़े हैं।

गांडेय से चुनाव लड़ेंगी कल्पना

गांडेय विधानसभा उप चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी लड़ेंगी। यह उप चुनाव भी किसी भी हाल में राज्य के सबसे हॉट सीट के मुकाबले कम नहीं होगा। इस उपचुनाव का परिणाम झारखंड में झामुमो की आगे की राजनीति और रणनीति को नई दिशा देगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही इस चुनाव में भी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। झारखंड की राजनीति में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद सभी दलों की चिंता बढ़ गई है। मतदाता सभी दलों की गतिविधियां देख रहा है, लेकिन खामोश है।

कमल खिलावन | **POLI नोक-झोंक** | **पंजा सिंह**

ये आए, वे गए

(झीलों की नगरी में पंजा सिंह उदास बैठे हैं। दोने में रबड़ी लिए कमल खिलावन बराबर बैठे हैं। चम्मच से रबड़ी का चटकारा लगाते हुए)

कमल खिलावन : *क्यों मुंह लटकाए हो बंधु!*

पंजा सिंह : *राष्ट्रीय प्रवक्ता, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी जी ने बुलाया था। बड़ी जिम्मेदारी देने वाले थे। यहां आए तो पता चला वे तो गए।*

कमल खिलावन : *जो कल तक तुम्हारा 'गौरव' था, अब हमारा गौरव है।*

पंजा सिंह: *मैं तो फैन था उनका। जब 2019 में एक टीवी चैनल की बहस में तुम्हारे बड़बोले प्रवक्ता से सवाल पूछा था कि फाइव ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, प्रवक्ता जी की बोलती बंद कर दी थी। मैं तब ही मुरीद हो गया था गौरव दादा का। उनके जैसा बनना चाहता था, पर ये क्या हो गया?*

कमल खिलावन : *तुम्हारे युवराज जी के ट्वीट री - ट्वीट करने वाले एक बॉक्सर भी हमारे यहां आ गए हैं। चल क्या रहा है तुम्हारे यहां।*

पंजा सिंह : *मजे ले लो। दिन हैं तुम्हारे। पर रिजल्ट आने दो, सारी हवा निकल जाएगी।*

कमल खिलावन: *बंधु। कैंडिडेट तो लाओ। बांसवाड़ा में एक दिन पहले तक कैंडिडेट फाइनल नहीं किया, गूगल पर सर्च कर रहे थे ।*

पंजा सिंह : *तुमने कौनसा मंगल ग्रह से उम्मीदवार उतारा, हमारे यहां से गए बंदे को टिकट दिया है।*

कमल खिलावन : *गुजरात में सुना है कैंडिडेट नहीं हैं, लिस्ट ही जारी नहीं कर पा रहे।*

पंजा सिंह : *प्रियवर, क्या आपके पास साउथ में कैंडिडेट हैं !*

कमल खिलावन: *मध्य प्रदेश में मध्यांतर हो गया है। आपका। लाख से ज्यादा का आंकड़ा है, जो आपके यहां से हमारे यहां आ गए।*

पंजा सिंह: *षड्यंत्र है ये आपका। ये लोकतंत्र नहीं।*

कमल खिलावन : *अब ये लोकतंत्र की बात तो करो ही मत। आपकी पार्टी ने तो बरसों तक डेमोक्रेसी का मजाक जो उड़ाया है।*

पंजा सिंह: *तो.. अब आप तो डिक्टेटर बन रहे हो। कभी गिरफ्तार करते हो, कभी नोटिस भेजते हो..*

कमल खिलावन: *अब पछताय होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है।*

पंजा सिंह : *सुनी है मैंने। बशीर बद्र का शेर आप भी सुन लो मान्यवर।*
गुरूर उस पर बहुत सजता है, मगर कह दो।
इसी में उस का भला है, गुरूर कम कर दे।

कमल खिलावन: *गुरूर.. लगता है.. सुरूर उतरा नहीं तुम्हारा। आओ हो जाएं दो दो हाथ।*

पंजा सिंह : *रुको.. (मोबाइल देखते हुए) मैसेज आया है.. अननोन नंबर से। कब तक पंजे में जकड़े रहोगे। कमल की तरह खिलना चाहो तो बताओ।*

कमल खिलावन : *दिखाओ तो..*

पंजा सिंह : *फ्लैश मैसेज था.. पढ़ते ही गायब..*

कमल खिलावन : *तुम भी आतिशी अंदाज में प्रेस कांफ्रेंस न कर दो, हो सकता है शायद मैसेज भी इसलिए गायब हुआ हो।*

पंजा सिंह : *अब मैं हो रहा हूं गायब। कोई भरोसा नहीं ये हमारे वालों का ही मैसेज हो, चैक कर रहे हों कि मैं क्या जवाब लिखता हूं। तुम्हारे तो पास बैठना ही गुनाह है इस वक्त। चल दिए अपन तो...*

(पंजा भाई नौ दो ग्यारह। कमल खिलावन बची हुई रबड़ी को उंगली में लपेट कर चटकारा लगाता है।)

- सुप्रिया शर्मा

आपकी बात

बाहरी दखल से परिवार में विवाद

परिवार जनों में व्यक्तिगत स्वार्थ व लालच बढ़ गया है। अहंकार भी इसमें बड़ी बाधा है। परिवार में बाहरी व्यक्ति की बातों को महत्त्व देकर घरवालों की उपेक्षा की जाती है। इससे परिवार के लोगों में कुंठा जन्म लेती है। सहनशक्ति की कमी व अपनी ही बातों को महत्व देना भी परिवार में विवाद का कारण है।

-भगवती प्रसाद गेहलोत, मंदसौर, मप्र

समन्वय और संवाद की कमी

समन्वय व संवाद की कमी भी परिवार में विवाद के कारण हैं। मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहने से आपस में समय देना कम हो गया है। परिवार के लोग अहंकार के कारण भी अपनी परेशानी साझा नहीं करते। हालत यह है कि आर्थिक युग में परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है। यह वाकई चिंताजनक स्थिति है।

- प्रहलाद यादव, महू, मध्यप्रदेश

आज का सवाल

विलासितापूर्ण जीवनशैली के क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

कड़ी कार्रवाई की जरूरत

वर्तमान का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अंधविश्वास को बेशक बढ़ावा दे रहा है। नेता अपने फायदे के लिए रीतिरिवाज व सामाजिक परिवेश की आड़ लेकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह वे जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी को भी अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।

- राकेश कुमार, जयपुर

अंधविश्वास का दुष्प्रभाव

यह विडंबना है कि जागरूकता और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद हमारा समाज अंधविश्वास के दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है। समाज में आज भी अंधविश्वास की जड़ें गहरे तक जमी हैं। नेता भी इसका कारण हैं। देश में आए दिन अंधविश्वास से जुड़ी अफवाहें जोर पकड़ती रहती हैं और इनकी आड़ में अपराध को अंजाम दिया जाता है।

-डॉ.अजिता शर्मा, उदयपुर